1

राजस्थान राज्य और अन्य इत्यादि

बनाम

भारत संघ इत्यादि

6 मई, 1977

[न्यायमूर्तिगण एम. एच. बेग, सी. जे., वाई. वी. चंद्रचूड़, पी. एन. भगवती, पी. के. गोस्वामी, ए. सी. गुप्ता, एन. एल. अंतवालिया और एस. मुर्तजा फजल अली]

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 131,256,257-गृह द्वारा सलाह

मंत्री, भारत संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री को अनुच्छेद 1 के तहत सुधार की सिफारिश करने के लिए दिनांकित किया। 163 राज्यपाल को अनुच्छेद के तहत विधान सभा को भंग करने के लिए। 174 (2) (बी)। - सलाह की प्रकृति, क्या मुकदमों और याचिकाओं में प्रार्थना के अनुसार कोई राहत दी जा सकती है।

शक्तियों के स्थूल पृथक्करण का सिद्धांत-न्यायालय के कर्तव्य की प्रकृति

नीतिगत मामलों और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के संबंध में भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 131। कला के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि। 356 - क्या ऐसी संतुष्टि मिल सकती है

केवल राज्यपाल की रिपोर्ट-ऐसे सती गुट पर सवाल उठाने की अदालत की शक्ति-कला का दूसरा भाग। 355 इसमें राज्य सरकार को अनुच्छेद 256,257 के तहत यूनिक सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानमंडल को भंग करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार को दिए गए निर्देश को शामिल किया गया है, चाहे ऐसा निर्देश असंवैधानिक, अवैध और अधिकार से बाहर हो।

भारत, 1950, अनुच्छेद 74,163,174,255,256,257,355 और 356 (1) (ए)। शब्द और वाक्यांश "राज्य" का अर्थ है "राज्य सरकार"-कॉन्स्टी भारत का संविधान, 1950, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के साथ पठित अनुच्छेद 367।

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 131-क्या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कला के तहत राहत देने के लिए न्यायालय। 131 ये "घोषणात्मक निर्णयों" तक ही सीमित हैं। भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 19 (1) (एफ), 31 और 32,195 और 356 -

विधानसभाओं के सदस्यों को अनुच्छेद के तहत अपना वेतन निकालने का अधिकार। 195— प्रकृति-चाहे वह विधायी सभा के विघटन की धमकी के परिणामस्वरूप हो या कला के तहत घोषणा। 356 (1) राज्य विधानसभाओं को भंग करने से याचिकाकर्ताओं/विधायकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है।

निषेधाज्ञा-स्थायी [अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश XXXIX सी. पी. सी. पढ़ें

उच्चतम न्यायालय नियम 1966 के आदेश XLVII के साथ-क्या यह अनुच्छेद के तहत एक घोषणा को चुनौती देने वाले मुकदमे में उचित राहत है। 356 .

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 95,131, के तहत एक मुकदमे की रखरखाव कला. 131 और अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं-भारत का संविधान, अनुच्छेद। 356 (1) राष्ट्रपति की शक्ति का दायरा और दायरा।

संविधान के अनुच्छेद 74 (1) के तहत "एक परिषद होगी - मंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे जो किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देंगे, सिवाय इसके कि संविधान द्वारा या उसके तहत

अपने विवेक से अपने या उनमें से किसी भी कार्य का प्रयोग करना आवश्यक है। दोनों कला के तहत। 74 और कला। 163 सवाल यह है कि क्या कोई है, और यदि है तो क्या, सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत, राज्यपाल

समय-समय पर विधान सभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद के तहत 172 (1) एक राज्य की विधान सभा, जब तक कि जल्द ही भंग नहीं हो जाती है, तब तक जारी रहेगी।

इसकी बैठक के लिए निर्धारित तिथि से छह साल के लिए और अब नहीं और छह साल की उक्त अवधि की समाप्ति विघटन के रूप में कार्य करेगी। सभा से। अनुच्छेद 256 और 257 में आदेश दिया गया है कि संघ का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो प्रतीत हों।

भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक होना। कला के तहत। 355 , " यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि सरकार प्रत्येक राज्य को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है यह "। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को सभी या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी संभालने का अधिकार देता है। राज्य सरकार के कार्यों और सभी या किसी भी शक्ति [1978] 1 एस. सी. आर.

राज्यपाल या किसी निकाय या किसी प्राधिकरण में निहित या प्रयोग करने योग्य राज्य के विधानमंडल के अलावा अन्य राज्य, यदि से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी राज्य का राज्यपाल या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट है कि राज्य में कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसे राज्य सरकार के अनुसार नहीं चलाया जा सकता संविधान के प्रावधान। कला की उप-धारा (5) के तहत। 356 " नहीं।

संविधान में कुछ भी होने पर, राष्ट्रपति की संतुष्टि खंड (1) अंतिम और निर्णायक होगा और इस पर किसी भी मामले में सवाल नहीं उठाया जाएगा।किसी भी आधार पर अदालत। लोकसभा जिसमें कांग्रेस (आर) के पास भारी बहुमत था

8 जनवरी, 1977 को भंग कर दिया गया था, हालांकि संविधान के तहत (42) संशोधन अधिनियम) इसके पास अपना विस्तारित कार्यकाल समाप्त करने के लिए एक और वर्ष था। में मार्च 1977 में हुए नए चुनावों में सत्तारूढ़ दल ने अपना बहुमत खो दिया और चला गया।

सत्ता से बाहर जिसका उसने स्वतंत्रता के बाद से प्रयोग किया था। 24 मार्च, 1977 को, जनता पार्टी जिसके पास था। भारी बहुमत से जीता वोट मतदाताओं ने केंद्र में नई सरकार का गठन किया। जिस तारीख को जनता सरकार ने पदभार संभाला, कांग्रेस (आर) विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता में थी बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

18 अप्रैल, 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री ने एक पत्र को संबोधित किया

कि वे अपने-अपने राज्यों के राज्यपालों को यह सलाह दे सकें कि वे अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधानसभाएँ। 174 (2) (ख) और एक की तलाश करें टेर का पत्र "संवैधानिक उदाहरणों और लोकतांत्रिक के अनुरूप" होगा। अभ्यास "।

22 अप्रैल, 1977 को "स्पॉट लाइट प्रोग्राम ऑफ ऑल" में एक साक्षात्कार में इंडिया रेडियो, श्री शांति भूषण, विधि, न्याय और कंपनी मंत्री मामलों ने कहा कि "के विघटन के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था चूंकि "लोगों के विश्वास का आनंद लेने पर एक गंभीर संदेह पैदा हो गया है, हाल के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को खारिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट उक्त साक्षात्कार 'स्टेट्समैन' सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। 23 अप्रैल को। रिपोर्ट की शुद्धता विवादित नहीं है।

छह वादी-राज्य, अर्थात् राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा ने इस अदालत में याचिका दायर की संविधान के अधिकार और वादी पर बाध्यकारी नहीं और इसके लिए प्रार्थना की केंद्र सरकार को सहारा लेने से रोकने वाला एक अंतरिम निषेधाज्ञा छह साल की निश्चित अवधि समाप्त होने तक विधानसभाओं को भंग करने के लिए कोई भी

कदम उठाना। पंजाब विधान सभा के कुछ सदस्य उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए एक रिट याचिका भी दायर की थी और इसी तरह के निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की थी।

वादियों की ओर से प्रमुख सामान्य प्रस्तुतियाँ और साथ ही याचिकाकर्ता थे:सबसे पहले, कि 18 अप्रैल 1977 का पत्र एकमात्र आधार का खुलासा करता है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक आसन्न घोषणा के बाद संबंधित राज्य की विधान सभा का विघटन और कि ऐसी घोषणा, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से छह राज्यों में मिनी मुकदमों को खारिज कर दिया जाता है और उनकी विधान सभाओं को भंग कर दिया जाता है पत्र में दिए गए आधार प्रथम दृष्टया कला के दायरे से बाहर हैं। 356 यह संविधान का उल्लंघन होगा और संघीय ढांचे के लिए विनाशकारी होगा।

दूसरा, कि, किसी भी मामले में, के विघटन के लिए पूर्ववर्ती शर्त राज्य विधानसभा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की कार्रवाई का अनुसमर्थन है। 356 ताकि संसद के दोनों सदनों की इच्छाओं को सुनिश्चित किए बिना किसी भी दर से विधानसभा का विघटन न हो सके।

तीसरा, जो आधार दिए गए हैं, वे संवैधानिक रूप से अधिकृत नहीं हैं।

उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। बचाव में उत्तरदाताओं का जवाब है:

सबसे पहले, कि मैदानों में लगाए गए आरोपों पर कोई भी मुकदमा इसके दायरे में नहीं आ सकता है कला का दायरा। 131 संविधान जो राज्यों की शिकायतों के लिए है, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्यों के संवैधानिक या अन्य कानूनी अधिकारों को शामिल किए बिना राज्य सरकारों और विधानमंडलों की मात्र संरचना से संबंधित नहीं है।

दूसरा, एक के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं " अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की मांग करना, अपने स्वभाव से, गैर-न्यायोचित है और उन्हें कला द्वारा स्पष्ट रूप से गैर-न्यायोचित भी बनाया गया है। · 356 (5) ताकि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कार्रवाई की वांछनीयता या आवश्यकता के बारे में, भले ही किसी राज्य को अपनी सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद में कानूनी और उचित रूप से रुचि रखने वाला कहा जा सके, ऐसा विवाद क्षेत्र से बाहर है।

न्यायोचित मामलों में। यदि अंतिम कार्रवाई या उसके आधार न्यायोचित नहीं हैं, तो उन पर अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी प्रक्रिया को चुनौती देकर हमला नहीं किया जा सकता है जो वास्तव में अनुमानित परिणाम या कार्रवाई का कारण बन सकती है या नहीं भी।

तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री का पत्र और उनका भाषण

केंद्रीय कानून मंत्री ने यह संकेत नहीं दिया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के व्यापक दायरे से बाहर आने वाली किसी भी चीज को अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करने के लिए ध्यान में रखा जा रहा है या लिया जाएगा। 356. इसलिए, वहाँ बताए गए मामलों पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं कहा जा सकता है।

चौथा, केवल कुछ तथ्यों की सूचना, पूरी तरह से इसके दायरे में कला. 356 संविधान की धारा, अनुच्छेद के तहत कार्रवाई के लिए भविष्य में कार्रवाई करने के लिए निषेध को उचित नहीं ठहराती है जब संकेतित तथ्यों और संभवतः अन्य तथ्यों के आधार पर स्थिति पर्याप्त गंभीर हो सकती है। 356 संविधान से। संघ के सर्वोच्च, 16 कार्यकारी अंगों की संवैधानिक रूप से अधिकृत कार्यकारी कार्रवाई की स्वतंत्रता को न्यायिक हस्तक्षेप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय स्पष्ट और गंभीरतम चरित्र के आधार पर। अदालत के सामने संभावनाओं से परे कुछ भी नहीं था ताकि कोई अग्रिम न हो। निषेधाज्ञा या आदेश दिया जा सकता है।

अदालत में मुकदमों के साथ-साथ याचिकाओं को खारिज करना। पकड़ना: प्रति बेग, सी. जे.

(1) विघटन और पुनर्निर्वाचन या प्रतिधारण के बीच चयन एक निश्चित अवधि के लिए विधानमंडल या सरकार की समान सदस्यता अवधि एक डेमो के तहत राजनीतिक समीचीनता और रणनीति के मामले हो सकते हैं हमारी व्यवस्था के तहत, फॉर्मा के माध्यम से राजनीतिक शक्ति की खोज क्रेटिक प्रणाली। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नीतियों के साथ कई राजनीतिक शक्तियों का गठन और कार्यक्रम और विचारधाराएँ कानूनी हैं। इसलिए, केवल अधिक प्राप्त करने का प्रयास पार्टी, अन्य दलों के विपरीत संवैधानिक रूप से निषिद्ध नहीं है या स्वयं अवैध है। [24 एफ-जी]

(2) हमारे संविधान और कानूनों का एक उद्देश्य निश्चित रूप से मतदाताओं को अपने राज्य की विधायिका चुनने का समय-समय पर अवसर देना है। उनकी राज्य सरकारों के चरित्र का भी निर्धारण करना। यह वस्तु है प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान को ऐसे अवसर देने के लिए। इसलिए एक नीति उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया गया मूल संरचना या योजना के विपरीत नहीं हो सकता है। संविधान से। [24 बी]

(3) संविधान के अनुच्छेद 356 (1) में "ए" के मूल्यांकन का आह्वान किया गया है। स्थिति "। जहाँ तक अनुच्छेद 356 (1) राजनीतिक और राजनीतिक मामलों को शामिल कर सकता है। कार्यकारी नीति और समीचीनता, न्यायालय इनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि

जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि राष्ट्रपति किस संवैधानिक प्रावधान का पता लगाने जा रहा है या उसने अनुच्छेद के तहत कार्रवाई के प्रयास के आधार पर उल्लंघन किया है। 356 (1) के लिए, जबकि कला। 74 (2) , न्यायालयों को राष्ट्रपति को मंत्रिस्तरीय सलाह के अस्तित्व या प्रकृति या सामग्री की जांच करने से अक्षम करता है, अनुच्छेद 356 (5) न्यायालयों के लिए किसी भी आधार पर राष्ट्रपति की संतुष्टि पर सवाल उठाना असंभव बनाता है। अतः न्यायालय केवल उनके लिए जो कुछ भी बचा है या राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर स्वीकार किया गया है, उस पर कार्रवाई की वैधता निर्धारित कर सकते हैं। [25 डी, 26 ई-एफ]

(4) यदि केंद्र सरकार सोचती है कि स्थिति की परिस्थितियाँ

यह मांग की जाए कि राज्य सरकारों को अपने मतदाताओं के हित में सत्ता का प्रयोग जारी रखने के लिए लोगों की नजर में अपने नैतिक अधिकारों को सही ठहराने के लिए एक नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा जनता के असंतोष का न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है, बल्कि यह उन कानूनी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों को भी प्रभावित करेगा जो केंद्र सरकार की एक पक्षीय राज्य या सामान्य रूप से भारतीय नागरिकों के प्रति हैं, जिनमें से सभी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि कला का सहारा लें। 356 संविधान की आवश्यकता नहीं है। [25 ई-एफ]

(5) केवल राजनीतिक ज्ञान या कार्यकारी नीति के सवाल ही नहीं हो सकते थे।

न्यायिक नियंत्रण के अधीन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकारी नीति को भी संवैधानिक रूप से स्वीकृत उद्देश्यों के अधीन किया जाना चाहिए। इसका अपना क्षेत्र और सीमाएँ हैं। लेकिन, जब तक यह उस क्षेत्र के भीतर काम करता है, तब तक इसके संचालन न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं। यह संविधान की सर्वोच्चता के तहत सत्ता के मोटे तौर पर पृथक्करण के सिद्धांत का भी एक हिस्सा है।

(6) आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान

कला. 352 , ऐसा प्रतीत होता है कि जो गंभीर और आसन्न हैं, वे अनुच्छेद 355 में उल्लिखित राज्य के प्रति संघ के कर्तव्य के पहले भाग में शामिल हैं, लेकिन अनुच्छेद 355 में उल्लिखित उस कर्तव्य के दूसरे भाग में शामिल हैं। 355 , ऐसा लगता है कि कुछ अलग और व्यापक चरित्र का है। ऐसा लगता है कि दूसरा भाग कवर करता है

वे सभी कदम जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रत्येक राज्य की सरकार "संविधान के प्रावधानों के अनुसार" चलती है। इसका विस्तार काफी चौड़ा लगता है। यह कर्तव्य का हिस्सा है

प्रत्येक राज्य के प्रति संघ जो कला के तहत एक घोषणा द्वारा कवर किया जाना चाहता है। 356. यह घोषणा गंभीर आपातकाल की नहीं है। वास्तव में, वहाँ "आपातकाल" शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक घोषणा है जिसका उद्देश्य या तो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से बचाव करना है या टूटने के दोषों को ठीक करना है। यह या तो एक निवारक या उपचारात्मक कार्रवाई हो सकती है। यह पर्याप्त है यदि राष्ट्रपति, संशोधित कला को देखते हुए। 73 (1) वास्तव में इसका अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यह निष्कर्ष निकालती है कि "राज्य की सरकार को संविधान के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है"। दूसरी ओर, कला के तहत कार्रवाई। 352 अधिक उचित रूप से, एक गंभीर और अपरिवर्तनीय खतरे को टालने या उससे निपटने के लिए केवल रक्षात्मक और सुरक्षात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। [30 सी-एफ]

(7) कला की भाषा। 356 इतना चौड़ा और ढीला है कि पालना और

इसे एक सीधी जैकेट के भीतर सीमित करना केवल इसकी व्याख्या या अर्थ नहीं होगा, बल्कि संविधान बनाने वाला कानून होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। [31 सी-डी]

एच. एच. केशवानंद भारती श्रीपदगलवारू बनाम। केरल राज्य, [1973]

सप. एस. सी. आर पी. 1 @ 89 , श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण [1976] 2 एस. सी. आर. 347 @539; हर शरण वर्मा, वी। चंद्र भान गुप्ता और अन्य। , ए. आई. आर. 1962 ऑल। 301 @ 307 संदर्भित किया गया।

(8) हमारे संविधान के प्रावधानों का अवलोकन यह इंगित करेगा कि,

हमारे संविधान में संघीय संरचना का जो भी स्वरूप हो, उसके संचालन को निश्चित रूप से, दोनों शक्तियों की सामग्री से आंका जाता है जो इसके कई प्रावधान उनके साथ ले जाते हैं और उनका जो उपयोग किया गया है, वह संघीय की तुलना में अधिक एकात्मक है। [33 एफ]

शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर. पी. 814 संदर्भित किया गया।

(9) एक मायने में भारतीय संघ संघीय है। लेकिन संघवाद की सीमा

इसमें काफी हद तक राजस्थान वी. यूनियन की प्रगति और विकास की जरूरतों के कारण पानी भरा हुआ है।

ऐसा देश जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से

समन्वित और सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत। ऐसी प्रणाली में राज्य केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित तरीके से देश के वैध और व्यापक रूप से नियोजित विकास के मार्ग में बाधा नहीं बन सकते हैं। हमें विशेष दिशाओं में ले जाने वाली केंद्र सरकार की विशेष कार्रवाइयों की वैधता के सवाल को अक्सर उचित समय पर लोगों के फैसलों से ही परखा और रोका जा सकता है।

न्यायालयों के निर्णयों द्वारा। इस कारण से, वे कानूनी चर्चा के बजाय राजनीतिक बहस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हमारे देश की विशेष आवश्यकताओं में राजनीतिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता और देश के सभी हिस्सों के आर्थिक विकास की योजना होनी चाहिए, ताकि कल्याण का निर्माण किया जा सके।

निर्धारित अन्य महान आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। प्रस्तावना की मजबूत केंद्रीय दिशाएँ अपरिहार्य प्रतीत होती हैं। [24 सी-ई]

(10) संविधान के अनुच्छेद 256 में ऐसे मामले शामिल हैं जहां राष्ट्रपति

संसद द्वारा जो उस राज्य पर लागू होती है। लेकिन, कला। 257 (1) एक व्यापक लागू करता है किसी राज्य पर अपनी शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करने का दायित्व है कि वह बाधा न डाले

संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो, जैसा कि दिखाई देगा

कला. 73 संविधान, कला के साथ पढ़ा जाता है। 248 यहाँ तक कि किसी विषय को भी शामिल किया जा सकता है

जिस पर कोई मौजूदा कानून नहीं है, लेकिन जिस पर संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं

संभव है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि, हालांकि, संविधान स्वयं विशेष रूप से यह निर्धारित नहीं करता है कि विघटन की शक्ति कब होनी चाहिए

मंत्रिपरिषद की सलाह पर सरकार द्वारा

राज्य, फिर भी, यदि उस मामले पर कोई निर्देश संघ द्वारा उचित रूप से दिया गया था राज्य सरकार के लिए, इसे पूरा करना एक कर्तव्य है। द.

राज्य विधानसभा के विघटन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

संविधान का प्रावधान या इस विषय पर बनाई गई कोई कानून। यह संभव है,

हालाँकि, केंद्र सरकार के लिए, अपनी अवशिष्ट कार्यपालिका का प्रयोग करते हुए

एक उचित दिशा के मुद्दे के लिए इसे एक उपयुक्त विषय मानने की शक्ति जब

यह मानता है कि देश में राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि एक नया

चुनाव राजनीतिक स्थिरता के हित में या स्थापित करने के लिए आवश्यक है

किसी राज्य की सरकार में लोगों का विश्वास। [36 बी-ई]

(11) निस्संदेह, यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करना उचित और स्वस्थ है।

सम्मेलनों का विकास होना चाहिए ताकि कला के तहत शक्ति विकसित हो सके। 356 (1) यह भी नहीं है

मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है और न ही इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई राजनीतिक स्थिति वास्तव में इसकी मांग करती है। यदि केंद्र सरकार के विचार और

राज्य सरकार इस विषय पर अलग है, कोई कारण नहीं है कि संघ सरकार को उस विकास में सहायता नहीं करनी चाहिए जिसे वह एक

उचित सलाह या निर्देश द्वारा स्वस्थ अभ्यास या परंपरा, और, यहाँ तक कि कला के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। 356 (1) इस उद्देश्य के लिए जब यह विचार करता है कि

इस तरह के निर्देश का पालन इतना आवश्यक है कि संवैधानिक

मशीनरी तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक कि यह हस्तक्षेप नहीं करती है। द.

इस प्रावधान या स्वीकृत तथ्यों पर शक्ति की अधिकता। इसके लिए नहीं है। अदालतों को तैयार करने के लिए, और, बहुत कम, एक कन्वेंशन को लागू करने के लिए, हालांकि आवश्यकता है

इस तरह के एक एक्सई के अभ्यास को विनियमित करने के लिए न्यायपूर्ण या उचित और उचित एक सम्मेलन

क्यूटिव पावर हो सकती है। यह पूरी तरह से कार्यकारी क्षेत्र के भीतर का मामला है।

संचालन। [36 ई-एच]

(12) सर्वोच्च न्यायालय केवल इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या कोई कार्रवाई की गई है।

कुछ आधारों पर ऐसे मामले पर प्रस्तावित, कला के तहत आता है। 356 (1)

संविधान का यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भिन्न हैं

इस सवाल पर कि क्या, किसी विशेष स्थिति में, राज्य का विघटन

सभा होनी चाहिए या नहीं। सबसे अधिक जो कोई कह सकता है वह यह है कि ए

राज्य विधानसभा में बहुमत की इच्छा के विरुद्ध विघटन एक गंभीर स्थिति है। और गंभीर बात। शायद यह देखा जा सकता है कि इसका सहारा लिया जाना चाहिए

कला के तहत। 356 (1) संविधान का केवल तभी जब "एक गंभीर स्थिति" हो

उभरा। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि केवल राज्य सरकार की हार हो। राज्य विधानसभा में अनिवार्य रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें एक विसंगति हो।

राज्य विधानसभा का गठन अनिवार्य है। यदि एक वैकल्पिक सरकार है

} 6

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

1978] 1 एससीआर।

यह है कि क्या राज्य विधानसभा में बहुमत में पार्टी का गठन राज्य सरकार ने अभी तक पूरी तरह से और दृढ़ता से काम किया है।

लोगों द्वारा अस्वीकृत, एक "गंभीर स्थिति" उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होने के लिए बाध्य है

जब तक "राजनीतिक संप्रभु" को एक नया निर्णय देने का अवसर नहीं दिया जाता है।

ए. इस तरह के प्रश्न का निर्णय निस्संदेह कार्यकारी क्षेत्र में निहित है। यह. इसमें "स्थिति" का सही अनुमान शामिल है। [41 बी-ई]

(13) संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शक्तियां निहित हैं -

सरकार में विधान सभा को हल करना, भले ही वह होना था राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन

इस तरह की सलाह देने की शक्ति स्वतः संघ द्वारा ले ली जाएगी सरकार, राज्य विधानसभा के विघटन के प्रयोजनों के लिए, जब अध्यक्ष

डेंट अनुच्छेद के तहत एक उद्घोषणा द्वारा सरकारी शक्तियों को ग्रहण करता है। 356 (1) . ए.

उद्घोषणा के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन उतना ही अच्छा होगा जितना कि

उस राज्य की सरकार द्वारा समाधान जिसकी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली गई हों। [37 सी-ई]

(14) वास्तव में, सामान्य प्रथा यह है कि राष्ट्रपति कला के तहत कार्य करता है। 356 (1)

केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर संविधान का। लेकिन शब्दों का उपयोग

" या अन्यथा "(अनुच्छेद 356 में) दर्शाता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अन्य सामग्रियों पर भी आधारित हो सकती है। हमारे संविधान की यह विशेषता इंगित करती है सबसे आश्चर्यजनक रूप से सरकार के संघीय सिद्धांतों पर इसके द्वारा किस हद तक पैठ बनाई गई है। [38 ए-सी]

शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर. पी. 875 संदर्भित किया गया। (15) स्टेटो के विघटन के लिए उचित समय के सवाल के रूप में

सभा कला के लिए कोई बाहरी मामला नहीं है। 356 (1) संविधान में, सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि उठाए गए प्रश्न कला का सहारा लेने के लिए पर्याप्त आधारों से परे नहीं जाते हैं। 356 (1) संविधान से। [41 एच, 42 ए]

के. के. अबू बनाम भारत संघ, ए. जे. आर. 1965 केरल 229; राव बीरेंद्र

सिंह बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1968 पंजाब 441; री में। ए. श्रीरामुलु, ए. आई. आर. 1974 ए. पी. 106, बिजेनानंद पटनायक और अन्य। वी. भारत के राष्ट्रपति और अन्य। , ए. आई. आर. 1974 उड़ीसा 52 का उल्लेख किया गया।

(16) मतदाताओं से अपील करके राजनीतिक जीत हासिल करने के प्रयास हैं -

सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के मान्यता प्राप्त नियमों के कुछ भाग प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हैं ताकि कुछ अन्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि कुछ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राजनीतिक जीत प्राप्त करने की इच्छा के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा, जिसे किसी पार्टी के सदस्य किसी राज्य में लोगों के लिए फायदेमंद मानते हैं, प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक विधि के रूप में, न केवल संविधान के तहत कानूनी और अनुमेय है, बल्कि स्पष्ट रूप से विभिन्न दलों द्वारा सही मानी जाने वाली नीतियों को लागू करने की शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र संभव और कानूनी साधन है, तो संभवतः इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। कि राजनीतिक विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य विधान सभा को भंग करना अपने आप में एक बाहरी उद्देश्य है जो अनुच्छेद के तहत बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। 356 संविधान से। [42 ई-एफ]

महान्यायवादी v. डॉ. कीसर का रॉयल होटल, 1920 एसी 508; लिवर्जिज बनाम।

एंडरसन 1942 एसी 206; अतिरिक्त। जिला. मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम। शिवकांत शुक्ला, 1976 सप. एससीआर 173, भगत सिंह और अन्य। वी. राजा सम्राट, 50 आई. ए. 169 राजा सम्राट बनाम। बेनोरीलाल शर्मा 72 1. ए. 57, पैडफील्ड और ओआरएस। वी. कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य और अन्य मंत्री। , 1968 ए. सी. 997 @1006 (लागू नहीं)।

(17) अनुच्छेद 356 (1) के तहत की गई कार्रवाई के सभी आधारों का खुलासा किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा जनता और उसके स्वयं के आधारों के प्रकटीकरण से पता चलता है कि अनुच्छेद के तहत एक आसन्न या वास्तविक घोषणा द्वारा संवैधानिक या कानूनी रूप से निषिद्ध या बाह्य या संपार्श्विक रूप से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। 356 संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय उस तरीके से कार्य करने के अपने कर्तव्य से नहीं हटेगा जिसमें कानून उसे कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन, जब मैदानी इलाकों में और अदालत के समक्ष याचिकाओं में लगाए गए आरोप, सार में, केवल कला के तहत कार्रवाई के आधारों की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। 356 (1) संविधान और उससे आगे नहीं, न्यायालय अनुच्छेद के तहत वाद-विवाद पर विचार के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। 131 या कला के तहत याचिकाएं। 32 संविधान से।

7

(18) अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणाएं इसके तहत रखी जानी चाहिए।

कला. 356 (3) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष संविधान का। हालांकि,

कला में कुछ भी नहीं है। 356 किसी भी सदन द्वारा विचार करने के लिए

संसद के विघटन की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त

अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधान सभा का गठन। 356 (1) , लेकिन,

दूसरी ओर, अनुच्छेद 356 (3) यह स्पष्ट करता है कि एक का भी एकमात्र प्रभाव संसद के किसी भी सदन द्वारा घोषणा को मंजूरी देने में विफलता या इनकार

यह है कि यह दो महीने के बाद काम करना बंद कर देता है। जाहिर है, इसका मतलब है कि

कम से कम दो महीने तक काम करें। इसलिए, इन दो महीनों में जो कुछ भी किया जाता है

केवल इसी कारण से इसे अवैध नहीं माना जा सकता है। [47 ए-बी]

(19) यह सच है कि कला के तहत शक्ति का प्रयोग। 356 से

संविधान संसदीय नियंत्रण के अधीन है। इसका मतलब है कि यह उप

दोनों सदनों के रूप में ऐसे नियंत्रण के लिए, जिनमें से राज्य परिषद वास्तव में

प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के लिए अवधि के दौरान अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है

जो घोषणा बनी रहती है। लेकिन, ऐसे संसदीय नियंत्रण का अस्तित्व,

एक सुरक्षा के रूप में संभवतः अवधि में जो किया जाता है उसकी वैधता को रद्द नहीं कर सकता है।

जिसके दौरान घोषणा रहती है। [47 सी-डी]

(20) हालांकि कला। 356 (1) ((क) संविधान के विरुद्ध प्रतिबंध लगाता है।

राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधान की विधायी शक्तियों की धारणा

प्रकृति, जिसे केवल संसद को हस्तांतरित किया जा सकता था, इसके प्रावधान, के साथ पढ़ा जाता है

जो राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के अधीन कानूनी रूप से वहन किया जा सकता है द्वारा व्यय को प्राधिकृत करने वाले पूर्व-विद्यमान राज्य कानूनों के अनुसार प्राधिकरण

अन्य प्राधिकारी या निकाय जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियाँ ली जा सकती हैं

कला. 356 (1) (ए)। किसी भी मामले में, कला के प्रावधान। 357 संभव नहीं हो सका

राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के विघटन के खिलाफ एक बाधा के रूप में उपयोग किया जाए

उद्घोषणा। न ही उनका उपयोग एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में पेश करने के लिए किया जा सकता है

कला के तहत राष्ट्रपति की घोषणा। 356 (1) (ए), शामिल, जैसा कि आमतौर पर होता है

राज्य विधानसभा का विघटन, दोनों या दोनों में से किसी एक का अनुमोदन करता है

दो, संसद के सदन। [49 ए-सी]

(21) भले ही एक के बीच अंतर करने के लिए कुछ आधार हों

राज्य के हित और अधिकार और उसकी सरकार या उसके सदस्यों के हित,

न्यायालय को राज्यों के अधिकार के बारे में बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक या कठोर दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी वास्तविक या काल्पनिक अधिकार के लिए मुकदमा करना, जिसे राज्य सरकार चुनती है

संबंधित राज्य की ओर से अनुच्छेद के तहत मुकदमा दायर करना। 131. [50 एफ-जी]

बिहार राज्य बनाम। भारत संघ और एएनआर। , [1970] 2 एस. सी. आर. 522 समझाया।

संयुक्त प्रांत बनाम। परिषद में गवर्नर जनरल, 1939 एफसीआर 124;

संदर्भित किया गया। चंद्रचूड़ जे.

(1) अनुच्छेद 131 (ए) में "भारत सरकार" वाक्यांश का उपयोग और

(ख) इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद का एक पक्ष सरकार होनी चाहिए

केंद्र में दिन "। भारत सरकार "का अर्थ है" भारत का संघ "

अनुच्छेद 131 (ए) का वास्तविक निर्माण सार में सही और व्यावहारिक रूप से सही है यह है कि भारत संघ और एक राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होना चाहिए। [53 ई-जी]

(2) भारत संघ और राज्य के बीच विवाद एक हो सकता है

कार्यालय में सरकार के बीच मतभेद से उत्पन्न होने वाला विवाद केंद्र में और राज्य में कार्यालय में सरकार। लेकिन, एक है

आगे पूर्व-आवश्यकता जो विवादों के वर्ग के दायरे को कम करती है

जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। यह आवश्यकता है कि विवाद होना चाहिए

एक प्रश्न शामिल है कि क्या कानून या तथ्य का है, जिस पर अस्तित्व या विस्तार

एक कानूनी अधिकार निर्भर करता है। यही योग्यता है जिसमें सही मार्गदर्शन शामिल है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी विशेष विवाद को कला के भीतर समझा जाता है। 131 .

सरकारों के बीच केवल झगड़ों का उस योजना में कोई स्थान नहीं है।

लेख। कला का उद्देश्य। 131 के समाधान के लिए एक मंच का खर्च उठाना है

विवाद जो उनके निर्णय के लिए किसी कानूनी विवाद के अस्तित्व या सीमा पर निर्भर करते हैं।

सही है। यह तभी होता है जब कोई कानूनी मुद्दा, न कि केवल राजनीतिक, सामने आता है।

किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार जिसे अनुच्छेद 131 आकर्षित करता है।

[

54 ए-सी] [1978] 1 एस. सी. आर.

8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) जब वादी अपने मुकदमों द्वारा सीधे या विशेष रूप से प्रश्न करता है

एक जारी करने के लिए केंद्र सरकार का संवैधानिक अधिकार और अधिकार

राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों को

अपने राज्यपालों को एक निश्चित सलाह दें और संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं। इन आधारों पर राज्य विधानसभाओं को भंग करने का केंद्र सरकार का अधिकार

मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री के पत्र में उल्लेख किया गया है, एक कानूनी, न कि एक

राजनीतिक, कानूनी अधिकार के अस्तित्व और विस्तार से उत्पन्न होने वाला मुद्दा

उत्पन्न होता है और सूट को इसके दायरे से बाहर होने के रूप में बाहर नहीं फेंका जा सकता है

कला. 131. [54 डी-ई]

(4) कला के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। 131 कि

वादी को अपने आप में एक कानूनी अधिकार का दावा करना चाहिए। कला. 131 इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और यह पर्याप्त है ताकि इसके प्रावधान लागू हो सकें कि वादी

प्रतिवादी द्वारा प्रतिपादित कानूनी या संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे वह भारत सरकार या कोई अन्य राज्य। इस तरह की चुनौती सूट लाती है

के लिए अनुच्छेद 131 की शर्तों के भीतर, न्यायालय के निर्णय के लिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह या वह विशेष विधान सभा पद पर बने रहने का हकदार है, बल्कि यह है कि क्या भारत सरकार, जो कथित आधारों पर विधानसभा को भंग करने के संवैधानिक अधिकार का दावा करती है, के पास ऐसा कोई अधिकार है।

[54 एफ-जी]

(5) राज्यों के पास चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ने का अधिकार और रुचि है।

संघ सरकार द्वारा स्थापित दावे का न्यायनिर्णयन। भारत सरकार और राज्यों के बीच संवैधानिक दायित्व का बंधन उस अधिकार को बनाए रखता है। [54 एच-एसएसए]

(6) "कानूनी अधिकार" अभिव्यक्ति जो कला में पाई जाती है। 131 होना चाहिए।

अपने उचित परिप्रेक्षय में समझा। संघ सरकार की शक्ति से स्वतंत्रता के अर्थ में राज्यों के कानूनी अधिकार में उनकी प्रतिरक्षा शामिल है। वे कला के तहत हकदार हैं। 131 , उस अधिकार का दावा करने के लिए या तो विरोध करके पूर्ण रूप से कि केंद्र के पास विधान सभा

को भंग करने की कोई शक्ति नहीं है या इस योग्यता के साथ कि ऐसी शक्ति का प्रयोग बताए गए आधारों पर नहीं किया जा सकता है। [55 ए-डी]

बिहार राज्य बनाम। भारत संघ, [1970] 2 एस. सी. आर. 522; लागू नहीं हुआ।

(7) कला के तहत उद्घोषणा द्वारा। 356 (1) विधान सभाएँ

नौ राज्यों को भंग कर दिया गया और उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ताओं का विधान सभाओं का सदस्य होना समाप्त हो गया और उनके ऐसे सदस्य न होने के परिणामस्वरूप वेतन का अधिकार जो वे केवल विधानसभाओं के सदस्य होने पर ही प्राप्त कर सकते थे, समाप्त हो गया। हालाँकि याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनका उद्देश्य उन्हें उनके वेतन से वंचित करने की घोषणा जारी करना नहीं था, लेकिन रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज किया जा सकता था कि याचिकाकर्ताओं के कथित मौलिक अधिकारों को नुकसान बहुत अप्रत्यक्ष और दूरस्थ था। [56 जी-एच]

(8) संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा या नहीं

कला में दिए गए आदेश के अनुसार शिक्षा को मंजूरी दी जाती है। 356 (3) , इसका दो महीने की अवधि के लिए एक सुनिश्चित जीवन है और उस अवधि के दौरान इसकी वैधता को कला में पढ़कर कम नहीं किया जा सकता है। 356 संसदीय परामर्श अनुमोदन की प्रकृति में एक पूर्ववर्ती शर्त, जो स्पष्ट रूप से उसमें नहीं पाई जाती है। [57 डी]

[उनके प्रभु ने इसके निहितार्थ पर विचार करना अनावश्यक समझा।

कला के खंड (5) का। 356 , 38 वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया और

स्टीफन कलंग में निर्णय के साथ सहमत "गैर-तरल" लागू किया गया

निंगकन वी। मलेशिया सरकार, एल. आर. (1970) ए. सी. 379,392]

प्रति भगवती जे। (गुप्ता जे. और स्वयं की ओर से)

(1) राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक होती है और ऐसा नहीं हो सकता।

वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के संदर्भ में निर्णय लिया गया। यह जानबूझकर और सलाह से उप-प्रभावी है क्योंकि जिस मामले के संबंध में उसे संतुष्ट किया जाना है, वह इस तरह का है कि इसका निर्णय अनिवार्य रूप से सरकार की कार्यकारी शाखा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह अपने स्वभाव से एक उपयुक्त विषय नहीं हो सकता है-न्यायिक निर्धारण का मामला और इसलिए इसे केंद्र सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया जाता है जो इसे तय करने की स्थिति में सबसे अच्छी है।

न्यायालय, परिस्थितियों में, तथ्यों की शुद्धता या पर्याप्तता के प्रश्न में नहीं जा सकता है राजस्थान बनाम संघ

9

और ऐसी परिस्थितियाँ जिन पर केंद्र सरकार की संतुष्टि आधारित है। यह अदालत के लिए एक खतरनाक अभ्यास होगा, दोनों क्योंकि यह इस तरह के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त साधन नहीं है और यह भी कि अदालत इस तरह से केंद्र सरकार के कार्य को हड़प लेगी और ऐसा करने में "राजनीतिक झंझट" में प्रवेश करेगी, जिससे उसे बचना चाहिए यदि वह लोगों के साथ अपनी वैधता बनाए रखना चाहता है। लेकिन, यदि संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है, तो अदालत को इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा, क्योंकि उस मामले में राष्ट्रपति को उस मामले के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं होगी, जिस पर उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति की संतुष्टि कला के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। 356 (1) और यदि यह दिखाया जा सकता है कि राष्ट्रपति को कोई संतुष्टि नहीं है, तो शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से अमान्य होगा। बेशक, कला के खंड 5 के कारण। 356 की संतुष्टि

राष्ट्रपति अंतिम और निर्णायक हैं और उन पर किसी भी आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमले से यह प्रतिरक्षा लागू नहीं हो सकती है जहां चुनौती यह नहीं है कि संतुष्टि अनुचित या अनुचित है, बल्कि यह है कि कोई संतुष्टि नहीं है।

ऐसे मामले में, यह राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त संतुष्टि नहीं है जो है

चुनौती दी गई, लेकिन संतुष्टि का अस्तित्व ही। ज्यादातर मामलों में यह होगा

कला के तहत शक्ति के प्रयोग को चुनौती देने के लिए, यदि असंभव नहीं है। 356

खंड (1), इस सीमित आधार पर भी, क्योंकि तथ्य और परिस्थितियाँ किस पर संतुष्टि आधारित है, यह ज्ञात नहीं होगा, लेकिन यह कहाँ संभव है,

उन्हें घोषणाओं से जानने के लिए संतुष्टि का अस्तित्व हमेशा हो सकता है

इस आधार पर चुनौती दी जाए कि यह दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी है या अप्रासंगिक जमीन। [81 जी, एच, 82 ए-एच, 83 ए-बी]

निंगकन वी। सरकार. मलेशिया, 1970 ए. सी. 379, राजा सम्राट बनाम। बेनोआरिलाल

सरमा, 72 आई. ए. 57 का उल्लेख किया गया।

(2) लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की हार नहीं हो सकती

स्वयं बिना किसी और के इस निष्कर्ष का समर्थन करते हुए कि सरकार

राज्य को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

यह। केवल इस आधार पर विधान सभा को भंग करना होगा -

राष्ट्रपति द्वारा सभी सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार का अप्रत्यक्ष प्रयोग संविधान में वापस बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही

मतदाता। जहाँ से संबंधित उम्मीदवारों की कुल हार हुई है

सत्तारूढ़ दल और कुछ वादी-राज्यों में, सत्तारूढ़ दल को नहीं किया गया है

एक भी सीट हासिल करने में सक्षम, यह दोनों के बीच पूर्ण अलगाव का प्रमाण है।

सरकार और जनता। यह स्वयंसिद्ध है कि कोई सरकार नहीं

संविधान के अनुसार कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जब तक कि उसे लोगों की सद्भावना और समर्थन प्राप्त न हो। जहाँ अलगाव की एक दीवार है जो सरकार को सरकार से विभाजित करती है

लोग और लोगों के दिलों में नाराज़गी और नफरत है

सरकार के खिलाफ, यह बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है

और प्रशासन भी लकवाग्रस्त हो सकता है। लोगों की सहमति है

सरकार के लोकतांत्रिक रूप का आधार और जब उसे वापस लिया जाता है

पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से तीव्रता के बारे में संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं

सत्तारूढ़ दल, सरकार के नैतिक अधिकार के खिलाफ जनता की भावना

इसे गंभीर रूप से कमजोर किया जाएगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां

लोग सरकारी प्राधिकार को सम्मान और आज्ञाकारिता देना बंद कर सकते हैं

और यहां तक कि सरकार के बीच संघर्ष और टकराव भी हो सकता है

ऐसे क्वेंस जिन्हें इस तरह के असामान्य से उत्पन्न होने की संभावना नहीं कहा जा सकता है स्थिति और वे सरकार के लिए इसे असंभव बना सकते हैं

राज्य को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। स्थिति इस तरह के परिणामों से भरी हुई है या नहीं, यह पूरी तरह से एक

सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए राजनीतिक निर्णय का मामला। लेकिन,

यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के परिणाम कभी नहीं हो सकते और यह कि जमीन

कि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल की पूर्ण और भारी हार के कारण

चुनाव, राज्य की विधान सभा ने इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया है

लोगों का और विधान सभा के बीच पूर्ण अलगाव है

कला और लोग कला के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक हैं। 356 , खंड (1)।

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर यह आधार स्पष्ट है

एक प्रासंगिक आधार जिसके संबंध में मामले के साथ उचित संबंध है

राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने से पहले संतुष्ट होना आवश्यक है।

खंड (1)। [85 ए-एच] 10

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

1978] 1 एस सी आर।

(3) प्रकृति के संबंध में दो सीमाएँ हैं।

सूट

का जो

उच्चतम न्यायालय द्वारा कला के तहत विचार किया जा सकता है। 131 .

इस

संबंध में एक

पक्ष और दूसरा विषय वस्तु के संबंध में है।

यह

मानती नहीं है

किसी भी निजी पक्ष को एक तरफ या दूसरी तरफ एक विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक विवाद जिसमें ऐसा निजी पक्ष शामिल है, उसके सामने लाया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय, जिसकी इस मामले पर अधिकारिता हो।

इसके अलावा, विवाद कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए न कि विवाद से।

राजनीतिक स्तर पर जो कानूनी अधिकार पर आधारित नहीं है। एक कानूनी अधिकार जो विषय है

यह स्थापित करता है। इसी तरह किसी मुकदमे में राहत देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति भी अनुच्छेद 131 के तहत केवल "घोषणात्मक घोषणा" तक ही सीमित नहीं है।

फैसला "। द.

उच्चतम न्यायालय के पास इस बात की शक्ति होगी कि उसके लिए जो भी आवश्यक राहत दी जाए मुकदमे में दावा किए गए कानूनी अधिकार का प्रवर्तन, यदि ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित है।

[64 ई-एच,

65 ए-डी, 66 सी

बिहार राज्य बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , (1970) 2 एस. सी. आर. 522, समझाया गया

& शक हुआ:

शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर. 814 संदर्भित।

(4) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग

खंड (1) कई व्यक्तियों के अधिकारों को हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह उल्लंघन कर सकता है न केवल विधान सभा के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार बल्कि

राज्य का संवैधानिक अधिकार भी इस बात पर जोर देने के लिए कि संघीय आधार

संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक संरचना का अनुच्छेद के तहत एक गैर-संवैधानिक हमले से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 356 खंड (1)। वर्तमान मुकदमे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले राज्यों के कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रयास करते हैं और मुकदमों को अनुच्छेद 131 के दायरे और दायरे से बाहर होने के कारण सीमित नहीं किया जा सकता है। [68 जी-एच, 69 ए]

(5) विधान सभा के विघटन की धमकी में शामिल नहीं था

अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 के तहत याचिकाकर्ताओं को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन। [63 एच, 64 ए]

(6) यह केवल तभी होता है जब किसी मौलिक अधिकार का सीधा आक्रमण होता है या

इस तरह के आक्रमण का आसन्न खतरा कि एक याचिकाकर्ता कला के तहत राहत ले सकता है। 32. मौलिक अधिकार पर प्रभाव प्रत्यक्ष और तत्काल होना चाहिए न कि अप्रत्यक्ष या दूरस्थ।

तत्काल मामले में, केवल इसलिए कि विधान के विघटन से

विधानसभा में, याचिकाकर्ताओं का सदस्य बनना बंद हो जाएगा और इस घटना के परिणामस्वरूप उनका वेतन कम हो जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि विघटन से उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता, इस प्रकार, अनुच्छेद के तहत रिट याचिका को बनाए रखने के हकदार नहीं हैं। 32. [63 डी, ई, 64 ए]

(7) भारत सरकार के गृह मंत्री का निर्देश कुछ भी नहीं था

लेकिन प्रत्येक वादी राज्य के मुख्यमंत्री को सरकार को संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने के लिए एक सलाह या सुझाव। इसे गलत तरीके से "निर्देश" के रूप में वर्णित किया गया है। इसके पीछे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। केंद्र सरकार के गृह मंत्री के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह या सुझाव देना हमेशा खुला रहता है और मुख्यमंत्री ऐसी सलाह या सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है जो वह उचित समझे। सलाह या

सुझाव का मुख्यमंत्री पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गृह मंत्री द्वारा जारी 'निर्देश' असंवैधानिक, अवैध या अधिकार से परे था। "निर्देश" को प्रभावी बनाने का भी कोई सवाल नहीं था और इसलिए, इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती थी। यदि "निर्देश" को स्वीकार नहीं किया जाता है और लागू नहीं किया जाता है तो यह निश्चित रूप से कला के तहत कार्रवाई का अग्रदूत हो सकता है। 356 खंड (1) और इसलिए, इसे खतरे का संकेत माना जा सकता है, लेकिन अपने आप में यह घोषणा या निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा करने के लिए राज्य में कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं दे सकता है। [77 एच, 78 ए-बी]

(8) यह सच है कि अगर अदालत के सामने लाया गया कोई सवाल विशुद्ध रूप से राजनीतिक है

प्रश्न जिसमें किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार या दायित्व का निर्धारण शामिल नहीं है, न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय केवल 11 से संबंधित है।

राजस्थान वी. यूनियन

कानूनी अधिकारों और देनदारियों के निर्णय के साथ। लेकिन, सिर्फ इसलिए कि एक सवाल

इसका एक राजनीतिक रंग है जो अपने आप में न्यायालय के लिए कोई आधार नहीं है

संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने से सिकुड़ें, अगर यह एक मुद्दा उठाता है

संवैधानिक निर्धारण। संविधान शुद्धतम राजनीति का विषय है और

शक्ति की संरचना। [79 जी-एच] *

(9) केवल इसलिए कि किसी प्रश्न का राजनीतिक रंग होता है, अदालत मोड़ नहीं सकती।

इसका हाथ निराशा में है और "न्यायिक हाथों को बंद करने" की घोषणा करता है। जब तक एक सवाल

यह उत्पन्न होता है कि क्या संविधान के तहत किसी प्राधिकरण ने सीमाओं के भीतर काम किया है

ऐसा करना उसका संवैधानिक दायित्व होगा। इस पर जोर देना आवश्यक है विशेष रूप से हाल के इतिहास के संदर्भ में सबसे स्पष्ट शब्द कि कॉन्स्टी

टचूशन सर्वोच्च लेक्स है, देश का सर्वोच्च कानून और इसमें कोई छूट नहीं है।

इसके ऊपर या उससे आगे सरकार की शाखा। [80 एफ-एच] ·

बेकर वी। कैन 369 यू. एस. 186; निक्सन बनाम। हर्नडन 273 यू. एस. 536; ब्राउन बनाम।

शिक्षा बोर्ड 347 यू. एस. 483; गोमिलियन बनाम। लाइटफुट 364 यूएस 339, कोल

ग्रोर वी। ग्रीन 328 यू. एस. 549 अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया।

गोस्वामी जे. के अनुसार

(1) हालाँकि कला में प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति। 131 "कोई विवाद" है, चौड़ाई

अभिव्यक्ति की प्रकृति के संबंध में आने वाले शब्दों द्वारा सीमित है

1

विवाद जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने मूल न्यायशास्त्र में स्वीकार किया जा सकता है

बोलचाल की भाषा। यह केवल एक विवाद है जिसमें कानून का कोई भी सवाल शामिल है या जिसका सामना करना पड़ता है।

जो प्रतिद्वंद्वी पक्ष के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है यह कला के तहत मुकदमे का विषय हो सकता है। 131. विवाद होना चाहिए

कानूनी अधिकारों के संबंध में हो न कि राजनीतिक चरित्र के विवादों के संबंध में। अनुच्छेद 131 उन पक्षों को संदर्भित करता है जिन्हें मुकदमे में शामिल किया जा सकता है और साथ ही

विवाद का विषय। [86 एफ-जी]

बिहार राज्य बनाम। भारत संघ, [1970] 2 एस. सी. आर. 522 संदर्भित।

(2) अनुच्छेद 131 कानूनी अधिकार की बात करता है। वह कानूनी अधिकार होना चाहिए कि

राज्य। किसी कानूनी अधिकार, उसके अस्तित्व या विस्तार के बारे में विवाद होना चाहिए

भारत सरकार और राज्यों के बीच आंदोलन करने में सक्षम। द.

अनुच्छेद 131 के दायरे में उत्पन्न होने वाले विवाद की प्रकृति

एक कानूनी अधिकार के संबंध में जो राज्यों को सरकार के खिलाफ दावा करने में सक्षम होना चाहिए रेनत। जहाँ गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं

राज्यों की सरकारों के मंत्री राज्यपालों को इसे भंग करने की सलाह देंगे

विधानसभाएँ और मुख्यमंत्री इस सलाह को स्वीकार करने से इनकार करते हैं,

यह एक ओर राज्य और सरकार के बीच विवाद नहीं है।

दूसरी ओर भारत। यह सरकार के बीच एक वास्तविक विवाद है

राज्य और भारत सरकार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जीवन का सवाल है और

राज्य सरकार के लिए मृत्यु लेकिन एक कानूनी इकाई के रूप में राज्य के लिए ऐसा नहीं है।

विधानसभा के भंग होने के बाद भी राज्य के पास रहेगा

जैसा कि संविधान में उपबंध किया गया है, कुछ समय के लिए ऐसी सरकार

एक आकस्मिकता। विवाद का विषय कानूनी से संबंधित नहीं है।

अनुच्छेद 131 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य के अधिकार

संविधान। [87 जी, 88 एच, 89. ए-बी, 90 सी]।

(3) चाहे स्थायी निषेधाज्ञा का मामला हो या अन्य उपयुक्त

इन मामलों में रिट की मांग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाती है कि वाद और रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य नहीं हैं। [92 सी-डी]

- (भगवती और ए. सी. गुप्ता, जे. जे. के साथ सहमति)

हेल्ड फर्थर: (4) मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 के तहत याचिकाकर्ताओं को गारंटी

विधान सभा के विघटन की धमकी के परिणामस्वरूप। अतः रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं और इनके लिए उत्तरदायी हैं -

अस्वीकृति। [90 सी-डी]

राजा सम्राट वी। बेनोरीलाल सरमा और ओआरएस। 72 आई. ए. 57: @ 64 ; भगत सिंह

& ओआरएस। वी. राजा सम्राट 58 आई ए 169; शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर पी. 814 संदर्भित किया गया।

2-

722 एससीआई/77 [1978] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12

पर उन्तवालिया, जे।

(1) यह मानते हुए कि कुछ सदस्यों द्वारा दायर रिट आवेदन

कला के तहत पंजाब के विधायक। 32 भारत के संविधान के प्रमुख हैं

अक्षम्य, याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की रिट जारी करने के लिए मामला नहीं बनाते हैं वर्तमान मामले में निर्देश या आदेश। [92 जी]

(2) कला के तहत स्थापित सूट। 131 , तत्काल मामले में, नहीं हैं

अप्राप्य। मुकदमों में जिस तरह का विवाद उठाया गया है, उसमें शामिल नहीं है कानून या तथ्य का कोई प्रश्न जिस पर किसी का अस्तित्व या विस्तार हो।

संबंधित राज्यों का कानूनी अधिकार निर्भर करता है। जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है वे हैं -

निश्चित रूप से और विशेष रूप से निषिद्ध क्षेत्र के भीतर जिसमें यह न तो है

न्यायालयों को प्रवेश करने की अनुमति है और न ही उन्हें कभी खुद को संभालना चाहिए

ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का खतरनाक कार्य। [92 एच, 93 ए, 95 डी-एफ, 97 डी]

भगत सिंह और ओआरएस। वी. राजा सम्राट 58 आई. ए. 169; राजा सम्राट बनाम। बेनोरी लाल सरमा और अन्य। 72 आई. ए. 57; लाखी नारायण दास बनाम। प्रांत बिहार आदि। 1949 एफ. सी. आर. 693 एम/एस। एस. के. जी. शुगर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और ओआरएस।, [1975] 1 एस. सी. आर. 312 पर भरोसा किया।

स्टीफन कलंग निंगकन बनाम। सरकार. मलेशिया का [1970] ए. सी. 379 संदर्भित। पर फजल अली जे।

(1) एक विवाद स्पष्ट रूप से यह मानता है कि विरोधी दावे होने चाहिए जो एक पक्ष द्वारा पेश किए जाने की मांग की जाती है और दूसरे द्वारा विरोध किया जाता है। एक. अनुच्छेद 131 के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि विवाद में शामिल होना चाहिए - कानून पर आधारित कानूनी अधिकार या। तथ्य। अगर केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने की सलाह दें, राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन घोषणा जारी करने के लिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्रीय सरकार के लिए एक घोषणा जारी करने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करने का कानूनी अधिकार है हालाँकि, राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वहाँ है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह आदेश देता हो कि राज्य सरकार परिषद के समक्ष परामर्श लिया जाना चाहिए या उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। मंत्रीगण राष्ट्रपति को किसी संबंधित मामले में अपनी सलाह प्रस्तुत करते हैं।

जहाँ तक विधानसभा के विघटन का संबंध है, राज्य को देना। द. राज्य सरकारों का अस्तित्व का अधिकार संविधान के प्रावधानों पर निर्भर करता है।

शिक्षण जो कला के अधीन हो। 356. यदि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करने और विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा जारी करने का निर्णय लेते हैं, तो राज्य सरकारों को अनुच्छेद में निहित संवैधानिक जनादेश पर कोई अधिकार नहीं है। 356 .

[103 बी, एफ-एच, 104 ए-बी]

(2) केवल तथ्य यह है कि राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए थे

अनावश्यक सलाह देने से कोई विवाद पैदा नहीं हो सकता है, यदि कोई पहले मौजूद नहीं है और न ही इस तरह का आचरण राज्य सरकार को कानूनी रूप से प्रभावित करेगा।

अनुच्छेद 131 के तहत निर्णय लेने का अधिकार। यदि राज्य सरकारों के पास ऐसा कानूनी अधिकार या उस मामले के लिए कोई अधिकार नहीं है, तो वे घोषणा या निषेधाज्ञा के लिए अदालत के समक्ष कोई दावा नहीं कर सकते हैं। जब तक कि पार्टियों के बीच कानूनी अधिकार से जुड़ा कोई मौजूदा विवाद न हो, तब तक कला द्वारा प्रदान किया गया मंच। 131 इसका लाभ किसी भी पक्ष द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्थापित नहीं किया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकार से जुड़ा कोई विवाद था और इसलिए, यह कला के आवश्यक अवयवों में से एक है। 131 पूरा नहीं होने के कारण, सूट अकेले इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं हैं। [104 सी-डी, 105 बी-सी]

संयुक्त प्रांत बनाम। गवर्नर जनरल इन काउंसिल (1939) एफ. सी. आर. 124,

136 पीछा किया।

(3) विधान सभा के सदस्यों के रूप में याचिकाकर्ताओं का अधिकार

पंजाब का राज्य एक मौलिक अधिकार नहीं है जैसा कि संविधान के भाग III में परिकल्पित है। अधिक से अधिक, विधानसभा के सदस्यों के रूप में भत्ता प्राप्त करने का अधिकार केवल विधानसभा के सदस्यों के रूप में उनके चुनाव के परिणामस्वरूप कानूनी अधिकार है। याचिकाकर्ताओं का अधिकार केवल एक सीमित और अनुचित अधिकार है।

के रूप में

यह केवल तब तक रहता है जब तक कि विधानसभा छह साल की अपनी सामान्य अवधि चलाती है। यदि राजस्थान वी. यूनियन द्वारा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो यह अधिकार भी समाप्त हो सकता है।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत एक उद्घोषणा जारी की। 356. इसलिए अधिकार केवल तब तक रहता है जब तक ये दोनों आकस्मिकताएँ नहीं होती हैं। संविधान विधानसभा के सदस्यों को किसी भी अधिकार या भत्ते की गारंटी नहीं देता है जो उन्हें स्थानीय अधिनियमों या नियमों द्वारा दिए जाते हैं। यह ऐसा अधिकार नहीं था जो संविधान से निकलता हो। इस प्रकार, किसी भी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 32 का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। [107 एफ-एच, 108 जी-एच]

एच. एम. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य।,

वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1971] 3 एस. सी. आर. 9, विशिष्ट।

(4) पत्र एक निर्देश के बराबर नहीं है जैसा कि कला द्वारा विचार किया गया है। 256

और 257 और मुख्यमंत्रियों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता क्योंकि यह विशुद्ध रूप से संबंधित राज्यों से संबंधित है, अर्थात्, विधानसभाओं के समाधान के लिए राज्यपालों को सलाह देना। केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्देश देकर राज्य सरकार की इस कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 256 या कला। 257 संविधान के विघटन के कारण

राज्यपाल द्वारा विधानसभा विशुद्ध रूप से राज्य से संबंधित मामला था और

यह अनुच्छेद, 256 या 257 के चार कोनों के भीतर नहीं आता था। [111 ए-एफ]

(उनके प्रभु ने इस बारे में कोई राय व्यक्त करने से परहेज किया

प्रश्न समझौते के रूप में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत

वास्तव में इस मामले में निर्णय लेने के लिए उनके प्रभु पद का उपयोग नहीं किया गया था)।

(5) कला का खंड (5)। 356 राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश देता है

कला. 356 न्यायिक जांच से पूर्ण प्रतिरक्षा। अदालतें ऐसा नहीं कर सकतीं।

सामग्री की पर्याप्तता या पर्याप्तता में जाएं जिसके आधार पर

केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद को कोई भी सलाह दे सकती है

राष्ट्रपति। [116 सी-डी और 120 जीजे

भगत सिंह और अन्य। वी. राजा सम्राट एल. आर. 58 आई. ए., 169,172, लाखी

नारायण दास बनाम। बिहार प्रांत, 1949 एफ. सी. आर. 693,699; मेसर्स एस. के. जी. शुगर

लिमिटेड वी. बिहार राज्य और अन्य। [1975] 1 एस. सी. आर. 312 ने आवेदन किया।

री में। श्रीरामुलु ए. एल. आर. 1974 ए. पी. 106, एस. आर. के. मनुमंथ राव बनाम। राज्य

ओ. जे. ए. पी. (1975) 2 ए. डब्ल्यू. आर. 277 अनुमोदित।

कोलेग्रोव वी। ग्रीन (1925) 328 यू. एस. 549 संदर्भित।

राजा वी। बेनोआरी लाल सरमा, एल. आर. 72 आई. ए. 57,64 ने समझाया।

पैडफील्ड बनाम। कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्री एल. आर. 1968 ए. सी. 997,

1007 अनुमोदन के साथ उद्धृत।

(6) यदि केंद्र सरकार की राय बाहरी पर आधारित थी या

अप्रासंगिक सामग्री या यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत विचारों द्वारा निर्देशित थी या अन्य उद्देश्यों के लिए, न्यायालय हमेशा हस्तक्षेप करेंगे और इस तरह की कार्रवाई करेंगे

दुर्भावनापूर्ण और इसे नीचे मार डालो। [119 बी]

डॉ. ए. के. शैहर और अन्य। वी. कुलपति, बनारस विश्वविद्यालय, [1961]

3 एस. सी. आर. 386 पीछा किया।

निरीक्षण:

मंत्रिपरिषद द्वारा अपनी सलाह देने में दिए गए कारणों के रूप में

राष्ट्रपति से न्यायालयों द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकती है, यह आशा की जाती है कि

केंद्र सरकार दूरगामी निर्णय ले रही है

संविधान के काम करने पर रोक, बहुत सावधानी और चौकसी के साथ कार्य करेगा

पीक्शन और कुछ मात्रा में निष्पक्षता के साथ ताकि पेशेवरों पर विचार किया जा सके और

विपक्ष और उनके सामने समस्याओं के विभिन्न रंग और विशेषताएँ

शांत और एकत्रित तरीके से। ऐसे मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए -

बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण और मजबूत और संरक्षित करने का इरादा संविधान। और इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा

सरकार। सी. एल. द्वारा दी गई अंतिमता की मुहर। (5) कला की। 356 में से

संविधान केंद्र सरकार के लिए एक मुफ्त लाइसेंस का संकेत नहीं देता है

राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दें और उन कारणों से आदेश पारित कराएं जो

वे पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी हैं या जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। आदेश का पारित होना। इस हद तक न्यायिक समीक्षा बनी हुई है।

[

121 बी-डी] [1978] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14

हेल्ड फर्थर: (बहुमत से असहमति)

(7) कला का आयात और उद्देश्य। 131 एक के बीच विवादों का फैसला करना है

राज्य और दूसरा या भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच।

संविधान के संस्थापकों ने संविधान में "राज्य" शब्दों का उपयोग किया है।

कला. 131 दोनों जानबूझकर और सलाह के साथ ताकि राज्य को एक के रूप में माना जा सके संघ की घटक इकाई अपने क्षेत्र और स्थायी संस्थान के साथ

टियोन। इन संस्थानों को चलाने वाले कर्मियों के बारे में सवाल केवल यह है कि

किसी राज्य और सरकार के बीच विवाद के अस्तित्व से असंबद्ध

भारत से। यह केवल तभी होता है जब किसी भी प्रति का पूर्ण उन्मूलन होता है एक राज्य की ऐसी व्यवस्था जो एक वास्तविक विवाद उत्पन्न कर सके। एक मात्र गति।

अनुच्छेद के तहत एक सभा का दुर्लभ विघटन। 356 यह उन्मूलन के बराबर नहीं है

राज्य विधानसभा का क्योंकि ऐसे विघटन के बाद, के प्रावधानों के तहत

संविधान, चुनाव आने वाले हैं और एक नई विधायिका होगी

जाहिर है कि मतदाताओं द्वारा उम्मीदवारों को चुनने के बाद अस्तित्व में आता है।

[107 बी-डी]

(8) कला के सही और उचित निर्माण पर। 131 संविधान के अनुसार

संविधान का अनुच्छेद 131। इसलिए, राज्य सरकारें जिनके पास है विवाद अनुच्छेद 131 में दिखाई देने वाले 'राज्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है

और, इसलिए, सूट इस आधार पर भी बनाए रखने योग्य नहीं हैं। [107 ई]

मौलिक न्यायनिर्णय: मूल सूट संख्या। 1 1977 के 6 तक।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत)

निरेन डे, एस. के. तिवारी, अधिवक्ता। जनरल। राजस्थान, एस. एम. जैन, मुकदमा संख्या 1 में वादी के लिए।

मुकदमे में वादी के लिए निरेन डे, राम पंजवानी और आई. एन. स्ट्रॉफ

नंबर 2

एच. आर. गोखले, राम पंजवानी, विजय पंजवानी, ओ. पी. शर्मा,

मुकदमा संख्या 3 में वादी के लिए एस. के. बग्गा और श्रीमती एस. बग्गा।

निरेन डे, डी. पी. सिंह, एस. सी. अग्रवाल और यू. पी. सिंह

वाद सं. 4 में वादी।

मदन भाटिया, मुकदमा संख्या 5 में वादी के लिए।

जी. रथ, अधिवक्ता। वादी की ओर से जनरल, उड़ीसा, निरेन डे, आर. के. मेहता

सूट नंबर 6 में।

सोली। जे. सोराबजी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ओ. एस. नं.

1-3 / 77) , बी. दत्ता, (सूट संख्या में। 1-3 / 77) और आर. एन. सचथी, सभी मामलों में प्रतिवादी/प्रत्यर्थियों के लिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एम. के. गर्ग, एस. सी. अग्रवाल और वी. जे. फ्रांसिस

रिट याचिकाओं में।

जे पी गोयल, एस के सिन्हा, बी बी सिंह और ए के श्रीवास्तव

आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता-ओ. एस. सं. 1/77 में गिरधारी लाल भार्गव।

आवेदक के लिए जे. पी. गोयल, शरद मनोहर और सी. जे. साहू:

हस्तक्षेप करने वाले-चौधरी देवी लाल लिखित याचिकाओं में।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय दिए गए:

बी. ई. जी. सी. जे. मूल सूट संख्या। 1 1977 के 6 तक, अब हमारे सामने

राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों की ओर से दायर किए गए हैं देश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा संघ राजस्थान बनाम।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

15

भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत। वहाँ हैं।

हमारे सामने भी तीन रिट याचिकाएँ, सं। 67 संघ के विरुद्ध पंजाब राज्य की विधान सभा के तीन सदस्यों द्वारा 1977 के 69 तक

भारत सरकार में गृह मंत्री श्री चरण सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री जैल सिंह। छह मुकदमे और तीन रिट याचिकाएं कुछ सामान्य सवाल उठाती हैं।

कानून और तथ्य। इसलिए, उन्हें एक साथ बहस करने की अनुमति दी गई। हम मुकदमों और याचिकाओं को विस्तार से सुनने के बाद पहले ही खारिज कर चुके हैं और अब ऐसा करने के लिए अपने कारण बताने का प्रस्ताव करते हैं जैसा कि हमारे 29 अप्रैल 1977 के आदेश में कहा गया है। तथ्य और कानून के प्रश्नों से निपटने से पहले मैं नक्काशियों की प्रकृति का संकेत दूंगा: प्रत्येक वादी द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता की शिकायत मांगी गई।

राजस्थान राज्य ने एक घोषणा के लिए कहा कि उसने क्या वर्णन किया है

केंद्रीय गृह मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को 18 अप्रैल, 1977 को जारी पत्र में निहित एक "निर्देश" के रूप में, "असंवैधानिक, अवैध और संविधान के अधिकार से बाहर है।

यह घोषणा और यह भी कि वादी राज्य "उक्त पत्र में निहित निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक सहयोगी या कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य इस घोषणा की मांग करता है कि "निर्देश

प्रतिवादी का अपने गृह मंत्री के माध्यम से 18 अप्रैल, 1977 का आदेश संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

पंजाब राज्य एक घोषणा के लिए कहता है कि वह क्या बताता है

" निर्देश/व्यवस्था "संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

बिहार राज्य इस पत्र को एक "निर्देश" कहता है और इसके लिए पूछता है

घोषणा करें कि यह "असंवैधानिक और अमान्य" है। यह एक घोषणा के लिए भी प्रार्थना करता है कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इसका पालन करने से इनकार करने को "संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के मुद्दे का आधार नहीं बनाया जा सकता है"। इसमें यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 356 को "लोकसभा के चुनावों में उक्त विधानसभा में बहुमत वाले दल की हार के बाद राज्य विधानसभा को भंग करने और उक्त विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता है"।

हिमाचल प्रदेश राज्य आठ घोषणाओं के लिए प्रार्थना करता है: सबसे पहले,

कि "राज्य की मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और वादी की विधानसभा इस आधार पर भंग होने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके पास विधान सभा में बहुमत है, लोकसभा चुनावों में हार गई थी और जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आ गई है"; दूसरा,

कि "प्रतिवादी की कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के एकमात्र विशेषाधिकार का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह राज्यपाल को सलाह देना उचित समझती है"; तीसरा, कि "संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा केवल इसलिए लागू किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में सत्ता में लौटी गई राजनीतिक पार्टी अलग होती है।

संविधान के तहत कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दिया जाए क्योंकि मतदाताओं के विचारों में परिवर्तन हुआ है जैसा कि कहा गया है।

प्रतिवादी के गृह मंत्री के 18 अप्रैल, 1977 के पत्र में ";

पाँचवाँ, कि "पत्र में उल्लिखित परिस्थितियाँ गठित नहीं करती हैं।

कानून और व्यवस्था के लिए खतरा, और, किसी भी मामले में, कानून के लिए ऐसा खतरा और

आदेश कानून के विघटन के लिए कोई संवैधानिक आधार नहीं बना सकता है।

वादी की लैटिव असेंबली "; छठा, कि" कारण और परिधि

प्रतिवादी द्वारा वादी के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में बताए गए नृत्य और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की धमकी दी गई

संविधान की धारा पूरी तरह से असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण है और यह कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर जारी की गई घोषणा पूरी तरह से शून्य होगी; सातवां, कि "संविधान के अनुच्छेद 356 (1) में पूर्ववर्ती और निर्धारित शर्त अस्तित्व में नहीं है"; आठवां, कि "वादी के विधानमंडल को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी की गई किसी भी घोषणा को संविधान के अनुच्छेद 356 (3) द्वारा परिकल्पित संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है"।

उड़ीसा राज्य ने एक घोषणा के लिए कहा कि "निर्देश"

18 अप्रैल, 1977 के पत्र में निहित, "असंवैधानिक, अवैध और संविधान के अधिकार से बाहर" है और यह भी कि वादी राज्य है " उक्त पत्र में निहित निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक या कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

इसके अलावा, छह मुकदमों में से प्रत्येक वादी एक पर्मा मांगता है

कुछ भी नहीं और साथ ही एक अंतरिम निषेधाज्ञा थोड़ी अलग शब्दों में लेकिन

मांगे गए इन सभी आदेशों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट और सामान्य है।

राजस्थान राज्य ने स्थायी निषेधाज्ञा "प्रतिबंध" की मांग की है

प्रतिवादी को उक्त पत्र में निहित निर्देश को किसी भी तरह से लागू करने से रोकना। यह स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग करता है।

संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेने वाले प्रतिवादी को रोकना

मार्च, 1978 से पहले राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले भारत सरकार ने राजाओं के राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया।

" मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शाश्वत "निषेधाज्ञा" की मांग की जाती है

भारत के प्रतिवादी संघ के खिलाफ अपनी सरकार को "पत्र में निहित निर्देशों को लागू करने और/या राज्य के विधान को भंग करने" से रोकने के लिए।

पंजाब राज्य "रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा" के लिए प्रार्थना करता है

प्रतिवादी को 18 अप्रैल 1977 के बयान में निहित निर्देशों को लागू करने और 18 अप्रैल 1977 के पत्र में

वादी राज्य का मुख्यमंत्री और प्रतिवादी को वादी राज्य की विधानसभा को भंग करने या मार्च 1978 से पहले अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने से रोकना।

' बिहार राज्य ने इस मुद्दे के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा का प्रतिवादी संघ "बिहार राज्य विधानसभा को भंग करने और राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के उद्देश्य से"। राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

17

हिमाचल प्रदेश राज्य ने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है

" संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत प्रतिवादी को कोई भी उद्घोषणा जारी करने से रोकना "प्रावधानों द्वारा विचार की गई स्थिति को छोड़कर और दूसरा केंद्र सरकार को राज्य की विधानसभा को भंग करने से रोकने के लिए" जब तक कि अनुच्छेद के तहत कोई उद्घोषणा जारी नहीं की जाती है। 356 संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान की अनुसमर्थन की जाती है। दूसरे शब्दों में, "क्वो उस्को" के लेखन की प्रकृति में एक निषेधात्मक आदेश की मांग की जाती है (जब तक कि एक शर्त पूर्ववर्ती पूरी नहीं हो जाती)।

उड़ीसा राज्य "स्थायी निषेधाज्ञा" के लिए प्रार्थना करता है

प्रतिवादियों को उक्त पत्र में निहित "निर्देश" को "किसी भी तरह से" और एक अन्य "स्थायी निषेधाज्ञा" को प्रभावी बनाने से रोकने के लिए

प्रतिवादियों को उड़ीसा राज्य की विधानसभा को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेने और मार्च 1980 से पहले राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कोई भी कदम उठाने से प्रशिक्षित करना। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य की विधानसभा के चुनाव 1974 में हुए थे।

आई।

छह राज्यों में से प्रत्येक ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए भी कहा है

ताकि सूट में प्रार्थना की गई नक्काशी निष्फल न हो।

पंजाब की रिट याचिकाओं में तीन याचिकाकर्ता मेम हैं।

पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य। वे दावा करते हैं कि संपत्ति के रूप में उनके मौलिक अधिकार को खतरा है

विधान सभा के सदस्य के रूप में अपना "वेतन" प्राप्त करने का अधिकार

आसन्न खतरा उन्हें अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय।

यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले में वादी द्वारा की गई कार्रवाई का कारण

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वाद के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा

कहा जाता है कि गृह मंत्री श्री चरण सिंह के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था

केंद्र सरकार में, और कहा जाता है कि एक बयान दिया गया है

श्री शांति भूषण, केंद्र सरकार में कानून मंत्री।

ये, अनुच्छेद 131 के तहत वादियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के अनुसार अनुच्छेद 32 के तहत, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करें कि

इसमें शामिल प्रत्येक राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा के बाद यदि श्री का पत्र क्या है

चरण सिंह बताते हैं कि "सलाह" प्रमुख द्वारा नहीं दी जाती है।

छह राज्यों में से प्रत्येक के मंत्री।

वादी की ओर से प्रमुख सामान्य प्रस्तुतियाँ

साथ ही याचिकाकर्ता इस प्रकार हैं:

सबसे पहले, श्री चरण सिंह का 18 अप्रैल का पत्र,

1977 , के तहत एक आसन्न घोषणा के एकमात्र आधार का खुलासा करता है

संबंधित राज्य की विधान सभा और ऐसी कोई घोषणा परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से मंत्रालयों को बर्खास्त किया जाता है

छह राज्यों और उनकी विधानसभाओं का विघटन पत्र में दिए गए आधार, प्रथम दृष्टया दायरे से बाहर हैं

संविधान का अनुच्छेद 356।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

1978] 1 एस सी आर।

18

दूसरा, कि, किसी भी मामले में, पूर्ववर्ती स्थिति

राज्य विधानसभाओं का समाधान बेथ द्वारा अनुसमर्थन है

राष्ट्रपति के संसद के सदन अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करते हैं

ताकि विधानसभा के विघटन पर, किसी भी दर पर, ले जा सके पार्लिया के दोनों सदनों की इच्छाओं को सुनिश्चित किए बिना स्थान

मन में।

तीसरा, कि दिए गए आधार संवैधानिक रूप से बाहर हैं

प्राधिकृत उद्देश्य और उद्देश्य प्रस्तावित कार्रवाई करते हैं,

इसके बावजूद, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक। हमारा ध्यान मैदानों में कुछ दावों और अधिवक्ताओं के लिए याचिकाओं की ओर भी आकर्षित किया गया था।

"वास्तव में द्वेष" और "कानून में द्वेष" की दलीलें।

भारत संघ की ओर से जवाब इस प्रकार हैं:

सबसे पहले यह कि मैदानों में लगाए गए आरोपों पर हमारे सामने कोई मुकदमा नहीं है

यह कला के दायरे में आएगा।

131 संविधान

का

जो केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों की शिकायतों के लिए है, न कि राज्यों के संवैधानिक या अन्य कानूनी अधिकारों को शामिल किए बिना केवल राज्य सरकारों और विधानमंडलों की संरचना से संबंधित शिकायतों के लिए।

दूसरा, अस्तित्व का आकलन करने के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं

अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का आह्वान करने वाली "स्थिति", अपने स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से गैर-न्यायोचित है, और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 (5) द्वारा स्पष्ट रूप

से गैर-न्यायोचित भी बनाया गया है ताकि, भले ही कोई राज्य अपनी सरकार और संघ के बीच विवाद में कानूनी और उचित रूप से भयभीत कहा जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कार्रवाई की वांछनीयता या आवश्यकता के बारे में सरकार, ऐसा विवाद न्यायसंगत मामलों के दायरे से बाहर है। यदि अंतिम कार्रवाई या उसके आधार न्यायोचित नहीं हैं, तो उन पर अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी प्रक्रिया को चुनौती देकर हमला नहीं किया जा सकता है जो वास्तव में अनुमानित परिणाम या कार्रवाई का कारण बन सकती है या नहीं भी।

तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री का पत्र और उनका भाषण

केंद्रीय कानून मंत्री यह संकेत नहीं देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के व्यापक दायरे से बाहर आने वाली किसी भी चीज़ को अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने के लिए ध्यान में रखा जा रहा है या ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, वहाँ बताए गए मामलों पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं कहा जा सकता है।

चौथा, केवल कुछ तथ्यों की सूचना, पूरी तरह से दायरे में

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए संकेतित तथ्यों और संभवतः अन्य तथ्यों के आधार पर भविष्य में कार्रवाई करने के लिए निषेध को उचित नहीं ठहराता है, जब स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। दूसरे शब्दों में, निवेदन यह था कि अब संभवतः यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि क्या अन्य तथ्य थे या नहीं या कौन से अन्य संभावित तथ्य, जो स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता

भविष्य में उत्पन्न होता है। संघ के सर्वोच्च कार्यकारी अंगों की अधिकृत कार्यकारी कार्रवाई को न्यायिक हस्तक्षेप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय स्पष्ट और गंभीरतम चरित्र के आधार पर। अभी, न्यायालय के समक्ष केवल संभावनाओं से परे कुछ भी नहीं था ताकि कोई अग्रिम निषेधाज्ञा या आदेश नहीं दिया जा सके।

राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

19

संघ की ओर से आपत्ति का पहला आधार इन तक सीमित है -

सूट। लेकिन, आपत्ति के शेष तीन आधार मुकदमों के साथ-साथ रिट याचिकाओं के लिए भी समान हैं।

भारत संघ की ओर से नोटिस स्वीकार किए गए और प्रारंभिक

ऊपर उल्लिखित आपत्तियों को मुकदमों और उसमें लगाए गए आरोपों पर याचिकाओं की स्थिरता के लिए लिया गया था। हम, इससे पहले, प्रारंभिक आपत्तियों पर दलीलें सुनने के लिए आगे बढ़े, जिसमें प्रतिवादियों या उत्तरदाताओं को लिखित बयान या जवाब दाखिल करने या औपचारिक रूप से मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं वादपत्रों और याचिकाओं में किए गए आरोपों की जांच करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वहां किए गए दावे, तथ्य के प्रश्नों पर, मुकदमों या मांगी गई राहत के लिए याचिकाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा करने के लिए पर्याप्त हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्री चरण सिंह द होम का पत्र

केंद्र सरकार में मंत्री, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को वादी और याचिकाकर्ताओं की शिकायत का प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है। इनमें से एक समान रूप से लिखे गए पत्र (राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र) को यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। यह इस प्रकार चलता हैः

" डी. ओ. सं. 355/एमएस/टी/77

गृह मंत्री

भारत

नई दिल्ली,

18

अप्रैल, 1977।

प्रिय श्री जोशी,

हमने आभासी पुनर्गठन से उत्पन्न सबसे अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया है

हाल के लोकसभा चुनावों में, विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की संख्या। अनिश्चितता का परिणामी माहौल हमारे लिए गंभीर चिंता का कारण बन रहा है। हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि इससे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मतभेद की भावना पैदा हुई है। बड़े पैमाने पर लोग अब किसी पार्टी की सत्ता में निरंतरता के औचित्य की सराहना नहीं करते हैं जिसे मतदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। अनिश्चितता, मतभेद और अनादर के माहौल ने पहले ही कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरों को जन्म दिया है।

2. प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञों की लंबे समय से यह राय रही है कि जब कोई विधानमंडल अब मतदाताओं की इच्छाओं या विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है और जब यह मानने के कारण हैं कि विधानमंडल और मतदाता भिन्न हैं, तो मतदाताओं से एक नया जनादेश प्राप्त करने की दृष्टि से विघटन सबसे उपयुक्त होगा। आपके राज्य में प्रचलित परिस्थितियों में, राजनीतिक संप्रभु के लिए एक नई अपील न केवल अनुमेय होगी, बल्कि आवश्यक और अनिवार्य भी होगी।

[1

978] 1 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20

3. इसलिए, मैं आपके विचार की ईमानदारी से सराहना करता हूं।

कि आप राज्यपाल को अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधानसभा को भंग करने और मतदाताओं से नए सिरे से जनादेश लेने की सलाह दे सकते हैं। हमारे सुविचारित विचार में, केवल यही होगा

संवैधानिक पूर्ववर्ती और लोकतांत्रिक प्रथाओं के अनुरूप।

4. मैं आभारी रहूंगा अगर आप कृपया मुझे बताएँ

23rd आप क्या करने का प्रस्ताव करते हैं।

संबंध में,

आप

की ईमानदारी से,

एसडी /

(चर

ण सिंह)

श्री हरिदेव जोशी,

राजस्थान के मुख्यमंत्री,

जयपुर "।

इस आरोप की पुष्टि करने के लिए कि पत्र एक "खतरे" का गठन करता है

सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई, प्रत्येक वादी राज्य की विधानसभा को भंग करने और उस पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो पर कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री श्री शांति भूषण के एक भाषण की रिपोर्ट से पुष्टि मांगी गई थी, जो 23 अप्रैल 1977 के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुई थी। हालाँकि, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट उनकी सच्चाई का स्वीकार्य प्रमाण नहीं हैं, फिर भी,

आई.

उस अर्क को पुनः उत्पन्न करें जो या तो उससे या उसके पदार्थ से जुड़ा हुआ था

केवल यह परीक्षण करने के लिए कि क्या यह मानते हुए भी कि इसकी सामग्री को उचित समय पर दिए जाने वाले स्वीकार्य साक्षय द्वारा साबित किया जाना था, सभी आरोपों को एक साथ लिया जाए तो कुछ कार्रवाई योग्य होगा। रिपोर्ट में कहा गया है:

" नौ राज्यों को सलाह देना संवैधानिक कर्तव्य है: शांति

भूषण।

केंद्रीय कानून मंत्री श्री शांति भूषण ने शुक्रवार को कहा कि

जिस रात विघटन के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था

नौ कांग्रेस शासित राज्यों में विधानसभाओं का गठन

समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, नए चुनावों की शुरुआत।

अखिल भारतीय के स्पॉट-लाइट कार्यक्रम में एक साक्षात्कार में

रेडियो ने कहा कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता

संविधान लोकतंत्र था, जिसका अर्थ था कि एक सरकार

लोगों की व्यापक सहमति से काम करना चाहिए

और केवल तब तक जब तक यह उनके आत्मविश्वास का आनंद लेता है। यदि राज्य

सरकारों ने हारने के बाद लोगों पर शासन करना चुना

लोगों का विश्वास, वे अलोकतांत्रिक होंगे

उन्होंने कहा कि सरकारें।

अनुच्छेद 355 के तहत संघ पर एक कर्तव्य डाला गया था।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारों का संचालन किया जाए

संविधान के अनुसार।

राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि वे उन्हें सलाह दें कि

राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य विधानसभाओं को भंग करने की सिफारिश करेंगे। कानून मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों के विश्वास का आनंद लेने पर एक गंभीर संदेह पैदा हो गया था, उनकी पार्टी को हाल के लोकसभा चुनावों में खारिज कर दिया गया था।

शक्ति का प्रयोग

उन्होंने जवाब दिया कि आखिरकार जब भी संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त की जाती है, तो यह केवल इसे प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है। जाहिर है कि संविधान उन परिस्थितियों का खाका तैयार किया जिनके तहत उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब वे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं तो केंद्र की ओर से उस शक्ति को समाप्त करना अप्रत्यक्ष था।

श्री शांति भूषण ने कहा कि वह यह समझने में विफल रहे कि राज्य सरकारों ने लोगों के पास अपना जनादेश मांगने के लिए जाने पर आपत्ति क्यों जताई। अगर हम लोगों की वास्तविक संप्रभुता और सर्वोच्चता को पहचानते हैं, तो कोई संभावित बाधा नहीं हो सकती है। अगर कोई

शासन करने के दिव्य अधिकार का दावा करता है, चाहे लोग उसे चाहते हों या नहीं, तो निश्चित रूप से लोगों के पास जाने पर आपत्ति हो सकती है।

पूर्वस्थिति अंत

राज्य विधानसभाओं के पूर्व परिपक्व विघटन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताते हुए श्री शांति भूषण ने कहा कि दो अनुच्छेद इस मामले से संबंधित हैं। अनुच्छेद 172 में सामान्य कार्यकाल के लिए प्रावधान किया गया था जो पहले पांच साल था। लेकिन इसे संविधान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा छह साल तक बढ़ा दिया गया था। तब अनुच्छेद 174 ने राज्यपाल को पांच या छह साल की सामान्य अवधि के दौरान भी समय-समय पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति दी। आम तौर पर इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना था।

उनसे पूछा गया था कि क्या मंत्रिपरिषद को अनुच्छेद 356 का सहारा लेने की अनुमति है।

अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने में विफल रहे।

श्री शांति भूषण ने समझाया कि अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य दिया गया था कि राज्यों में सरकारें संविधान के अनुसार चलती रहें। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान

संविधान "। बल्कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता लोकतंत्र थी जिसका अर्थ था कि [1978] 1 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार को व्यापक सहमति के साथ काम करना चाहिए

लोग और केवल तब तक जब तक यह विश्वास का आनंद लेता है

लोग।

निरंतर गोपनीयता

श्री शांति भूषण ने कहा कि केवल एक तथ्य यह है कि

राज्यों में सरकारों ने विश्वास का आनंद लिया

वे उस विश्वास का आनंद लेते रहे। अगर कोई स्थिति है। उत्पन्न हुआ जिसमें सरकार पर एक गंभीर संदेह डाला गया था

लोगों के निरंतर विश्वास का आनंद लेते हुए, तब

विधानसभा को समय से पहले भंग करने का प्रावधान मध्यम रूप से संचालन में आया।

प्रावधान न केवल शक्ति देता है बल्कि यह एक

कर्तव्य क्योंकि यह शक्ति कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात्,

विधानसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और सरकार

यह देखने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए कि क्या यह जारी है

शासन करने के लिए लोगों का विश्वास। हारने के बाद भी -

लोगों का विश्वास, अगर सरकार ने चुना

लोगों को नियंत्रित करें, यह अलोकतांत्रिक होगा। ऐसा नहीं होगा।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार।

ठीक यही व्यापक के पीछे का दर्शन था।

अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्तियाँ। 355 और 356।

जाहिर है कि कुछ अधिकार दिए जाने थे

यह सुनिश्चित करें कि संविधान के तहत पदाधिकारी थे

संविधान के अनुसार काम करना।

जैसा कि कई राज्य थे, जाहिर है कि एक भी नहीं था

राज्य को यह शक्ति दी जा सकती है। इसलिए, यह शक्ति

केंद्र सरकार को यह देखने के लिए सौंपा गया था कि राज्य

सरकारें संविधान के अनुसार कार्य कर रही थीं

जिसका अर्थ था लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार

और सम्मेलन।

पूरी तरह से भावनात्मक नहीं

जवाब: एक और सवाल श्री शांति भूषण ने किया।

.....इस बात से सहमत नहीं हैं कि पूरा संविधान 42 वां संशोधन

अधिनियम अनैतिक था। लेकिन गंभीर आपत्तियां थीं।

नैतिकता के आधार पर उस अधिनियम के लिए। जब यह संशोधन

संसद के माध्यम से जल्दबाजी की गई थी, पाँच साल का कार्यकाल सदस्य समाप्त हो गए। उनका कार्यकाल था। वास्तव में समाप्त हो गया और

उनके पास इस तरह के अधिनियम को लागू करने का निरंतर जनादेश नहीं था

42 वें संशोधन के रूप में महत्वपूर्ण अधिनियम। इसके परिणाम

लोकसभा चुनावों ने यह भी दिखाया था कि लोगों ने

वास्तव में उन्हें संशोधन को लागू करने का जनादेश नहीं दिया गया:

- 42 वें संशोधन पर दूसरी आपत्ति यह थी कि

आपातकाल के दौरान विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता

पार्टियाँ जेल में थीं। वे अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके।

राजस्थान बनाम. यूनियन (बेग, सी. जे.)

23

श्री शांति भूषण ने कहा कि 42 वें संशोधन में

अधिनियमित किया गया। जैसा कि मंत्रियों ने पालन करने की शपथ ली थी

संविधान द्वारा, वे प्रावधानों की उपेक्षा नहीं कर सके

के

साथ

42 वां संशोधन तब तक बना रहा जब तक यह बना रहा।

परिणामस्वरूप उन राज्यों में चुनाव कराना संभव नहीं था

जहाँ राज्य सरकारों ने जनादेश नहीं खोया था जैसा कि लोकसभा चुनावों में परिलक्षित हुआ था "।

मैंने शिकायत के दो बुनियादी स्रोतों को मैदानों में निर्धारित किया है

और इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या यह मानते हुए कि इस तरह के राज्य के प्रस्ताव केंद्र सरकार के दो बहुत ही जिम्मेदार और महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा किए गए थे, वे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत निषेधाज्ञा या विधानसभा के सदस्यों द्वारा रिट याचिकाओं को बनाए रख सकते हैं।

जहाँ तक श्री चरण सिंह के पत्र का संबंध है, यह निश्चित रूप से है।

इसमें संविधान के अनुच्छेद 356 का भी उल्लेख नहीं है। फिर भी, श्री शांति भूषण का भाषण, यह मानते हुए कि

सही ढंग से सूचित किया गया था, अनुच्छेद 355 और 356 का उल्लेख करता है

संविधान और के मूल उद्देश्यों में से एक के दृष्टिकोण की व्याख्या करता है

संविधान जिसका पालन कानून की राय में किया जा सकता है मंत्री, 'द्वारा सुरक्षित रहें, कला का सहारा लें। 356 संविधान से। द.

भाषण कानून मंत्री के विचार को व्यक्त करता है कि एक था

संविधान के अनुच्छेद 355 द्वारा केंद्र सरकार पर डाला गया कर्तव्य की वर्तमान राय के बीच एक अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ट्यूशन

निर्वाचक मंडल और विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभाओं की संरचना

आज जिन राज्यों में सरकारें सत्ता में हैं, उनमें इन विचारों को दर्शाया गया है

प्रत्येक राज्य में केवल एक समय में प्रचलित निर्वाचकों का बहुमत

जब राज्य विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था। द.

सवाल यह है कि क्या इन राज्य सरकारों का विश्वास बरकरार है

वर्तमान में मतदाता हैं या नहीं, इसका उत्तर केवल निर्णायक रूप से दिया जा सकता है -

स्वयं निर्वाचक। यही अनन्य अधिकार और विशेषाधिकार था।

एक लोकतांत्रिक संवैधानिक योजना और कानून के तहत निर्वाचकों की।

कानून मंत्री के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारित नहीं कर सकते हैं

अत्यधिक प्रतिकूल होने के बावजूद अब सत्ता में बने रहने का अधिकार इन दलों के सदस्यों के विरुद्ध निर्वाचक मंडल का निर्णय

सरकार का हिस्सा है। उनकी राय में ऐसा करना इसके विपरीत होगा।

हमारे संविधान में अंतर्निहित लोकतंत्र के बुनियादी मानदंडों के लिए।

यदि वह किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत

" कार्यकारी कार्रवाई के संवैधानिक रूप से निर्धारित तरीके की धमकी, किसी भी परिस्थिति में, अनुच्छेद 356 के तहत नहीं किया जा सकता है, हम हो सकता है

प्रदान की गई संवैधानिक शक्ति के दुरुपयोग या अधिकता को रोकने में सक्षम

प्रो जारी करने की शक्ति के सभी कथित प्रयोग पर न्यायिक नियंत्रण

अनुच्छेद 256 के तहत आरोप या तो निहित या स्पष्ट रूप से नहीं हैं।

वर्जित भले ही कोई प्रस्तावित कार्रवाई स्पष्ट रूप से अधिकार से बाहर हो। लेकिन अगर

दोनों केंद्रीय मंत्रियों के विचार संवैधानिक स्थिति बताते हैं।

सही है, किसी के लिए "दुरुपयोग" या "शक्तियों के दुरुपयोग" का कोई सवाल ही नहीं है।

संपार्श्विक उद्देश्य या एक "रोक-टोक" या धोखाधड़ी करने वाला

संविधान "या" वास्तव में द्वेष "या" कानून में द्वेष "(शब्द)

दोष के विभिन्न रंगों और शक्ति की अधिकता के प्रकारों को दर्शाता है)।

पहले के मामलों में धमकी भरी कार्रवाई के आरोपों पर उत्पन्न हो सकता है

हम, जो वास्तव में केवल इसी के बराबर है; केंद्र सरकार समर्थक

निर्वाचकों को देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्य करना।

[

1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24

विभिन्न राज्यों में यह दिखाने का एक नया मौका है कि क्या वे जारी हैं

संबंधित राज्य सरकारों और उनकी सरकारों में विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है नीतियों द्वारा प्रदान किए गए विपरीत साक्षय के बावजूद

हाल के लोकसभा चुनाव।

हमारे संविधान और कानूनों का एक उद्देश्य निश्चित रूप से देना है

निर्वाचकों को अपने राज्य की विधायिका चुनने का आवधिक अवसर

और, इस प्रकार, उनके राज्य के शासन के चरित्र को निर्धारित करने के लिए

मन में भी। यह प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान का उद्देश्य है।

को

ऐसे अवसर दें। अत:, इसकी सेवा के लिए एक नीति तैयार की गई और

संविधान की मूल संरचना या योजना के विपरीत नहीं हो सकता है

टचूशन। सवाल यह है कि क्या उन्हें वह मौका मिलना चाहिए। अब या बाद में राजनीतिक औचित्य या कार्यपालिका का सवाल हो सकता है।

नीति। क्या यह कानूनी अधिकार का भी सवाल हो सकता है जब तक कि कोई

पूर्व में विधान सभा के विघटन के विरुद्ध निषेध

एक निश्चित अवधि समाप्त हो गई है? अगर कोई संविधान था

निषेध, ताकि केंद्र सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई

हम उस संवैधानिक फैसले का उल्लंघन कर सकते थे

हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन, क्या हम ऐसा तब कर सकते हैं जब कोई स्थिरता न हो

न्यायिक प्रावधान जो किसी राज्य के विधानमंडल को अधिकार देता है -

कुछ अधिशासी परिस्थितियों के बावजूद अनसुलझा रहना जो

एक दृष्टिकोण के अनुसार, क्या इसका विघटन आवश्यक हो सकता है?

इस न्यायालय के लिए कार्रवाई करना संभव हो सकता है यदि तथ्य और

प्रस्तावित कार्रवाई का समर्थन करने के लिए उल्लिखित परिस्थितियाँ ऐसी थीं

कला के दायरे से पूरी तरह बाहर। 356 या इतना स्पष्ट रूप से के साथ संघर्ष में

एक संवैधानिक प्रावधान जो शक्ति की अधिकता का सवाल हो सकता है

जाहिर तौर पर उत्पन्न हुए हैं। यदि, उदाहरण के लिए, एक आधिकारिक कथन,

एक केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया था कि एक विघटन है

केवल इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री या पूरी परिषद

किसी राज्य के मंत्री किसी विशेष जाति या पंथ से संबंधित होते हैं।

यह आग्रह किया जाए कि प्रस्तावित कार्रवाई भारतीय नागरिकों के कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी और

इस तरह के आधार पर भेदभाव। हालांकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है।

गेशन या हमारे सामने मैदानों में इसके विवरण जो कैपा हो सकते हैं इस निष्कर्ष को जन्म देने का कारण यह है कि ऐसा कोई भी संवैधानिक रूप से

निषिद्ध कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

विघटन और पुनर्निर्वाचन या प्रतिधारण के बीच चयन

एक निश्चित अवधि के लिए विधायिका या सरकार की एक ही सदस्यता एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत राजनीतिक औचित्य और रणनीति के मामले हो सकते हैं। हमारी व्यवस्था के तहत, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों और विचारधाराओं के साथ कई राजनीतिक दलों के गठन के माध्यम से राजनीतिक शक्ति की खोज कानूनी है। इसलिए

यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी पार्टी के लिए अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास, उस पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में, अन्य दलों के विपरीत, संवैधानिक रूप से निषिद्ध है।

या

अपने आप में अवैध। नैतिक या यहाँ तक कि राजनीतिक आपत्तियाँ भी हो सकती हैं

यह आग्रह किया जा

सकता है कि राज्य

कुछ परिस्थितियों में ऐसे पाठ्यक्रम। रंग पर सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक नीति के मामलों पर केंद्र सरकार के साथ मतभेदों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या सलाह के बिना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अधिकार राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

पहले के विघटन के मामलों को छोड़कर, राज्य के विधायकों की ओर से दावा किया गया था, जैसे कि वे अपनी विधानसभाओं के स्थायी रूप से निर्धारित जीवन काल की समाप्ति तक विधायक के रूप में बने रहने के लिए कानूनी अधिकार थे। हम यहाँ केवल भंग करने के कानूनी अधिकारों और इस तरह के विघटन के लिए कानूनी बाधाओं के बारे में चिंतित हैं।

राजनीतिक और नैतिक आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने का एक नया अवसर दिया जाना चाहिए।

की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपने निर्णय की घोषणा करना। राज्यों में सरकारें जब अपने और अपनी सरकारों के विचारों के बीच व्यापक विचलन के बहुत विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं। कानून मंत्री का विचार है कि, जहां किसी राज्य में उस पार्टी के खिलाफ भारी चुनावी फैसला होता है, जिससे उसकी सरकार संबंधित होती है, वहां स्थिति न केवल उचित ठहराती है, बल्कि एक नए चुनाव का सहारा लेती है या राजनीतिक संप्रभुता के लिए एक अपील अनिवार्य बनाती है। मुझे लगता है कि यह काफी हद तक एक राजनीतिक और नैतिक मुद्दा है। हम केवल संवैधानिक प्रावधानों के साथ इसके संबंधों के बारे में चिंतित हैं। यदि मतदाताओं या उन अधिकारियों के मन और भावनाओं पर इसका प्रभाव ऐसा है जिन्हें दिन-प्रतिदिन का प्रशासन जारी रखना है तो यह होगा। सरकार के उद्देश्यों को ही विफल कर दें। संविधान या किसी राज्य में सरकार के लिए संविधान के तहत कार्य करना असंभव बनाना, यह इस

निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता है। हम यह नहीं भूल सकते कि अनुच्छेद 356 (1) "स्थिति" के मूल्यांकन का आह्वान करता है। हम आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सभी प्रकार के कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली या न होने वाली स्थितियों में निर्णयों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं या संभावित कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं:

.

यदि केंद्र सरकार सोचती है कि स्थिति की परिस्थितियों की मांग है कि राज्य सरकारों को अपने मतदाताओं के हित में सत्ता का प्रयोग करने के लिए लोगों की नजर में अपने नैतिक अधिकारों को सही ठहराने के लिए एक नए जनादेश की मांग करनी चाहिए, या फिर जनता के असंतोष का न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है, बल्कि यह उन कानूनी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों को भी प्रभावित करेगा जो केंद्र सरकार की किसी विशेष राज्य या सामान्य रूप से भारतीय नागरिकों के प्रति हैं, जिनमें से सभी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है? मेरा मानना है कि इस तरह के मामले में केंद्र सरकार के फैसले को प्रतिस्थापित करना असंभव है।

भले ही राज्य में अलग-अलग कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक अंगों की स्थापना के पीछे एक संघीय ढांचा देखना संभव हो और जैसा कि हमारे सामने आग्रह किया गया है कि जब तक राज्य सरकारों और उनकी विधानसभाओं ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों में लापरवाही या किसी भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उन्हें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदान किए गए तंत्र के साथ-साथ अतीत में कई अवसरों पर इसका उपयोग करने के तरीके से भी स्पष्ट है।

यह ऐसी स्थिति में करना है जो अब हमारे सामने है। संविधान के अनुच्छेद 131 का उद्देश्य निश्चित रूप से हमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस तरह के विवाद पर अपील न्यायालय के रूप में बैठने में सक्षम बनाना नहीं था।

राज्य सरकार। और, हमारा संविधान लचीला नहीं है ऐसी स्थिति की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उपकरण।

यह हो सकता है कि हमारे संविधान के तहत केवल सत्ता के पदों के लिए संघर्ष की बहुत अधिक गुंजाइश है ताकि महान उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित और हमारे लोगों द्वारा अपने सपनों को वास्तविकता देने के लिए आवश्यक सही शासन मानसिक नीतियों को राजनीतिक सत्ता के लिए हाथापाई में उपेक्षित किया जाता है। हालाँकि, हमारे सामने यह मुद्दा नहीं है कि क्या एक पक्ष या दूसरा पक्ष उन उद्देश्यों और उद्देश्यों में विफल रहा है जिनके लिए लोग देते हैं। अपने लिए हमारे जैसे संविधान। यह हमारे लिए नहीं है

यह तय करें कि क्या एक पार्टी जिसे अतीत में अपने अवसर मिले हैं, ने अपने हाथों में राजनीतिक और कानूनी शक्ति दर्ज करने के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया है, या जो अब केंद्र में सत्ता का उपयोग करते हैं, वे हमारे लोगों के हितों या सार्वजनिक भलाई के दृष्टिकोण से अधिक बुद्धिमानी, अधिक ईमानदारी से या अधिक प्रभावी ढंग से ऐसा करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोगों को खुद देना है। मुझे लगता है कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने यह अनुमान लगाने के लिए कुछ आधार बताए हैं कि लोगों को राजनीतिक संप्रभुता देने का समय आ गया है-नौ राज्यों में राज्य सरकारों और विधानसभाओं के भविष्य पर भी एक तरह से अपना निर्णय देने का मौका।

जो संवैधानिक रूप से आपत्ति के लिए खुला नहीं है। जहाँ तक कला धारा 356 (1) में राजनीतिक और कार्यकारी नीति के मामले शामिल हो सकते हैं और समीचीनता अदालतें इनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि

यह दिखाया गया है कि राष्ट्रपति किस संवैधानिक प्रावधान पर जा रहे हैं

अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के स्वीकृत आधारों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करता है, जबकि अनुच्छेद 74 (2) न्यायालयों को पूछताछ से अक्षम करता है। राष्ट्रपति को मंत्रिस्तरीय सलाह के अस्तित्व या प्रकृति या विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 356 (5) न्यायालयों के लिए "किसी भी आधार पर" राष्ट्रपति की संतुष्टि पर सवाल उठाना असंभव बनाता है। इसलिए, न्यायालय केवल राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है, उस पर विचार करने के लिए उनके पास जो कुछ भी बचा हो, उस पर कार्रवाई की वैधता निर्धारित कर सकते हैं। सीखा हुआ परामर्श

वादी और याचिकाकर्ताओं के लिए, जब अनुच्छेद 356 के साथ सामना किया जाता है

(5) , उन्होंने कहा कि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले प्रावधान के रूप में इसकी वैधता को चुनौती देंगे। हालाँकि, हमने अनुच्छेद 356 (5) में विशिष्ट प्रतिबंध के अलावा भी मुकदमों और याचिकाओं की स्थिरता के बारे में सुना। और, मैं उन अन्य आपत्तियों के साथ मूल रूप से निपटने का प्रस्ताव करता हूं।

इस न्यायालय ने संविधान के अधिकार के तहत किए जाने वाले सभी कृत्यों की संवैधानिकता के अंतिम न्यायाधीश के रूप में अपने संवैधानिक कार्य को कभी नहीं छोड़ा है। इसने तथ्य या कानून के प्रश्नों को निर्धारित करने से तब तक इनकार नहीं किया है जब तक कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है और न्याय का कारण अपने कार्यों से स्पष्ट होने में सक्षम है। लेकिन, यह अपने लिए यह नहीं मान सकता कि संविधान कहीं और अधिकार देता है या संविधान द्वारा राज्य के अन्य विभागों को सौंपे गए कार्यों को करता है जो बेहतर तरीके से सुसज्जित हो सकते हैं। उन्हें करने के लिए पेड। सभी के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन संविधान के संरक्षकों में राजस्थान बनाम का उल्लंघन न करने का कर्तव्य शामिल है।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

27

अन्य संवैधानिक अंगों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके उनकी अपनी संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों की सीमाएँ। केवल राजनीतिक ज्ञान या कार्यकारी नीति के प्रश्नों को न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकारी नीति को भी संवैधानिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के अधीन होना चाहिए। इसका अपना क्षेत्र और सीमाएँ हैं। लेकिन, जब तक यह उस क्षेत्र के भीतर काम करता है, तब तक इसके संचालन न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं।

उग्रता। यह संविधान की सर्वोच्चता के तहत शक्तियों के मोटे तौर पर पृथक्करण के सिद्धांत का भी एक हिस्सा है जो बार-बार प्रतिपादित किया जाता है

इस न्यायालय द्वारा और जिसका न्यायालय निर्विवाद रूप से पालन करता है

जब एक की सही व्याख्या पर इसके विचार भिन्न होते हैं या बदल जाते हैं

विशेष संवैधानिक प्रावधान।

इसलिए यह मानते हुए कि श्री चरण सिंह का पत्र

कानून मंत्री के कथित भाषण के संदर्भ ने आधार बनाया

एक बिल्कुल सही निष्कर्ष कि अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई संविधान राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा यदि "सलाह"

इसमें निहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वीकार नहीं किया जाता है, केवल

यहाँ हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या आर्टिक्ल का ऐसा उपयोग है।

356 संविधान किसी भी तरह से असंवैधानिक या कानूनी था।

दुर्भावनापूर्ण। एक ही मुद्दे को रखने का एक और तरीका होगा पूछना। क्या प्रो के लिए केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा बताए गए उद्देश्य

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की गई, यह मानते हुए कि

ऐसा प्रस्ताव या धमकी मिल सकती है। कहा जा सकता है कि

संविधान के अनुच्छेद 356 के उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक।

पंजाब के याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए श्री आर. के. गर्ग ने कहा है कि

जो हमें प्रतीत होता है, उसे आगे बढ़ाएँ, बहुत ही अधिकार के अनुसार

विद्वान वकील द्वारा उद्धृत, हमारे संविधान को समझने के तरीके पर

कहा जाता है कि यह दृष्टिकोण के लिए एक बहुत अच्छा औचित्य है

केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा मारा गया। श्री गर्ग ने एक मार्ग पर भरोसा किया

एच. एच. केशवानंद भारती में सीकरी, सी. जे. के निर्णय से श्रीपादगलवारू बनाम। केरल राज्य: (1)

" मुझे कला की व्याख्या करनी चाहिए। 368 हमारे संविधान की स्थापना में

यह, हमारे इतिहास की पृष्ठभूमि में और के प्रकाश में

हमारी आकांक्षाएँ और आशाएँ और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियाँ।

इसके पंखों के नीचे कोई अन्य संविधान इस तरह से नहीं है

विविध लोग, जिनकी संख्या अब 550 मिलियन से अधिक है,

विभिन्न भाषाओं और धर्मों के साथ और विभिन्न चरणों में

आर्थिक विकास का, एक राष्ट्र में, और कोई अन्य नहीं

राष्ट्र ऐसी विशाल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है।

यह वहाँ भी कहा गया था (पृ. 69):

" मुझे शायद ही यह देखने की आवश्यकता है कि मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ

साधारण कानून, लेकिन एक संविधान जो स्थापना के अलावा सरकार के लिए एक तंत्र, एक महान और भव्य है

दृष्टि। दर्शन को प्रस्तावना में शब्दों में रखा गया था और

मौलिक अधिकार प्रदान करके आंशिक रूप से किया गया

लोग। इस दृष्टि को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था

निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा "।

(1) [1973] सप. एस. सी. आर. 1

3-

722 एससीआई/77 [1978] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28

मुझे ऐसा लगता है कि अगर "लोगों की आकांक्षाएँ और आशाएँ", "। प्रस्तावना में पाए जाने वाले महान और भव्य दृष्टिकोण और "राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों" पर अध्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह तय करने में कि संविधान के प्रावधानों को किसी विशेष सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है या नहीं, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अंत:क्रियाशीलता का दायरा काफी व्यापक और व्यापक हो जाता है, ताकि संविधान के प्रावधानों का पालन किया जा सके। जब तक हम केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में बहुमत के दृष्टिकोण से बंधे हैं, तब तक इसके

प्रावधानों के पीछे निहित उद्देश्य और सिद्धांत भी, यदि कोई ऐसा कहे तो, कमोबेश, संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे कोई विशेष दृष्टिकोण या प्रस्तावित कार्रवाई, किसी विशेष स्थिति में, संविधान को लागू करने या नष्ट करने के बराबर है, इस प्रकार एक अत्यधिक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन जाता है जिस पर संविधान के पत्र को पृष्ठभूमि में रखा जाता है।

जैसा कि मैं, कड़ाई से बोल रहा हूँ, केवल कानून से संबंधित हूँ, जैसा कि मैं हूँ

इसे संविधान में पाते हुए, मैं अब अनुच्छेद 356 की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ूंगा जैसा कि मुझे लगता है। इसमें लिखा है:

" 356 (1) यदि राष्ट्रपति से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर

किसी राज्य के राज्यपाल या अन्यथा, संतुष्ट हैं कि एक स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसमें राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है

इसके प्रावधानों के अनुसार किया जाए

संविधान, राष्ट्रपति घोषणा द्वारा कर सकते हैं

(ए) के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं मान लें

राज्य सरकार और सभी या कोई भी शक्तियाँ

राज्यपाल या किसी अन्य में निहित या प्रयोग करने योग्य

विधानमंडल के अलावा राज्य में अन्य निकाय या प्राधिकरण

राज्य की प्रकृति;

(ख) घोषणा करता है कि विधानमंडल की शक्तियाँ

राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रयोग करने योग्य होगा।

संसद का;

(ग) इस तरह के आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें।

राष्ट्रपति को जो आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होता है

पूर्ण रूप से निलंबित करने के प्रावधान सहित या आंशिक रूप से इसके किसी भी प्रावधान का संचालन

में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संविधान

बताइए:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी लिखित नहीं होगा

राष्ट्रपति को स्वयं को किसी भी रूप में ग्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय में निहित या प्रयोग करने योग्य शक्तियाँ, या

किसी के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करना

उच्च से संबंधित इस संविधान का प्रावधान

अदालतें।

(2) ऐसी किसी भी घोषणा को निरस्त या बदला जा सकता है।

बाद की घोषणा द्वारा।

(3) इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक घोषणा रखी जाएगी।

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष और, सिवाय जहां वह

यह एक घोषणा है जो पिछली घोषणा को रद्द करती है, राजस्थान बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

2

दो महीने की समाप्ति पर काम करना जब तक कि पहले न हो

उस अवधि की समाप्ति जिसे रेसो द्वारा अनुमोदित किया गया है

संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव:

बशर्ते कि यदि ऐसी कोई घोषणा (एक नहीं हो रही है

पिछली घोषणा को रद्द करने की घोषणा) जारी की जाती है।

एक समय जब लोक सभा भंग हो जाती है या लोक सभा का विघटन इस दौरान होता है

इस खंड में निर्दिष्ट दो महीने की अवधि और यदि

घोषणा को मंजूरी देने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया है

राज्य परिषद द्वारा, लेकिन इसके संबंध में कोई संकल्प नहीं

इस तरह की घोषणा हाउस ऑफ द पियो द्वारा पारित की गई है

उस अवधि की समाप्ति से पहले, घोषणा

उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव तीस दिनों की अवधि का यह लोक सभा द्वारा भी पारित किया गया है।

(4) इस प्रकार अनुमोदित घोषणा, जब तक कि निरस्त नहीं की जाती,

छह महीने की अवधि समाप्त होने पर काम करना बंद कर दें

दूसरे प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से

खंड (3) के तहत घोषणा को मंजूरी देना:

बशर्ते कि यदि और इतनी बार अनुमोदन करने वाले प्रस्ताव के रूप में

इस तरह की घोषणा को जारी रखने के लिए पारित किया जाता है

जिस तारीख से इस खंड के तहत यह अन्यथा होगा कार्य करना बंद कर दिया है , लेकिन ऐसी कोई घोषणा किसी भी मामले में नहीं होगी।

मामला तीन साल से अधिक समय से लागू है:

बशर्ते कि यदि सदन का विघटन

लोग छह महीने की ऐसी किसी भी अवधि के दौरान होते हैं और

इस तरह के प्रो के जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव

क्लैमेशन को राज्य परिषद द्वारा पारित किया गया है, लेकिन नहीं

इस प्रकार के बल में निरंतरता के संबंध में संकल्प लोक सभा द्वारा घोषणा पारित की गई है

उक्त अवधि के दौरान, घोषणा समाप्त हो जाएगी

लोक सभा अपने पुनर्गठन के बाद पहले बैठती है जब तक कि तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले

घोषणा के जारी रहने को मंजूरी देना

लोक सभा द्वारा भी पारित किया गया है।

(5) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद,

खंड (1) में उल्लिखित राष्ट्रपति की संतुष्टि होगी -

अंतिम और निर्णायक और किसी भी न्यायालय में पूछताछ नहीं की जाएगी

किसी भी जमीन पर "।

यह सच है कि अनुच्छेद 356 भाग XVIII में आता है, जो "एर" से संबंधित है।

एन. सी. आई. प्रावधान "। लेकिन आपात स्थिति और आपात स्थिति होती है।

अनुच्छेद 352 द्वारा कवर की गई आपात स्थिति केवल तभी घोषित की जा सकती है जब पी

एन. टी. संतुष्ट है कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसके तहत सुरक्षा

उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा है।

युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति ", अनुच्छेद 352 (3) यह दर्शाता है कि जिसे "वर्तमान और आसन्न खतरे के नियम" के रूप में जाना जाता है

ऐसी आपात स्थितियों पर लागू होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कब्र अनुच्छेद 352 द्वारा परिकल्पित आपातकाल वास्तविक ओ. सी. से पहले होना चाहिए।

युद्ध या आंतरिक अशांति की उपस्थिति। इसके खतरे की निकटता

काफी है। लेकिन इसके विपरीत अनुच्छेद 356 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

संकोचन। अनुच्छेद के तहत "आपातकाल की घोषणा" के प्रभाव

संविधान के अनुच्छेद 353 और 354 में धारा 352 दी गई है।

अध्याय के पहले तीन लेखों के बाद। XVIII अनुच्छेद 355 का अनुसरण करता है

जो लागू करता है:

" 355. प्रत्येक की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा।

बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्य और

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार चलती रहे

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार "।

अब, आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 352, जिसे गंभीर और आसन्न होना चाहिए, शामिल किया गया है।

में उल्लिखित राज्य के प्रति संघ के कर्तव्य के पहले भाग द्वारा अनुच्छेद 355, लेकिन उस कर्तव्य का दूसरा भाग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 355 में किया गया है।

यह कुछ अलग और व्यापक चरित्र का प्रतीत होता है। द. ऐसा लगता है कि दूसरा भाग उन सभी चरणों को शामिल करता है जो "सुनिश्चित करने के लिए" पर्याप्त हैं।

कि सरकार। प्रत्येक राज्य के अनुसार किया जाता है

संविधान के प्रावधान।

इसका विस्तार काफी चौड़ा लगता है। यह

है।

यह स्पष्ट है कि यह प्रत्येक राज्य के प्रति संघ के कर्तव्य का हिस्सा है

यह घोषणा गंभीर आपातकाल की नहीं है। वास्तव में शब्द वहाँ आपातकाल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक घोषणा है जिसका उद्देश्य या तो

में संवैधानिक तंत्र की विफलता के खिलाफ रक्षा करने के लिए टूटने के प्रभावों को बताएँ या उनकी मरम्मत करें। यह या तो एक पूर्व हो सकता है

वेंटिव या एक उपचारात्मक क्रिया। यह पर्याप्त है यदि "राष्ट्रपति", जिसमें

संशोधित अनुच्छेद 73 (1) के दृष्टिकोण का वास्तव में अर्थ है -

मंत्री, निष्कर्ष निकालते हैं कि "राज्य की सरकार नहीं हो सकती है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया। उस पर

दूसरी ओर, अनुच्छेद 352 के तहत कार्रवाई, अधिक उचित रूप से, केवल बचाव है कब्र को रोकने या उससे मिलने के लिए गंभीर और सुरक्षात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और

आसन्न खतरा।

संवैधानिक तंत्र क्या है जिसकी विफलता या निकटता है?

क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत इस विफलता से निपट सकते हैं? क्या यह काफी है? यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें संविधान के एक या अधिक प्रावधान

जिनका किसी राज्य में पालन नहीं किया जा रहा है, या वे किस हद तक नहीं कर सकते हैं ऐसे मामले हैं जिन पर बड़े मतभेद हैं

हैं।

संभव है। यदि एक व्यापक उद्देश्य, जैसे कि एक लोकतांत्रिक सरकार का

हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है जिसका उपयोग किया गया था

इस न्यायालय द्वारा, जैसा कि एच. एच. केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में किया गया था, जिसे "बुनियादी संरचना" कहा गया है, उसका अनुमान लगाने का भी मतलब था

अनुच्छेद 356 द्वारा सेवा प्रदान की जाए, एक "स्थिति" का दायरा जिसमें घोषणा की जाए

इसके नीचे जो बनाया जा सकता है वह व्यापक लगेगा। यदि "मूल संरचना"

बुनियादी लोकतांत्रिक मानदंडों को अपनाता है, की संवैधानिक मशीनरी अनुच्छेद 356 का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान बनाम संघ (बेग, सी. जे.) के लिए किया जा सकता है।

ऐसे मानदंडों के बारे में अपने दृष्टिकोण का अनुपालन सुनिश्चित करना, जब राज्य सरकार अपनी राय में उनका पालन करने में विफल रही हो। संघ सरकार कह सकती है: " यदि, जिसे हम लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बुनियादी मानते हैं, वह आपके द्वारा नहीं किया जाता है, तो हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि आपके राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा नहीं चलाई जा सकती है। उस स्थिति में हम अनुच्छेद 356 के तहत आपकी शक्ति को अपने हाथ में ले लेंगे और आपके राज्य के लोगों के लिए ऐसा करेंगे जो आपको खुद करना चाहिए था। संविधान का अनुच्छेद 356 (1), किसी भी तरह से, हमें इस तरह के दृष्टिकोण के रास्ते में खड़ा नहीं लगता है।

फिर से, यदि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो शामिल हैं

राज्य सरकार या उसका विधानमंडल किसी भी संविधान को लागू करने के लिए राष्ट्र के आदेश या निर्देश, उचित विधान द्वारा, सहमत हो सकते हैं

एक संभावित दृष्टिकोण के लिए, ले जाने के लिए अपने कर्तव्यों की विफलता के रूप में माना जाए

संविधान की क्या आवश्यकता है। हमारी कठिनाई यह है कि भाषा

अनुच्छेद 356 का इतना व्यापक और ढीला है कि इसे एक के भीतर सीमित कर दिया जाए।

कानून बनाने वाला संविधान जो, फिर से, कड़ाई से नहीं कहता है, हमारे क्षेत्र में झूठ बोलते हैं।

ऊपर बताई गई संभावनाएं काफी हद तक संभव प्रतीत होती हैं।

अनुच्छेद 356 (1) में उपयोग की गई काफी व्यापक भाषा से और

"बुनियादी संरचना" का यह दृष्टिकोण, कहने के लिए, सिद्धांतों को जोड़ने के लिए प्रतीत होता है। प्रावधानों के लिए। यदि ऐसा है, तो हमारे लिए यह कहना असंभव हो जाता है कि

केंद्र सरकार, भले ही वह संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा ले

किसी राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत को लागू करने के लिए शिक्षा, असंवैधानिक रूप से कार्य करती है,

जब तक वह सिद्धांत या सिद्धांत अंतर्निहित उद्देश्य द्वारा कवर किया जाता है

आयोजित की गई प्रस्तावना में पाए गए संविधान के भाव

संविधान का हिस्सा बनना।

हम यहाँ यह निर्धारित करने के लिए नहीं बैठे हैं कि क्या एक बुनियादी की अवधारणा

केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में पाई गई संरचना के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण या अधिक सटीक परिभाषा। मैं यहाँ उल्लेख कर सकता हूँ कि

मैंने निम्नलिखित व्याख्या दी जिसे मैं मूल समझता हूँ।

केशवानंद के अनुसार हमारे संविधान की संरचना

भारती का मामला (ऊपर), संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत

एक हिस्सा था:

" तीन संवैधानिक रूप से अलग-अलग अंगों में से कोई भी नहीं

राज्य हमारे संविधान की मूल योजना के अनुसार कर सकता है

आज, संवैधानिक रूप से अपनी सीमाओं से बाहर कूदें

दूसरे में अधिकार का निर्दिष्ट क्षेत्र या कक्षा।

यह सिद्धांत का तार्किक और स्वाभाविक अर्थ है

संविधान की सर्वोच्चता "। (देखिए: श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण) (1)।

भले ही हम एक बुनियादी संरचना की अवधारणा को कम कर दें

उद्धृत परिच्छेद में पाई गई अवधारणा के अनुसार इसे लाना

(1) [1976] एस. सी. आर. 347 539 पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32

ऊपर, हम केवल उस कार्यकारी नीति को समाप्त कर सकते थे जो

बुनियादी संरचना से स्पष्ट रूप से एक विचलन प्रतीत होता है माँगें। कानून मंत्री के भाषण की रिपोर्ट के रूप में क्या होगा

दिखाता है, निष्पक्ष और उचित रूप से एक नीति के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य मजबूत करना है:

या जो उस बुनियादी संरचना में शामिल है उसे सुरक्षित नहीं किया जा सका इस न्यायालय द्वारा नियंत्रित या नियंत्रित किया जाता है क्योंकि यह एक प्रयास होगा

एक क्षेत्र के भीतर कार्यकारी नीति को नियंत्रित करें जो अपनी है और जहां इसकी है। इस न्यायालय द्वारा सर्वोच्चता को बरकरार रखा जाना चाहिए और लगातार बरकरार रखा जाना चाहिए।

ऊपर व्यक्त किए गए विचारों में अंतर्निहित मूल धारणा यह है कि

राज्य के तीन अंगों में से प्रत्येक-कार्यपालिका, विधानमंडल

और न्यायपालिका के पास अधिकार और संचालन की अपनी कक्षा है।

इसे होना ही चाहिए।

अन्य अंगों द्वारा उस क्षेत्र के भीतर काम करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए, भले ही वह वहाँ गलतियाँ करता है। यह राज्य के तीन अंगों में से किसी एक के लिए नहीं है।

या तो ठीक करने के लिए या दूसरे पर आरोप लगाने के लिए उंगली उठाने के लिए

क्योंकि यह सोचता है कि दूसरे द्वारा कुछ त्रुटि की गई है जब

अपनी शक्तियों की सीमाओं के भीतर कार्य करना। लेकिन, अगर या तो निष्पादन

अधिक या विधानमंडल अपनी शक्तियों के दायरे को पार कर जाता है, यह खुद को रखता है

उस क्षेत्र में जहाँ उस अधिकता के प्रभाव फिर से सक्षम होने चाहिए

न्यायपालिका द्वारा की गई गलती का निवारण कब किया जाना चाहिए ठीक से उसके सामने लाया गया। इस योजना का ईमानदारी से पालन

हमारे संवैधानिक तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है

नियंत्रण और संतुलन। इसका अर्थ है उचित सम्मान और विश्वास।

अन्य दो द्वारा हमारे गणराज्य का प्रत्येक अंग।

हर शरण वर्मा बनाम। चंद्र भान गुप्ता और अन्य।, (1) द.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही टिप्पणी की:

" न्यायालय के लिए राजनीतिक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

शक्तियाँ और शिकायतें जो किसी भी राजनीतिक की आवश्यकता बनाती हैं

कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं

प्रत्येक अपने भीतर की विशिष्ट परिस्थितियों से परिचित है। अपना क्षेत्र है और जटिल प्रश्नों का विशेष ज्ञान है

जिनसे दूसरे को इनकार किया जाता है। हर किसी के पास होना चाहिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कठोर विवेक। के कृत्य

कार्यपालिका लंबे समय तक न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के लिए तैयार नहीं है

क्योंकि कानून या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह.

इस प्रकार है कि न्यायालय सामान्य रूप से किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकता है

कानून के प्रति अनादर को बढ़ावा देना। इस न्यायालय को विस्तार करना चाहिए सरकार की अन्य शाखाओं के प्रति भी यही शिष्टाचार, जो

उनसे प्राप्त करता है और अनावश्यक बनाने से बचता है

मंत्रियों के कार्यों के विवेक पर टिप्पणी

सरकार "।

हालाँकि, हमारे सामने यह जोरदार रूप से तर्क दिया गया है कि जैसे

यह संवैधानिक योजना का एक हिस्सा है कि न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। अपने क्षेत्र के भीतर काम करना, और, जैसे न्यायपालिका कार्यकारी या विधायी कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि

(1) ए. आई. आर. 1962 ऑल। 301 307 पर।

राजस्थान वी. यूनियन '(बेग, सीजे)

33

शक्ति की कोई अधिकता नहीं है, जिस पर न्यायालयों के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है, इसी तरह, केंद्र सरकार इस दलील पर किसी राज्य में सरकार के सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के कानूनी अधिकारों के बीच अनुरूपता की कमी है। मतदाताओं की राय जो केवल राज्य सरकार के सत्ता में बने रहने के नैतिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह का कथित नैतिक आधार केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत कार्रवाई का कानूनी अधिकार नहीं देता है। श्री निरेन डे का आग्रह है कि यह गंभीर बंदरगाह का एक संवैधानिक मुद्दा उठाता है।

1

कुछ दलीलों में, यह दावा किया गया है कि नैतिक याचिका की मांग की गई थी

राज्य के लोगों की ओर से अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के कानूनी अधिकार का रंग दिया जाना, केवल राजनीतिक रणनीति के मामले को कानूनी और संवैधानिक रूप देने का प्रयास है। यह सुझाव दिया जाता है कि केंद्र सरकार जनता पार्टी और उसके राजनीतिक सहयोगियों की हालिया भारी जीत के परिणामस्वरूप देश में फैली अस्थायी भावना का अनुचित प्रभाव लेना चाहती है। दूसरे शब्दों में, दोनों। संघीय ढांचे में राज्य की स्वायत्तता की सीमा और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक शक्ति का कथित दुरुपयोग, जिसे इसके लिए बाहरी कहा जाता है, राज्यों की ओर से उठाया गया है। ये विचार अनुच्छेद 356 (1) के उचित निर्माण के साथ-साथ उन मामलों के लिए सहायक के रूप में हमारे सामने रखे गए हैं जो

सही तथ्यों का पता लगाने के बाद सावधानीपूर्वक जांच और निर्णय लिया जाना चाहिए।

हम अमूर्त सिद्धांत की चर्चा शुरू करने के लिए अनिच्छुक हैं।

हमारे स्पष्ट प्रावधानों के सामने संघवाद की अधिकता। संविधान। फिर भी, जैसा कि सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के निर्माण में सहायक के रूप में किया गया है, जिसकी मूल संरचना, निस्संदेह,

राष्ट्र के भाग्य को नियंत्रित करने वाले दस्तावेज़ के एक पक्षीय प्रावधान की भाषा की व्याख्या करते समय भी इसका पता लगाना होगा।

हम इस पहलू पर भी कुछ कहने से बच नहीं सकते।

हमारे संविधान के प्रावधानों का एक अवलोकन इंगित करेगा

कि, एक संघीय संरचना के जो भी रूप हमारे संविधान हो सकता है है, इसके संचालन निश्चित रूप से, दोनों को शक्ति की सामग्री से आंका जाता है

जिसके कई प्रावधान उनके साथ होते हैं और जिसका उपयोग किया जाता है

उनसे बना, संघीय की तुलना में अधिक एकात्मक। मैं उपयोग का उल्लेख करता हूँ।

जो संवैधानिक प्रावधानों से बनाया गया है क्योंकि संवैधानिक

राष्ट्रीय अभ्यास और परंपराएं आपस में जुड़ी हुई या जुड़ी हुई हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के वास्तविक उद्देश्य और कार्य को समझना कि दोनों को अक्सर अलग नहीं देखा जा सकता है। और सामग्री कहाँ है

किसी प्रावधान की भाषा से शक्तियाँ इतनी अस्पष्ट और ढीली दिखाई देती हैं,

जैसा कि हमें अनुच्छेद 356 (1) में प्रतीत होता है, ऊपर दिए गए कारणों से,

अभ्यास और परंपराएँ इतनी स्पष्ट हो सकती हैं कि अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

कानून के पत्र से अधिक नहीं। किसी भी तरह से उनका तलाक नहीं हो सकता।

संवैधानिक कानून से। वे हमें नीचे भी प्रासंगिक लगते हैं।

में उपयोग किए गए शब्दों का उद्देश्य, महत्व और अर्थ

अनुच्छेद 356 (1)। यह [1978] 1 एस. सी. आर. के अवलोकन से भी स्पष्ट होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34

शमशेर सिंह बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। पंजाब राज्य (1)

संघवाद के अस्तित्व के लिए डायसी ने दो शर्तों का प्रतिपादन किया

ये थे: सबसे पहले, "स्विट्जरलैंड के कैंटन जैसे देशों का एक निकाय,

अमेरिका के उपनिवेश, या कनाडा के प्रांत, इतने करीब से

स्थान के अनुसार, इतिहास के अनुसार, नस्ल के अनुसार, या इस तरह के, जो सक्षम हो उनके निवासियों की नज़रों में, आम राष्ट्र का एक प्रभाव

"; और, दूसरी बात, एक संघीय संगठन की स्थापना के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

प्रणाली "भावना की एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति का अस्तित्व है देशों के निवासी "। उन्होंने बताया कि बिना किसी इच्छा के

एकजुट होने के लिए संघवाद का कोई आधार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इच्छा हो तो

एकजुट सभी महत्वपूर्ण में एक एकीकृत पूरे बनाने की सीमा तक जाता है सरकार के मामले, यह एक संघीय के बजाय एक एकात्मक उत्पन्न करता है

संविधान। इसलिए, उन्होंने कहा, एक संघीय राज्य "एक राजनीतिक अनुबंध है।

राज्य के रखरखाव के साथ राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य स्थापित करने का इरादा

अधिकार "। जिस हद तक राज्य के अधिकारों को अलग से संरक्षित किया जाता है

और संरक्षित यह बताता है कि किसी को किस हद तक अभिव्यक्ति दी गई है

दो विरोधाभासी आग्रहों में से ताकि एकता के बिना एक संघ हो

सरकारी मामलों में। एक अर्थ में, इसलिए, भारतीय संघ है

संघीय। लेकिन, इसमें संघवाद का विस्तार काफी हद तक कम हो गया है किसी देश की प्रगति और विकास की आवश्यकताओं के अनुसार जिसे

राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वित होना, और सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत। ऐसे में

प्रणाली, राज्य वैध और समझने के रास्ते में खड़े नहीं हो सकते हैं

द्वारा निर्देशित तरीके से देश का सक्रिय रूप से नियोजित विकास

केंद्र सरकार। विशेष रूप से वैधता का सवाल

केंद्र सरकार की कार्रवाई हमें विशेष दिशाओं में ले जा रही है

अक्सर केवल लोगों के निर्णयों द्वारा परीक्षण और निर्धारित किया जा सकता है

न्यायालयों के निर्णयों की तुलना में उचित समय पर। इसके लिए

सही मायने में कहें तो राजनीतिक बहस के लिए वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

कानूनी चर्चा के बजाय। अगर हमारे देश की विशेष ज़रूरतें हैं,

राजनीतिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता और सुनियोजित आर्थिक विकास

देश के सभी हिस्सों का विकास, ताकि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सके

जहाँ "न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" प्रबल होना है और

अन्य महान आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए प्रस्तावना में निर्धारित, मजबूत केंद्रीय दिशाएँ अपरिहार्य प्रतीत होती हैं।

यह देश की आवश्यकता है। कि, किसी भी तरह से, मूल प्रतीत होता है

हमारे कई संवैधानिक प्रावधानों के पीछे की धारणा।

श्री ग्रैनविल ऑस्टिन ने "भारतीय संविधान-संविधान की आधारशिला" में लिखा है।

एक राष्ट्र "(पृ. देखें। 186) हमारे संविधान के एक खाते के दौरान बनाते हुए, इंगित करते हैं कि हमारी संविधान सभा के सदस्य

इतिहास में संघ '। 'अर्ध-संघीय' और 'वैधानिक' जैसे शब्द विद्वान लेखक द्वारा 'विकेंद्रीकरण' को प्रकाशात्मक नहीं पाया गया

टिंग। हमारे संविधान निर्माताओं की अवधारणाएँ और आकांक्षाएँ थीं -

अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से अलग। हमारा संविधान कर सकता है

निश्चित रूप से डॉ. के. सी. व्हीयर की "फेडेरा" की धारणा को मूर्त रूप देने के लिए नहीं कहा जाता है।

"जहाँ" किसी देश की सामान्य और क्षेत्रीय सरकारें

अपने दायरे में एक-दूसरे से स्वतंत्र रहें। श्री ऑस्टिन ने सोचा

कि हमारी प्रणाली, अगर इसे संघीय कहा जा सकता है, तो इसका वर्णन किया जा सकता है

के रूप में

" सहकारी संघवाद "। इस शब्द का उपयोग एक अन्य लेखक श्री.

(1) [1975] 1 एस. सी. आर पी. 814 .

राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

35

ए. एच. बिर्च (देखें संघवाद, वित्त और सामाजिक विधान) कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका पी। 305) , एक प्रणाली का वर्णन करने के लिए जिसमें:

.....प्रशासनिक सहयोग का अभ्यास

सामान्य और क्षेत्रीय सरकारें, आंशिक निर्भरता क्षेत्रीय सरकारें सामान्य से भुगतान पर

सरकारें, और तथ्य यह है कि सामान्य सरकारें, द्वारा

सशर्त अनुदान का उपयोग, अक्सर विकास को बढ़ावा देता है

उन मामलों में विचार जो संवैधानिक रूप से सौंपे गए हैं

क्षेत्रों "।

हमारे देश में राष्ट्रीय योजना में विशाल राशि का वितरण शामिल है।

सभी राज्यों में रहने वाले नागरिकों से कर के रूप में एकत्र की गई राशि

राज्यों और के लिए केंद्र सरकार के निपटान में रखा

उल्लिखित "सशर्त अनुदान" के बिना भी राज्यों के लाभ

ऊपर। इसलिए, जिस तरह से राज्य सरकारें काम करती हैं और

केंद्र सरकार द्वारा उनके निपटान में रखी गई राशियों से निपटना या

वे सामान्य प्रशासन को कैसे जारी रखते हैं, यह भी हो सकता है कि

केंद्र सरकार के लिए काफी चिंता।

हालाँकि डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि हमारा संविधान संघीय है

" चूंकि यह स्थापित करता है जिसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है ", उन्होंने यह भी कहा।

'संघवाद के तंग सांचे' से बचा गया जिसमें अमेरिकी कॉन्स्टी टच्यूशन जाली थी। डॉ. अम्बेडकर, प्रमुख वास्तुकारों में से एक

हमारा संविधान, हमारे संविधान को एकात्मक दोनों मानता है

साथ ही समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संघीय '।

अगर तब हमारा संविधान एक केंद्रीय सरकार बनाता है जो है

" उभयचर ", इस अर्थ में कि यह या तो संघीय या यूनी पर आगे बढ़ सकता है

टेरी प्लेन, स्थिति और परिस्थितियों की जरूरतों के अनुसार

एक मामले में, जिस प्रश्न पर हमें विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है वह यह है कि क्या "स्थिति" का आकलन जिसमें केंद्र सरकार को होना चाहिए

संघीय या एकात्मक स्तर पर चलना संघ के लिए मामला है सरकार या इस न्यायालय को स्वयं विचार करना और निर्धारित करना है। प्रत्येक

गणराज्य के निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शक्तियों की सीमाओं को जाने। न्यायपालिका आम तौर पर तभी आती है जब किसी भी तरह की अधिकार से बाहर की पूछताछ की जाती है

कार्रवाई शामिल है, क्योंकि इसके संबंधित अधिकारों से संबंधित प्रश्न

डोमेन।

मैं बता सकता हूं कि दोनों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलू हैं।

संघ और विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित राज्य

संविधान। मैं यहाँ उन लोगों का उल्लेख कर सकता हूँ जो देने से संबंधित हैं।

में से

" केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश

कारण अनुच्छेद 365 प्रदान करता है:

" 365. जहाँ कोई राज्य इसका पालन करने या करने में विफल रहा हो।

एक्सई के अभ्यास में दिए गए किसी भी निर्देश को प्रभाव दें

संविधान, राष्ट्रपति के लिए यह अभिनिर्धारित करना विधिसम्मत होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार कर सकती है

इसके प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए संविधान।"

[

1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36

अनुच्छेद 256 और 257 में विभिन्न विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर

केंद्र सरकार राज्य सरकार को कार्यकारी निर्देश दे सकती है

भावनाएँ। संविधान का अनुच्छेद 73 (1) (ए) हमें बताता है कि

संघ की शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिन पर "संसद" कानून बनाने की शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 248 पूर्व में निहित है।

संसद में किसी भी विषय पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ

समवर्ती या राज्य सूचियों में सूचीबद्ध नहीं है। अनुच्छेद 256

संविधान में ऐसे मामले शामिल हैं जहां राष्ट्रपति देना चाहते हैं।

किसी राज्य को संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में निर्देश बनाए गए किसी मौजूदा कानून के दायरे में आने वाले मामले के संबंध में सरकार

किसी राज्य पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का व्यापक दायित्व है संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालने का एक तरीका

जो, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 73 से दिखाई देगा, पढ़ें

अनुच्छेद 248 के साथ एक ऐसा विषय भी शामिल हो सकता है जिस पर कोई अस्तित्व नहीं है

कानून है लेकिन जिस पर संसद द्वारा कुछ कानून बनाना संभव है। यह.

विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है जब विघटन की शक्ति होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया गया

राज्य, फिर भी यदि उस मामले पर केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को उचित रूप से निर्देश दिया गया था, तो इसे पूरा करना कर्तव्य है।

राज्य विधानसभा के विघटन का समय शामिल नहीं है।

बाहर निकलें।

संविधान के किसी विशिष्ट प्रावधान या इस विषय पर बनाए गए किसी कानून द्वारा। हालाँकि, केंद्र सरकार के लिए यह संभव है

अपनी अवशिष्ट कार्यकारी शक्ति को उचित दिशा के मुद्दे के लिए एक उपयुक्त विषय मानने के लिए जब यह मानता है कि राजनीतिक

देश में स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक स्थिरता के हित में या सरकार में लोगों का विश्वास स्थापित करने के लिए एक नया चुनाव आवश्यक है। एक राज्य से।

निस्संदेह, यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करना उचित और स्वस्थ है।

सम्मेलनों का विकास होना चाहिए ताकि अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग न तो मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से किया जाए और न ही जब कोई राजनीतिक स्थिति वास्तव में इसकी मांग करती है तो इसका प्रयोग किया जा सके। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विचार इस विषय पर भिन्न हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार को एक स्वस्थ प्रथा या परंपरा के विकास में सहायता नहीं करनी चाहिए, जिसे वह एक उचित सलाह या निर्देश के रूप में मानती है, और यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 356 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जब वह इस तरह के नियमों के पालन पर विचार करती है।

ए

निर्देश इतना आवश्यक है कि संवैधानिक तंत्र

नहीं कर सकते

कार्य जैसा कि यह करने के लिए था जब तक कि यह हस्तक्षेप न करे। यह न्यायालय, किसी भी दर पर, अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्तियों के इस तरह के उपयोग को बाधित नहीं कर सकता है और जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, प्रावधान का सहारा लेना इतना घोर विकृत और अनुचित नहीं दिखाया जाता है कि इस प्रावधान का पेटेंट दुरुपयोग माना जाता है।

तथ्य।

और,

हमारे सामने लगाए गए आरोपों पर हम इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यह न्यायालयों के लिए नहीं है कि वे एक सम्मेलन तैयार करें, और, बहुत कम, लागू करें, हालांकि, आवश्यक या न्यायसंगत और उचित

विनियमित करने के

लिए समझौता

ऐसी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग हो सकता है।

यह पूरी तरह से

एक मामला है।

कार्यकारी क्षेत्र के भीतर, संचालन के,

यह आग्रह करना व्यर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 172 (1) में संशोधन किया जाए।

एड, एक विधायी राजस्थान बनाम संघ (बेग, सी. जे.) के लिए छह साल की अपरिवर्तनीय अवधि निर्धारित करता है।

जा।

अपनी पहली बैठक से सभा क्योंकि इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से अपवाद है "जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए।" जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह संविधान या किसी विधान सभा के चुनाव कराने से संबंधित किसी कानून में कहीं भी निर्धारित नहीं है कि कौन सी परिस्थितियां इसके विघटन को उस अवधि से पहले उचित ठहराएंगी जो अन्यथा उसे प्राप्त होगी।

अल।

यह तर्क दिया गया था कि कानून को भंग करने के लिए सशक्त एकमात्र प्राधिकरण

संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत स्थानीय विधानसभा एक राज्य का राज्यपाल होता था जिसे राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी परिस्थिति में राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए कहने के लिए न तो सलाह दे सकती है और न ही सलाह के रूप में निर्देश दे सकती है। जाहिरा तौर पर, निर्माण के जिस सिद्धांत पर भरोसा किया गया था, वह एक बहुत अधिक उपयोग किया जाने वाला और आसानी से दुरुपयोग किया जाने वाला सिद्धांत था। एक्सक्लूसिओ अल्टरियस "। हमें नहीं लगता कि इस तरह का सिद्धांत हमारे सामने वादियों की उतनी मदद कर सकता है जितना कि संविधान के अनुच्छेद 356 में बहुत स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को स्वयं करने के लिए प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति निहित है, भले ही वह राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो, लेकिन ऐसी सलाह देने की शक्ति स्वचालित रूप से केंद्र सरकार द्वारा राज्य विधानसभा को भंग करने के उद्देश्यों के लिए ले ली जाएगी जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा द्वारा सरकारी शक्तियों को ग्रहण करता है। घोषणा के बाद राष्ट्रपति द्वारा भंग करना उतना ही अच्छा होगा जितना कि सरकार द्वारा और न ही किसी ऐसे राज्य द्वारा जिसका अधिकार छीन लिया गया हो।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की स्थिति

भारतीय संघ की एक इकाई के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद का औपचारिक माध्यम, जिसे संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा "अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा" नियुक्त किया गया है, को भी हमारे सामने बहस के दौरान छुआ गया था। एक ओर, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, वह आम तौर पर, एक संवैधानिक परंपरा के कारण, मुख्यमंत्री के माध्यम से उन्हें दी गई अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं, सिवाय उन

असाधारण परिस्थितियों के जो मेरे विद्वान भाइयों भगवती और जे. जे. अय्यर द्वारा बताई गई हैं।
,

शमशेर सिंह के मामले में, ऊपर (पी। 875) एक स्थिति जिसमें एक एपी

निर्वाचक मंडल को भंग करने की मांग की जाती है। दूसरी ओर, "संविधान और कानून" के रक्षक और पूरे देश के हितों और विशेष रूप से अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए पहरा देने वाले के रूप में, राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां निहित हैं जिनका उपयोग वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है। उनके स्वतंत्र कार्यों में से एक केंद्र सरकार को रिपोर्ट बनाना है जिसके बल पर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्ति है।

356 (1) संविधान का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक वह लोगों के व्यापक हित में कार्य करता है, राष्ट्रपति द्वारा "संविधान और कानून की रक्षा के लिए" नियुक्त किया जाता है, वह उसकी ओर से एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।

संघ का और इस बात पर नजर रखनी होगी कि प्रशासनिक तंत्र कैसे नेरी और संवैधानिक सरकार का प्रत्येक अंग [1978] 1 एस. सी. आर. में काम कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38

राज्य। जब तक वह सभी सरकारी गतिविधियों और उनके बारे में जनता की भावनाओं की स्थिति पर इस तरह की नजर नहीं रखते हैं, तब तक वह रिपोर्ट बनाने के अपने कार्य को संतोषजनक रूप से निष्पादित नहीं कर सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि का आधार बन सकता है। वास्तव में, सामान्य प्रथा यह है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य करता है। लेकिन, "या अन्यथा" शब्दों का उपयोग (अनुच्छेद 356 में) दर्शाता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अन्य सामग्री पर भी आधारित हो सकती है। हमारे संविधान की यह विशेषता सबसे आश्चर्यजनक रूप से इंगित करती है कि सरकार के संघीय सिद्धांतों पर इसके द्वारा किस हद तक पैठ बनाई गई है।

श्री सीतलवाड़ ने अपने टैगोर लॉ व्याख्यान, 1974 में "यूनियन एंड

राज्यपाल की भूमिका से निपटने के दौरान राज्य संबंधों का अवलोकन किया गया है। 164-165) :

" संविधान की शुरुआत के बाद से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का बार-बार प्रयोग किया गया है।

टचूशन। इसके अभ्यास के अवसर न केवल राज्य में स्थिर शासन बनाए रखने में शक्ति के महत्व पर जोर देते हैं, बल्कि उस महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हैं जो सरकार को और न ही संघ कार्यपालिका को अनुच्छेद 356 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने में निभानी होती है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र कई तरीकों से काम करने में विफल हो सकता है। एक राजनीतिक गतिरोध हो सकता है; उदाहरण के लिए, जहां एक मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को एक वैकल्पिक सरकार बनाना असंभव लगता है; या, जहां किसी कारण से, विधानसभा में बहुमत रखने वाली पार्टी एक मंत्रालय बनाने से इनकार कर देती है और राज्यपाल द्वारा बहुमत हासिल करने में सक्षम गठबंधन मंत्रालय खोजने के प्रयास विफल हो जाते हैं। किसी राज्य की सरकार को उन मामलों में भी संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा माना जा सकता है जहां एक मंत्रालय, हालांकि ठीक से गठित किया गया है, संविधान के प्रावधानों के विपरीत कार्य करता है या संविधान द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता है और राज्यपाल द्वारा मंत्रालय को आदेश देने के लिए बुलाने के प्रयास विफल हो गए हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता भी हो सकती है जहां मंत्रालय संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा वैध रूप से जारी किए गए निर्देशों को पूरा करने में विफल रहता है। कुछ स्थितियों का कथन, जो अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदान किए गए तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, इन स्थितियों के संबंध में राज्यपाल की महत्वपूर्ण स्थिति और अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के मामले में अपने कर्तव्यों की गंभीर जिम्मेदारी को दर्शाता है।

और संविधान का 356 "।

तब यह सवाल उठाया गया कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किया जा रहा है, यह राजस्थान बनाम संघ (बेग, सी. जे.) द्वारा अधिग्रहण करने के बराबर नहीं है।

39

राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए, तथ्यों और सीमाओं के आधार पर राज्य विधानसभाओं को भंग करने की शक्तियों के बारे में, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय में राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए पर्याप्त आधार थे, जबकि संविधान में प्रावधान है कि

यह राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना था। इस तरह का तर्क वास्तव में एक घेरे में एक तर्क है। यह माना जाता है कि इस मामले में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के कार्यों का केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करना अनुच्छेद 356 (1) के दायरे से बाहर था। एक ऐसी स्थिति जिसमें, केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार,

राज्य मंत्रिपरिषद गलत तरीके से राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह देने में विफल रही थी, ताकि कार्रवाई की जा सके।

अनुच्छेद 356 (1) के तहत लिया जाना चाहिए, जिसमें अपवादात्मक होगा

सामान्य रूप से कार्यों के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले लेख निलंबित कर दिए जाते हैं।

और बिल्कुल भी काम न करें। यदि संविधान का अनुच्छेद 356 (1) या

किसी अन्य अनुच्छेद में कोई प्रावधान था जो प्रोही के बराबर था।

राज्य विधानसभाओं को भंग करने की शक्तियों को ग्रहण करने के विरुद्ध विभाजन

भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यह एक अलग मामला होगा, लेकिन कि, के रूप में

हम बार-बार इंगित कर चुके हैं, यहाँ स्थिति नहीं है। वास्तव में,

अनुच्छेद 356 (1)। जाहिर है, अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा प्रभावी होने के लिए अनुच्छेद 174 के संचालन को निलंबित करना होगा। यह स्पष्ट है

कि कारणों में से एक, शायद लाने का मुख्य कारण

अब हमारे सामने आने वाले मामलों में यह असाधारण स्थिति इनकार है

राज्य के मुख्यमंत्रियों को उन्हें भेजी गई सलाह का पालन करना जो

वे कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में दिए गए 'निर्देश' के बराबर हैं।

संघ सरकार की।

यदि संवैधानिक रूप से सही प्रथाओं को भी इंगित किया जा सकता है और

केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया ताकि हमारे संविधान के प्रावधान

यह उस तरीके से काम कर सकता है जिसमें वे करने का इरादा रखते थे और

उनकी कोई भी वस्तु निराश नहीं है, यह देखने के लिए उपयोगी हो सकता है कन्वेंशन जो क्राउन की "विशेषाधिकार" शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है

इंग्लैंड में संसद का विघटन। अपने कानून में Dicey

संविधान 10 वीं एडन।, (पी पर। 432) ने देखा:

" संक्षेप में, विघटन का विशेषाधिकार गठित हो सकता है।

प्रतिनिधि की इच्छा को ओवरराइड करने के लिए इस तरह से कार्यरत रहें

संवेदी निकाय, या जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से "कहा जाता है। लोगों का

कि कुछ मामलों में विशेषाधिकार का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है कि राष्ट्र की इच्छा पर शून्य। लेकिन वास्तव में यह बहुत अलग है।

बुद्धिमान हैं। कभी-कभी क्राउन की विवेकाधीन शक्ति

हो सकता है, और संवैधानिक उदाहरणों के अनुसार कुछ

समय होना चाहिए, एक मौजूदा हाउस ऑफ कॉम को हटाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए

अपने अधिकार के धन। लेकिन कारण यह है कि सदन अंदर क्यों जा सकता है

संविधान के अनुसार शक्ति से वंचित किया जाए और

अस्तित्व का यह है कि एक अवसर उत्पन्न हुआ है जिस पर

यह मानने का उचित कारण है कि सदन की राय नहीं है निर्वाचकों की राय। एक विघटन अपने सार में है

कानूनी से राजनीतिक संप्रभु के लिए एक अपील।

लूशन स्वीकार्य है, या आवश्यक है, जब भी की इच्छा

विधायिका अलग है या उचित रूप से अलग माना जा सकता है

राष्ट्र की इच्छाओं से "।

डाइसी द्वारा यह बताया गया था कि पूर्व का पारंपरिक उपयोग

एक असाधारण स्थिति में संसद को भंग करने के लिए क्राउन का अनुरोध

यह, तब भी जब सत्ता में सरकार को एक माजो का समर्थन प्राप्त था

इसके पीछे नैतिकता स्थापित की गई थी। उन्होंने दो उदाहरण दिए; एक उदाहरण

1784 में संसद का समाधान और 1834 में दूसरा।

संभवत:, दो उदाहरण, पचास वर्षों के अंतराल के साथ

उन्हें, द्वारा पर्याप्त माना जाता था। डायसी एक सम्मेलन स्थापित करने के लिए

"संविधान के कानून और प्रथा" या एर्स्किन पर ऑसन के रूप में मे का "संसदीय अभ्यास", हमें कोई अलग परिणाम की ओर ले जाता है।

डाइसी के बयान से पता चलता है: सबसे पहले, वहाँ है, ब्रिटिश कॉन के अनुसार

उल्लेख, एक सरकार का एक "अधिकार", जो अब आदेश नहीं देता है हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत का समर्थन, एक डिसो की मांग करने के लिए

मतदाताओं या "राजनीतिक संप्रभु" को अपील करने के लिए मजबूर करना; और, दूसरी बात, क्राउन में एक "ओवरराइडिंग" विवेकाधिकार भी है।

प्रधानमंत्री की सलाह की अवहेलना करने के लिए, के प्रवक्ता

मंत्रियों का पूरा निकाय, उनके पीछे निचले सदन में बहुमत के साथ, और एक असाधारण स्थिति में भंग करने के लिए मजबूर करना।

"द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ

संसद ", संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुभवों के विशेष संदर्भ में

कैम्ब्रिज में डॉ. बी. एस. मार्केसिनिस द्वारा राज्य और ग्रीस

" अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक कानून श्रृंखला (1972) में विभिन्न लेखकों के विचारों और राजनीतिक स्थितियों के विवरणों की विस्तृत चर्चा की गई है जो इन समाधानों के संबंध में हाल के दिनों में उत्पन्न हुए थे। यह अध्ययन यह आकलन करते समय क्राउन की गंभीर जिम्मेदारी को सामने लाता है कि प्रो. लास्की ने कहा कि "गंभीर परिस्थितियाँ जिनमें क्राउन आम चुनाव को मजबूर करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है" जिसके परिणामस्वरूप "सम्राट और उसके लोगों के बीच सीधा टकराव" हो सकता है यदि राजा हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत द्वारा समर्थित सरकार की सलाह के विपरीत कार्य करता है। कीथ, जेनिंग्स, लास्की, ह्यूबर्ट और मॉर्गन जैसे संवैधानिक वकीलों और विशेषज्ञों के विचारों पर व्यापक चर्चा के बाद, डॉ. मार्केसिनिस ने 31 जुलाई, 1914 को राजा को लिखे गए ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री एस्क्विथ के एक प्रभावशाली पत्र का उल्लेख किया। उस पत्र में निम्नलिखित अंश था:

" संप्रभु के पास निस्संदेह अपनी सत्ता को बदलने की शक्ति है।

सलाहकार लेकिन यह इंगित करना प्रासंगिक है कि वहाँ किया गया है

पिछले 130 वर्षों के दौरान, केवल एक अवसर पर

राजा ने उस मंत्रालय को बर्खास्त कर दिया है जिसके पास अभी भी

हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास, (वे जारी रखते हैं:)

सर्वोत्तम हित में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है।

क्राउन एंड द कंट्री, इसके अलावा एक अभ्यास, इतना लंबा समय है

ब्लश्ड और अनुभव से इतनी अच्छी तरह से उचित है, रहना चाहिए

असंबद्ध। यह सिंहासन पर बैठने वाले को सभी से मुक्त करता है।

कार्यपालिका के कार्यों के लिए पी. सी. आर. सोनल जिम्मेदारी और

विधायिका "। राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

राजा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें "दलगत राजनीति के क्षेत्र में घसीटे जाने" के खिलाफ सलाह दी, चाहे राजा "चाहें या न चाहें" और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम किया।

जहाँ तक इस तरह के विषय पर स्वस्थ परंपराओं का विकास है

लोकतांत्रिक सरकार के तंत्र के संतोषजनक संचालन के लिए आवश्यक, यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के काम करने में रुचि रखने वाले सभी दलों के बीच एक व्यापक सहमति या आम सहमति हो सकती है और होनी चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर न्यायालय अपनी राय दे सकता है कि किसी पक्ष में आगे बढ़ने के लिए उचित पूर्ववर्ती या दृष्टिकोण या कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है।

कुलर स्थिति है। यह न्यायालय केवल इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या कुछ आधारों पर ऐसे मामले पर प्रस्तावित कार्रवाई, गिर जाएगी

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस सवाल पर भिन्न हैं कि क्या, किसी विशेष मामले में

नहीं। सबसे अधिक जो कोई कह सकता है वह यह है कि इसके खिलाफ विघटन राज्य विधानसभा में बहुमत की इच्छाएँ गंभीर और गंभीर होती हैं।

बात है। शायद हम यह देख सकते हैं कि इसका सहारा लिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत केवल तभी जब "एक महत्वपूर्ण स्थिति" हो।

यह उत्पन्न हुआ है। जैसा कि डॉ. मार्केसिनिस के अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा नहीं है

हमेशा आवश्यक है कि, एक बहु-पक्षीय प्रणाली के तहत, केवल हार

राज्य विधानसभा में राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से एक ऐसी स्थिति जिसमें राज्य विधानसभा का विघटन अनिवार्य हो।

यदि एक वैकल्पिक सरकार बनने में सक्षम है तो कौन सी सरकार

राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन देता है, यह नहीं हो सकता है

आदेश तब भी दिया जाता है जब राज्य में सत्ता में सरकार हार जाती है

सभा। हालाँकि, स्थिति बहुत अलग हो सकती है जब एक

राज्य सरकार के पास इसके पीछे राज्य विधानसभा में बहुमत है लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य विधानसभा और राज्य सरकार

इस समय के लिए पूरी तरह से और जोरदार रूप से खारिज कर दिया गया है

लोग जो एक "गंभीर स्थिति" उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होने के लिए बाध्य है जब तक कि

"राजनीतिक संप्रभु" को एक नया निर्णय देने का अवसर दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न पर निर्णय निस्संदेह कार्यपालिका में निहित है।

क्षेत्र। ऐसा हो सकता है कि मतदाताओं से अपील करने की आवश्यकता को केवल राज्य सरकार को बार-बार दंडित करने के लिए एक छोटे से भेष के रूप में सामने रखा जाए।

अल्पावधि के भीतर विघटन, अनुच्छेद 356 (1) का उपयोग

इस तरह के उद्देश्य के लिए इस तरह के काल्पनिक में स्पष्ट रूप से अपमानजनक और बाहरी प्रतीत हो सकता है। और बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में संघ की कार्रवाई

सरकार दुर्भावनापूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति से अधिक प्रतीत हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वादपत्र या याचिका में आरोप लगाया गया। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सलाह एक आधार पर है -

केंद्र सरकार की राय में इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या है, इसके अनुमान के परिणामस्वरूप एक समान सामान्य नीति का मामला ताकि राज्यों के लोगों को यह दिखाने का अवसर दिया जाए कि क्या राज्यों में पार्टी सत्ता में है

ऐसी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो केंद्र सरकार की कथित नीतियों से भिन्न हो सकती हैं। कोई तथ्य नहीं है

संघ की राज्य सरकार या राज्य विधानसभा के खिलाफ किसी भी सदस्य सरकार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी दिखाना। के रूप में

राज्य विधानसभा के विघटन के लिए उचित समय का सवाल

यह संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के बाहर का मामला नहीं है।

सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि उठाए गए प्रश्न पर्याप्त से परे नहीं जाते हैं

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) का सहारा लेने के लिए आधार।

हमारे देश में राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति है

केंद्र सरकार या राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया गया

के तहत एक घोषणा के बाद केंद्र सरकार के निर्देश

दो दर्जन से अधिक अवसरों पर संविधान का अनुच्छेद 356 (1)

संविधान के प्रारंभ के बाद से। इनमें से कई

अवसरों पर, अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति की घोषणाएँ थीं

उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न आधारों पर हमला किया गया। हर मौके पर

हमला विफल रहा। हमारे सामने जिन मामलों का उल्लेख किया गया वे थे: के. के. अबू बनाम

भारत संघ और अन्य। (1) राव बरिंदर सिंह बनाम। भारत संघ

& ओआरएस। (2), श्रीमुलू (3) और बिजयानंद पटनायक और अन्य।

वी. भारत के राष्ट्रपति और अन्य। (1)।

हमारे ध्यान में लाए गए किसी भी मामले में राष्ट्रपति की शक्ति नहीं थी

राज्य विधानसभा को भंग करना, या तो एक घोषणा के माध्यम से

अनुच्छेद 356 (1) स्वयं या उसके बाद, इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह आता है

अनुच्छेद 356 (1) के बाहर। हमारे सामने यह आग्रह किया गया था कि एकमात्र उद्देश्य

अभिप्रेत घोषणाओं का विघटन की खरीद होना

राजनीतिक जीत हासिल करने के उद्देश्य से राज्य विधानमंडल थे बाहरी और दुर्भावनापूर्ण दोनों। यह हमें लगता है कि दावे हैं कि

यह धारणा कि शक्ति के प्रयोग का पूरा उद्देश्य है केवल राजनीतिक जीत हासिल करने के लिए।

जैसा कि हमने ऊपर इंगित करने की कोशिश की है, राजनीतिक सुरक्षा के प्रयास

जीत, मतदाताओं से अपील करके, मान्यता प्राप्त फैसलों का हिस्सा हैं

सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली जो प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति देती है ताकि कुछ अन्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि किसी पार्टी के सदस्यों द्वारा किसी राज्य में लोगों के लिए लाभकारी माने जाने वाले कुछ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राजनीतिक जीत हासिल करने की इच्छा के साथ ऐसी परीक्षा, जिसे प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक विधि के रूप में माना जाता है, न केवल संविधान के तहत कानूनी और अनुमेय है, बल्कि स्पष्ट रूप से, विभिन्न दलों द्वारा सही मानी जाने वाली नीतियों को लागू करने की शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र संभावित वैध और कानूनी साधन है, तो संभवतः यह दावा नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक जीत हासिल करने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा को भंग करना, अपने आप में, एक बाहरी उद्देश्य है जो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कि कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे सीधे नहीं किया जा सकता है, पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उद्देश्य या साधन कानूनी रूप से प्रोही बाइटेड हैं। हमारे सामने आने वाले मामलों में, यह हमें प्रतीत नहीं होता है कि मैदानों में राजनीतिक जीत हासिल करने का उद्देश्य, अपने आप में, कानूनी रूप से निषिद्ध है। न ही कानून में ऐसा कुछ है जो अपनाए गए साधनों का सहारा लेने पर प्रतिबंध लगाता है। दलीलों या याचिकाओं में कोई दावा नहीं है

(1) ए. आई. आर. 1965 केर। 229 .

(2) ए. आई. आर. 1968 पुंज। 441 .

(3) ए. आई. आर. 1974 ए. पी. 106.

(4) ए. आई. आर. 1974 उड़ीसा 52.

राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

कि कुछ भी कानूनी रूप से निषिद्ध उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से निषिद्ध साधनों द्वारा किया जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है। केवल इतना ही सुझाव दिया गया है कि विधानसभाओं को भंग करके राज्यों में चुनावी जीत हासिल करने का प्रयास करना नैतिक रूप से उत्तरदायी है ताकि वहां सत्ता में मौजूद कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाया जा सके। किसी भी उद्देश्य या अपनाए गए साधनों के नैतिक मूल्य के ऐसे प्रश्न पर, यह न्यायालय संभवतः इस मामले में नहीं बैठ सकता है।

निर्णय। यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है कि दलीलें और याचिकाएं कानून की नजर में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के उद्देश्य के लिए कुछ भी बाहरी खुलासा नहीं करती हैं। प्रतिलेखन के अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के लिए आधारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता बिल्कुल अलग मामला है। हम नहीं सोचते कि हम अंदर जा सकते हैं

यहाँ यह सब।

हम पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य की शिकायत में

"विशेषाधिकार" शब्द का उपयोग राज्य के राज्यपाल की शक्ति के लिए किया गया है।

अनुच्छेद 174 के तहत एक विधान सभा को भंग करना, जैसे कि

कुछ सर्वोपरि "विशेषाधिकार" द्वारा उस "विशेषाधिकार" का उल्लंघन था

केंद्र सरकार द्वारा दावा किया गया। मुझे नहीं लगता कि शब्द

हमारे संविधान के तहत प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का त्याग करें। अंग्रेज़ी में कानून "विशेषाधिकार" शब्द का उपयोग "विवेकाधीन के अवशेष" के लिए किया जाता है।

क्राउन के हाथों में किसी भी समय छोड़ी गई शक्ति क्या ऐसी है

वास्तव में शक्ति का प्रयोग स्वयं राजा या उसके मंत्रियों द्वारा किया जाए।

(देखिए: संविधान कानून में कीर और लॉसन के मामले, 5 वीं संस्करण। पी। 151) .

संसद के अधिनियम के अधिकार के बिना किया जाता है यह विशेषाधिकार "। (डाइसी: संविधान का कानून, 10 वीं संस्करण। ,

पी। 425) . हालाँकि, यह ब्रिटिश संविधान का एक स्थापित सिद्धांत है।

राष्ट्रीय कानून कि विशेषाधिकार का कोई भी दावा पारित होने से बच नहीं सकता है

कानून उसी विषय को शामिल करता है क्योंकि तथाकथित विशेषाधिकार

कानून में विलय (अटॉर्नी जनरल v. डॉ. कीसर रॉयल

होटल (1)। यह कानून के खिलाफ नहीं हो सकता है। हमारे संविधान के तहत

उस तकनीकी अर्थ में कोई "विशेषाधिकार" नहीं है। सभी संवैधानिक शक्तियाँ हमारे लिखित संविधान द्वारा विनियमित होती हैं। हो सकता है

किसी ऐसे मामले पर सम्मेलनों के विकास के लिए जगह जो पूरी तरह से शामिल नहीं है

विवेक या शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में। लेकिन, यह एक "विशेषाधिकार" से अलग मामला। हमारे संविधान के तहत,

उस शक्ति के कारण, जो न तो विधायी है और न ही न्यायिक, शामिल है

कैप्शन के अनुसार: " कार्यकारी "। इस प्रकार, अधिकांश पूर्व के समतुल्य गेटिव शक्तियाँ हमारे कानून के तहत "एक्सई" शीर्षक के तहत गिरेंगी।

सांस्कृतिक "शक्तियाँ। क्योंकि "विशेषाधिकार" शब्द कभी-कभी होता है

एक व्यापक गैर-तकनीकी अर्थ में उपयोग किया जाता है, कुछ ऐसा जो पूर्व देता है

किसी शक्ति के लिए श्रेष्ठता या एक प्रमुख विशेषता, यह कहा जा सकता है कि

ऐसी शक्ति केंद्र सरकार में अनुच्छेद 356 (1) के तहत दर्ज की गई है।

उस उपबंध के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर संविधान का। द.

ऐसे मामलों में केवल सवाल यह है कि क्या मामला किसके संबंध में है

केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है या उसने कार्रवाई की है या उसके दायरे में नहीं है संविधान के अनुच्छेद 356 (1) का दायरा। अगर यह अंदर है

उस क्षेत्र में, न्यायालय किसी भी दर पर जमीन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कि यह बाहरी है।

जब भी इसके तहत घोषणा जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

(1) [1920] ए. सी. 508

4-722 एससीआई/77.

आधार पर पूछताछ नहीं की जा सकी। कुछ डिक्टा वहाँ पाया गया ऐसा प्रतीत होता है कि घोषणाएँ जारी करने के लिए शक्ति का प्रयोग है

किसी भी परिस्थिति में न्यायसंगत नहीं है। इस अदालत ने ऐसा नहीं किया है

उस हद तक चला गया। यदि यह वास्तव में संघ की ओर से कहा गया है सरकार ने कहा कि एक विशेष आधार पर कार्रवाई की गई थी जो

वास्तव में यह अनुच्छेद 356 (1) के दायरे से पूरी तरह बाहर है।

या किसी भी आधार पर प्रश्न में बुलाया गया था लेकिन क्योंकि यह स्वीकार किया गया था अनुच्छेद 356 (1) के बाहर के मामलों पर।

के तहत एक घोषणा जारी करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक चुनौती

संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रवेश करना और भी कठिन होगा। इन सभी विचारों को अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक से अधिक माना जाता है।

जिसके पास ही न्याय करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी और साधन हो सकते हैं ऐसा मुद्दा, अदालतों को बताता है कि राष्ट्र एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है

राष्ट्रीय आपातकाल जिसके दौरान इसका अस्तित्व या स्थिरता हो सकती है

दांव पर है। यही वह सिद्धांत था जो निर्णय को नियंत्रित करता था

हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लिवर्जिज v. एंडरसन (')। सिद्धांत यह है कि अभिवादन सिद्धांत में संक्षेप में कहा गया है: सालुस पोपुली सुप्रीम लेक्स। और,

यह वह सिद्धांत था जिसकी जांच करने की शक्ति से यह न्यायालय वंचित था। या किसी भी सामग्री पर सवाल उठाते हैं जिस पर ऐसी घोषणाएं आधारित हो सकती हैं,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम में कार्य किया। शिवकांत

शुक्ला (2)। हमें उस हद तक जाने की जरूरत नहीं है जब हमारे सामने है।

केवल अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा।

दोनों पक्षों ने भगत सिंह और ओआरएस का संदर्भ दिया था। वी.

राजा-सम्राट, ("), जहाँ प्रिवी काउंसिल ने प्रो की व्याख्या की भारत सरकार अधिनियम की धारा 72 का दृष्टिकोण, जो अधिकृत करता है

जो छह महीने से अधिक नहीं चलने वाला था। उस मामले में आपातकाल के अस्तित्व पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया था। विस्काउंट डुनेडिन, प्रेक्षित (पृ. 172):

" आपातकाल की स्थिति एक ऐसी चीज है जिसकी अनुमति नहीं है।

किसी भी सटीक परिभाषा का: यह मामलों की स्थिति का आह्वान नहीं कर सकता है।

कठोर कार्रवाई के लिए, जिसे कुछ लोगों द्वारा इस तरह से आंका जाना है

एक. यह स्पष्ट से अधिक है कि किसी को होना चाहिए

गवर्नर-जनरल, और वह अकेले। कोई अन्य दृष्टिकोण होगा।

पूरे प्रावधान को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दें। आपातकाल

तत्काल कार्रवाई की मांग करता है, और उस कार्रवाई को निर्धारित किया जाता है

गवर्नर द्वारा लिया जाए-जनरल "।

गवर्नर-जनरल की शक्ति को "एक निरपेक्ष" के रूप में वर्णित किया गया था।

भगत सिंह के मामले (ऊपर) में "शक्ति", लेकिन वादी के विद्वान वकील ने वहाँ के अवलोकन पर भरोसा किया कि "इसका उपयोग केवल आवश्यकता के चरम मामलों में किया जाना है जहां भारत की अच्छी सरकार है।

(1) [1942] एसी 206।

(2) [1976] पूरक। एस. सी. आर 172

(3) 50 टी. ए. 169.

इसकी माँग करते हैं। " हमें नहीं लगता कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान से बहुत अधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है, जो वास्तव में हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 का अग्रदूत था और एक साम्राज्यवादी युग में एक अलग संदर्भ में उपयोग के लिए था। फिर भी, यह दर्शाता है कि न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करने के प्रावधान के बिना भी, गवर्नर-जनरल की व्यक्तिपरक संतुष्टि को निर्विवाद माना गया था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के उपयोग और दायरे पर विचार करते समय हमारे सामने जो विचार उत्पन्न हुए हैं, वे प्रिवी काउंसिल के समक्ष उस कैस्क में बिल्कुल भी नहीं थे।

राजा सम्राट वी। बेनोरीलाल सरमा और अन्य। (1) से भी संबंधित

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 72 के तहत गवर्नर-जनरल की शक्तियां बनाने वाले अध्यादेश का हवाला दिया गया था। उस मामले में, भगत सिंह के मामले (ऊपर) पर टिप्पणी की गई थी। यह देखा गया

(पी पर। 62):

" भगत सिंह के मामले में आपातकाल की परिभाषा

संपूर्ण होने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन यह कहता है कि इसका अर्थ है कठोर कार्रवाई की मांग करने वाले मामलों की स्थिति, और यह कि

तत्काल कार्रवाई की मांग की। आपातकाल का मतलब यह नहीं है कि बड़े पैमाने पर आपातकाल। एस के तहत। 72 सरकार की

भारत अधिनियम आपातकाल जिसके साथ गवर्नर-जनरल

एक मौजूदा आपात स्थिति होनी चाहिए और कॉल करना चाहिए

विशेष प्रकार की तत्काल कार्रवाई के लिए जो वह चाहता है

लेने के लिए पोज देते हैं। यदि विशेष प्रकार की आपात स्थिति जो गवर्नर में-जनरल की राय एक विशेष प्रकार को उचित ठहराती है

कार्रवाई अपने आप में पूरी तरह से संभावना में है और मौजूद नहीं है।

तब हालांकि कुछ की आपात स्थिति मौजूद हो सकती है

अन्य प्रकार, जो एस के तहत उचित नहीं होगा। 72 , अध्यादेश

बनाया जा रहा है। आपात स्थिति की आवश्यकता तत्काल कार्रवाई, उस धारा के तहत, एक शर्त का आधार है

यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे अकेले ही पूरा किया जाना चाहिए।

इससे पता चलता है कि न्यायालय एक शर्त के अस्तित्व की जांच कर सकता है

आपातकालीन शक्तियों के उपयोग के लिए पूर्ववर्ती।

पैडफील्ड से निम्नलिखित मार्ग का भी संदर्भ दिया गया था।

& ओआरएस। वी. कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य और अन्य मंत्री। ( ) पी पर।

1006) :

" कहा जाता है कि मंत्री का निर्णय प्रशासनिक होता है।

न्यायिक नहीं बल्कि न्यायिक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कर सकता है। जैसा वह पसंद करता है, चाहे वह सही हो या गलत। इसका कोई मतलब नहीं है।

कि अदालतें उसे ठीक करने में असमर्थ हैं। अच्छे प्रशासक

ट्रेशन के लिए आवश्यक है कि शिकायतों की जांच की जानी चाहिए और कि शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए। जब संसद ने

उस उद्देश्य के लिए मशीनरी स्थापित करें, यह इसके लिए नहीं है

मंत्री इसे एक तरफ से ब्रश करें। उसे मना नहीं करना चाहिए

बिना किसी उचित कारण के शिकायत की जांच कराएँ। "

हमारे सामने गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल के मामले नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा कवर किया गया प्रकार। फिर भी,

(1) 72 आई. ए. 57.

(2) [1968] ए. सी. 997 पी. 1006 .

[

1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46

समान सिद्धांत असाधारण के अभ्यास को नियंत्रित करते प्रतीत होते हैं।

उच्चतम कार्यकारी प्राधिकरण को अनुच्छेद 356 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ

Ind.an संघ के संबंध जिनसे अत्यधिक समझदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिम्मेदारी। इस तरह का विचार, अस्तित्व के साथ संयुक्त

मंत्रियों द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर संसदीय नियंत्रण सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी, लिवर में ध्यान में रखा गया था

साइडगे का मामला (ऊपर), न्यायिक से दूर रहने के लिए। अन्य हस्तक्षेप:

अदालतों ने सहमति से केवल पर्याप्तता के सवाल उठाने वाले मुद्दों को रखा है।

कार्यकारी कार्य के आधारों की योग्यता, जैसे कि अनुच्छेद के तहत एक

356 (1) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गैर-न्यायोचित है। संशोधित लेख 356 (5) संविधान इंगित करता है कि संविधान निर्माताओं ने किया

नहीं चाहते कि ऐसा मुद्दा केवल आधारों की पर्याप्तता का सवाल उठाए

न्यायसंगत होना। उसी प्रभाव के लिए इसमें निहित प्रावधान हैं

अनुच्छेद 352 (5), 360 (5)। इसी प्रकार, अनुच्छेद 123 (4), 212 (4), 239 बी (4) उन मामलों की जांच करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता को रोकता है जो निहित हैं।

निष्पादक विवेक के भीतर। इस तरह का विवेकाधिकार एक द्वारा शासित होता है

नीति का बड़ा तत्व जो अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है

पेटेंट या निर्विवाद दुर्भावना या अधिकता के मामलों को छोड़कर अदालतें

शक्ति। इसका अभ्यास उन सामग्रियों पर आधारित है जिनकी जाँच नहीं की जा सकती है। कोर का। वास्तव में, यह कल्पना करना मुश्किल है कि कार्रवाई के आधार कैसे हैं

अनुच्छेद 356 (1) के तहत जांच की जा सकती है जब अनुच्छेद 74 (2) निर्धारित करता है।

कि "यह सवाल कि क्या कोई है, और यदि है, तो क्या सलाह दी गई थी

राष्ट्रपति के मंत्रियों से किसी भी न्यायालय में पूछताछ नहीं की जाएगी।

यह सच है कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, द्वारा दी गई सलाह

राष्ट्रपति के मंत्रियों से पूछताछ नहीं की जा सकती है। यह भी स्पष्ट है इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का संशोधित अनुच्छेद 74 (1),

जिसकी वैधता को किसी भी पक्ष द्वारा हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, राष्ट्रपति पर यह अनिवार्य बनाता है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री के माध्यम से उन्हें दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे। फिर भी, यदि केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत की गई कार्रवाई के सभी आधारों को जनता के सामने प्रकट किया जाता है और उसके स्वयं के आधारों के प्रकटीकरण से पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय या कानूनी रूप से निषिद्ध या बाह्य या संपार्श्विक उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय उस तरीके से कार्य करने के अपने कर्तव्य से नहीं हटेगा जिसमें कानून उसे कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन, जब हम पाते हैं कि मैदानों और हमारे समक्ष याचिकाओं में किए गए आरोप, सार में, केवल संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के आधारों की पर्याप्तता से संबंधित हैं, और आगे नहीं जाते हैं, तो हम अनुच्छेद 131 के तहत मैदानों या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

मैं कुछ अन्य मामलों को भी नहीं छोड़ना चाहूंगा जिन पर पहले बहस हुई थी।

हम अपने विचारों की इस व्यापक अभिव्यक्ति से अछूते हैं। यह आग्रह किया गया कि राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति, भले ही इसे संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किया जा सके, राज्य सरकार के इस विषय पर केंद्र सरकार के निर्देश को लागू करने में विफल रहने के बाद, तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि यह मामला संसद के दोनों सदनों के समक्ष नहीं रखा गया था ताकि यह इस तरह के नियंत्रण के अधीन हो कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राजस्थान बनाम संघ (बेग, सी. जे.) को चुन सके।

इसके ऊपर व्यायाम करें। अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के तहत रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से, हालांकि, इस तर्क के लिए, अनुच्छेद 356 में संसद के किसी भी सदन द्वारा विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त, लेकिन, दूसरी ओर, अनुच्छेद 356 (3) यह स्पष्ट करता है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा घोषणा को मंजूरी देने में विफलता या इनकार का एकमात्र प्रभाव यह है कि यह दो महीने के बाद काम करना बंद कर देता है। जाहिर है, इसका मतलब है कि यह कम से कम दो महीने तक काम करता है। इसलिए, इन दो महीनों में जो कुछ भी किया जाता है, उसे केवल गलत कारणों से अवैध नहीं माना जा सकता है। स्वीकृति के लिए हमारे सामने रखी गई व्याख्या संविधान के प्रावधानों की भाषा के सीधे विपरीत है। इसलिए, इसे हमारे द्वारा पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग संसदीय नियंत्रण के अधीन है। इसका मतलब यह है कि यह इस तरह के टकराव के अधीन है क्योंकि दोनों सदन, जिनमें से राज्य परिषद वास्तव में राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उस अवधि के दौरान अभ्यास करने में सक्षम हो सकते हैं जिसके लिए घोषणा रहती है। लेकिन, इस तरह के संसदीय सलाहकार नियंत्रण का अस्तित्व, एक सुरक्षा के रूप में, उस अवधि में जो किया जाता है उसकी वैधता को संभवतः रद्द नहीं कर सकता है जिसके दौरान घोषणा रहती है।

श्री आर. के. गर्ग द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि, जब तक कि संसद

संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (सी) को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा के बाद राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य विधानमंडल के लिए विधायी रूप से कोई भी व्यय करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह की घोषणा करने के बाद, हमें राज्य विधानसभा के विघटन के खिलाफ एक निहित निषेध लागू करने के लिए कहा गया था जब तक कि संसद के दोनों सदनों ने इस पर चर्चा और अनुमोदन नहीं किया था।

अनुच्छेद 357 का शीर्षक है "प्रो के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग"

अनुच्छेद 356 "के तहत जारी किया गया मानहानि। यह नीचे दिया गया है:

" 357 (1) . जिसके द्वारा खंड के अधीन जारी की गई उद्घोषणा

(1) अनुच्छेद 356 के अनुसार यह घोषित किया गया है कि

राज्य का विधानमंडल इसके द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जा सकेगा।

संसद का प्राधिकरण सक्षम होगा--

(क) संसद द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने के लिए

राज्य के विधान-मंडल का कानून बनाने के लिए, और

राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत करें, बशर्ते कि

शर्तों के रूप में वह लागू करने के लिए उचित सोच सकते हैं, शक्ति

इस प्रकार निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किया गया

उस ओर से;

(ख) संसद के लिए, या राष्ट्रपति या अन्य लेखक के लिए

जिनके अधीन कानून बनाने की ऐसी शक्ति निहित है

उपखंड (क), शक्तियाँ प्रदान करने वाले कानून बनाना और

कर्तव्यों को लागू करना, या प्रदान करने के लिए अधिकृत करना संघ पर शक्तियाँ और कर्तव्यों का अधिरोपण

या इसके अधिकारी और अधिकारी; [1978] आई. एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

: 48

(ग) राष्ट्रपति को अधिकृत करने के लिए जब

हाउस ऑफ

लोग सत्र व्यय में नहीं हैं

द.

मंजूरी मिलने तक राज्य की समेकित निधि

संसद द्वारा इस तरह के व्यय का।

(2) विधायिका की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी कानून

संसद या राष्ट्रपति या अन्य द्वारा राज्य की प्रकृति

खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी जो

संसद या राष्ट्रपति या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी नहीं बल्कि अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा जारी करने के लिए,

करने के लिए सक्षम रहे हैं, की सीमा तक

अक्षमता, एक की समाप्ति पर प्रभाव डालना बंद कर देता है घोषणा समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि

किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर कार्य करें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, जब तक कि

जिन रियायतों का प्रभाव इस प्रकार समाप्त हो जाएगा, उन्हें जल्द ही निरस्त कर दिया जाएगा।

या अधिनियम द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना पुनः अधिनियमित किया गया उचित विधानमंडल "।

मुझे लगता है कि अनुच्छेद 357 का इस घटना से बहुत कम लेना-देना है।

राज्यों की सरकारों की शक्तियों के बाद राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यय

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किए गए हैं। यह वास्तव में स्थिति को नियंत्रित करता है जब विधायी

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसी घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और किसी भी प्राधिकरण या प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण कर सकता है।

राज्य विधानमंडल के अलावा अन्य राज्य में निकाय। घोषणा में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) (बी) द्वारा परिकलित एक घोषणा भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है जो संसद के अधिकार द्वारा या उसके तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग को सक्षम बनाती है। यह है।

केवल तभी जब उद्घोषणा में अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत यह घोषणा भी हो कि राष्ट्रपति के अधिकार के तहत राज्य की संचित निधि से व्यय करने का प्रश्न हो।

" संसद द्वारा इस तरह के व्यय की मंजूरी के लंबित रहने पर "उत्पन्न हो सकता है। संसद द्वारा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे समेकित कोष से व्यय को अधिकृत करने की राष्ट्रपति की शक्ति केवल उन सहजताओं के लिए प्रदान की गई है जहां संविधान के अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्ति संसद को हस्तांतरित कर दी गई है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। यह एक तात्कालिकता है जो केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब एक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानमंडल के कार्यों को संसद में निहित करने की आवश्यकता होती है ताकि राष्ट्रपति संसदीय मंजूरी की प्रत्याशा में खर्च को अधिकृत करने में सक्षम हो सकें जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा हो। जब राष्ट्रपति की घोषणा अनुच्छेद के तहत किसी भी घोषणा को लागू नहीं करती है। 356 (1) ((ख) क्योंकि राष्ट्रपति शासन अल्पकालिक होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति को राज्य के विधानमंडल द्वारा पहले से बनाए गए किसी कानून के तहत कुल व्यय करने से अक्षम करे। उस कानून के अनुसार होने वाला व्यय कला के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा। 356 (1) ((क) संविधान का।

राजस्थान वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

. 49

दूसरे शब्दों में, हालांकि कला। 356 (1) ((a) संविधान का

राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों की धारणा के खिलाफ एक प्रतिबंध लगाता है, जिसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है

संसद, फिर भी, इसके प्रावधानों को कला के साथ पढ़ा जाता है। 357 संविधान के अनुसार, ऐसे किसी भी व्यय पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य न करें जो राष्ट्रपति द्वारा कानूनी रूप से या राष्ट्रपति के अधिकार के तहत पूर्व-विद्यमान राज्य कानूनों के अनुसार किया जा सकता है जो अन्य प्राधिकरणों या निकायों द्वारा व्यय को अधिकृत करते हैं जिनकी शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत लिया जा सकता है। 356 (1) (ए)। किसी भी मामले में, कला के प्रावधान। 357 संभवतः के विघटन के खिलाफ एक बार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा राज्य विधानसभा। न ही उनका उपयोग अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की घोषणा की पूर्व शर्त के रूप में आयात और पढ़ने के लिए किया जा सकता है। 356 (1) (क) राज्य विधानसभा का विघटन, जैसा कि वह आमतौर पर करता है, संसद के दोनों या दोनों में से किसी एक सदन का अनुमोदन शामिल है। अनुच्छेद के तहत घोषणाएं जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 357 के प्रावधानों से कुछ शर्तों को पूर्ववर्ती या वर्जित करना। 356 (1) संविधान पूरी तरह से अनुचित होगा। अलग-अलग उद्देश्यों के लिए संवैधानिक प्रावधानों को एक-दूसरे के साथ मिश्रित और संयोजित नहीं किया जा सकता है जब प्रत्येक विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्राधिकरणों या निकायों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के विभिन्न सेटों को विनियमित करने के लिए होता है।

रखरखाव के लिए आपत्तियां भी सामने रखी गईं

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत हमारे समक्ष इस आधार पर वाद दायर किया जाता है कि यह प्रावधान केवल भारत सरकार और एक या अधिक "राज्यों" के बीच या दो या अधिक "राज्यों" के बीच के विवादों को शामिल करता है। यह प्रावधान जो यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया जा सकता है, निम्नानुसार है: —

" 131. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन,

उच्चतम न्यायालय, किसी अन्य के अपवर्जन के लिए कुरी, किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है-- -

(क) भारत सरकार और एक या अधिक के बीच

राज्य; या

((b) भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच

या एक तरफ के राज्य और एक या अधिक अन्य राज्य

अन्य; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच;

यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है

(चाहे कानून का हो या तथ्य का) जिस पर अस्तित्व या विस्तार

कानूनी अधिकार निर्भर करता है;

बशर्ते कि उक्त अधिकारिता का विस्तार एक तक नहीं होगा

किसी संधि, समझौते, संयोजक से उत्पन्न होने वाला विवाद,

सगाई सनद या अन्य समान उपकरण जो,

प्रारम्भ होने से पहले प्रवेश किया गया या निष्पादित किया गया यह संविधान, इस तरह के कॉम के बाद भी जारी है

उल्लेख, या जो यह प्रावधान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार इस तरह के विवाद का विस्तार नहीं है "।

1

[1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50

यह तर्क दिया गया था कि एक राज्य और राज्य के बीच अंतर है।

राज्य सरकार। यह आग्रह किया गया था कि अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र

131 विशेष प्रकार के विवादों के लिए एक विशिष्ट है जिसमें

राज्यों को इसमें रुचि लेनी चाहिए, न कि केवल सरकारों को।

ऐसे राज्य जो आ और जा सकते हैं। यह बताया गया था कि यदि

यूनिकैन सरकार ने किसी भी राज्य को किसी भी संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की

राज्य या उसके लोगों की ओर से राज्य सरकार। लेकिन, यह था प्रस्तुत किया, संविधान द्वारा किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया है

कि इसकी सरकार या विधान सभा जारी रहेगी

जिस पर और वह अधिकार जिसके द्वारा विघटन की शक्ति हो सकती थी उस स्थिति में प्रयोग किया जाए जिसमें लोगों को सामना करना पड़ा

नौ संबंधित राज्य।

बिहार राज्य बनाम के परिच्छेदों का संदर्भ दिया गया था। संघ का

भारत और एन. आर. (1) और संयुक्त प्रांत v. गवर्नर-जनरल

परिषद में। (2) मुझे ऐसा लगता है कि राज्य में इस न्यायालय का निर्णय

बिहार और भारत संघ और अन्र। (ऊपर) काफी हद तक आधारित था

यह धारणा कि अनुच्छेद 131 उसी क्षेत्र को कवर करने के लिए था

एस के रूप में। 204 भारत सरकार अधिनियम। इसके अलावा, विद्वान

संघ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने

भारत का संवैधानिक कानून, द्वितीय संस्करण। खण्ड. पी पर II। 1385) लेख 142 (1) संविधान के आदेशों के प्रवर्तन के लिए प्रावधान करता है

यह न्यायालय। बिहार मामले (ऊपर) में व्यक्त विचार प्रतीत होता है।

इस तथ्य से काफी प्रभावित होने के लिए कि कोई समर्थक नहीं था प्रवर्तन के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दृष्टि

संघीय न्यायालय के आदेशों के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 142 (1) ऐसा लगता है /

उस मामले में अनदेखी की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 300 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि "सरकार।

किसी राज्य का प्रशासन राज्य के नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

इससे श्री निरेन डे चाहते थे कि हम यह निष्कर्ष निकालें कि इसमें कोई अंतर नहीं है।

न्यायिक संस्थाओं के रूप में किसी राज्य और राज्य सरकार के बीच संबंध।

भले ही एक के बीच अंतर करने के लिए कुछ आधार हों

राज्य के हित और अधिकार और उसकी सरकार या उसके सदस्यों के हित बर्ज़, मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक या अति लेने की आवश्यकता है

किसी भी अधिकार के लिए मुकदमा करने के राज्य के अधिकारों का तकनीकी दृष्टिकोण, वास्तविक या

काल्पनिक, जिसे राज्य सरकार की ओर से लेने का विकल्प चुनती है

अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे में संबंधित राज्य। इसके अलावा

डब्ल्यूसी के रूप में

विस्तार से सुनने के बाद कोई राहत नहीं देने का फैसला किया है

तर्क और बहस के गुणों पर पूरी तरह से विचार किया गया

दोनों पक्षों से, मुझे नहीं लगता कि हमें इस अवसर पर निर्धारण करने की आवश्यकता है

सायन, अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे का सटीक दायरा। मैं आधार बनाना पसंद करता हूँ

अन्य आधारों पर मेरा निर्णय।

मैदानों और पेटी में निर्धारित मामलों पर विचार करना

हमारे सामने, हर कल्पनीय कोण से, मैं इसे खोजने में असमर्थ हूं

(1) [1970] 2 एस. सी. आर 522

(2) [1939] एफ. सी. आर. 124

राजस्थान वी. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

51

किसी भी निषेधाज्ञा या रिट या आदेश के अनुदान के लिए कार्रवाई का कारण किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ एक मैंडमस की प्रकृति में

पार्टियाँ।

मेरी राय में, शायद तकनीकी रूप से अधिक सही क्रम में,

हमारे सामने जो स्थिति रही होगी, उससे प्राप्त निष्कर्षों पर मैं, नियमों के आदेश XXIII, नियम 6 के तहत वाद-विवाद को खारिज करता हूं।

इस न्यायालय का, और सीमित रूप से रिट याचिकाओं को अस्वीकार करना। आखिरकार, हम कुछ प्रारंभिक सुनवाई के चरण से आगे नहीं बढ़े थे

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री सोली सोराबजी द्वारा हमारे समक्ष मुकदमों और याचिकाओं की स्थिरता पर आपत्तियां रखी गईं। हालाँकि, हमने इन प्रारंभिक आपत्तियों पर बहुत पूरी दलीलें सुनीं, लेकिन हमने इस न्यायालय के नियमों के भाग III के प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी मुद्दे को तैयार नहीं किया, जो इसके मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू होता है। अदालत, इससे पहले कि हम आम तौर पर एक मुकदमे को औपचारिक रूप से खारिज कर दें। हालाँकि, जिस रूप में हम पहले ही अपने आदेश पारित कर चुके हैं, 29 अप्रैल, 1977 को हमारे द्वारा अनुमोदित वाद और याचिकाओं को खारिज करने का काफी हद तक वही प्रभाव पड़ता है जो कार्रवाई के एक परीक्षण योग्य कारण का खुलासा करने में विफलता के लिए वाद की अस्वीकृति का होता है, मैं पहले से दर्ज आदेशों से सहमत हूं। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

चंद्रचूड़, जे.-वह लोकसभा जिसमें कांग्रेस (आर)

भारी बहुमत था जिसे 18 जनवरी, 1977 को भंग कर दिया गया था

हालांकि संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम के तहत, इसके पास अपना विस्तारित कार्यकाल समाप्त करने के लिए एक और वर्ष था। मार्च 1977 में लोकसभा के लिए नए सिरे से मत विभाजन किए गए जिसमें सत्तारूढ़ दल ने अपना बहुमत खो दिया और सत्ता से बाहर हो गया जिसका इस्तेमाल उसने स्वतंत्र होने के बाद से किया था। 24 मार्च, 1977 को जनता पार्टी, जिसने मतदाताओं का निर्णय हासिल किया, ने केंद्र में नई सरकार का गठन किया। यह एक अभूतपूर्व घटना है क्योंकि इस देश के इतिहास में पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल किसी भी संघीय राज्य में सत्ता में नहीं है। जिस दिन जनता पार्टी ने सत्ता संभाली, उस दिन कांग्रेस (आर) बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में सत्ता में थी।

18 अप्रैल, 1977 को श्री चरण सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री,

इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके विचार के लिए "ईमानदारी से प्रशंसा" करते हुए एक पत्र संबोधित किया कि वे अपने-अपने राज्यों के राज्यपालों को "अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य विधानसभा को भंग करने और मतदाताओं से एक नए

जनादेश की मांग करने" की सलाह दे सकते हैं। " गृह मंत्री के पत्र के अनुसार, केवल यही "संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रथाओं के अनुरूप" होगा।

22 अप्रैल को "स्पॉट-लाइट प्रोग्राम" में एक साक्षात्कार में

ऑल इंडिया रेडियो, श्री शांति भूषण, कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री ने कहा कि "कांग्रेस शासित नौ राज्यों में विधानसभाओं के समाधान और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था", क्योंकि "लोगों के विश्वास का आनंद लेने पर एक गंभीर संदेह पैदा हो गया था, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को खारिज कर दिया गया था"। इस साक्षात्कार की एक रिपोर्ट 23 तारीख के 'स्टेट्समैन' सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। रिपोर्ट की शुद्धता विवादित नहीं है।

[1

978] 1 एससीआर।

52

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25/26 अप्रैल को नौ में से छह राज्यों ने इस मामले में मुकदमा दायर किया था।

कला के तहत न्यायालय। 131 संविधान से। 25 तारीख को, तीन मीम पंजाब विधान सभा के सदस्यों ने इस संबंध में रिट याचिकाएं दायर कीं।

कला के तहत न्यायालय। 32. 29 अप्रैल को एक सर्वसम्मत आदेश द्वारा, हम

मुकदमों और रिट याचिकाओं के साथ-साथ अंतरिम प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया गया

राहत मिलती है। आदेश के कारण बताए जाने बाकी थे।

सम्मान के साथ, मैं अपने प्रभु प्रमुख के निष्कर्ष से सहमत हूं

न्याय लेकिन यह देखते हुए कि मामला एकल प्रकृति का है, मैं हमारे सामने चर्चा किए गए कुछ मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

वास्तव में, प्राप्त करने के लिए मुकदमे और रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

एक घोषणा कि मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के पत्र में निहित निर्देश असंवैधानिक है, कि राज्य सरकार कानूनी या संवैधानिक रूप से इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, कि मुख्यमंत्रियों

द्वारा निर्देश को प्रभावी बनाने से इनकार करने को कला के तहत घोषणा जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। 356 और यह कि उक्त अनुच्छेद को राज्य विधानसभाओं को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। रिट याचिकाकर्ता अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित होने की शिकायत करते हैं, क्योंकि यदि विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, तो उन्हें इन विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में वेतन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। वादियों और याचिकाकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री के निर्देश को प्रभावी बनाने से भारत संघ को रोकने के लिए अनुरोध किया जाता है।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया है

जिन मुकदमों का पहले निपटारा किया जा सकता है, उनकी रखरखाव पर आपत्ति। संविधान का अनुच्छेद 131 (ए) उच्चतम न्यायालय को, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में अनन्य मूल अधिकारिता प्रदान करता है, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दायर मुकदमों में शामिल विवाद कला के दायरे से बाहर है। 131 चूंकि विवाद भारत सरकार और राज्य के बीच नहीं है, बल्कि विवाद एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर नौ राज्य सरकारों में से प्रत्येक के बीच है। विवाद इस सवाल से संबंधित है कि क्या राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए और वकील के अनुसार, इसमें कोई सवाल शामिल नहीं है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। क्या राज्य

विधानसभाओं को भंग किया जाना चाहिए या नहीं, यह राजनीतिक त्वरितता का विषय है और हालांकि किसी राज्य में कुछ समय के लिए सत्ता में रहने वाली सरकार को पूर्ण कार्यकाल के लिए विधानसभा के बने रहने में रुचि हो सकती है, लेकिन राज्य को इस तरह के बने रहने को सुनिश्चित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वास्तव में, यह आग्रह किया जाता है कि राज्य सरकार के अलावा राज्य को इस सवाल में भी दिलचस्पी नहीं है कि क्या किसी विशेष विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए या नहीं क्योंकि एक संवैधानिक इकाई के रूप में राज्य को कभी भी सरकार के रंग में दिलचस्पी नहीं है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि विधानसभाएँ आ सकती हैं और जा सकती हैं लेकिन राज्य हमेशा के लिए जीवित रहता है और इसलिए विवाद कला के दायरे से बाहर है। 131 .

राजस्थान बनाम. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

53

प्रारंभिक आपत्ति एक अव्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है

संविधान का कार्यकरण और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 को लागू करता है लेकिन धारा में कुछ भी निहित नहीं है। 3 (58) उस अधिनियम का, जो "राज्य" को परिभाषित करता है या धारा 3 (60) जो "राज्य सरकार" को परिभाषित करता है, इस प्रश्न को निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या वर्तमान प्रकृति के सूट कला के दायरे के लिए विदेशी हैं। 131. सामान्य खंड अधिनियम में निहित "राज्य" और "राज्य सरकार" की कार्य-एक-दिवसीय परिभाषाएं न तो अभियोग की समस्या को छूती हैं।

संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट और "राज्य सरकार" का अर्थ है "राज्यपाल"। इस न्यायालय में मुकदमा दायर करने वाले सभी छह राज्यों को पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। और हालांकि एक बिंदु है जो कला में "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति के गैर-उपयोग को चालू करता है। 131 , एक बिंदु जिस पर मैं वर्तमान में विचार करूंगा, तथ्य यह है कि शब्दकोश को लागू करने का कोई अवसर नहीं है। कला की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम, धारा 3 (60)। 131 .

"राज्य सरकार" अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति और उपयोग

कला में "राज्य" अभिव्यक्ति के स्थान पर। 131 , कहा जाता है कि यह आंतरिक साक्षय प्रस्तुत करता है कि किसी मुकदमे के उस अनुच्छेद के तहत आने के लिए, विवाद भारत सरकार और राज्य के बीच उत्पन्न होना चाहिए, न कि दोनों के बीच।

भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार। द इन

यह तर्क दिया जाता है कि त्रयी साक्षय इस संदर्भ में अधिक विश्वसनीयता मानता है कि लेख "भारत सरकार" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जब इसका अर्थ सरकार था, जो राज्य से विरोधाभासी था। कला में विशेष अभिव्यक्तियों की उपस्थिति। 131 मेरी राय में, भारत संघ की ओर से सुझाए गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। कला में "भारत सरकार" वाक्यांश का उपयोग। 131 (अ)

और (ख) इसका यह अर्थ नहीं है कि विवाद का एक पक्ष होना चाहिए

केंद्र में आज की सरकार "। भारत सरकार "

इसका अर्थ है "भारत का संघ" क्योंकि यदि इस तर्क में योग्यता है कि

कला। 131 उन विवादों को नहीं समझती है जिनमें सरकार

ए। राज्य के विपरीत राज्य को इस बात का पालन करना चाहिए कि तदनुसार, "भारत सरकार" का अर्थ भी केंद्र में सत्ता में रहने के लिए सरकार नहीं हो सकता है। कला का वास्तविक निर्माण। 131 ((क) सार में सत्य और व्यावहारिक रूप से सत्य यह है कि भारत संघ और किसी राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होना चाहिए।

यह विरोधाभासी लग सकता है क्योंकि यदि प्रारंभिक आपत्ति है

यह कहना आसान नहीं होगा कि "भारत का शासन" शब्द का अर्थ है "कार्यालय में सरकार" और "राज्य" शब्द का अर्थ है "कार्यालय में सरकार" नहीं, बल्कि एक राजनीति के रूप में राज्य। लेकिन सुविधाजनक व्याख्याएं व्याख्याओं से जुड़े मुद्दों के महत्व को धुंधला करने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए, इन शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है, इसे स्वीकार करने और संवैधानिक योजना को तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसा कि उचित रूप से माना जा सकता है।

भारत संघ और किसी राज्य के बीच विवाद हो सकता है

एक विवाद जो केंद्र में कार्यालय में सरकार और राज्य में कार्यालय में सरकार के बीच मतभेदों से उत्पन्न होता है। कार्यालय में 'का अर्थ है' सत्ता में 'लेकिन बाद की अभिव्यक्ति के उपयोग से समझदारी से बचा जा सकता है कि सत्ता के साथ क्या होता है। लेकिन एक और पूर्व शर्त है जो कला के दायरे में आने वाले विवादों के वर्ग के दायरे को कम करती है। 131. यह आवश्यकता है कि इस अधिनियम में एक प्रश्न शामिल होना चाहिए, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। यह योग्यता ही यह निर्धारित करने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कला के भीतर किसी विशेष विषय को समझा जाता है या नहीं। 131. उस अनुच्छेद की योजना में सरकारों के बीच केवल झगड़ों का कोई स्थान नहीं है। उन्हें अदालत की कार्यवाही की तुलना में कहीं और और कम गंभीर और पवित्र तरीके से हल किया जाना चाहिए। कला का उद्देश्य। 131 उन विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना है जो उनके निर्णय के लिए किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा पर निर्भर करते हैं।

यह तभी होता है जब कोई कानूनी मुद्दा, न कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा को छूते हुए उत्पन्न होता है। 131 आकर्षित होता है।

मुझे यह मानना असंभव लगता है कि छह लोगों द्वारा दायर किए गए मुकदमे

राज्य किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या विस्तार के आधार पर किसी प्रश्न से जुड़े विवाद को नहीं उठाते हैं। वादी, अपने मुकदमों द्वारा, सीधे और विशेष रूप से केंद्र सरकार के संवैधानिक अधिकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यपालों को एक निश्चित सलाह देनी चाहिए। वादी गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उल्लिखित आधारों पर राज्य विधानसभाओं को भंग करने के केंद्र सरकार के संवैधानिक अधिकार पर भी सवाल उठाते हैं। इस प्रकार कानूनी अधिकार के अस्तित्व और विस्तार से उत्पन्न होने वाला कानूनी मुद्दा, राजनीतिक नहीं, स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है और मुकदमों को कला के दायरे से बाहर होने के रूप में नहीं फेंका जा सकता है। 131 .

प्रारंभिक आपत्ति की त्रुटि इस धारणा में निहित है कि यह

कला को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है। 131 कि वादी को अपने आप में एक कानूनी अधिकार का दावा करना चाहिए। उस अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और यह पर्याप्त है ताकि इसके प्रावधान लागू हो सकें कि वादी प्रतिवादी द्वारा प्रतिपादित कानूनी या संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाए, चाहे वह भारत सरकार हो या कोई अन्य राज्य। इस तरह की चुनौती आती है

कला की शर्तों के भीतर सूट। 131 क्योंकि, न्यायालय के निर्णय के लिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह या वह विशेष विधान सभा है वे पद पर बने रहने के हकदार हैं, लेकिन क्या भारत सरकार, जो कथित आधारों पर विधानसभा को भंग करने के संवैधानिक अधिकार का दावा करती है, के पास ऐसा कोई अधिकार है।

मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि राज्य एक राज्य के रूप में हकदार नहीं है

इस तरह का विवाद खड़ा करना। एक संघ में, चाहे वह शास्त्रीय हो या अर्ध-शास्त्रीय, राज्यों को एक ओर संघीय सरकार की शक्तियों की परिभाषा में और दूसरी ओर अपनी शक्तियों की परिभाषा में बहुत रुचि है। उन शक्तियों के परिसीमन से संबंधित विवाद

पहले से है

विशेष रूप से वह जिसमें संघीय राज्य, संघीय सरकार से कम नहीं, रुचि रखते हैं। इसलिए राज्यों के पास राजस्थान बनाम संघ (चंद्रचूड़, जे.) का अधिकार है।

55

और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित दावे का विरोध करने और निर्णय लेने का हित। भारत सरकार और राज्यों के बीच संवैधानिक दायित्व का बंधन इस अधिकार को बनाए रखता है।

"कानूनी अधिकार" अभिव्यक्ति जो कला में पाई जाती है। 131 होना चाहिए।

अपने उचित परिप्रेक्षय में समझा। एक सख्त अर्थ में, कानूनी अधिकार हैं कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी और हितों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जो कानून

अर्थ में, "सही" शब्द का उपयोग कानूनी से प्रतिरक्षा के अर्थ में किया जाता है एक अन्य प्रतिरक्षा की शक्ति शक्ति से मुक्ति है

जिस तरह से स्वतंत्रता अधिकार से छूट है उसी तरह से दूसरे की

किसी और से। कमीज में प्रतिरक्षा, कोई अधीनता नहीं है। (1) आर. डब्ल्यू. एम. डायस

अपने "न्यायशास्त्र" (1976 एड। पीपी। - 33-4) कि "सही" शब्द

अर्थ में लगातार बदलाव आया है और चार अलग-अलग अर्थों को दर्शाता है

एक व्यक्ति की गतिविधि, या संभावित गतिविधि से संबंधित विचार

दूसरे का संदर्भ। इन चार न्यायिक संबंधों में से एक, के अनुसार

विद्वान लेखक के लिए, "आप नहीं कर सकते" संबंध है, जो है प्रतिरक्षा के अधिकार के समान जो "स्वतंत्रता को दर्शाता है

दूसरे की शक्ति "(पृ. 58)। न्यायशास्त्र पर पैटन की पुस्तक (तीसरा संस्करण।

पी। 256) इसमें कानूनी अधिकारों की एक समान व्याख्या शामिल है। कानूनी अधिकार

राज्यों की अपनी प्रतिरक्षा में शामिल है, स्वतंत्रता के अर्थ में संघ सरकार की शक्ति। कला के तहत वे हकदार हैं।

131 , उस अधिकार का दावा करने के लिए या तो निरपेक्ष रूप से तर्क देते हुए कि

केंद्र के पास विधानसभाओं को भंग करने की कोई शक्ति नहीं है या

योग्यता कि ऐसी शक्ति का प्रयोग जमीन पर नहीं किया जा सकता है बताया गया है।

यह सच है कि राज्य, ब्रिटिश सम्राट की तरह, कभी नहीं मरता। ए.

विधानसभा भंग हो सकती है, एक मंत्रिपरिषद जा सकती है

आपातकाल घोषित किया जा सकता है जो राज्यों को प्रभावित कर सकता है ' विधायी और कार्यपालिका के मामलों में शक्ति। राज्य इन पर कायम है।

उथल-पुथल। लेकिन यह कहना संवैधानिक रूप से अनुचित है कि राज्य

उसके संबंध में दावा करने के लिए कानूनी अधिकार। क्या ऐसा था, जो तब हैं कानूनी अधिकार जो राज्य अपनी सरकार से अलग करते हैं,

कला के तहत आंदोलन कर सकते हैं। 131 ? दावे की प्रकृति जो भी हो,

यह तर्क हमेशा सामने रखा जा सकता है कि सरकार, न कि

राज्य, वह दावा करने में रुचि रखता है। ऐसी कठोर व्याख्या

कला के दायरे में। 131 वस्तुतः इसे एक मृत-पत्र में बदल देगा और मनमानी शक्ति के उपयोग के खिलाफ एक बहुमूल्य सुरक्षा को नष्ट करें। द.

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा प्रचार की गई व्याख्या

इसलिए जहाँ तक लेख की भाषा की बात है, उससे बचना चाहिए।

इसकी अनुमति देता है, जो मेरी राय में यह करता है।

संविधान सभा की बहस (खंड। 8 , पीपी। 588-590)

प्रश्न पर कोई प्रकाश न डालें।

बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ (2)

हमारे सामने उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कोई वास्तविक सहायता प्रदान नहीं करता है। उस में

मामले में, अदालत ने कला के तहत दायर मुकदमों में तीन मुद्दे उठाए। 131. द.

(1) सैलामोंड का न्यायशास्त्र 11 वां संस्करण। पीपी। 276-7 .

(2) [1970] 2 एस. सी. आर 522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

56

[1978] 1 एस सी आर।

पहला मुद्दा जो इस सवाल से संबंधित था कि क्या मुकदमे अंदर थे

3

कला का दायरा। 131 न्यायालय द्वारा उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि उसने अभिनिर्धारित किया था दूसरे मुद्दे पर कि मुकदमे बनाए रखने योग्य नहीं थे , क्योंकि एक निजी

पार्टी को प्रेरित किया गया था। एकमात्र सहायता जो प्राप्त की जा सकती है उस मामले में निर्णय से यह कहा गया है कि इसके तहत विवाद

कला। 131 कानूनी अधिकारों के संबंध में होना चाहिए न कि किसी के विवादों के संबंध में राजनीतिक चरित्र "और यह कि हालांकि इसे परिभाषित करना अनावश्यक था

संघवाद यह स्थापित करता है "(पी। 529)। ये अवलोकन प्रभावित नहीं करते हैं संविधान जिसे मैंने कला पर रखा है। 131. मैंने कोशिश की है कि

उस अनुच्छेद के तहत प्रकृति को प्रस्तुत करें और इन मुकदमों द्वारा, राज्य सरकारें एक कानूनी मुद्दा उठा रही हैं, राजनीतिक नहीं। उनका दावा

कि भारत सरकार के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है

उसके द्वारा दावा की गई शक्ति और इसलिए, इस न्यायालय को घोषणा करनी चाहिए कि वे

वे उस शक्ति के प्रयोग से प्रतिरक्षित हैं। राज्यों का कहना है कि

प्रतिरक्षा का कानूनी अधिकार जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वतंत्रता को दर्शाता है

दूसरे की शक्ति से।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति

इसलिए मुकदमों की रखरखाव के लिए सामान्य रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए।

हालाँकि, रिट याचिकाओं में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है जैसे कि हो सकता है

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उनकी याचिकाओं को बनाए रखना

कला। 32 संविधान से। वे तर्क देते हैं कि धमकी दी गई डिसो

जिस विधान सभा के वे सदस्य हैं, उस विधान सभा का गठन

अनिवार्य रूप से उन्हें उस वेतन को प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित कर दें जिसके लिए वे हैं

ऐसे सदस्यों के रूप में हकदार। उनके अनुसार, यह एक उल्लंघन है

कला का ज्ञान। 19 (1) (च) संविधान का जो सभी शहरों को गारंटी देता है

संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार।

याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत जारी करने पर निर्भर है

विधानसभा को भंग करने की घोषणा, जो तब तक जारी नहीं की गई थी

इन मामलों में तर्कों का निष्कर्ष। शिकायतें

काल्पनिक विचारों पर मौलिक अधिकारों के आक्रमण का आर्क कला के तहत इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। 32. लेकिन घोषणा है

यदि जारी किया गया है, तो रिट को खारिज करना अति-तकनीकी होगा।

इस आधार पर याचिकाएं कि याचिकाकर्ताओं का कोई आक्रमण नहीं था '

उस तारीख को अधिकार जब इस न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं।

लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की गई

याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया कार्य अप्रत्यक्ष और दूरस्थ है, प्रत्यक्ष या निकटवर्ती नहीं है।

राष्ट्रपति द्वारा कला के तहत जारी की गई घोषणा द्वारा। 356 (1) में से

संविधान, नौ राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, उस पर लागू किया गया था

उन राज्यों को। नतीजतन, रिट याचिकाकर्ताओं का सदस्य बनना बंद हो गया। विधान सभाओं से। और उनके बंद होने के परिणामस्वरूप

ऐसे सदस्य, वेतन प्राप्त करने का उनका अधिकार, जो वे केवल प्राप्त कर सकते थे यदि वे विधानसभाओं के सदस्य थे, तो समाप्त हो गए। हालांकि

याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह नहीं था

उन्हें उनके वेतन से वंचित करने के लिए घोषणा जारी करने का इरादा,

रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि

याचिकाकर्ताओं के कथित मौलिक अधिकार को नुकसान बहुत अप्रत्यक्ष है

और दूरस्थ।

राजस्थान बनाम. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

57

फिर भी, मैं द्वारा उठाए गए विवाद से निपटना चाहूंगा

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री आर. के. गर्ग ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत जारी की गई घोषणा। 356 (1) संविधान की कोई शक्ति नहीं हो सकती और संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बिना उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 356 (1) राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 (3) में आदेश दिया गया है कि ऐसी प्रत्येक घोषणा संसद के सदन के समक्ष रखी जाएगी और, सिवाय इसके कि जहां यह पिछली घोषणा को निरस्त करने वाली घोषणा है, वहां पर इसका संचालन बंद हो जाएगा।

दो महीने की समाप्ति जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले न हो

इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह.

इस स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह मानना असंभव है कि प्रो

क्लैमेशन में न तो बल हो सकता है और न ही वैधता हो सकती है जब तक कि इसे अनुमोदित नहीं किया जाता है

संसद। कला की योजना। 356 कि घोषणा जारी की गई है

घटना। यदि इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित किया जाता है दो महीने की समाप्ति से पहले, इसके संचालन को बढ़ाया जाता है

कला के खंड (4) में उल्लिखित अवधि। 356. लेकिन यह या नहीं

इस तरह से अनुमोदित है, घोषणा में दो की अवधि के लिए एक सुनिश्चित जीवन है

महीनों और उस अवधि के दौरान इसकी वैधता को कम नहीं किया जा सकता है

कला में पढ़ना। 356 संसद की प्रकृति में एक पूर्ववर्ती स्थिति

अप्रूवल जो, स्पष्ट रूप से, उसमें नहीं पाया जाता है। प्रावधान

कला के खंड (3) के लिए। 356 इस स्थिति को और भी स्पष्ट करता है। अगर

घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है या

इसका विघटन दो महीने की अवधि के दौरान होता है, और

काज्या सभा, लेकिन लोकसभा नहीं, घोषणा को मंजूरी देती है दो महीने के भीतर, यह तीस दिनों की समाप्ति पर काम करना बंद कर देता है।

जिस तारीख से पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक होती है। अगर पहले भी

तीस दिनों की उपरोक्त अवधि की समाप्ति, लोकसभा भी

इसे मंजूरी देता है, इसका जीवन में उल्लिखित अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा

खंड (4)। दूसरे शब्दों में, संसद का पूर्व अनुमोदन या

इसके दोनों सदनों में से कोई भी प्रस्ताव को वैधता देने के लिए आवश्यक नहीं है।

मैशन। यदि घोषणा अस्वीकृत हो जाती है तो क्या होगा

दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का गठन नहीं होता है। इन कार्यवाहियों में निर्णय के लिए, और हालांकि, यह एक के रूप में दिखाई देगा

संवैधानिकता की बात है कि घोषणा फिर भी हो सकती है

दो महीने की अवधि के लिए संचालन में, यह उचित है

इस तरह की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, एक परिपक्व राजनीतिक निर्णय घोषणा को निरस्त करने के पक्ष में झुकेंगे। इस तरह

संवैधानिक संकट व्याख्या के लिए एक सुरक्षित सुराग प्रदान नहीं कर सकते हैं संविधान।

कला के प्रावधानों के बीच विरोधाभास। 356 और 123 इलूमी है।

नेटिंग। अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है

प्र

चार करना

अध्यादेशों में खंड (2) द्वारा यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक

अध्या

देश होगा

पुनः संयोजन से छह सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर दें

यदि, तथापि, छह सप्ताह की अवधि की समाप्ति से पहले,

यह उन संकल्पों में से दूसरे के पारित होने पर काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार, जबकि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत जारी की गई घोषणा।

किसी भी घटना में दो महीने की अवधि के लिए संचालन में जारी है, और

एक ही गणमान्य व्यक्ति द्वारा जारी अध्यादेश का संचालन बंद हो जाता है

जल्द से जल्द

इसे अस्वीकार करने वाले दो प्रस्तावों में से दूसरे को एक द्वारा पारित किया जाता है

संसद का सदन।

इस भेद का कारण भाषा से स्पष्ट है और

संबंधित प्रावधानों का संदर्भ। अनुच्छेद 356 में कहा गया है -

"आपातकालीन प्रावधान" नामक अध्याय का सहारा लेने का इरादा है -

स्थितियों के उस असाधारण वर्ग में, जो हालांकि घटित हुई हैं

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। टूटना। राज्य के मामलों और प्रशासन में संविधान का है

कला में निहित आपातकालीन प्रावधान के अभ्यास के लिए अवसर।

356. संविधान निर्माताओं का शायद यह इरादा था कि

गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से तभी निपटा जा सकता है जब राष्ट्रपति

एक घोषणा जारी करने के लिए सशक्त है और उस घोषणा को एक दिया जाता है

न्यूनतम दो महीने का जीवन, चाहे संसद इसे मंजूरी दे या

नहीं। दूसरी ओर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति सीमित है

ऐसे अवसरों पर जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी नहीं है

सत्र। चूँकि यह शक्ति आंशिक रूप से पार के दोनों सदनों से सह-संबंधित है। बकाया अवकाश में होने के कारण, यह प्रावधान किया गया था कि अध्यादेश समाप्त हो जाएगा

संसद की पुनः सभा से छह सप्ताह की समाप्ति पर, और यदि यह उस अवधि के भीतर दोनों सदनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है,

दोनों संकल्पों में से दूसरे को पारित करना।

श्री गर्ग ने लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की।

अगर यही कला की सही व्याख्या है। 356. यह तर्क नहीं है

मुझसे अपील करें क्योंकि वही संविधान जिसके तहत लोग

इस देश ने भारत को एक संप्रभु "डेमो" बनाने का संकल्प लिया क्रेटिक "रिपब्लिक, ने इसे सशक्तीकरण युक्त कानूनों का एक कानून दिया

अपने नागरिकों को हिरासत में लेना, अध्यादेश पारित करना और आपात स्थिति घोषित करना। ए.

आपातकाल की घोषणा के कई परिणाम सामने आते हैं

हमारे संविधान की लोकतांत्रिक नींव और संघीय संरचना दोनों को बाधित करने के लिए। संघ की कार्यकारी शक्ति तब किसी भी राज्य को निर्देश देने तक फैली हुई है कि किस तरीके से

उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है; कानून बनाने की संसद की शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जो संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं;

कला के प्रतिबंध। 19 राज्य की कोई भी कानून बनाने की शक्ति पर

या कोई कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए हटा दिया जाता है और यह एक सर्वविदित तथ्य है।

हाल के इतिहास का कि प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार

मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यदि इस तरह के कठोर उपायों को लागू करने और इस तरह के कठोर कानूनों को पारित करने की शक्ति संविधान के लोकतांत्रिक कामकाज का एक हिस्सा है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि न केवल राष्ट्रपति की घोषणा कला के तहत की जाती है। 356 इसके लिए संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह कम से कम दो महीने की अवधि, अनुमोदन या कोई अनुमोदन के लिए पूरी तरह से प्रभावी है। इस नियम का कारण यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें तेजी से कार्य करना अनिवार्य हो और संसदीय प्रक्रिया का सहारा लेना, इसमें शामिल देरी के कारण, लोकतंत्र के कामकाज को मजबूत करने के बजाय बाधित कर सकता है। इसलिए संविधान ने प्रावधान किया है सुरक्षा-असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए वाल्व। उनके पास एक दोषरहित राजस्थान बनाम है।

यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

रूखे लिबास और एक दमनकारी सामग्री लेकिन वे लोकतंत्र को बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, न कि नष्ट करने के लिए। गलती, यदि कोई हो, तो संविधान के निर्माण में नहीं बल्कि उसके काम करने में है।

यह निस्संदेह सच है कि दो की इस अभेद्य अवधि के भीतर

महीनों, राष्ट्रपति, निश्चित रूप से परिषद की सलाह पर कार्य करते हुए मंत्री, कला के खंड (ए) से (सी) के तहत विभिन्न कदम उठा सकते हैं।

अपरिवर्तनीय हो सकता है और वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसा ही एक कदम हो सकता है राज्य विधानसभा का विघटन और नए सिरे से चुनाव कराना।

वहाँ तक। लेकिन यहाँ भी, अंतिम बिंदु पर जो मेरे पास है

क्षमा करें, इसका उत्तर यह है कि संविधान स्पष्ट रूप से विशाल और राष्ट्रपति पर विभिन्न शक्तियाँ यदि वह एक निश्चित संतुष्टि पर पहुँचता है।

कला के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। 360 (1) ढोते हैं।

इसके साथ प्रति के वेतन को कम करने के लिए प्रतिबंध जारी करने की शक्ति

संघ के मामलों के संबंध में सेवारत बेटे, जिनमें शामिल हैं

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कला का खंड (2)।

360 कला का खंड (2) बनाता है। 352 वित्त की घोषणाओं पर लागू परिणाम के साथ आपात स्थिति, कि कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई

घोषणा जारी होने के बाद दो महीने की अवधि के दौरान,

यह उस अवधि के लिए अलंघनीय है। कि वास्तव में, आम है

धागा जो कला के माध्यम से चलता है। 352 , 356 और 360। निलंबन

मौलिक के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार

अधिकार, कला के निषेध को हटाना। 19 बनाने के विपरीत

कानून और कार्यकारी कार्रवाई करना, के तहत शक्तियों की धारणा कला के खंड (ए), (बी) और (सी)। 356 प्रोक्ला के दौरान पूर्ण प्रभाव पड़ता है

मेशन कम से कम दो महीने की अवधि के दौरान काम कर रहे हैं।

उन दो महीनों के दौरान की गई कार्रवाई, यदि अपरिवर्तनीय है, तो अपरिवर्तनीय बनी हुई है

ठीक किया गया।

इस तर्क में भी कोई सार नहीं है कि प्रो जारी करके

कला के तहत क्लैमेशन। 356 , राष्ट्रपति शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है

राज्य विधानसभा को भंग करें। कला के खंड (ए) के अनुसार। 356 (1) , प्रेसी

घोषणा द्वारा सभी या किसी भी कार्य को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं।

राज्य सरकार की और सभी या निहित शक्तियों में से कोई भी

राज्यपाल में या उसके द्वारा प्रयोग करने योग्य। अनुच्छेद 174 (2) (बी) सशक्त बनाता है

राज्यपाल समय-समय पर "विधान सभा को भंग" करेगा

समय। यह मुझे किसी भी गंभीर विवाद के लिए असमर्थ लगता है कि द्वारा

कला में निहित प्रावधानों का कारण। 356 (1) ((a) राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निहित और प्रयोग करने योग्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

कला के तहत। 174 (2) ((ख) राज्य की विधान सभा को भंग करना।

यह विचार के लिए छोड़ देता है एक तर्क की ओर से आगे बढ़ाया गया

श्री निरेन डे, श्री गोखले और विद्वानों द्वारा राज्य सरकारें

हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ता। श्री राम पंजवानी, श्री का समर्थन करते हुए गोखले ने उस तर्क का समर्थन करने के लिए ग्रंथों का हवाला दिया। तर्क का मूल

विचार यह है कि विधान सभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति

कि नौ राज्यों को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है सभाएँ और गृह मंत्री के आदेश में निहित कारण

मुख्यमंत्रियों को पत्र पूरी तरह से अपर्याप्त और अप्रासंगिक हैं

प्रस्तावित कार्रवाई करना। कई अन्य विकल्पों का आग्रह किया जाता है, भारत सरकार स्थिति को पूरा करने के लिए गोद लेने के लिए तैयार है

गृह मंत्री ने इसकी शिकायत की लेकिन ऐसा करने के बजाय, उन्होंने उन नौ विधानसभाओं को भंग करने की धमकी देकर भारी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिनमें कांग्रेस (आर) के पास बहुमत है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि नौ राज्यों में सत्ता में मौजूद कांग्रेस (आर) सरकारों को समाप्त करने के लिए सत्ता के इस तरह के नग्न दुरुपयोग को असंवैधानिक के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। श्री गोखले ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 356 का खंड (5), जिसे 38 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था, राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए अंतिमता प्रदान करता है और इसे अदालतों की पहुंच से बाहर रखता है, दुर्भावनापूर्ण शक्ति के प्रयोग को रद्द करने के लिए कोई बाधा नहीं है। वकील का कहना है कि कानून की नजर में एक आदेश का कोई अस्तित्व नहीं है, और अदालतों को ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करके अन्याय को कायम नहीं रखना चाहिए। इन तर्कों में एक परिचित, हालांकि अजीब, प्रतिध्वनि है लेकिन यह बिंदु से परे है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि विद्वान सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं इस धारणा के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, हालांकि यह विरोधाभासी है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा पुष्टि की गई कि प्रस्तावित घोषणा पूरी तरह से गृह मंत्री के पत्र में निहित कारणों पर आधारित होने की संभावना है। फिर भी, मुझे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल लगता है कि वे कारण कला के तहत एक घोषणा जारी करने की शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक हैं। 356 संविधान का। उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए संतोषजनक है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। गृह मंत्री के पत्र में निहित कारण ऐसे नहीं हो सकते हैं जो आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि निन्क राज्यों में संवैधानिक तंत्र टूट गया है। लेकिन संभावनाओं की प्रधानता द्वारा प्रमाण की परीक्षा, परिस्थितियों की परीक्षा को एकमात्र परिकल्पना के अनुरूप होने की बात तो छोड़िए, राष्ट्रपति की घोषणा की संवैधानिक

वैधता पर विचार करने में पूरी तरह से अनुचित है। यह राष्ट्रपति को तय करना है कि क्या विशेष विवरण की स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे सभी या किसी भी शक्ति को ग्रहण करने के लिए एक घोषणा जारी करना आवश्यक हो गया है।

कला के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित है। 356 (1) . उनसे अपेक्षा की जाती है और उन्हें निष्पक्षता से निर्णय लेना चाहिए, लेकिन हम उनकी टिप्पणियों पर निर्णय नहीं ले सकते।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या स्थिति का कोई अन्य दृष्टिकोण उचित रूप से संभव नहीं है। जब तक प्रस्तावित या की गई कार्रवाई के लिए दिए गए कारणों, यदि किसी का खुलासा किया जाता है, विशेष शक्ति के प्रयोग के साथ एक उचित संबंध रखता है, राष्ट्रपति की संतुष्टि को निर्णायक माना जाना चाहिए। तब यह न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं होगा। हालाँकि, यदि दिए गए कारण संतुष्टि के गठन के लिए पूरी तरह से बाहरी हैं, तो घोषणा इस हमले के लिए खुली होगी कि यह कानूनी दुर्भावना से दूषित है।

यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। गृह मंत्री के पत्र से पता चलता है कि

(i) हाल के लोकसभा चुनावों में विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के आभासी पुनर्गठन से एक अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी; (ii) अनिश्चितता का परिणामी माहौल गंभीर चिंता का कारण था; (iii) स्थिति ने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मतभेद की भावना पैदा कर दी थी; (iv) राजस्थान वी. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.) में लोग।

61

विशाल ने एक पार्टी के सत्ता में बने रहने के औचित्य की सराहना नहीं की, जिसे मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था; और (v) अनिश्चितता, मतभेद और अनादर के माहौल ने कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरों को जन्म दिया था। इन कारणों के आधार पर गृह मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक संप्रभुता के लिए एक नई अपील न केवल अनुमति योग्य थी, बल्कि अनिवार्य हो गई थी। इन आधारों को, किसी भी कारण के साथ, खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि नौ राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की दृष्टि से एक घोषणा जारी करने की आवश्यकता के साथ कोई मूल संबंध नहीं है।

सदन द्वारा दिए गए कारणों की अधिक गहराई से जांच करना।

मंत्री को एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना है जहाँ से न्यायाधीशों को सावधानीपूर्वक दूर रहना चाहिए। वह क्षेत्र राजनेता के लिए आरक्षित है और अदालतों को इसमें अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। यह हमेशा एक आसान काम नहीं होता है क्योंकि

सीमांकन की रेखा जो इस न्यायालय के कार्यों को सरकार के कार्यों से अलग करती है, धुंधली हो जाती है, जब संवैधानिक समस्याएं उच्च नीतियों से संबंधित मुद्दे उठाती हैं।

कार्यकारी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी टोक्विल ने उल्लेख किया कि

1832 कि

जल्दी या बाद में हर राजनीतिक सवाल न्यायिक सवाल बन जाता है। इसलिए लियो फेफर ने सोचा कि हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने "यह सर्वोच्च है, लेकिन यह वास्तव में एक न्यायालय नहीं है" (1)। यह एक चेतावनी है

यह अच्छी तरह से याद रखने योग्य है लेकिन यह अदालतों को अपने कार्यों को करने से नहीं रोकना चाहिए यदि वे पाते हैं कि लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक शक्ति का उपयोग इसे नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्री का पत्र स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से रेखा के सुरक्षित पक्ष पर है और मुझे इस पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।

पत्र में उनके द्वारा बनाए गए मामले की ईमानदारी या उसमें बताए गए तथ्यों की प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए। जैसा कि न्यायमूर्ति हार्लन एफ. ने कहा।

स्टोन ने अपनी अक्सर उद्धृत असहमति वाली राय में कहा: अदालतें अकेले नहीं हैं।

सरकार की एजेंसी जिसके पास क्षमता होनी चाहिए

शासन "(2)।

इसलिए मुझे इस प्रश्न में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सरकार

गृह मंत्रालय में बताए गए कारणों के अलावा भी भारत के पास कारण हैं

राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने की सलाह देने के लिए टेर का पत्र। अगर

उनके पास अब तक बहुत अच्छा है। हो सकता है कि वे उन्हें प्रकट करने का विकल्प न चुनें लेकिन

यदि वे ऐसा करते हैं, जैसा कि उन्होंने अब किया है, तो वे न्यायिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं।

यह देखने के सीमित उद्देश्य के लिए कि क्या कारण सही हैं

प्रस्तावित कार्रवाई के साथ कोई तर्कसंगत संबंध। मैं झुकी हुई हूँ

राय है कि सरकार लोगों के श्रेय का दावा नहीं कर सकती है

प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का खुलासा करने में निष्पक्षता के लिए प्रतिबंध और

साथ ही इस न्यायालय को निष्कर्ष निकालने की सीमित शक्ति से इनकार करता है।

क्या कारणों में आवश्यक सांठगांठ है या पूरी तरह से बाहरी हैं

प्रस्तावित कार्रवाई। यह तर्क कि "यदि मंत्री को इसकी आवश्यकता नहीं है कारण दें, क्या फर्क पड़ता है अगर वह बुरे लोगों को ओवर देता है-ऐसा लगता है कि

दुर्भावना की जमीन। यह तर्क, चाहे कहा गया हो, नहीं बनाया गया था विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा लेकिन यह दिलचस्प है कि

(1) " लियो फेफर द्वारा लिखित यह माननीय न्यायालय, भारतीय प्रतिकृति 1967, पृ. 7।

(2) संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। बटलर-297 यू. एस. 1,87।

पता करें कि इसे लॉर्ड डेनिंग एम. आर. द्वारा पैडफील्ड बनाम में कैसे खदेड़ा गया था। कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय (1)।

के खंड (5) के निहितार्थ पर विचार करना भी अनावश्यक है।

कला। 356 जिसे 38 वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बनाया गया था, जो किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में पूछे जाने के लिए खुला नहीं था। मैंने घोषणा की वैधता को इस दृष्टिकोण पर बरकरार रखा है कि इसके समर्थन में उद्धृत कारण इसके साथ संबंध रखते हैं।

सवाल पर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में निर्णयों का हवाला दिया गया था

क्या ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायसंगत है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने इस न्यायालय, संघीय न्यायालय, प्रिवी काउंसिल और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भरोसा किया कला के खंड (5) के अलावा यह दिखाने के लिए न्यायालय। 356 , राष्ट्रपति की संतुष्टि निर्णायक होती है और न्यायालयों को इसके पीछे जाने की कोई शक्ति नहीं होती है। इन निर्णयों पर मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके निर्णय में पूरी तरह से चर्चा की गई है। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, मैं उसे व्यक्त करना पसंद करता हूं

इस प्रश्न पर कोई राय नहीं है सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि हालांकि इस प्रश्न को "अच्छी तरह से हल किया गया" माना जाता है, लेकिन स्टीफन कलोंग निंग कान बनाम में प्रिवी काउंसिल। मलेशिया सरकार (1) ने कहा:

" क्या द्वारा वैधानिक शक्तियों के तहत एक घोषणा

संघ के सर्वोच्च प्रमुख को पहले चुनौती दी जा सकती है कुछ या किसी भी आधार पर अदालतें एक संवैधानिक प्रश्न है।

दूरगामी महत्व का जो वर्तमान स्थिति में

अधिकारी, अस्थिर और बहस योग्य बने हुए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक कानून की इस शाखा में, जिसे राजनीतिक नीतियों के विचारों से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है, केवल एक प्रस्ताव को अच्छी तरह से स्थापित कहा जा सकता है: इस शाखा में कोई सवाल नहीं है।

कानून अच्छी तरह से स्थापित है "। राजनीतिक सवाल 'खुला तिल' है।

अभिव्यक्ति जो विज्ञापन प्राप्त करने या रोकने के लिए एक कूटशब्द बन सकती है

निषिद्ध क्षेत्रों में मिशन। और यह संविधान का एक स्वीकृत तथ्य है।

राष्ट्रीय व्याख्या कि न्यायसंगतता की सामग्री इस बात के अनुसार बदलती है कि न्यायाधीश की मूल्य प्राथमिकताएं दिन की बहुआयामी समस्याओं पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। इतिहास के बारे में जागरूकता उन प्राथमिकताओं का एक अभिन्न अंग है। अंतिम विश्लेषण में, जिन लोगों

के लिए उपशीर्षक का अर्थ है, उन्हें इस डर से मोहभंग में अपना चेहरा इससे दूर नहीं करना चाहिए कि न्याय एक इच्छा है।

फिर ये सर्वसम्मत आदेश के समर्थन में मेरे कारण हैं जो

न्यायालय ने 29 अप्रैल, 1977 को पारित किया।

भगवती, जे.-इनमें विचार के लिए दो मुख्य प्रश्न उठते हैं।

मुकदमे और रिट याचिकाएँ। एकटा ई अछि कि सूट रखरखाव योग्य अछि कि नहि।

अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं के तहत संविधान, और दूसरा यह है कि इसका दायरा और दायरा क्या है

अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति और क्या और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है

राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग। इन्हें जन्म देने वाले तथ्य फैसले में मुकदमों और रिट याचिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

(1) एल. आर. [1968] ए. सी. 997,1006

(2) एल. आर. [1970] ए. सी. 379,392।

राजस्थान वी. यूनियन (भगवती, जे.)

63

विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया और उन्हें दोहराना हमारी ओर से व्यर्थ अभ्यास होगा। इसलिए हम दृढ़ संकल्प के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए सीधे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत संवैधानिक महत्व के हैं।

हम पहले मुकदमों की रखरखाव के सवाल की जांच करेंगे।

और रिट याचिकाएँ। पंजाब राज्य के तीन विधायकों ने अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के तहत गारंटीकृत संपत्ति के मानसिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की हैं।

और 31. वे शिकायत करते हैं कि अगर राज्य की विधान सभा

अनुच्छेद 356 के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य को भंग कर दिया जाता है।

खंड (1), भारत सरकार द्वारा धमकी के रूप में, वे होंगे विधायिका के सदस्यों के रूप में वेतन प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित

विधानसभा और वेतन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति होने के कारण, वहाँ होगा अनुच्छेदों के तहत संपत्ति के उनके अधिकार का असंवैधानिक उल्लंघन होना

19 (1) (च) और 31 और इसलिए वे इस न्यायालय में जाने के हकदार हैं।

अनुच्छेद 32 इस तरह के खतरे वाले उल्लंघन को रोकने के लिए। यह विवाद स्पष्ट रूप से अस्थिर है। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, और वास्तव में

यह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के सामने निष्पक्षता से कहा जाना चाहिए जिन्होंने बड़ी क्षमता के साथ मामले का तर्क दिया, कि उन्होंने विरोध नहीं किया

इसके विपरीत, कि यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की आशंका है,

संबंधित व्यक्ति अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय से संपर्क करने का हकदार है।

32 और एक समयबद्ध कार्रवाई के रूप में निषेधाज्ञा के माध्यम से राहत का दावा करते हैं।

लेकिन याचिकाकर्ताओं के रास्ते में कठिनाई यह है कि ऐसा नहीं है

यह कहना संभव है कि विधान के विघटन की धमकी से

विधानसभा, याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा

एड। यह केवल तभी होता है जब किसी मौलिक अधिकार का सीधा आक्रमण होता है।

या इस तरह के आक्रमण का आसन्न खतरा कि एक याचिकाकर्ता राहत मांग सकता है

अनुच्छेद 32 के तहत। मौलिक अधिकार पर प्रभाव होना चाहिए

प्रत्यक्ष और तत्काल और अप्रत्यक्ष या दूरस्थ नहीं। सिर्फ इसलिए कि, विधान सभा के विघटन से, याचिकाकर्ताओं

सदस्य बनना बंद हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप वे हार जाते हैं

उनके वेतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि विघटन उनका उल्लंघन करेगा संपत्ति का अधिकार। यह विघटन का अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा

लेकिन यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

संपत्ति के लिए। यदि याचिकाकर्ताओं का तर्क सही था, तो भी

सिविल सेवक को कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने पर बर्खास्त किया जाता है।

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या यहाँ तक कि किसी

अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला प्राधिकरण

शिकायत करने का हकदार हो कि बर्खास्तगी के कारण, वह किया गया है

वेतन के अपने अधिकार से वंचित है और इसलिए यह उसके लिए सक्षम है

उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 के उल्लंघन के आधार पर मान्य। यह ज़रूर

संविधान निर्माताओं का इरादा कभी नहीं हो सकता था। प्रत्यक्ष

विधान सभा के विघटन की वास्तविकता यह होगी कि

याचिकाकर्ताओं का सदस्य बनना बंद हो जाएगा और जाहिर है कि किसी के पास नहीं है विधान सभा के सदस्य के रूप में बने रहने का मौलिक अधिकार।

यह सच है कि यदि याचिकाकर्ता विधानमंडल के सदस्य नहीं रह जाते हैं विधानसभा में, वे वेतन प्राप्त करने का अपना अधिकार खो देंगे, लेकिन कि

उनके लेजिस के सदस्य बने रहने का परिणाम होगा

लैटिव असेंबली और के विघटन के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं

विधान सभा। इसलिए हम हैं। इस दृष्टिकोण से कि विधान सभा के विघटन की धमकी में [1978] 1 एस. सी. आर. शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन

अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 के तहत और चूंकि कोई अन्य मौलिक अधिकार नहीं है: याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, यह माना जाना चाहिए कि वे हैं

अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को बनाए रखने का हकदार नहीं है।

यह हमें सूट की रखरखाव के सवाल पर ले जाता है। वहाँ

राजस्थान, मध्य राज्यों द्वारा हमारे समक्ष छह मुकदमे दायर किए गए हैं

प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। इनमें से प्रत्येक

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे दायर किए गए हैं। यह लेख

सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है, अपवर्जन के लिए

अन्य सभी न्यायालयों में, मुकदमों की कुछ श्रेणियों के संबंध में और

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" 131. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन,

उच्चतम न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय को अपवर्जित करते हुए, किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है

((a) भारत सरकार और या उससे अधिक के बीच

राज्य; या

((b) भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच

या एक तरफ के राज्य और एक या अधिक अन्य राज्य

दूसरी ओर, या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच,

यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है

(चाहे कानून का हो या तथ्य का) जिस पर अस्तित्व या विस्तार

कानूनी अधिकार निर्भर करता है।

बशर्ते कि उक्त अधिकारिता का विस्तार एक तक नहीं होगा

सगाई, सनद या अन्य समान उपकरण जो, प्रारम्भ होने से पहले प्रवेश किया गया या निष्पादित किया गया

संविधान, इस तरह के कॉम के बाद भी चल रहा है

उल्लेख, या जो यह प्रावधान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार इस तरह के विवाद का विस्तार न करें। "

मुकदमे की प्रकृति के संबंध में दो सीमाएँ हैं जिन पर इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। एक पक्षकारों के संबंध में है और दूसरा विषय वस्तु के संबंध में है। अनुच्छेद खंड (ए), (बी) और (सी) में इतने शब्दों में प्रावधान करता है कि विवाद भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और एक तरफ किसी अन्य राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच होना चाहिए। यह किसी भी निजी पक्ष को एक या दूसरे पक्ष में विवाद के रूप में प्रस्तुत करने पर विचार नहीं करता है। विवाद के समान संबंध खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट एक या दूसरी श्रेणी के भीतर आने चाहिए। यह बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था। भारत संघ और ए. एन. आर. (1) जहाँ यह

एक विवाद जो इसके दायरे में आता है

अदालत ने कहा: अनुच्छेद 131 का निर्धारण केवल उसमें उल्लिखित मंच में किया जा सकता है।

(1) [1970] 2 एस. सी. आर 522:

राजस्थान। वी. यूनियन (भगवती, जे.)

65

अर्थात्, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बशर्ते कि किसी भी कथित विवाद में किसी भी निजी पक्ष का अनुरोध नहीं किया गया हो, चाहे वह नागरिक हो या फर्म या निगम किसी राज्य के साथ

संयुक्त रूप से या वैकल्पिक रूप से। जिस विवाद में ऐसा निजी पक्ष शामिल है, उसे इस अदालत के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए, जिसका इस मामले पर अधिकार क्षेत्र हो। यह पार्टियों के लिए सीमा है। विषय-वस्तु के संबंध में दूसरी सीमा इन शब्दों से निकलती है "यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (चाहे वह कानून या तथ्य का हो) शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है।" ये शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विवाद कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए न कि राजनीतिक योजनाओं पर विवाद जो कानूनी अधिकार पर आधारित न हो, उदाहरण के लिए, श्री सीर्वाज द्वारा पृष्ठ 1385 पर 'भारत के संविधान संबंधी कानून' पर अपने प्रसिद्ध कार्य में दिया गया एक उदाहरण लें: एक दावा है कि एक राज्य परियोजना

इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए। विवाद में, भारत सरकार या किसी राज्य के कानूनी अधिकार का दावा या पुष्टि शामिल होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। बस इतना ही आवश्यक है कि यह एक गैलन अधिकार होना चाहिए। यह सच है कि बिहार राज्य में v. भारत संघ और ए. एन. आर. (ऊपर) यह न्यायालय, विवाद के दायरे पर चर्चा करते हुए जो

उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत यह निर्धारित किया जा सकता है कि "इतना निश्चित है कि कानूनी अधिकार जो विवाद का विषय है, संविधान और उसके द्वारा स्थापित संघवाद के संदर्भ में उत्पन्न होना चाहिए।" लेकिन यह अवलोकन, जहाँ तक यह सुझाव देता है कि कानूनी अधिकार वह होना चाहिए जो संविधान के तहत उत्पन्न होता है, अनुच्छेद 131 की भाषा की तुलना में बहुत आगे जाता है। लेख केवल 'कानूनी अधिकार' की बात करता है और नहीं करता है इसे किसी भी अन्य शब्द से योग्य बनाएँ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की संबंधित धारा 204 में प्रावधान काफी अलग था। इसमें एक प्रावधान था कि विवाद अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या से संबंधित होना चाहिए। या उसके अधीन बनाए गए परिषद् के आदेश का या

उस राज्य के विलय के दस्तावेज के आधार पर संघ में निहित विधायी या कार्यकारी प्राधिकरण। इस प्रावधान को अनुच्छेद 131 में जानबूझकर और योजनाबद्ध रूप से हटा दिया गया है और अब किसी भी कानूनी अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमे द्वारा लागू किया जा सकता है बशर्ते -

पक्ष खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट चरित्र को भरते हैं। द.

जिस प्रश्न पर इसलिए निर्णय लेने में विचार करने की आवश्यकता है

मुकदमों की रखरखाव क्षमता यह है कि क्या राज्यों का कोई कानूनी अधिकार है

मुकदमों में साबित होने की मांग की। हम वर्तमान में इस पर विचार करेंगे।

प्रश्न, लेकिन ऐसा करने से पहले, हमें एक और त्रुटि इंगित करनी चाहिए

जो, सबसे बड़े सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने निर्णय लिया

बिहार राज्य का मामला बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (ऊपर) लगता है गिर गया। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे में केवल एक आदेश

जिसे उच्चतम न्यायालय निर्णय देने वाली घोषणा कर सकता था

दिए गए, अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का कार्य एक था अंत। यदि यह निष्कर्ष सही था, तो स्पष्ट रूप से वर्तमान मुकदमे

भारत सरकार को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग

अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी करने से, खंड (1) नहीं कर सका वह और समान रूप से इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती थी,

लेकिन विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अपनी सामान्य स्पष्टता के साथ

और निष्पक्षता ने स्वीकार किया कि वह इसका समर्थन करने की स्थिति में नहीं था

देखें। यह दृष्टिकोण गलत और दो बहुत अच्छे कारणों से प्रतीत होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1

978] 1 एससीआर।

66

सबसे पहले, यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि जहां भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा-204 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि संघीय न्यायालय अपनी मूल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, एक घोषणात्मक निर्णय के अलावा कोई निर्णय नहीं देगा, वहीं दिया जाने वाली राहत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाला कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 131 में नहीं पाया जाता है। अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमे में राहत देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति केवल 'घोषणात्मक निर्णय' तक सीमित नहीं है। दूसरा,

जैसा कि श्री सीरवई ने पृष्ठ 1385 पर अपनी पुस्तक में बताया है, "जब किसी अदालत को पक्षों के बीच विवाद के संबंध में स्पष्ट अधिकार क्षेत्र दिया जाता है, तो यह मानना उचित है कि अदालत के पास संपूर्ण विवाद को हल करने की शक्ति है", जब तक कि इसकी शक्ति स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ से सीमित न हो। अनुच्छेद 131 में ऐसी कोई सीमा नहीं है और इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत किसी मुकदमे में केवल एक घोषणात्मक निर्णय दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट

यदि ऐसा कानूनी अधिकार स्थापित किया जाता है तो मुकदमे में दावा किए गए कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए जो भी राहत आवश्यक है, उसे देने की शक्ति होगी।

अब इस सवाल की ओर मुड़ते हुए कि क्या वर्तमान सूट चाहते हैं

राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों पर एक नज़र डालना आवश्यक है। भाग III के प्रयोजन के लिए 'राज्य' को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 367, खंड (1) के कारण, इसका वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के तहत है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3, खंड (56) में 'राज्य' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 'संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य'। राजस्थान के राज्य,

मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य हैं और इसलिए वे संविधान के अर्थ के भीतर राज्य हैं। अनुच्छेद 1, खंड (1) घोषणा करता है कि भारत, अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा और एक राज्य अनिवार्य रूप से भारत संघ का एक घटक भाग है। संविधान के भाग VI में राज्यों के संबंध में प्रावधान हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाना है। अनुच्छेद 163 एक मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान करता है जिसके प्रमुख एक मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह दे सकते हैं, सिवाय एक के संबंध में। सीमित क्षेत्र जहाँ वह संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है या उनमें से कोई भी अपने विवेचना में। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में नए संशोधित अनुच्छेद 74, खंड (1) में है, लेकिन अब शमशेर सिंह और अन्र में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप यह अच्छी तरह से तय हो गया है। वी. पंजाब राज्य (1) कि अनुच्छेद 163 (2), 371 ए (1) (बी) और (डी) द्वारा कवर किए गए संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र को छोड़कर। 371 ए (2) (बी) और (एफ) और छठी अनुसूची, पैरा 9 (2), गवर्नर भी परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

मंत्री। यह मोटे तौर पर संबंधित प्रावधानों की योजना है -

(1) [1975 1 एस. सी. आर 814

राजस्थान वी. यूनियन (भगवती, जे.)

67

राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग। राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है और उस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल और विधान सभा के साथ-साथ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी शामिल है। अनुच्छेद 172 में प्रावधान है कि किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा, जब तक कि जल्द ही भंग नहीं हो जाती है, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से छह साल तक जारी रहेगी। मूल रूप से यह कार्यकाल पाँच साल का था, लेकिन 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे छह साल तक बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 233 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और यह प्रावधान करता है कि ऐसे मामले में राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि

संविधान के प्रावधान राज्य की कार्यकारी शक्ति है

राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और मिनिस की एक परिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है

राज्य के विधान-मंडल द्वारा और राज्य में विधायी शक्ति

एक आकस्मिक स्थिति जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो

राज्यपाल।

अब, यह निर्धारित करने के लिए कि किसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा

अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत धमकी भरी कार्रवाई से, हमें समर्थन करना चाहिए। इस धारणा पर जोर देना कि इस तरह की कार्रवाई, जब की जाएगी, तो नुकसान होगा

शीर्षक रूप से अमान्य, क्योंकि यदि यह वैध होता, तो कोई कारण नहीं होता

शिकायत के लिए। सवाल यह है: जिसके पास कार्रवाई का कारण होगा यदि अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत असंवैधानिक कार्रवाई की गई थी? अगर

राज्यपाल में निहित राज्य की कार्यकारी शक्ति ले ली गई थी

राष्ट्रपति या राज्य की विधायी शक्ति से दूर थे

राज्य के विधानमंडल या राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि या

संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिकार के तहत थे

विघटित-ये सभी कार्य हैं जो अनुच्छेद के तहत किए जा सकते हैं। 356 , खंड (1) कौन व्यथित होगा? क्या राज्य यह कह सकता है कि

इसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है? हमारा मानना है कि यह हो सकता है। क्या यह अधिकार नहीं है? संविधान के तहत राज्य कि उसकी कार्यकारी शक्ति होगी

राज्य के किसी भी कार्य को छोड़कर राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है

सरकार या राज्यपाल की कोई भी शक्तियाँ राज्यपाल द्वारा ग्रहण की जाती हैं। अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत शक्ति का वैध प्रयोग? है।

यह राज्य के लिए इस बात पर जोर देने के लिए सक्षम नहीं है कि उसके पास इसका अधिकार बना रहेगा। अपने कानून बनाने के लिए विधायिका, जब तक कि इसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है या यह वैध है

विघटित? क्या यह राज्य का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि उसके कानून

इसकी विधायिका द्वारा किया जाएगा, जब तक कि राष्ट्रपति घोषणा नहीं करता है

अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत शक्ति का अधिकार, कि राज्य का विधानमंडल लेखक द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाएगा।

संसद का अधिकार? संविधान के तहत राज्य के ये अधिकार

अनुच्छेद के तहत शक्ति के अमान्य प्रयोग से निश्चित रूप से प्रभावित होगा

356 , खंड (1)।

सरकार की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

भारत सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 131 में 'राज्य' अभिव्यक्ति है 'राज्य सरकार' का पर्याय नहीं है और इसके आंतरिक प्रमाण हैं

लेख में कहा गया है कि दोनों अलग हैं। जब के कार्य राज्य सरकार असंवैधानिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती है, यह

क्या राज्य सरकार व्यथित होगी न कि राज्य।

[1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68

किसी राज्य में किसी विशेष मंत्री परिषद द्वारा शासित होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसा तब भी होता है जब कोई विधान सभा भंग हो जाती है। यह सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार है जो प्रभावित हो सकता है न कि राज्य का अधिकार। विधान सभा की चर्चा है राज्य के विघटन के समान नहीं है, ताकि राज्य में कार्रवाई का कारण बन सके। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि यदि राज्य के राज्यपाल या विधान सभा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो यह राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राज्य संविधान के तहत एक राज्यपाल और एक विधान सभा का हकदार है, लेकिन उनका तर्क था कि केवल राज्य सरकार की शक्तियों को ग्रहण करना या विधानमंडल से राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति को छीनना और इसे संसद के अधिकार से या उसके तहत प्रयोग करने योग्य बनाना या विधान सभा को भंग करना राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यह विवाद अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

यह सच है कि 'राज्य' और 'राज्य सरकार' के बीच अंतर है।

और यह भेद अनुच्छेद 131 की भाषा से भी स्पष्ट है और इसलिए, उस अनुच्छेद की प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या राज्य सरकार से अलग राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अब, निस्संदेह, किसी राज्य को इस बात पर जोर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि उसके पास विधान सभा के सदस्यों के रूप में एक विशेष मंत्रिपरिषद या विशेष व्यक्ति होंगे। लेकिन संविधान के तहत किसी राज्य को निश्चित रूप से यह कहने का अधिकार है कि उसकी कार्यकारी और विधायी शक्तियों

का उपयोग संविधान में दिए गए तरीके से किया जाएगा। यदि यह कहा जा सकता है कि किसी राज्य की विधान सभा को समाप्त करने पर उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो यह देखना मुश्किल है कि जब विधान सभा को समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो कोई अन्य निर्णय कैसे हो सकता है। पहले मामले में, राज्य असंवैधानिक रूप से अपने विधायी अंग से वंचित है और इसकी विधायी शक्ति पत्र में किसी अन्य प्राधिकरण को दी गई है, संवैधानिक रूप से नियुक्त अंग बना रहता है लेकिन इसे उस अवधि के लिए अप्रभावी बना दिया जाता है जिसके दौरान विधायी शक्ति असंवैधानिक रूप से किसी अन्य प्राधिकरण में निहित होती है। जहाँ तक राज्य का संबंध है, हम दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं देख पा रहे हैं। स्थिति वही है चाहे विधायी शक्ति के प्रयोग के लिए संवैधानिक रूप से नियुक्त अंग को काट दिया जाए या लकवाग्रस्त कर दिया जाए। यदि एक राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है, तो दूसरा भी उतना ही करता है। यह हो सकता है कि यदि किसी विधान सभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है और अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत आकस्मिक कार्रवाई के कारण संसद द्वारा या उसके तहत राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तो विधान सभा के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के कानूनी अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग कई व्यक्तियों के अधिकारों को हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह न केवल विधान सभा के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए राज्य के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन कर सकता है कि संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक ढांचे के संघीय आधार का अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत असंवैधानिक हमले से उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इसलिए हमारा विचार है कि राजस्थान बनाम संघ (भगवती, जे.)

69

कि वर्तमान मुकदमे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले राज्यों के कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रयास करते हैं और मुकदमों को अनुच्छेद 131 के दायरे और दायरे से बाहर होने के कारण सीमित नहीं किया जा सकता है। हमें गुण-दोष के आधार पर मुकदमों पर विचार करना चाहिए।

महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है

गुण-दोष के आधार पर यह बताया जाता है कि अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत शक्ति का दायरा और दायरा क्या है। क्या राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य विधानमंडल को

भंग कर सकते हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या इस शक्ति पर कोई सीमाएँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अनुच्छेद 356 के विभिन्न खंडों की योजना और भाषा और उस उद्देश्य और उद्देश्य की जांच करना आवश्यक है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 356 भाग XVIII में आता है जिसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद शामिल हैं जो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं। हममें से एक (जे. भगवती) के पास अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम में इंगित करने का अवसर है। एस. एस. शुक्ला (1) कि तीन प्रकार की आपात स्थिति हो सकती है

एक राष्ट्र के जीवन में संकट। पहला वह है जहां देश की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रामकता से खतरा है: दूसरा खतरे या आंतरिक अशांति की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है जिसकी गणना की जाती है

देश के जीवन को बाधित करता है और स्थायी सरकार के अस्तित्व को खतरे में डालता है और तीसरा अवसर तब आता है जब अर्थव्यवस्था टूट जाती है या संभावित रूप से टूट जाती है जिससे देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होता है। पहले दो प्रकार के आपातकाल से अनुच्छेद 352 में निपटा गया है, जबकि तीसरे प्रकार से निपटा गया है

संतुष्ट है कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत की सुरक्षा या इसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा है, चाहे वह युद्ध से हो या बाहर से

अवैध आक्रामकता या आंतरिक अशांति, वह घोषणा द्वारा, उस आशय की घोषणा करें और उस अनुच्छेद के खंड (2) के लिए आवश्यक है

कि ऐसी घोषणा प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी

संसद और "यह दो की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी।

महीनों तक जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे मंजूरी नहीं दी गई हो संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा "। संवैधानिक

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के निहितार्थ। खंड

(1) विशाल हैं और वे अनुच्छेद 250,353,354,358 में प्रदान किए गए हैं और

359. आपातकाल एक असाधारण स्थिति है, जो एक से उत्पन्न होती है

राष्ट्रीय संकट, कुछ व्यापक और व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं

केंद्र सरकार और संसद पर इसका मुकाबला करने की दृष्टि से

स्थिति और सामान्य स्थितियों को बहाल करें। ऐसी ही एक शक्ति यह है कि

अनुच्छेद 250 द्वारा जो यह प्रावधान करता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान

यदि संसद चल रही है, तो उसके पास कानून बनाने की शक्ति होगी

भारत के किसी भी क्षेत्र के संबंध में भारत के पूरे या किसी भी भाग में

राज्य सूची में सूचीबद्ध मामले। इस प्रावधान का प्रभाव है -

कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित संघीय संरचना को बाहर रखा गया है

अभी के लिए कार्रवाई। इसी तरह की एक और शक्ति यह है कि

अनुच्छेद 353 द्वारा प्रदत्त जो कहता है कि उस समय के दौरान प्रोक्ला

आपातकाल लागू है। संघ की कार्यकारी शक्ति

संघीय सिद्धांत से भी अवहेलना करता है जो आधार बनाता है संविधान। के संवैधानिक सिद्धांत से यह विचलन

असाधारणता के कारण संविधान द्वारा संघवाद की अनुमति दी गई है

(1) [1976) सप. एस. सी. आर 172

संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार के निरंतर अस्तित्व के लिए खतरे से उत्पन्न होने वाली स्थिति। फिर हम अनुच्छेद 355 पर आते हैं जो संघ को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य देता है कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न होने वाली एक अन्य प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के प्रावधान हैं और जहां तक सामग्री की बात है, वह इस प्रकार है:

" 356. (1) यदि राष्ट्रपति से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर

किसी राज्य के राज्यपाल या अन्यथा, संतुष्ट हैं कि एक स्थिति

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति घोषणा द्वारा

(ए) के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं मान लें

राज्य सरकार और सभी या कोई भी शक्तियाँ राज्यपाल या किसी निकाय में निहित या प्रयोग करने योग्य

या विधानमंडल के अलावा राज्य में प्राधिकरण

राज्य;

(ख) यह घोषणा करता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ

के अधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाएगा

संसद,

(ग) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान बनाएँ जैसे -

राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होता है

घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाना, में

पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबन के लिए प्रावधान

इस संविधान के किसी भी प्रावधान का संचालन

राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित;

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को प्राधिकृत नहीं करेगी

उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करना, या किसी प्रोव के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करना। उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान का गठन।

(2) ऐसी किसी भी घोषणा को निरस्त या बदला जा सकता है।

बाद की घोषणा द्वारा।

(3) इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक घोषणा रखी जाएगी।

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष और, सिवाय जहां वह

पिछली उद्घोषणा को निरस्त करने वाली उद्घोषणा है, बंद करें

दो महीने की समाप्ति पर काम करना जब तक कि पहले न हो

उस अवधि की समाप्ति जिसे संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया है

संसद के दोनों सदनों की स्थिति:

*

(5) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद,

अंतिम और निर्णायक होगा और किसी भी मामले में पूछताछ नहीं की जाएगी। किसी भी आधार पर अदालत। राजस्थान बनाम.

यूनियन (भगवती, जे.)

71

चूँकि अनुच्छेद 357, खंड (1) पर रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से कुछ निर्भरता रखी गई थी, हम इन शर्तों में उस खंड के प्रासंगिक भाग को पुन: प्रस्तुत करेंगे:

1 357। (1) जहाँ खंड के अधीन जारी की गई उद्घोषणा द्वारा

(1) अनुच्छेद 356 के अनुसार यह घोषित किया गया है कि

राज्य का विधानमंडल इसके द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जा सकेगा।

संसद का अधिकार, यह सक्षम होगा

(ग) राष्ट्रपति के लिए लोक सभा को अधिकृत करने के लिए राज्य की संचित निधि से सत्र व्यय में नहीं है, जब तक कि इस तरह के व्यय की मंजूरी नहीं दी जाती है

संसद "।

अब अनुच्छेद 356, खंड (1) की भाषा के एक स्पष्ट स्वाभाविक निर्माण पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति इस खंड के तहत कार्रवाई तभी कर सकता है जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा दी

गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का यह संतोष कि "ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, एक पूर्ववर्ती शर्त है जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। जब यह पूर्व शर्त पूरी हो जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत कार्रवाई कर सकता है और उपखंड में निर्दिष्ट सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उस खंड के खंड (ए), (बी) और (सी)। इन शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से संघीय सिद्धांत की जड़ पर हमला करता है।

क्योंकि यह राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित करता है, जो संविधान द्वारा स्थापित संघीय संरचना में, राज्यपाल द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति में प्रयोग की जा सकती है और राज्य के विधानमंडल की शक्तियों को छीन लेती है और वे संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं। राज्य का विज्ञापन मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए लिया जाता है जिसका अर्थ है अनुच्छेद 74, खंड (1) के कारण प्रभावी और सार रूप में केंद्र सरकार और अन्यथा भी, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है और राज्य की विधायी शक्ति भी संसद को हस्तांतरित की जाती है। राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भी भंग कर सकता है, क्योंकि जब वह अनुच्छेद 356, खंड (1) उपखंड (ए) के तहत राज्यपाल की सभी शक्तियों को अपने पास ग्रहण करता है, तो उसके द्वारा ग्रहण की गई शक्तियों में से एक अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विधानसभा को भंग करने की शक्ति होगी। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 356, खंड (1) में अधिनियमित संघवाद के सिद्धांत में गंभीर प्रवेश करता है

संविधान और इसकी अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, और इसलिए, जब राष्ट्रपति को पता चलता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को चलाया नहीं जा सकता है, तो वह अनुच्छेद के तहत कार्य कर सकता है। 356 सी. एल. (1) वास्तव में यह

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72

ऐसा करना और संघीय व्यवस्था स्थापित करना उनका संवैधानिक दायित्व होगा

जहाँ तक उस राज्य का संबंध है, तंत्र कार्रवाई से बाहर है। यह है।

वास्तव में एक बहुत ही कठोर शक्ति, जिसका यदि दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, तो वह नष्ट कर सकती है।

संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन और

इसके नुकसान की संभावना को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया था। डॉ. अम्बेडकर ने बहस को समाप्त करते हुए अपने भाषण में संकेत दिया

इस लेख पर:

" मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से इनकार नहीं करता कि वहाँ है

इन लेखों के दुरुपयोग या उपयोग की संभावना

राजनीतिक उद्देश्य। लेकिन आपत्ति हर हिस्से पर लागू होती है।

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह के लेख कभी नहीं होंगे। ऑपरेशन में बुलाया जाएगा और वे एक मृत बने रहेंगे

पत्र। अगर उन्हें ऑपरेशन में लाया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि

राष्ट्रपति, जो इन शक्तियों से संपन्न हैं, लेंगे वास्तव में प्रशासकों को निलंबित करने से पहले उचित सावधानी बरतें

प्रांतों का वर्गीकरण "।

लेकिन इस अनुच्छेद में छिपे खतरे के बावजूद, संविधान निर्माता

सोचा कि कॉन्स्टी के टूटने के मामले में कोई विकल्प नहीं था

राज्यों में शिक्षण तंत्र और इसलिए उन्होंने इस अनुच्छेद को अपनाया,

भले ही यह घृणित धारा 93 के समान था जो विकृत हो गई थी

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रतीक है।

राष्ट्रवादी आकांक्षाओं पर। संविधान निर्माता, जागरूक

के रूप में

वे इस शक्ति के प्रयोग से बहने वाले गंभीर परिणामों के थे, इस शर्त के साथ अपने अभ्यास की रक्षा करके इसे सीमित कर दिया कि

राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाए

अब, जब पूर्ववर्ती को सीमित करने की शर्त की संतुष्टि पर

शक्ति के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा जारी की जाती है

अनुच्छेद 356, खंड (1), इसे अनुच्छेद 356 के खंड (2) के तहत बाद की घोषणा द्वारा किसी भी समय निरस्त या बदला जा सकता है। खंड

(3) अनुच्छेद 352 के खंड (2) की तरह, अनुच्छेद 356 के लिए आवश्यक है कि अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक घोषणा

संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और यह

दो महीने की समाप्ति पर काम करना बंद कर देता है जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले, इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 356, खंड (3) में अधिनियमित प्रावधान से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा कारण (1) के तहत शक्ति का प्रयोग संसद के दोनों सदनों के नियंत्रण के अधीन है। अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा पूर्व में लागू नहीं होगी।

जब तक इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से पहले राज्य की विधान सभा को भंग करने जैसी कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अन्यथा संसदीय नियंत्रण पराजित हो जाएगा और

} , राजस्थान वी. यूनियन (भगवती, जे.)

केंद्र सरकार के लिए यह संभव होगा कि वह एक तथ्य प्रस्तुत करे संसद के दोनों सदनों को पूरा करना और कोई भी सदन इस गड़बड़ी को दूर करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह घोषणा को अस्वीकार कर दे। इसके अलावा, संसद का कोई भी सदन अस्वीकार कर सकता है

दो महीने की समाप्ति से पहले भी घोषणा और जहां ऐसा होता है, राष्ट्रपति घोषणा को तुरंत रद्द करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि घोषणा संसद के किसी भी सदन की इच्छा की अवहेलना करते हुए "सदन के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को नष्ट किए बिना" जारी नहीं रह सकती है। . यह भी आग्रह किया गया कि दो महीने की अवधि के दौरान, घोषणा के आधार पर किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो एक अंतिम और अपरिवर्तनीय परिणाम लाएगा, अगर राष्ट्रपति के पास यह मानने का कारण है कि संसद का कोई भी सदन इसे मंजूरी नहीं दे सकता है, या संसद के दोनों सदनों का नियंत्रण पूरी तरह से शून्य हो जाएगा और

कार्यपालिका संसद के दोनों सदनों को पारित करके विधान सभा को भंग करने जैसी अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने में सक्षम होगी और

उनकी इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। यह स्पष्ट रूप से इसके विपरीत होगा

लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत। रिलायंस भी था

अनुच्छेद 357, खंड (1), उपखंड (सी) पर रखा गया था और यह इंगित किया गया था

कि जिसके द्वारा खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा घोषित किया कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां लागू होंगी

संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत देय, कोई व्यय नहीं

राज्य की समेकित निधि बिना अनुमोदन के खर्च की जा सकती है संसद द्वारा की गई प्राथमिकता, लेकिन जब लोक सभा नहीं है

सत्र में राष्ट्रपति मंजूरी मिलने तक इस तरह का खर्च उठा सकते हैं।

संसद द्वारा। इसका मतलब है कि अगर लोक सभा में है

उद्घोषणा जारी किए जाने के समय या जितनी जल्दी हो सके सत्र

उद्घोषणा के जारी होने के बाद सभाएँ, राष्ट्रपति करेंगे

खर्च की मंजूरी के लिए तुरंत संसद जाना होगा और यदि संसद मंजूरी नहीं देती है, तो खर्च अनाधिकृत होगा।

और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।

इस प्रकार राष्ट्रपति पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण है, अर्थात, केंद्र सरकार, पर्स के माध्यम से और इसलिए इस अवधि के दौरान

दो महीने के लिए, राष्ट्रपति व्यय से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं

राज्य की संचित निधि से बाहर निकालना जब तक कि वह आश्वस्त न हो कि इस तरह के खर्च को संसद द्वारा मंजूरी दी जाएगी। द.

सुझाव यह था कि चूंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं है राज्यसभा में, राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी नहीं कर सकते हैं

उसे खर्च से जुड़े कार्यों के निर्वहन के लिए बढ़ाना

राज्य की समेकित निधि। इन तर्कों का पक्ष से आग्रह किया गया

याचिकाकर्ताओं ने खंड (1) से (3) के निर्माण का प्रश्न उठाया है।

अनुच्छेद 356।

अब, यदि हम अनुच्छेद के खंड (1) से (3) की भाषा को देखें

356 यह स्पष्ट है कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा वैध रूप से जारी की जाती है।

खंड (1) के तहत इसका तत्काल बल और प्रभाव होता है और इसका प्रभाव होता है। पार के दोनों सदनों की मंजूरी पर निर्भर नहीं किया जाता है

देनदारी। अनुच्छेद 356 के किसी भी खंड या किसी भी खंड में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अन्य अनुच्छेद कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होगी

खंड (1) के अधीन उद्घोषणा जारी करना जब दोनों में से कोई एक या दोनों सदन

राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने की शक्ति यह है कि उसे इस बात से संतुष्ट रहें कि राज्य सरकार को [1978] 1 एस. सी. आर. पर नहीं चलाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। कहाँ का राष्ट्रपति इतने संतुष्ट हैं, और, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राष्ट्रपति का अर्थ है

केंद्र सरकार, वह एक घोषणा जारी कर सकता है, तब भी जब दोनों

या संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति को यह दिया जाता है

शक्ति क्योंकि तत्काल कार्रवाई करनी पड़ सकती है जब एक पूर्व

संविधान के टूटने के कारण आकस्मिक स्थिति पैदा हो गई है

राज्य में राष्ट्रीय तंत्र। यह एक आपातकालीन शक्ति है और इसमें

और संविधान को टालने या उसका मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है राज्य में राष्ट्रीय विघटन और इसके अलावा एक संवैधानिक बाध्यता

संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कार्रवाई करने में कोई भी देरी संभावित मामलों में निराश कर सकती है

राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य और उद्देश्य।

ऐसे मामलों में शीघ्रता प्रभावशीलता का सार हो सकती है और कार्रवाई में देरी के कारण पब लाइसेंस ब्याज प्रभावित हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति इस शर्त से सीमित नहीं है कि इसका प्रयोग संसद के किसी भी या दोनों सदनों के सत्र के दौरान नहीं किया जा सकता है। फिर, अनुच्छेद 356 के खंड (3) में यह प्रावधान है कि खंड (1) के तहत जारी की गई घोषणा दो महीने की समाप्ति पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। इसका मतलब है कि यह दो महीने की अवधि के लिए काम करना जारी रखेगा, जब तक कि इसे जल्द ही रद्द नहीं कर दिया जाता। यह केवल दो महीने से अधिक के विस्तार के उद्देश्य से है कि संसद के दोनों सदनों की मंजूरी अनुच्छेद 356 के खंड (3) द्वारा आवश्यक है। अगर

ऐसी कोई मंजूरी आने वाली नहीं है, घोषणा दो महीने की समाप्ति के बाद जारी नहीं रह सकती है, लेकिन तब तक यह निश्चित रूप से जारी रहती है और इसका पूरा बल और प्रभाव होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 356 का खंड (3) यह नहीं कहता है कि घोषणा केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन पर ही लागू होगी, और न ही यह प्रावधान करता है कि

संसद के किसी भी सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर दो महीने की समाप्ति से पहले भी इसका संचालन बंद हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के खंड (3) की भाषा की तुलना अनुच्छेद 123 से करना दिलचस्प है। खंड (2) इस संबंध में, अनुच्छेद 123, खंड (1) राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं और उस अनुच्छेद के खंड (2) में प्रावधान है कि ऐसा अध्यादेश "संसद की पुनः सभा से छह सप्ताह की समाप्ति पर लागू नहीं होगा, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा उन प्रस्तावों में से दूसरे के पारित होने पर पारित किए जाते हैं"। यह अध्यादेश संसद की पुनः सभा से छह सप्ताह की समाप्ति तक जारी रहेगा जब तक कि उस तारीख से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है। लेकिन कब?

हम।

अनुच्छेद 356 के खंड (3) पर आते हुए, हम पाते हैं कि खंड (1) के तहत जारी की गई घोषणा के जीवन के संबंध में एक अलग योजना उस खंड में अपनाई गई है। अनुच्छेद 356 का खंड (3) संसद के दोनों सदनों को दो महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अस्वीकृति द्वारा घोषणा को समाप्त करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है और यह केवल तभी होता है जब घोषणा का जीवनकाल दो महीने की अवधि से आगे बढ़ाया जाता है जिसे दोनों राजस्थान बनाम संघ (भगवती, जे.) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

75

अतः संसद के सदनों में यह स्पष्ट है कि दो महीने की समाप्ति से पहले संसद के किसी भी सदन द्वारा अस्वीकृति की घोषणा के जीवन के लिए कोई संवैधानिक प्रासंगिकता नहीं है और इस तरह की अस्वीकृति के बावजूद घोषणा दो महीने की अवधि तक लागू रहेगी।

इस चर्चा से यह स्पष्ट होगा कि कब कोई घोषणा की जाएगी।

अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा वैध रूप से जारी किया जाता है, इसका तत्काल बल और प्रभाव होता है, जिस क्षण इसे जारी किया जाता है और जहां, घोषणा द्वारा, राष्ट्रपति ने उपखंड (ए) के तहत राज्यपाल की शक्तियों को अपने पास ग्रहण कर लिया है, वह उन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल के रूप में पूरी तरह से और प्रभावी रूप से करने का हकदार

है, दो महीने की अवधि के दौरान जब घोषणा लागू होती है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद द्वारा कोई सीमा नहीं लगाई गई है कि ये शक्तियाँ

राज्यपाल का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा तभी किया जा सकता है जब उनके पास

कोई अपरिवर्तनीय अनुक्रम नहीं और जहां उनका ऐसा परिणाम होता है, जब तक घोषणा दोनों द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाती, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

संसद के सदन। जबकि घोषणा के दौरान लागू है

दो महीने की अवधि में राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

उनके द्वारा ग्रहण किए गए राज्यपाल और न्यायालय किसी भी सीमा को नहीं पढ़ सकते हैं।

जो चौड़ाई को कम करने का प्रभाव डालेगा और

ऐसी शक्तियों का विस्तार उनके अभ्यास को केवल उन्हीं तक सीमित करके

ऐसे मामले जहां कोई अपरिवर्तनीय परिणाम यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि

मरम्मत से परे। जब राज्यपाल की कोई शक्ति ग्रहण की जाती है

उद्घोषणा के तहत राष्ट्रपति, दोनों के दौरान कर सकते हैं जिन महीनों में घोषणा लागू होती है, राज्यपाल जो कुछ भी करें

इस तरह की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और यह मायने नहीं रखेगा कि क्या ऐसी शक्ति के प्रयोग का परिणाम अंतिम और अपरिवर्तनीय है या

नहीं। अन्यथा धारण करना पूर्ण प्रभाव देने से इनकार करना होगा

घोषणा जो जैसा कि ऊपर बताया गया है, के साथ काम करना जारी रखता है दो महीने की अवधि के दौरान पूर्ण बल और शक्ति। यह होगा

अनुच्छेद 356 का पुनर्लेखन और पार्लिया के दोनों सदनों का अनुमोदन करना

घोषणा के लागू होने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त

जहाँ तक विशेष शक्ति का संबंध है। अब एक

राज्यपाल की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जा सकती हैं

घोषणा विधान सभा को भंग करने की शक्ति है

कला के तहत राज्य का। 174 (2) ((ख) और इसलिए राष्ट्रपति भी

उस समय के दौरान विधान सभा को भंग कर सकते हैं जब प्रो

क्लैमेशन लागू है। यह देखना मुश्किल है कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है।

राष्ट्रपति द्वारा शक्ति को अनुमोदन पर सशर्त बनाया जा सकता है

संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा। अगर घोषणा

यह दो महीने की अवधि के दौरान पूरी ताकत और प्रभाव रखता है

संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बिना, राष्ट्रपति

लेजिस को भंग करने के लिए राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना राज्य की स्थानीय विधानसभा

संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा। यह सच है कि एक बार

राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा को भंग कर दिया जाता है

घोषणा के तहत उसके द्वारा ग्रहण की गई शक्ति, यह असंभव होगा

यदि घोषणा द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए

इस बात पर संदेह है कि घोषणा के लागू होने के समय के दौरान यह अधिकार था। यह स्पष्ट रूप से एक आवश्यक शक्ति है क्योंकि वहाँ हो सकता है

6-

722 एससीआई 77 [1978] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76

ऐसे मामले जहां विधान के विघटन की शक्ति का प्रयोग

स्थिति को सुधारने के लिए सभा अनिवार्य हो सकती है

संवैधानिक तंत्र के टूटने के कारण उत्पन्न

राज्य और इस शक्ति का तुरंत प्रयोग करने में विफलता निराश कर सकती है

घोषणा का मूल उद्देश्य और उद्देश्य

के तहत

अनुच्छेद 356, खंड (1)। इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क, रिट याचिकाओं में कि दोनों द्वारा घोषणा के अनुमोदन से पहले दो महीने की अवधि के दौरान

संसद के सदन, कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं, जैसे कि

राज्य की विधान सभा, राष्ट्रपति द्वारा ली जा सकती है। द.

राष्ट्रपति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाए कि घोषणा हो सकती है संसद के एक या दूसरे सदन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा। में

सबसे पहले, एक संवैधानिक शक्ति का अस्तित्व या इसकी वैधता

इसके अभ्यास को संभावित महाद्वीप के संदर्भ से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

जेन्सी। न्यायालय अनुमान के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता है और अनुमान नहीं लगा सकता है कि दो महीने की समाप्ति पर स्थिति क्या होगी-क्या घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा या नहीं। दूसरा, यह पूरी तरह से महत्वहीन है कि घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है या नहीं।

क्योंकि भले ही इसे इस तरह से अनुमोदित नहीं किया जाता है, यह दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी और प्रभावी बना रहेगा, जब तक कि इसे जल्द से जल्द रद्द नहीं किया जाता है। यह समझना भी मुश्किल है कि अनुच्छेद 357, खंड (1), उपखंड (सी) संभवतः याचिकाकर्ताओं के तर्क की सहायता कैसे कर सकते हैं। उस उपखंड में प्रावधान किया गया है कि जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति संसद द्वारा इस तरह के व्यय की मंजूरी की प्राप्ति तक राज्य की कन्सोली दिनांकित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप, यह संभव है कि -

संसद इस तरह के खर्च को मंजूरी नहीं देती है, गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक संभावना है जो राजनीति की व्यावहारिक वास्तविकता में शायद ही उत्पन्न

होगी और यह हमें अनुच्छेद 356 की भाषा पर रखने से विचलित करने की आवश्यकता नहीं है जो इसकी भाषा की एकमात्र सही व्याख्या है। जब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर घोषणा जारी करता है। यह तर्कसंगत है कि लोक सभा, जिसमें केंद्र सरकार को प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं, राज्य की संचित निधि से व्यय को मंजूरी देगी। इसलिए, हमारा विचार है कि दो महीने की अवधि के दौरान भी, संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा की मंजूरी के बिना, राष्ट्रपति घोषणा के तहत राज्यपाल द्वारा ग्रहण किए गए अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं।

यह अनुच्छेद 356 के खंड (1) और (3) की सही संवैधानिक व्याख्या है जो इन खंडों की भाषा और संदर्भ और सेटिंग द्वारा निर्देशित है जिसमें वे होते हैं। पहली नज़र में यह शर्मनाक लग सकता है कि यह संवैधानिक व्याख्या घोषणा और उसके तहत शक्तियों के प्रयोग के मुद्दे पर संसदीय केंद्र को पूरी तरह से समाप्त कर देगी और केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन को संभालने और विधानसभा को पंगु बनाने या भंग करने के लिए स्वतंत्र होगी, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि संसद का एक या दूसरा सदन इसे मंजूरी न दे। लेकिन यह आशंका राजस्थान बनाम।

यूनियन (भगवती, जे.)

77

किसी भी अनुचित चिंता का कारण बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग की संभावना पर आधारित है। यह याद रखना चाहिए कि केवल इसलिए कि कभी-कभी सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, यह शक्ति के अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता अभी तक ऐसी सरकार की कल्पना करने में सक्षम नहीं हुई है जिसके पास अपनी सभी वैध जरूरतों का जवाब देने के लिए पर्याप्त शक्ति हो और साथ ही शरारत करने में असमर्थ हो। अंतिम विश्लेषण में, बहुत कुछ प्रशासन के प्रभारी लोगों की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र और प्रबुद्ध और सतर्क जनमत की आवश्यकता पर निर्भर होना चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि यदि संसद का कोई भी सदन अस्वीकार करता है तो काफी जटिलता और असाधारण परिणामों की एक तीखी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

घोषणा और इसलिए, राजनीतिक और व्यावहारिक ज्ञान

उच्चतम क्रम और अत्यधिक चिंता की चौकसी

अनिवार्य रूप से प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार को सूचित करें अनुच्छेद 356, खंड (i) द्वारा प्रदत्त भारी शक्ति। इसके अलावा,

यह याद रखना चाहिए कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का सिद्धांत

संसद हमारी सरकार की लोकतांत्रिक संरचना के मूल में स्थित है।

और केंद्र सरकार अपने सभी कार्यों के लिए पार के प्रति जवाबदेह है

दायित्व जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हों और यदि

केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जो अनुचित हो या

निश्चित रूप से उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए वहाँ रहें। राजनीतिक नियंत्रण अनुभव अनुचित कार्यों के खिलाफ संसद द्वारा की गई जाँच हमेशा एक हितकारी जाँच होगी।

कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग या इसका दुरुपयोग या दुरुपयोग। और

अंत में, राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियाँ, यानी केंद्रीय

सरकार, एक सीमित शक्ति होने के नाते, इसका प्रयोग, के भीतर होगा

न्यायिक समीक्षा क्षमता। ये ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आशंका कि केंद्र सरकार जानबूझकर कार्य कर सकती है या

अनुच्छेद 356, खंड (1) के तहत एक घोषणा जारी करने में लापरवाही से

संसद के दोनों सदनों को पारित करके और उनकी उपेक्षा करके।

यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या कोई निषेधाज्ञा हो सकती है

भारत संघ द्वारा इसे प्रो जारी करने से रोकने के खिलाफ मंजूरी दी गई

राज्यों की विधानसभाओं का गठन और विघटन

कला के तहत। 356 , सी. एल. ((i) इसके लिए प्राथमिक राहत का दावा किया गया है।

सूट में राज्य। इस सवाल का तर्क एक डिमरर पर दिया गया है। मानो मैदानों में किए गए कथन सही थे। हम पहले करेंगे।

धीरे-धीरे इस प्रश्न पर विचार करें, लेकिन इससे पहले, हम एक का निपटारा कर सकते हैं

केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने मुकदमों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री (इसके बाद देखें)

वादी राज्यों के रूप में लाल)। वादी राज्यों में से प्रत्येक ने मांग की है

एक घोषणा कि श्री चरण सिंह का 'निर्देश' 'असंवैधानिक' है

राष्ट्रीय, अवैध और संविधान के अधिकार से बाहर "और एक निषेधाज्ञा पुनः

भारत संघ को इस 'निर्देश' को लागू करने से प्रशिक्षित करना। हम. यह देखने में विफल रहता है कि ऐसी घोषणा या निषेधाज्ञा कैसे दी जा सकती है

अदालत। श्री चरण सिंह का 'निर्देश' और कुछ नहीं बल्कि एक सलाह है।

या प्रत्येक वादी राज्य के मुख्यमंत्री को सिफारिश करने का सुझाव दें।

राज्यपाल को संघ की विधान सभा को भंग करने के लिए

निश्चित राज्य। इसे गलत तरीके से 'निर्देश' के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें है। इसके पीछे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह हमेशा गृह [1978] 1 एस. सी. आर. के लिए खुला रहता है।

केंद्र सरकार के मंत्री को सलाह या सुझाव देना

इसका परिणाम निकलता है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि श्री चरण सिंह द्वारा जारी 'निर्देश' असंवैधानिक, अवैध या अधिकार से परे था। प्रभाव देने का भी कोई सवाल ही नहीं है ' इसलिए, 'निर्देश' और इसकी अनुपूरण को रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। 'निर्देश', यदि स्वीकार नहीं किया जाता है और लागू नहीं किया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से कला के तहत कार्रवाई के लिए एक अग्रदूत होगा। 356 , सी. एल. (I) और, वहाँ पहले, एक खतरे के संकेत के रूप में माना जा सकता है, लेकिन अपने आप में खड़े होकर, यह घोषणा या निषेधाज्ञा के लिए राज्य में कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं देता है। धमकी के खिलाफ मांगी गई राहत की ओर मुड़ना

कला के तहत शक्ति का प्रयोग। 356 , सी. एल. (I) हम पाते हैं कि इस राहत में जो प्रार्थना की गई है वह 'प्रतिवादी को रोकने वाला स्थायी निषेधाज्ञा' है। कला के तहत सहारा लेने से। 356 राज्य की विधान सभा को भंग करने के लिए भारत के संविधान का

और से

मार्च, 1978 से पहले राज्य विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कोई भी कदम उठाना। वास्तव में यह सराहना करना मुश्किल है कि इस न्यायालय द्वारा इस तरह का व्यापक और व्यापक निषेधाज्ञा कैसे दी जा सकती है।

भारत संघ को कला के तहत अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग करने से प्रशिक्षित करना। 356 , सी. एल. (आई)। इस न्यायालय द्वारा भारत संघ को राज्य के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से कैसे रोका जा सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह सुनिश्चित करना भारत संघ का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे और राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार पर भी अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करने का समान रूप से संवैधानिक दायित्व है। 356 , सी. एल. ((i) यदि वह पाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। क्या यह न्यायालय भारत संघ के खिलाफ एक व्यापक आदेश जारी कर सकता है कि राज्य में जो भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अनुच्छेद के तहत शक्ति का प्रयोग करना कितना भी आवश्यक हो सकता है। 356 सी. एल. (1) , भारत संघ मार्च, 1978 से पहले राज्य की विधान सभा को भंग करने और राज्य विधान सभा के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उस शक्ति का सहारा नहीं लेगा। यह स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्वों के उसके निर्वहन में बाधा डालेगा और इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपने तरीके से इस कठिनाई को महसूस करते हुए, वादी-राज्यों ने निषेधाज्ञा की राहत को केवल श्री चरण सिंह के 'निर्देश' में निर्धारित आधार तक सीमित रखने की मांग की और कानून मंत्री श्री शांति भूषण द्वारा उनके द्वारा आकाशवाणी पर दिए गए एक भाषण में दिए गए बयान में कहा। वादी-राज्यों के अनुसार, वह आधार यह था कि चूंकि इन राज्यों में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को मार्च 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इन राज्यों की विधानसभाओं ने मतदाताओं की इच्छाओं या विचारों को फिर से व्यक्त नहीं किया और इसलिए राजनीतिक संप्रभुता के लिए एक नई अपील आवश्यक और अनिवार्य हो गई थी और इसलिए, मतदाताओं से एक नया जनादेश प्राप्त करने के लिए इन राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। वादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह एकमात्र आधार था जिस पर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था। 356 , सी. एल. (I) और चूंकि यह मैदान पूरी तरह से बाहरी था और राजस्थान बनाम संघ (भगवती, जे.)

कला के तहत कार्रवाई करने के लिए मूल शर्त के लिए अप्रासंगिक। 356 , सी. एल. (1) , केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से इस खंड के तहत कार्रवाई करने की हकदार नहीं थी और यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकार की सीमाओं से बाहर होगी। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दो गुना जवाब देकर इस तर्क का मुकाबला किया। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि यह कहना सही नहीं है कि श्री चरण सिंह और श्री शांति भूषण द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण ही एकमात्र सामग्री है

या कला के तहत संभावित कार्रवाई के लिए आधार। 356 , सी. एल. (1) . उन्होंने आग्रह किया कि इन दोनों मंत्रियों के दृष्टिकोण की तुलना उस सलाह से नहीं की जा सकती जो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दे सकती है। 74 , सी. एल. (1) वादी-राज्यों की विधानसभाओं के विघटन के संबंध में। कला के तहत शक्ति का प्रयोग। 356 , सी. एल. (1) , यह कहा गया था, एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करता है

विभिन्न और विविध विचारों पर निर्भर करने वाली परिस्थितियाँ और यह कहना संभव नहीं है कि राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने में मंत्रिपरिषद अंततः किन आधारों पर विचार कर सकती है।

कला. 74 , सी. एल. (1) . दूसरा उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी स्थिति में मैदान

कि वादी-राज्यों की विधानसभाओं ने मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया था और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि

लोगों की इच्छा, और इसे प्रभावी बनाना, यह उचित था कि

विधानसभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए और चुनाव होना चाहिए

आयोजित, एक ऐसा मैदान था जिसका मूल संघ के साथ उचित संबंध था

कला के तहत शक्ति के प्रयोग का आह्वान करने के लिए। 356 , सी. एल. (1) और

यह एक वैध और प्रासंगिक आधार था जिसमें लिया जा सकता था

इस संतोष पर पहुँचने के लिए कि राज्य सरकार

संघ के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है

व्यवस्था। ये दलों के प्रतिद्वंद्वी विवाद थे जिन्हें हम

अब विचार के लिए आगे बढ़ना होगा।

लेकिन ऐसा करने से पहले, हमें एक दूसरे का उल्लेख करना चाहिए

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क जिसने इस प्रश्न के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करें।

दयालु। उन्होंने तर्क दिया कि सवाल यह है कि क्या किसी विशेष राज्य में

ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ राज्य सरकार नहीं हो सकती है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया और,

इसलिए, कला के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। 356 , सी. एल. (1) अनिवार्य रूप से

संविधान द्वारा संघ कार्यपालिका को सौंपा गया एक राजनीतिक प्रश्न

और उस कारण से यह न्यायालय के समक्ष न्यायोचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया

कि समस्या की राजनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह उचित नहीं है न्यायिक निर्धारण में सक्षम और इसलिए न्यायालय को इससे दूर रहना चाहिए

इसकी पड़ताल की जा रही है। हमें नहीं लगता कि हम इस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं। में से बेशक, यह सच है कि यदि न्यायालय के समक्ष लाया गया कोई प्रश्न विशुद्ध रूप से है

एक राजनीतिक प्रश्न जिसमें किसी भी कानूनी या कानूनी प्रावधान का निर्धारण शामिल नहीं है

संवैधानिक अधिकार या दायित्व, न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि

न्यायालय केवल कानूनी अधिकारों के निर्णय से संबंधित है और

देनदारियाँ। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक सवाल का राजनीतिक रंग होता है,

कि अपने आप में कोई आधार नहीं है कि न्यायालय को प्रदर्शन करने से क्यों सिकुड़ना चाहिए

संविधान के तहत अपना कर्तव्य निभाना यदि यह संवैधानिक मुद्दा उठाता है

दृढ़ संकल्प। प्रत्येक संवैधानिक प्रश्न आवंटन से संबंधित है।

और सरकारी शक्ति का प्रयोग और कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं इसलिए, राजनीतिक होने में विफल हो सकते हैं। संविधान शुद्धतम विषय है।

राजनीति, शक्ति की एक संरचना और जैसा कि चार्ल्स ब्लैक ने [1978] 1 एस. सी. आर. में बताया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

80

संवैधानिक कानून 'संवैधानिक कानून' में परिप्रेक्षय कानून और राजनीति के एक प्रतिच्छेदन का प्रतीक है, जिसमें राजनीतिक शक्ति के मुद्दे हैं -

न्यायिक में काम करते हुए, कानूनी परंपरा में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य किया गया

संस्थान, कानून की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, वकीलों की तरह सोचते हैं। यह श्री न्यायमूर्ति ब्रेनन द्वारा राय में इंगित किया गया था

बेकर बनाम में उनके द्वारा दिया गया न्यायालय। कैर, (1) अमेरिकी संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, कि "केवल इस तथ्य का कि मुकदमा एक राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा चाहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक राजनीतिक प्रश्न प्रस्तुत करता है।" इसे निक्सन बनाम में अधिक जोरदार शब्दों में रखा गया था। हर्नडन (2) ने कहा कि इस तरह की आपत्ति "शब्दों के खेल से थोड़ी अधिक है"। बेकर बनाम में निर्णय। कैर, (सुप्रा) वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति थी। इससे पहले भी बेकर बनाम। कैर। , संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतें सामान्य समझ में कई 'राजनीतिक' प्रश्नों से निपट रही थीं। यहां तक कि ब्राउन बनाम में सर्वोच्च न्यायालय का पृथक्करण निर्णय। शिक्षा बोर्ड (3) का स्पष्ट रूप से राजनीतिक रंग था। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के राजनीतिक अधिकार के संबंध में प्रश्नों का भी विचार किया और मतदान में और गोमिलियन बनाम में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ राहत के बारे में कोई संकोच महसूस नहीं किया। लाइटफुट (4), इसने ऐसा तब भी किया जब नस्लीय भेदभाव गुप्त था, एक नगरपालिका सीमा को फिर से तैयार करके हासिल किया जा रहा था ताकि लगभग सभी नीग्रो को शहर के मताधिकार से बाहर रखा जा सके, और कोई गोरा नहीं। यह सच है कि कोलेग्रोव बनाम में। ग्रीन (5) सुप्रीम कोर्ट ने इलिनोइस में कांग्रेस की असमानताओं को दूर करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उस मामले में बैठने वाले सात न्यायाधीशों में से केवल तीन ने इस आधार पर अपना निर्णय

लिया कि उनके सामने प्रस्तुत किया गया प्रश्न राजनीतिक और गैर-न्यायसंगत था और यह दृष्टिकोण प्रभावी था और सर्वोच्च न्यायालय ने बेकर बनाम मामले में तथ्य को उलट दिया। कैर। बेकर बनाम में सर्वोच्च न्यायालय। कैर ने माना कि यह संघीय न्यायालयों की क्षमता के भीतर था कि वे एक कार्रवाई का मनोरंजन करें

समान संरक्षण खंड के विपरीत विधायी जिलों को विभाजित करने वाले कानून को चुनौती देना। इस मामले ने स्पष्ट रूप से एक ऐसे विवाद का फैसला किया जो चरित्र में राजनीतिक था, अर्थात् विधायी जिलों का विभाजन, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समान संरक्षण खंड के उल्लंघन का एक संवैधानिक प्रश्न सीधे शामिल था और वह प्रश्न स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से निर्णय लेने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर था। इसलिए, यह देखा जाएगा कि केवल इसलिए कि एक प्रश्न का राजनीतिक रंग होता है, न्यायालय निराशा में अपने हाथ नहीं मोड़ सकता है और "न्यायिक हाथों को बंद" घोषित नहीं कर सकता है। जब तक कोई सवाल उठता है कि क्या संविधान के तहत किसी लेखक ने अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर काम किया है या उसे पार किया है, यह निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। वास्तव में ऐसा करना उसका संवैधानिक दायित्व होगा। यह स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है, विशेष रूप से हाल के इतिहास के संदर्भ में, कि संविधान सर्वोच्च शब्द है, जो देश का सर्वोच्च कानून है, और इसके ऊपर या उससे परे सरकार का कोई विभाग या शाखा नहीं है। सरकार का प्रत्येक अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका, अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करता है और उसे कार्य करना पड़ता है

(1) 369 यू. एस. 186 (2) 273 यू. एस. 536 (3) 347 यू. एस. 483 (4) 364 यू. एस. 339 (5) 328 यू. एस. 549

राजस्थान बनाम. यूनियन (भगवती, जे.)

81

अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर हो या कोई भी उच्च अधिकारी, यह दावा नहीं कर सकता कि वह संविधान के तहत अपनी शक्ति की सीमा का एकमात्र न्यायाधीश होगा या क्या उसकी कार्रवाई संविधान द्वारा निर्धारित ऐसी शक्ति की सीमा के भीतर है। यह न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है और इस न्यायालय को यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा गया है कि क्या

क्या सरकार की प्रत्येक शाखा को प्रदत्त शक्ति है, चाहे वह

सीमित, और यदि हां, तो सीमाएँ क्या हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती है। यह इस न्यायालय का दायित्व है कि वह इस बात को कायम रखे

संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक सीमाओं को लागू करना। कि

यह कानून के शासन का सार है। श्री न्यायमूर्ति के शब्दों को उद्धृत करने के लिए

बेकर बनाम में ब्रेनन। कैर, "यह तय करते हुए कि क्या किसी मामले में कुछ है

संविधान द्वारा एक अन्य शाखा के लिए किया गया उपाय सरकार या क्या उस शाखा की कार्रवाई किसी भी सीमा से अधिक है

अधिकार प्रतिबद्ध किया गया है, अपने आप में संविधान में एक नाजुक अभ्यास है

राष्ट्रीय व्याख्या और अंतिम रूप से इस न्यायालय की जिम्मेदारी है

संविधान के दुभाषिया "। जहाँ स्पष्ट रूप से असंबद्ध है

संविधान के तहत शक्ति का प्रयोग, यह कर्तव्य है

अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह न भूलें कि इस न्यायालय के लिए उतना ही

सरकार की अन्य शाखाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और

लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाना। अदालत का काम उन लोगों की पहचान करना है संवैधानिक योजना में मूल्य और मामलों में उन्हें जीवन में काम करने के लिए

जो अदालत तक पहुँचता है। " रणनीति और विवेकपूर्ण संयम से किसी भी तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए।

शक्ति लेकिन साहस और जिम्मेदारी की स्वीकृति का अपना स्थान है।

भी "। न्यायालय इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और न ही उसे बचना चाहिए। क्योंकि इसने संविधान के लिए विशेषाधिकार की शपथ ली है और

इस देश के लोगों के प्रति भी जवाबदेह है। वास्तव में हैं।

इस न्यायालय के कई निर्णय जहां संवैधानिक मुद्दे रहे हैं

धार्मिक सिद्धांतों के प्रश्नों में निहित होने के बावजूद,

सामाजिक प्रथाएँ, आर्थिक सिद्धांत या शैक्षिक नीतियाँ। अदालत ने

इन मामलों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मामलों पर निर्णय नहीं लिया गया है

इससे पहले और ऐसा करने में, न्यायालय इस तथ्य से विचलित नहीं हुआ है कि इन संवैधानिक प्रश्नों के ऐसे अन्य निहितार्थ हो सकते हैं या

पहलू। इसलिए, हम यह जांचने से इनकार नहीं कर सकते कि क्या कोई है।

राष्ट्रपति द्वारा किया गया संवैधानिक उल्लंघन

करने के लिए दसियों, केवल इस आसान आधार पर कि सवाल राजनीतिक है टोन, रंग या रंग में।

लेकिन जब हम यह कहते हैं, तो हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि संवैधानिक

इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल यह कहने तक सीमित है कि क्या सीमाएँ

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन किया गया है या

ऐसी सीमाओं का उल्लंघन होता है। यहाँ शक्ति पर एकमात्र सीमा है

कला के तहत राष्ट्रपति का। 356 , सी. एल. (1) कि राष्ट्रपति को करना चाहिए इस बात से संतुष्ट रहें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ सरकार

राज्य को इसके प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

संविधान। राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक होती है और

किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह जानबूझकर किया गया है

और सलाह से व्यक्तिपरक क्योंकि वह मामला जिसके संबंध में वह है

संतुष्ट होना ऐसी प्रकृति का है कि इसका निर्णय अनिवार्य रूप से होना चाहिए

सरकार की कार्यकारी शाखा को छोड़ दिया गया। एक व्यापक हो सकता है

उत्पन्न होने वाली स्थितियों की सीमा और उनके राजनीतिक निहितार्थ

और यह तय करने के लिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टें हैं, परिणामों का मूल्यांकन करना पड़ सकता है

[

1978] 1 एससीआर।

स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। यह. ए नहीं है निर्णय जो संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित हो सकता है

राज्यों ने "न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय स्थिति" के रूप में वर्णित किया है।

आईस "। यह काफी हद तक मूल्यांकन के आधार पर एक राजनीतिक निर्णय होगा विविध और विविध कारक, तेजी से बदलती परिस्थितियाँ, संभावित परिणाम

प्रश्न, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, प्रेरणाएँ और विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएँ लोगों और उनके प्रत्याशित भविष्य के व्यवहार और कई अन्य

सार्वजनिक मामलों और व्यावहारिकता के अनुभव के आलोक में विचार जटिल और अक्सर जिज्ञासु समायोजनों का टिक प्रबंधन जो

एक आधुनिक लोकतांत्रिक के अत्यधिक परिष्कृत तंत्र को बनाएँ

सरकार। इसलिए यह अपने स्वभाव से एक उपयुक्त विषय नहीं हो सकता है।

न्यायिक निर्धारण के लिए मामला और इसलिए इसे व्यक्तिपरक पर छोड़ दिया जाता है

इसे तय करें। अदालत परिस्थितियों में, प्रश्न में नहीं जा सकती है तथ्यों और परिस्थितियों की शुद्धता या पर्याप्तता जिस पर

केंद्र सरकार की संतुष्टि आधारित है। यह होगा कि

न्यायालय के लिए खतरनाक अभ्यास, दोनों क्योंकि यह एक उपयुक्त प्रशिक्षक नहीं है

इस प्रकार के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए और इसलिए भी कि न्यायालय

इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्य को हड़प लेगा और

ऐसा करने के लिए, राजनीतिक झाड़ी में प्रवेश करें, जिससे उसे बचना चाहिए यदि ऐसा करना है लोगों के साथ अपनी वैधता बनाए रखें। वास्तव में यह संभव नहीं होगा

न्यायशास्त्र की पूर्ण कमी के अलावा, न्यायालय द्वारा इस अभ्यास को करने के लिए

ऐसा करने के लिए बोलचाल, क्योंकि कला के कारण। 74 सी. एल. (2) , सवाल यह है कि

यदि कोई और यदि ऐसा है तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, और इसके अलावा, "कदम

और आशंकाएँ जो ज्ञात नहीं हैं और हमेशा नहीं की जा सकती हैं उन लोगों को पता है जो जो किया गया है उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। (वीडियो

यदि संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी पर आधारित है और अप्रासंगिक आधारों पर, न्यायालय के पास इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा,

क्योंकि उस मामले में राष्ट्रपति को उस मामले के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं होगी जिसे वह संतुष्ट करना चाहता है। राष्ट्रपति का सती गुट अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। 356 , सी. एल. (1) और यदि यह दिखाया जा सकता है कि राष्ट्रपति को कोई संतुष्टि नहीं है, तो शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से अमान्य होगा। बेशक सी. एल. के कारण। (5) कला की। 356 , राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है और किसी भी आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमले से यह प्रतिरक्षा लागू नहीं हो सकती है जहां चुनौती यह नहीं है कि संतुष्टि अनुचित या अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह है कि कोई संतुष्टि नहीं है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त संतुष्टि को चुनौती नहीं दी जाती है, बल्कि संतुष्टि के अस्तित्व को ही चुनौती दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करने का कारण देता है। 356 , सी. एल. (1) और कहते हैं कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की ऊंचाई पांच फीट से कम है और इसलिए, उनकी राय में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। क्या ऐसे मामले में राष्ट्रपति की तथाकथित संतुष्टि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह बेतुका या विकृत या दुर्भावनापूर्ण है या

(1) [1970] ए. सी. 379

यह पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधार है और इसलिए यह कोई भी गुट नहीं है। यह निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में कला के तहत शक्ति के प्रयोग को चुनौती देना असंभव नहीं तो मुश्किल होगा। 356 , सी. एल. (1) यहां तक कि इस सीमित आधार पर भी, क्योंकि जिन तथ्यों और परिस्थितियों पर संतुष्टि आधारित है, वे नहीं होंगे

ज्ञात है, लेकिन जहां यह संभव है, संतुष्टि के अस्तित्व को हमेशा इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है। इस प्रस्ताव को राजा सम्राट बनाम में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के निर्णय से समर्थन प्राप्त होता है। बनवारी लाल सरमा (1) जहाँ विस्काउंट

साइमन, एल. सी. ने सहमति व्यक्त की कि गवर्नर जनरल को यह घोषणा करते हुए कि आपात स्थिति मौजूद है, ईमानदारी से और अपने वैधानिक के अनुसार कार्य करना चाहिए। शक्तियाँ। यह संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र है जिसमें कला के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 356 , सी. एल. (1) न्यायिक समीक्षा के अधीन है और अलग है

इससे, यह न्यायालय के पास संतुष्टि को चुनौती देने के लिए नहीं रह सकता है राष्ट्रपति ने कहा कि था में स्थिति पर विचार किया गया: खंड मौजूद है।

आइए अब हम तथ्यों की ओर मुड़ें और उनके प्रकाश में उनकी जांच करें

यदि यह सकारात्मक रूप से स्थापित किया जा सकता है (1) कि प्रस्तावित कार्रवाई कला के तहत राष्ट्रपति। 356 , सी. एल. (1) केवल इस पर आधारित होगा

इस आधार पर कि वादी-राज्यों की विधानसभाओं के पास है

मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया और इसलिए उन्हें, लोगों को चुनाव करने का अवसर देने की दृष्टि से भंग किया जाए

उनके सच्चे प्रतिनिधि और (2) कि यह आधार पूरी तरह से बाहरी है

और उस प्रश्न के लिए अप्रासंगिक जिसके लिए राष्ट्रपति को विचार करना है अपेक्षित संतुष्टि तक पहुँचने का उद्देश्य, वादी-राज्य

भारत संघ के खिलाफ निषेधाज्ञा का मामला हो सकता है। लेकिन हम।

डरते हैं कि इन दोनों प्रस्तावों में से किसी को भी नहीं कहा जा सकता है

वर्तमान सूट में स्थापित।

री: प्रस्ताव 1: तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

वादी का-यह आधार बताता है कि विधान सभाएँ

वादी का-राज्यों ने लोगों का जनादेश खो दिया है और अब नहीं

निर्वाचकों की इच्छा को प्रतिबिंबित करना एकमात्र आधार है जिस पर अध्यक्ष: कार्य करेगा, यदि वह शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है

कला. 356 , सी. एल. (1) , जो, हमारे आदेश के बाद

29 अप्रैल, 1977 में उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है। यह सच है कि यह जमीन है

श्री चरण सिंह के 'निर्देश' में उल्लिखित और श्री शांति भूषण, लेकिन यह चरम पर खतरनाक होगा

इस धारणा पर आगे बढ़ें कि इससे पहले यह एकमात्र आधार होगा

मंत्रिपरिषद जब यह विचार करती है कि क्या लेना है या नहीं

कला के तहत कार्रवाई। 356 , सी. एल. (1) . इससे पहले अन्य आधार हो सकते हैं

मंत्रिपरिषद जिसे श्री द्वारा व्यक्त नहीं किया गया हो सकता है

चरण सिंह और श्री शांति भूषण। यह भी संभव है कि ए

तेजी से बदलती स्थिति, नए आधार तब तक उभर सकते हैं जब तक

मंत्रिपरिषद इस प्रश्न पर विचार करती है और ये आधार हो सकते हैं -

मंत्रिपरिषद को कला के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए राजी करें।

356 , सी. एल. (1) . न्यायालय व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की बराबरी नहीं कर सकता है।

श्री चरण सिंह और श्री शांति भूषण की सलाह से

मंत्रिपरिषद और न ही न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा

(1) 72 आई. ए. 57.

एफ.

एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84

[1978] 1 एस सी आर।

ए.

वे आधार जो अंतत: मिनिस की परिषद के साथ वजन करेंगे

टर्स। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह एकमात्र आधार संदर्भ नहीं है श्री चरण सिंह के निर्देश में लाल। उसके बाद भी

वादी में सत्तारूढ़ दल से संबंधित उम्मीदवार-राज्यों, इंगित किया बाहर:

बी.

अनिश्चितता का परिणामी माहौल गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मतभेद की भावना। बड़े पैमाने पर लोग अब औचित्य की सराहना करते हैं

एक पार्टी की सत्ता में निरंतरता जो अचूक रही हो

मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अनिश्चितता का माहौल,

भेदभाव और अनादर ने पहले ही गंभीर स्थिति पैदा कर दी है

सी.

कानून और व्यवस्था के लिए खतरा "।

वह आधार जिस पर तर्क की पूरी अधिरचना वादी-राज्य इस प्रकार वांछित हैं।

री: प्रस्ताव 2: इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर इस प्रस्ताव के तहत उत्पन्न

पहला प्रस्ताव, लेकिन चूंकि सवाल हमारे सामने तर्क दिया गया था

कुछ विस्तार से, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करना उचित समझते हैं। द. सवाल यह है: क्या यह आधार हो सकता है कि किसी राज्य की विधान सभा

मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया है और यह कि विधायी

कहा जा सकता है कि विधानसभा और राज्य एक दूसरे से भिन्न हैं। कला के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक होना। 356 .

सी. आई. (1) ? क्या इसका उस मामले से कोई संबंध है जिसके संबंध में

ई.

राष्ट्रपति को अनुच्छेद के तहत संतुष्ट होना आवश्यक है। 356 , सी. एल. (1) ? करता है। यह राज्य सरकार के सहमति से चलने पर बिल्कुल भी वहन करता है

संविधान के प्रावधानों के साथ संबंध? अब, हमें कोई संदेह नहीं है केवल इसलिए कि किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ता है

लोकसभा के चुनाव या उसके लिए, पंच में

याट क्लीक्शंस, कि अपने आप में यह कहने का कोई आधार नहीं हो सकता है कि

राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता। के अनुसार

एफ.

संविधान के प्रावधान। हमारे संघ के तहत संघीय संरचना कथन स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि सत्ता में एक दल हो सकता है

राज्य में और दूसरा केंद्र में। यह भी कोई असामान्य घटना नहीं है।

कि एक ही निर्वाचक मंडल एक पार्टी के सदस्यों के बहुमत का चुनाव कर सकता है

विधान सभा के लिए, जबकि एक ही समय में बहुमत का चुनाव करना

लोकसभा में किसी अन्य दल के सदस्य। इसके अलावा, कानून

एक बार निर्वाचित होने के बाद, स्थानीय सभा को एक विशिष्ट कार्यकाल के लिए जारी रखना होता है और

जी.

समाप्ति से पहले लोकसभा के चुनावों में केवल हार
इस शब्द के बिना और कुछ भी आप इसके विघटन के लिए कोई आधार नहीं होगा

यह। जरूरी नहीं कि हार सभी मामलों में संकेत देती है कि

मतदाता अब मुद्दों के कारण सत्तारूढ़ दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं

अलग हो सकता है। लेकिन भले ही यह एक निश्चित बदलाव का संकेत था

मतदाताओं की राय, कि अपने आप में कोई आधार नहीं होगा
विघटन, क्योंकि संविधान में विचार किया गया है कि आम तौर पर

एच.

निर्वाचक मंडल की इच्छा; कार्यकाल के अंत में व्यक्त की जाएगी

विधान सभा और बीच में मतदाताओं की इच्छा में परिवर्तन

प्रासंगिक नहीं होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान में राजस्थान बनाम संघ (भगवती, जे.) नहीं है।

85

व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करें। यदि ऐसा प्रावधान होता तो शायद इस तर्क को उचित ठहराया जा सकता था कि राज्य में सत्तारूढ़ दल लोकसभा के चुनाव में हारने के बाद, विधानसभा का बने रहना संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं होता। विधान-मंडल के एक प्रावधान को भंग करने के लिए, लोकसभा चुनावों में किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल की हार, बिना किसी और चीज के, इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकती कि राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। केवल इस आधार पर विधानसभा को भंग करना राष्ट्रपति द्वारा सभी सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार का अप्रत्यक्ष प्रयोग होगा, जिसमें संविधान में मतदाताओं द्वारा भी वापस बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहां की स्थिति पूरी तरह से अलग है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां लोकसभा चुनाव में किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल को एक साधारण हार का सामना करना पड़ा हो। सत्तारूढ़ दल के

उम्मीदवारों की कुल हार हुई है। कुछ वादी राज्यों में सत्तारूढ़ दल एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया है। इस देश के इतिहास में कभी भी इतना स्पष्ट और स्पष्ट निर्णय नहीं आया है

लोगों द्वारा दिया जा रहा है, कभी भी सत्तारूढ़ दल में अविश्वास का इतना बड़ा वोट नहीं। जब सत्तारूढ़ दल को इस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ता है और लोगों ने उसकी नीतियों के खिलाफ खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, तो यह दोनों दलों के बीच पूर्ण अलगाव का लक्षण है। सरकार और जनता। यह स्वयंसिद्ध है कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार कुशलता और प्रभावी ढंग से तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसे सद्भावना और समर्थन प्राप्त न हो।

लोगों से। जहाँ विभाजन की एक दीवार है जो विभाजित होती है

लोगों की ओर से सरकार, और सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में नाराजगी और घृणा है, यह बिल्कुल भी नहीं है

संभावना है कि इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है और प्रशासन भी लकवाग्रस्त हो सकता है। लोगों की सहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है।

सरकार का रूप और जब उसे इतनी पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के वापस ले लिया जाता है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जनता की भावना की तीव्रता के बारे में संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है, तो सरकार का नैतिक अधिकार

गंभीर रूप से कमजोर किया जाएगा और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ लोग सरकार को सम्मान और आज्ञाकारिता देना बंद कर सकते हैं

अधिकार और यहाँ तक कि संघर्ष और टकराव के बीच विकसित हो सकता है

सरकार और जनता प्रशासन के पतन की ओर ले जाती है।

ये सभी परिणाम हैं जिनके उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

इस तरह की असामान्य स्थिति से और वे इसे असंभव बना सकते हैं

राज्य सरकार के अनुसार चलने के लिए

संविधान के प्रावधान। क्या स्थिति भरी हुई है

इस तरह के परिणामों के साथ या नहीं, सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय का विषय है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि

इस तरह के परिणाम कभी नहीं हो सकते हैं और इस आधार पर कि लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की पूर्ण और भारी हार

राज्य की विधान सभा ने प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया है

लोगों की इच्छा और कानूनविदों के बीच पूर्ण अलगाव है

स्थानीय सभा और लोग पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक हैं

कला का उद्देश्य। 356 , सी. आई. (1) . हम इसे तथ्यों और संदर्भ के आधार पर मानते हैं।

वर्तमान मामले की जटिलताएं यह आधार स्पष्ट रूप से एक प्रासंगिक आधार है जिसका उस मामले के साथ उचित संबंध है जिसके संबंध में अध्यक्ष

कला के तहत कार्रवाई करने से पहले डेंट को संतुष्ट करना आवश्यक है। 356 . सी. आई. (1) .

ये वे कारण हैं जो हमारे बनाने में हमारे साथ प्रबल हुए हैं

मुकदमे और रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए 29 अप्रैल, 1977 का आदेश।

और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करना।

गोस्वामी, जे.-हम पहले ही मुकदमों और रिट याचिका को खारिज कर चुके हैं।

29 अप्रैल, 1977 को, और तदनुसार प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया

अंतरिम आदेश। हमने बाद में अपने कारण बताने का वादा किया और

अब ऐसा ही कहा जा सकता है।

इन सभी मामलों के तथ्य विद्वान के निर्णय में दिखाई देते हैं।

एड मुख्य न्यायाधीश और दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

इन मुकदमों में शामिल बुनियादी प्रश्न ये हैं:

(1) क्या मुकदमे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत हैं?

भारत?

(2) न्यायालय के न्यायशास्त्र के संबंध में अनुच्छेद 356 का क्या दायरा है?

बोलचाल?

(3) यदि मुकदमे झूठ बोलते हैं, तो क्या स्थायी निषेधाज्ञा का कोई मामला है और,।

एक मध्यवर्ती कदम के रूप में, एक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए

यह?

(4) रिट याचिकाकर्ताओं को कोई मौलिक अधिकार दें

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उनके आवेदनों को कम करना?

इन मुकदमों के साथ-साथ रिट याचिकाओं में केंद्रीय मुद्दा

यह किसी राज्य की सरकार और विधान सभा के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद का संवैधानिक अधिकार है जो संविधान में दिए गए अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जारी रहता है।

मुकदमे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किए जाते हैं। लेख

131 इस न्यायालय को किसी भी विवाद में अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र देता है

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच:

या

(ख) भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच

एक तरफ और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य: या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच।

यद्यपि अनुच्छेद 131 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति कोई भी विवाद है, अभिव्यक्ति की चौड़ाई उन शब्दों से सीमित है जो विवाद की प्रकृति के संबंध में अनुसरण करते हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया जा सकता है। यह केवल एक विवाद है जिसमें कानून या तथ्य का कोई भी प्रश्न शामिल है जिस पर प्रतिद्वंद्वी पक्ष के कानूनी अधिकार का अस्तित्व

या विस्तार निर्भर करता है जो अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे का विषय हो सकता है। विवाद कानूनी अधिकारों के संबंध में होना चाहिए न कि राजनीतिक चरित्र के विवादों के संबंध में। इस प्रकार, अनुच्छेद उन पक्षों को संदर्भित करता है जो मुकदमेबाजी के साथ-साथ विवाद के उप-क्षेत्र मामले में भी शामिल किए जा सकते हैं। (बिहार राज्य बनाम देखें। भारत संघ और अन्र.) . (1)

(1) [1970] 2 एस. सी. आर 522

राजस्थान बनाम. यूनियन (गोस्वामी, जे.)

87

मुकदमे, रूप में, राजस्थान राज्यों द्वारा दायर किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन विवाद न्यायनिर्णयन के लिए माँगा गया है। के दायरे या दायरे में

अनुच्छेद 131? यह पहला सवाल है।

सरकार के संसदीय रूप में जब एक सरकार

दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, राज्य की निरंतरता नहीं टूटती है। वहाँ

सरकार के जीवन में एक ऐसा क्षण आ सकता है जब यह बंद हो जाए।

वास्तव में लोगों का प्रतिनिधि होना और इसलिए, के हित

राज्य एक राजनीति या कानूनी इकाई के रूप में और सरकार की संस्था के रूप में

पार्टी प्रणाली पर ब्लिश समान होना बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में

राज्य सरकार द्वारा इसके नाम पर किया गया मुकदमा, तथ्यात्मक या आसन्न रक्षा में केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ राज्य

पूर्व का वैध अस्तित्व और निरंतरता का अधिकार संबंधित नहीं होगा। राज्य के कानूनी अधिकार के लिए। फैसला, चाहे सच में हो और

वास्तविकता एक विशेष स्थिति मौजूद है या स्पष्ट रूप से आसन्न है, हो सकता है

सही हो या गलत, लेकिन यह एक राजनीतिक मुद्दा है। न्यायालय का न्यायशास्त्र

बोलचाल राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से न्यायिक है।

मुकदमा करने का किसी विशेष राज्य का अधिकार हमेशा इसके बराबर नहीं होता है -

सभी मामलों में मंत्रिपरिषद का अधिकार। भले ही एक गो

सरकार राज्य का जीवन चलाती है। चाहे कोई विशेष परिषद मंत्री अपने अस्तित्व के खतरों से बच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

बहुमत के विश्वास का आनंद लेने की अपनी क्षमता पर तुरंत

विधानमंडल लेकिन यह भी, अंतिम उपाय में, आनंद लेने की अपनी क्षमता में राजनीतिक संप्रभु, मतदाताओं का विश्वास। सवाल हैं।

बाद वाले क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अत्यधिक राजनीतिक रंग और एपी के होते हैं।

सरकार के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है न कि कानूनी अधिकारों से

राज्य से। वादियों द्वारा उत्तेजित अधिकार मुख्य रूप से हैं - संबंधित सरकारें जो जारी रखने में रुचि रखती हैं

विधायिकाएँ जिनका विश्वास वे प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, यह

गृह मंत्री ने अपने पत्र में दावा किया है कि ये विधान मंडल

लोगों का जनादेश खो दिया है और इसके स्पष्ट सबूत हैं

जिसके परिणामस्वरूप वे लोगों का विश्वास खो चुके हैं संसद के हाल के आम चुनाव में निर्णय। अदालत ने

इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यह सही आकलन है या नहीं। द.

केंद्र सरकार को राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है।

हालांकि,

भले ही भारत सरकार का कोई राजनीतिक निर्णय कानूनी प्रभाव डालता हो

एक कानूनी इकाई के रूप में राज्य के अधिकार, उसका अस्तित्व और विस्तार अधिकार अनुच्छेद 131 के तहत परीक्षण योग्य होगा। सवाल यह है कि क्या यह कानूनी है?

विवाद में शामिल राज्य के अधिकार?

अनुच्छेद 131 कानूनी अधिकार की बात करता है। वह कानूनी अधिकार होना चाहिए कि

राज्य से। किसी कानूनी अधिकार, उसके अस्तित्व या विस्तार के बारे में विवाद,

भारत सरकार के बीच आंदोलन करने में सक्षम होना चाहिए और राज्यों को। अनुच्छेद के दायरे में विवाद की प्रकृति

131 जो उभरता है वह एक कानूनी अधिकार के संबंध में है जिसे राज्य प्राप्त कर सकते हैं

सरकार के खिलाफ दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य

एक पक्ष के रूप में अपने स्वयं के कानूनी अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए जो सरकार

भारत ने किसी कारण को जन्म देने से इनकार किया है या इनकार करने में रुचि है

कार्रवाई। यह तय करने के उद्देश्य से कि क्या अनुच्छेद 131 है

इसलिए, विवाद की विषय वस्तु का पता लगाना बहुत अच्छा लगता है

:

संकेत।

भाग VI राज्यों से संबंधित है। "राज्य" शब्द परिभाषित नहीं है।

हालांकि, भाग 5 में अनुच्छेद 131 के उद्देश्य के लिए "राज्य" को भाग 3 (मौलिक) के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया है।

अधिकार)। यह परिभाषा भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के लिए भी है। अनुच्छेद 367 (1) के तहत, वंशावली खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधान संविधान की व्याख्या के लिए

लागू होते हैं। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) राज्य को परिभाषित करती है। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के बाद, संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य का अर्थ होगा और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। संविधान की पहली योजना में 22 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (60) के तहत अलग से परिभाषित किया गया है-इस प्रकार अंतर बनाए रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य या भारत सरकार के कानूनी अधिकारों से संबंधित है। राज्यों या भारत सरकार के अधिकारों को बाधित करने वाले संविधान के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन अनुच्छेद 131 के तहत न्यायोचित होगा। इसी तरह, सीमा

दो राज्यों के बीच करों और अन्य शुल्कों से प्राप्तियों के प्रतिद्वंद्वी दावों से संबंधित विवाद या विवाद इस न्यायालय द्वारा संज्ञेय हैं, केवल कुछ उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए। अब इन उपर्युक्त मामलों में कार्यकारी अभिकर्ता होने के नाते, सरकार से अलग एक कानूनी इकाई के रूप में राज्य के अधिकार शामिल होंगे। भले ही

एक

सरकार को दूसरी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इस तरह का विवाद कम या गायब नहीं होगा क्योंकि राज्य बना रहता है और कार्रवाई का कारण बना रहता है।

उपरोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, हम इन मुकदमों में शामिल विवाद की प्रकृति की जांच करने का कार्य करेंगे। थोड़ी देर में।

बयान में कहा गया है कि राज्यों को गृह मंत्री के पत्र में निहित सलाह या निर्देश का पालन न करने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कार्यकारी कार्यों को ग्रहण करने के लिए गंभीर खतरे की आशंका है। यह सच है कि किसी अवैध कार्रवाई की धमकी भी किसी मुकदमे या कार्यवाही के लिए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करती है।

अनुच्छेद 172 (1) के तहत उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्य विधानसभाएं, यदि पहले भंग नहीं की गईं, तो अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से छह साल की अवधि के लिए जारी रहेंगी और इस दृष्टि से सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ और महीनों तक जारी रहेगी। दूसरी ओर, उड़ीसा राज्य की विधान सभा, जिसने 1974 में अपना चुनाव कराया था, सामान्य रूप से 1980 तक जारी रहेगी जब तक कि विधानसभा भंग नहीं हो जाती। राज्यों को आशंका है कि विधानमंडलों का यह सामान्य जीवन समाप्त होने जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 172 (1) के तहत उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यह स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों के लिए एक कारण प्रस्तुत करता है

वादियों के अनुसार।

विवाद इस प्रकार है: भारत सरकार के गृह मंत्री राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि वे राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्रियों ने सलाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुकदमा दायर कर दिया। इस विवाद की प्रकृति क्या है?

एक ओर दावा है कि राजस्थान वी. यूनियन (गोस्वामी, जे.)

89

राज्य की वर्तमान सरकार को जारी रखने का अधिकार और विधान सभा को जारी रखने की आवश्यकता और दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के कार्यों को संभालने के लिए अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार। इस विवाद में महान संवैधानिक महत्व का एक प्रमुख मुद्दा शामिल है और पीड़ित पक्ष के पास किसी भी महत्वपूर्ण क्षति के खिलाफ शिकायत करने के लिए अन्य उपयुक्त मंच हो सकता है। फिर भी, यह एक ओर राज्य और दूसरी ओर भारत सरकार के बीच विवाद नहीं है। यह राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच एक वास्तविक विवाद है।

यह है।

इसमें कोई शक नहीं कि यह राज्य सरकार के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, लेकिन

विधानसभा के लिए राज्य की सरकार बनी रहेगी समय, जैसा कि संविधान में ऐसी आकस्मिकता में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 168 के तहत राज्य के विधानमंडल में सरकार होती है।

न ही और विधान सभा या जहाँ कोई विधान है

राज्य विधानमंडल जिसमें मंत्रिपरिषद कार्यकारी है अकेले निकाय राज्य विधानमंडल का गठन भी नहीं करता है। गवर्नर

मंत्रिपरिषद या राज्य के सदस्यों के अधिकार इसलिए, विधानमंडल को राज्य के अधिकारों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

भले ही वे अधिकार राज्य सरकार के हों, प्रो

अस्थायी।

राज्य और सरकार के बीच अंतर लाया जाता है

निम्नलिखित परिच्छेदों में स्पष्ट स्पष्टता के साथ -

" राज्य और उसकी सरकार के बीच का अंतर

किसी दिए गए मानव व्यक्ति के बीच के समान है, जैसे

एक नैतिक और बौद्धिक व्यक्ति, और उसकी भौतिक शारीरिक

निकाय राज्य शब्द द्वारा राजनीतिक व्यक्ति को समझा जाता है

या ऐसी संस्था जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है। के द्वारा

सरकार शब्द को वह अभिकरण समझा जाता है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को तैयार किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और निष्पादित किया जाता है। द.

सरकार इस प्रकार राज्य के तंत्र के रूप में कार्य करती है, और जो इस यंत्र को चलाते हैं।

.....

के रूप में कार्य करें

राज्य के एजेंट "। (1)

" सभी संवैधानिक रूप से संगठित राज्यों में राज्य है -

अदालतों में मुकदमा करने की अनुमति न केवल संदर्भ के साथ अपने स्वामित्व या संविदात्मक हितों में, लेकिन

अपने नागरिक निकाय के सामान्य हितों की ओर से।

कब

बाद की क्षमता में वादी के रूप में उपस्थित होना इसे के रूप में जाना जाता है

पेरेन्स पेट्रिया। इस न्यायशास्त्र संबंधी सिद्धांत में कहा गया है

कानून और प्रक्रिया का साइक्लोपीडिया निम्नानुसार है:

' एक राज्य, किसी भी अन्य पक्ष की तरह, मुकदमा नहीं चला सकता है।

जब तक कि यह प्रतीत न हो कि उसकी इस विषय में इतनी रुचि है उसके द्वारा मुकदमा लाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए।

(1) वेस्टल डब्ल्यू. विलो द्वारा सार्वजनिक कानून की मौलिक अवधारणाएँ

पृष्ठ 49.

[1

978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

90

लेकिन इस संबंध में एक अंतर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

संप्रभुता में लोगों द्वारा या राज्य द्वारा किए गए कार्यों के बीच

क्षमता, और कुछ आर्थिक ब्याज पर आधारित सूट

स्वामित्व अधिकार '। (1)

" राज्य और शासन के बीच अंतर का मूल्य

यह संभावना है कि यह संस्थागत निर्माण की पेशकश करता है

राज्य के अभिकर्ताओं को बदलने के लिए तंत्र, अर्थात

सरकार, जब बाद वाला खुद को इसके लिए अपर्याप्त दिखाता है

जिम्मेदारियाँ "। (2)

मेरा स्पष्ट मत है कि विवाद का विषय

ये मुकदमे संविधान के अनुच्छेद 131 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों के कानूनी अधिकारों से संबंधित नहीं हैं। इसलिए ये मुकदमे कानूनी रूप से विचारणीय नहीं हैं और इस आधार पर उन्हें खारिज किया जा सकता है।

रिट याचिकाओं के संबंध में मुझे अवसर मिला था

जाओ।

मेरे भाइयों भगवती और गुप्त के निर्णयों के माध्यम से और मैं उनके तर्क और निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि विधान सभा के विघटन की धमकी के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 के तहत याचिकाकर्ताओं को दिए गए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

हालाँकि, प्रस्तावित कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण होने का सवाल

आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए गृह मंत्री के बारे में विस्तार से बहस की गई, मुझे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये आधार, प्रत्यक्ष रूप से, पूरी तरह से निरर्थक हैं।

दूरदर्शी और बाहरी और यहाँ तक कि दुर्भावनापूर्ण भी। श्री निरेन डे ने राजा-सम्राट बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख किया। बेनोआरी लाल सरमा और अन्य (3) और हमें निम्नलिखित अंश पढ़ा:

" यह देखा जाना चाहिए कि धारा (सरकार की धारा 72)

भारत अधिनियम, 1935) में गवर्नर-जनरल की आवश्यकता नहीं है।

यह बताने के लिए कि कोई आपातकाल है, या क्या आपातकाल है या तो अध्यादेश के पाठ में है या बिल्कुल भी है, और मान रहा है

कि वह ईमानदारी से और अपने वैधानिक के अनुसार कार्य करता है

शक्तियाँ, यह अदालतों के पास उनकी समीक्षा को चुनौती देने के लिए नहीं हो सकती हैं

कि आपातकाल मौजूद है "।

उपरोक्त परिच्छेद पर भरोसा करते हुए श्री डे प्रस्तुत करते हैं कि यह न्यायालय इस बात की जांच करने का हकदार है कि निर्देश दुर्भावनापूर्ण है या नहीं।

(1) वेस्टल डब्ल्यू. विलो द्वारा सार्वजनिक कानून की मौलिक अवधारणाएँ। 487-488 .

(2) हेरोल्ड जे. लास्की द्वारा सिद्धांत और व्यवहार में स्थिति, पृष्ठ 25।

(3) 72 आई. ए. 57,64।

राजस्थान वी. यूनियन (गोस्वामी, जे.)

91

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है

भगत सिंह और अन्य बनाम। राजा-सम्राट (1) जो कि प्रिवी काउंसिल का निर्णय है, बेनोआरी लाल सरमा के मामले (ऊपर) में अपनाया गया। उन्होंने हमें निम्नलिखित अंश पढ़ा। --

" आपातकाल की स्थिति एक ऐसी चीज है जिसकी अनुमति नहीं है।

किसी भी सटीक परिभाषा के लिए। यह बुलाए जाने वाले मामलों की स्थिति को दर्शाता है

कठोर कार्रवाई के लिए, जिसे कुछ लोगों द्वारा इस तरह से आंका जाना है

एक. यह स्पष्ट से अधिक है कि किसी को होना चाहिए गवर्नर-जनरल, और वह अकेले। कोई अन्य दृष्टिकोण होगा

पूरे प्रावधान को पूरी तरह से अक्षम बनाना। आपातकाल की मांगें

तत्काल कार्रवाई, और वह कार्रवाई करने के लिए निर्धारित है

गवर्नर-जनरल द्वारा। यह केवल वही है जो प्रचार कर सकता है

गेट द ऑर्डिनेंस "।

हमारे संविधान में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख हैं और

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य

(अनुच्छेद 74)। संशोधन से पहले भी यह स्थिति थी

42 वें संशोधन द्वारा संविधान का अनुच्छेद 74 (1) (देखें)

सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ मंत्रियों का समूह राष्ट्रपति जो अपने कृत्यों के प्रयोग में कार्य करेगा

ऐसी सलाह के अनुसार "। न्यायिक रूप से क्या व्याख्या की गई थी

असंशोधित अनुच्छेद 74 (1) के तहत अब यह संसदीय हो गया है।

संविधान संशोधन द्वारा मान्यता। अत: यह हो सकता है कि

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत निर्णय

जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वह मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है।

क्योंकि गृह मंत्री के पत्र में कुछ कारण दिए गए हैं,

यह नहीं कहा जा सकता है कि वे ही एकमात्र आधार होंगे जो वजन करेंगे।

मंत्रिपरिषद के साथ जब वे अंतत: निर्णय लेते हैं जब

मुख्यमंत्रियों ने इस सलाह को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे भी हैं

कई अभेद्य जो पत्र के समय के बीच हस्तक्षेप कर सकते हैं और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की वास्तविक सलाह।

आगे के घटनाक्रम या आशंका हो सकती है

जिसे सरकार को नहीं लेना पड़ सकता है और अंत में जब

मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है और राष्ट्रपति को प्रो जारी करने की सलाह देती है। अनुच्छेद 356 के तहत अदालत को पूछताछ करने से रोक दिया जाएगा

मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह में।

(अनुच्छेद 74 (2)। फिर अनुच्छेद 356 (5) के तहत। संतुष्टि

अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा जारी करने में राष्ट्रपति का

अंतिम और निर्णायक होगा और किसी भी अदालत में उससे पूछताछ नहीं की जाएगी।

किसी भी जमीन पर। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे सामने इन शर्तों में कि क्या संविधान निर्माता का अनुच्छेद 356 (5)

क्या यह संविधान के अधिकार के बाहर है या नहीं। यहाँ तक कि अतिरिक्त वकील भी

जनरल ने अपनी दलीलें अनुच्छेद 356 (1) डी की शर्तों पर आधारित कीं।

अनुच्छेद 356 (5) भगत सिंह के मामले (ऊपर) पर भरोसा करते हुए कि

राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि न्यायसंगत नहीं है। इसमें है।

(1) 58 आई. ए. 169,172।

(2) [1975] 1 एस. सी. आर 814

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ के इस रुख के बारे में श्री डे ने बेनोआरी लाल सरमा के मामले (ऊपर) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने संकेत दिया है कि अदालत द्वारा दुर्भावना के सवाल पर विचार किया जा सकता है। श्री डे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत एक दुर्भावनापूर्ण आदेश कानून की नजर में कोई आदेश नहीं होगा।

मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह न्यायालय, जो अंतिम उपाय है।

क्योंकि उत्पीड़ित और भ्रमित लोग, अच्छे के लिए, इस बात पर विचार करने से इनकार करते हैं कि कब यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो सकती है कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि, मैं जल्दबाजी में यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री के पत्र में दिए गए आधारों को कल्पना की कोई ताकत नहीं माना जा सकता है। इन आधारों का संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा के विषय के साथ उचित संबंध होगा। मामला पूरी तरह से अलग होता अगर कोई प्रस्ताव नहीं होता, लेकिन, इन विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित करके मतदाताओं से अपील करने के लिए।

मेरे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे और रिट याचिकाएं नहीं हैं

मैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आवश्यक महसूस नहीं करता कि क्या इन मामलों में स्थायी निषेधाज्ञा या अन्य उपयुक्त रिट का कोई मामला है। मुकदमे और रिट याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी थीं।

मैं एक ठंडे झटके के साथ रिकॉर्ड के साथ भाग लेता हूं। मुख्य न्यायाधीश थे

यह हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने उन्हें उस समय देखा जब हम पहले ही आदेश की घोषणा करने के बाद निर्णय पर विचार कर रहे थे और बातचीत के दौरान इस लंबित मामले का उल्लेख था। मैंने इस रहस्योद्घाटन को सबसे अधिक चिंतित विचार और यहां तक कि सबसे मजबूत न्यायिक प्रतिबंध दिया है, जिसे एक न्यायाधीश प्रयोग करना पसंद करेगा, मेरे पास इसे रिकॉर्ड पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह उम्मीद करते हुए कि राष्ट्रपति के उच्च कार्यालय की महिमा, जो किसी भी विवाद के उच्च जलचिह्न से परे होनी चाहिए, भविष्य में प्रभावित नहीं होगी।

अनटवालिया, जे. इन मामलों में पीठ का सर्वसम्मत आदेश

29 अप्रैल, 1977 को वितरित किया गया था। आदेश के समर्थन में निर्णय अब दिए जा रहे हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख निर्णय में दिए गए कारणों से आम तौर पर सहमत होने के बावजूद, कुछ बिंदुओं पर मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहूंगा और अपनी खुद की कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

कुछ द्वारा दायर रिट आवेदनों की रखरखाव के बारे में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पंजाब विधानमंडल के सदस्य, मैं, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। मैं उनके पक्ष में मान लूंगा कि सीमा पर आवेदन बनाए रखने योग्य हैं। फिर भी वे ऐसा नहीं करते

किसी भी प्रकार की रिट, निर्देश या आदेश जारी करने के लिए मामला बनाएँ।

लेकिन अनुच्छेद 131 के तहत दायर किए गए मुकदमों की स्थिरता के बारे में

विभिन्न राज्यों द्वारा मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि यह मुद्दा अत्यधिक विवादास्पद है और कठिनाई से मुक्त नहीं है, फिर भी मुकदमों में उठाए गए प्रकार के विवाद में कोई सवाल शामिल नहीं है चाहे वह कानून या तथ्य का हो, जिस पर राज्यों के किसी भी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो।

निर्भर करता है। मेरे विचार से जो विवाद उठाया गया है, वह दोनों के बीच है।

भारत सरकार और संबंधित राज्यों की सरकार या विधान सभा। एक या एक से अधिक अंगों, अर्थात् सरकार, विधानमंडल या किसी राज्य की न्यायपालिका की तुलना राज्य से नहीं की जा सकती है। यद्यपि अनुच्छेद 131 में आने वाला "कानूनी अधिकार" न केवल राज्यों के संवैधानिक अधिकारों बल्कि अन्य प्रकार के कानूनी अधिकारों को भी शामिल करता है, लेकिन विवाद राज्य के क्षेत्र, संपत्ति या किसी अन्य प्रकार के कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए।

राज्य। मोटे तौर पर, इन मामलों में विवाद की प्रकृति है -

कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अन्य में

शब्दों में, भारत सरकार के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है

विधानमंडल को भंग करने के लिए घोषणा करने के लिए अनुच्छेद 356

संबंधित राज्य की स्थानीय विधानसभा और परिषद को हटाने के लिए

मंत्री, उस राज्य में सत्ता में विशेष सरकार। इस तरह की

विवाद, मेरी राय में, कानूनी अधिकार के संबंध में विवाद नहीं है।

भारत संघ की एक इकाई का गठन करें। यह उससे कम है। क्या है? आरोप है कि विवादित घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति

सरकार के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं संभाल लेगा।

राज्य की और राज्य द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या कोई भी शक्ति

विधानसभा को भंग करने की शक्ति सहित राज्यपाल

अनुच्छेद 174 (2) (बी)। इस तरह की प्रस्तावित या खतरे वाली कार्रवाई प्रभावित करती है।

सत्ता में सरकार और विधान सभा का कानूनी अधिकार यह राज्य विधानमंडल का एक भाग है, लेकिन स्वयं राज्य का नहीं। द.

नि:संदिग्ध रूप से राज्य को एक राज्यपाल और एक सरकार होने का अधिकार है।

रूप या दूसरा और विधानमंडल। इसके किसी भी हिस्से को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

उन्मूलन राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित करेगा। लेकिन यह काफी नहीं है। यह कहना सही है कि किसी राज्य को एक विशेष राज्यपाल रखने का कानूनी अधिकार है

अनुच्छेद 174 में प्रयुक्त "विघटित" शब्द के विपरीत मैं इंगित करूँगा किसी राज्य की विधान परिषद के "उन्मूलन" का प्रावधान

अनुच्छेद 169 में उल्लिखित है। इसी तरह, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए, मैं

अनुच्छेद 153 का उल्लेख किया जा सकता है जो प्रदान करता है "एक राज्यपाल होगा

प्रत्येक राज्य के लिए ", और अनुच्छेद 156 जो एक विशेष राज्य के लिए प्रावधान करता है।

राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करने वाले राज्यपाल। यदि ए.

सरकार की किसी कार्रवाई या धमकी के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है भारत में अनुच्छेद 153 के तहत यह राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित करेगा क्योंकि

राज्यपाल के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर विवाद की चिंता है।

केवल राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष राज्यपाल को हटाना, केवल पद धारण करने वाले व्यक्ति या सरकार के कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है

हालांकि सूक्ष्म, महत्वपूर्ण और सराहनीय है, भाषा से स्पष्ट है अनुच्छेद 131 के विभिन्न खंडों के साथ-साथ परिभाषाओं से भी

खंड अधिनियम। इसलिए, मेरे सुविचारित निर्णय में, मुकदमे इंस्टाई के रूप में हैं। अनुच्छेद 131 के तहत टचूटेड बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

लेकिन मैं मुकदमों को खारिज किए जाने से संतुष्ट नहीं रहूंगा।

केवल इस तकनीकी आधार पर।

गुण-दोष के बारे में कुछ शब्दों में संक्षेप में बता रहा हूँ।

जिन सूटों पर मैं जोर देना चाहूंगा, पहली बार में, कि यह है

यह मान लेना, मान लेना या निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि प्रो का एकमात्र आधार

राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई [1978] 1 एस. सी. आर. के पत्र में उल्लिखित तथ्य हैं।

संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री या भारत सरकार के कानून मंत्री का भाषण। इसके विपरीत किसी भी दावे के समर्थन में न तो कोई वारंट है और न ही किसी भी दावे में पर्याप्त सामग्री का खुलासा किया गया है। दूसरा, भले ही कोई वादी के पक्ष में इस तरह के तथ्य को मान ले

या याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रकट किए गए तथ्य, निस्संदेह, विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के क्षेत्र में हैं, जो अनिवार्य रूप से गैर-न्यायसंगत हैं। ऐसे क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में चिह्नित करना वैध होगा जिसमें यह न तो अनुमत है। न्यायालयों को प्रवेश करना चाहिए और न ही उन्हें कभी भी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का खतरनाक कार्य अपने ऊपर लेना चाहिए। चीजों की प्रकृति में राष्ट्रपति को एकमात्र न्यायाधीश होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, निश्चित रूप से, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उनकी संतुष्टि के लिए कि क्या ऐसी स्थिति मौजूद है या नहीं जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी संतुष्टि किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट की प्राप्ति या अन्यथा पर आधारित हो सकती है। न तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए अपनी संतुष्टि के लिए सभी तथ्यों और सामग्रियों को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है और न ही अनुच्छेद 356 (1) में परिकल्पित ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने के बारे में उनका निष्कर्ष, आम तौर पर, प्रकट किए गए तथ्यों पर भी चुनौती देने के लिए खुला है।

हालाँकि, मुझे यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि मैं इस विचार को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकता कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए घोषणा के आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और, मैं संविधान (38वां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुच्छेद के खंड (5) में निहित प्रावधान के बावजूद ऐसा कह रहा हूं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा या अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के संबंध में हमारे सामने प्रचार किए गए अलग-अलग विचारों के समर्थन में,

चरम काल्पनिक उदाहरण एक तरफ या दूसरी तरफ उद्धृत किए गए थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसे अधिकांश उदाहरण अभी भी मौजूद हैं।

केवल परिकल्पना और एक काल्पनिक दुनिया में। उन्हें वास्तविक रूप में खोजना मुश्किल है लेकिन फिर भी किसी दिए गए मामले या मामलों में असंभव नहीं है। फिर फर्क कहाँ है? अनुच्छेद 356 में खंड (5) या कुछ अन्य अनुच्छेदों, जैसे कि आरती खंड 352 और 123 में इसी तरह के

खंड की शुरूआत से पहले भी, न्यायालयों के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जिसे लोकप्रिय और आम तौर पर राजनीतिक अधिनियम कहा जाता है।

मैदान। यदि राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कार्रवाई की वैधता को, उदाहरण के लिए, उपरोक्त उल्लिखित तीन अनुच्छेदों में से किसी के तहत चुनौती दी जाती है, तो तथ्यों की जांच करके स्थिति की वास्तविकता में झाँकने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता को आकर्षित करते हुए, या तो वैधता या दुर्भावना के आधार पर न्यायालयों ने हमेशा विरोध किया है और निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रलोभन का विरोध करना जारी रखेंगे; उदाहरण के लिए, भगत सिंह और अन्य v. राजा-सम्राट; (1) राजा-सम्राट बनाम। बेनोआरी लाल सरमा और अन्य; (")

(1) 58 , भारतीय अपील, 169. (2) 72 भारतीय अपील, 57.

राजस्थान वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

95

लाखी नारायण दास बनाम। बिहार प्रांत आदि। (1) और मेसर्स एस. के. जी. शुगर लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (2) . इसे चित्रात्मक रूप से रखने के लिए खंड (5) ने ऐसे बंद दरवाजों पर केवल एक मुहर लगा दी है ताकि न्यायालयों को प्रोही द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश कराने के प्रलोभन या आग्रह की अधिक दृढ़ता से जांच की जा सके। सत्ता के क्षेत्र से बाहर की पार्टी द्वारा हमेशा प्रयास किए गए हैं, यदि मैं इसकी तुलना उपरोक्त निषिद्ध क्षेत्र से कर सकता हूं, तो न्यायालय को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए ताकि राष्ट्रपति द्वारा सत्ता में सरकार की सलाह पर असाधारण कदम उठाने के खिलाफ राहत दी जा सके। दूसरी ओर, सत्ता में पार्टी ने हमेशा इस तरह के कदम का विरोध किया है। लोकतंत्र में जनमत और मताधिकार की धारा किसी विशेष जहाज को तट के एक तरफ या दूसरी तरफ धकेल सकती है। लेकिन इस कोर्ट को, पोल स्टार की तरह, सभी नाविकों के मार्ग का मार्गदर्शन करना है और सभी नाविकों को एक समान तरीके से वर्तमान से अलग रखना है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई विशेष जहाज इस तट पर है या नहीं।

लेकिन फिर, मेरा यह कहने से क्या मतलब था कि एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है

एक ऐसा मामला जहां न्यायालय की अधिकारिता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है? मेरा मतलब यह है। यदि निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए बिना, बाड़ पर रहते हुए, लगभग राष्ट्रपति के विवादित आदेश या धमकी भरी कार्रवाई के बावजूद, यह कहना यथोचित रूप से संभव है कि

कानून की नजर में यह कोई आदेश या कार्रवाई नहीं है क्योंकि यह किसी विशेष अनुच्छेद के शब्दों का घोर उल्लंघन है, इस धारणा को उचित ठहराते हुए कि आदेश अधिकार से बाहर है, पूरी तरह से अवैध है या दुर्भावना से पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में यह कानून में किसी भी तरह का आदेश नहीं होगा। तब यह न्यायालय इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन नहीं है और इसके बजाय, इसे रद्द कर सकता है। लेकिन न्यायालय के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करके तथ्यों की जांच करके इस तरह के निष्कर्ष निकालना अक्षम और खतरनाक है। यह कहना भी उतना ही असमर्थनीय होगा कि न्यायालय इसे निरस्त करने में असमर्थ होगा।

आदेश, यदि उसके चेहरे पर, या, यदि मैं इसे रख सकता हूं, तो निषिद्ध क्षेत्र के संदर्भ में घूमकर, न्यायालय इस आदेश को केवल ढोंग या संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत दी गई असाधारण शक्तियों का एक रंगीन विसर्जन मानता है। किसी मामले में यह निष्कर्ष निकालना संभव हो सकता है कि यह शक्ति के प्रयोग में धोखाधड़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर सभी में कहा है: व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के मामले शायद ही कभी होने की संभावना है और भले ही वे बहुत कम हों, न्यायालयों को तथ्यों के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के उनके प्रलोभन की जांच करके ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जो अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रकृति के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में लॉर्ड मैक डर्मोट ने स्टीफन कलोंग निंगकन और मलेशिया सरकार (3) के मामले में पृष्ठों 391-92:

" सरकार द्वारा न्यायोचित होने का मुद्दा उठाया गया

मलेशिया ने संघीय न्यायालय में मतभेद पैदा किया,

मलेशिया के प्रभु राष्ट्रपति और मलेशिया के मुख्य न्यायाधीश

मलाया का मानना है कि घोषणा की वैधता नहीं थी

न्यायसंगत और ओंग जे. ने माना कि यह था। क्या एक पेशेवर

के सर्वोच्च प्रमुख द्वारा वैधानिक शक्तियों के तहत अभियोग

(1) [1949] F.C.R.693।

(2) [1975] 1 एस. सी. आर, 312.

(3) [1970] अपील मामले, 379।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1

978] 1 एससीआर।

संघ को कुछ मामलों में अदालतों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है

कोई भी आधार दूरगामी संवैधानिक प्रश्न है।

प्राधिकरणों की वर्तमान स्थिति का महत्व,

अस्थिर और बहस योग्य बना हुआ है "।

मेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुप्रयोग में और

निषिद्ध क्षेत्र का सीमांकन, राय कभी-कभी भिन्न हो सकती है,

" कभी-कभी गलतियाँ या तो निषिद्ध क्षेत्र के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से बड़ा करके या अनुचित रूप से सीमित करके की जा सकती हैं। लेकिन ऐसे अंतर

बहुत ना में निहित हैं। न्याय के प्रशासन के माध्यम से

मानव एजेंसी। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है और न ही कोई समझ सकता है

एक बेहतर कार्यप्रणाली की खोज करें। जो भी हो। न्यायालयों और न्यायाधीशों

उनका प्रबंधन करना न्यायशास्त्र की अपनी सीमाओं का न्याय करने के लिए सबसे अच्छे मध्यस्थ हैं।

जिसे मैंने एक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, उसे देखने की कोशिश की जाएगी और उस क्षेत्र को जितना संभव हो उतना बड़ा बनाएं और पार्टी उस क्षेत्र से बाहर हो जाए

रखें और उस क्षेत्र को उतना ही रखना है जितना कि यह मानवीय रूप से है और कानूनी रूप से एक या दूसरे पक्ष के लिए ऐसा करना संभव है। यह है।

परिभाषित करने का प्रयास करने के लिए न तो संभव है और न ही उचित या उपयोगी है

एक या दूसरे तरीके से उदाहरण लेकर इस तरह के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए जब न्यायालय यह कहने में सक्षम होगा कि "मैं बाहर निकल रहा हूँ।

निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए बिना राष्ट्रपति का विशेष आदेश

या इसके विपरीत "। इन मामलों में मैं यह कहकर संतुष्ट रहूंगा कि,

हम अपने सामने रखे गए तथ्यों को देखते हैं, वे विशेष रूप से पेशेवर के भीतर हैं।

घिरा हुआ क्षेत्र।

विवाद का मुख्य विषय यह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते।

घोषणा करें क्योंकि जब प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है संसद अनुच्छेद 356 के खंड (3) के अनुसार यह सुनिश्चित करती है या

बहुत संभावना है कि इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा जहां

संबंधित राज्यों में सत्ता में पार्टी स्पष्ट बहुमत में है; किसी भी राज्य में

घटना, राष्ट्रपति को कोई भी लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए

बिना विधानसभा भंग करने की घोषणा के अनुसार कार्रवाई

संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन, विघटन के अधिनियम के रूप में

अपरिवर्तनीय होगा और संघीय ढांचे का घोर उल्लंघन होगा

संविधान से। मुझे सत्ता पर इस तरह की सीमा के शब्द नहीं मिलते हैं।

संविधान सभा द्वारा बनाए गए और पारित किए गए मूल अनुच्छेद में या लाए गए किसी भी संशोधन में राष्ट्रपति का उसमें समय-समय पर। की गई घोषणा और उसके अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई, यदि अन्यथा वैध है और जिस तरह से और सीमा के भीतर मैंने ऊपर संकेत दिया है, उसे चुनौती देने के लिए खुला नहीं है, तो

घोषणा समाप्त होने तक वैध, जिसकी अधिकतम अवधि संसद के सदनों की मंजूरी के बिना भी दो महीने है। उस पर

राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा का प्रतिसंहरण या संसद के किसी भी सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति या गैर-अनुमोदन

केवल अपने संचालन पर रोक लगाने वाले के समक्ष घोषणा के अनुसार की गई कार्रवाई को किसी भी तरह से प्रभावित या अमान्य किए बिना काम करना बंद कर देता है। किसी भी निकाय ने अभी तक यह सुझाव नहीं दिया है, न ही कोई ऐसा कर सकता है, किसी भी औचित्य की झलक के साथ कि राष्ट्रपति को मूल संविधान द्वारा भी इतनी व्यापक शक्ति प्रदान की गई है जिसे पारित किया गया है और राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.) को अपनाया गया है।

97

भारत के लोगों द्वारा संविधान के मूल संघीय ढांचे के तथाकथित विनाश के लिए कोई प्रासंगिकता हो सकती है। इसमें मैं अपने लिए, अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने की कार्रवाई या अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत घोषणा के अनुसार की गई कार्रवाई के बीच कोई सराहनीय या प्रासंगिक अंतर नहीं देखता। राजनेताओं, राजनीतिक विचारकों, न्यायविदों और अन्य लोगों के बीच उचित और वास्तविक मतभेद हो सकते हैं कि क्या गृह मंत्री के कार्यकाल में अब तक प्रकट की गई प्रस्तावित कार्रवाई के आधार या भारत सरकार के कानून मंत्री के भाषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार को नहीं चलाया जा सकता है। सबसे पहले, अनुच्छेद 356 के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के लिए अन्य आधार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही खारिज कर दिया जाए, लेकिन प्रकट किए गए तथ्यों पर निकाले गए निष्कर्ष को इतना विकृत, गलत और स्पष्ट रूप से अस्थिर नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को यह कहने में सक्षम बनाया जा सके कि

न्यायालय घोषणा कर सकता है कि उद्घोषणा की प्रस्तावित कार्रवाई

इन तथ्यों पर उन मामलों की श्रेणी में आता है जहां न्यायालय

राष्ट्रपति को आदेश देकर धमकी भरी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित ठहराया जाए

या तो घोषणा जारी करने के लिए या एक की विधानसभा को भंग करने के लिए

विशेष राज्य। मैं, एक के लिए, सावधानीपूर्वक खुद को इससे बचाऊंगा

किसी भी राय को एक या दूसरे तरीके से व्यक्त करना सिवाय इसके कि

मेरे सुविचारित निर्णय में अब तक प्रकट किए गए तथ्य निश्चित रूप से और

विशेष रूप से निषिद्ध क्षेत्र और वहां निकाले गए निष्कर्षों के भीतर

से उचित रूप से संभव है, विशेष रूप से लेख की पृष्ठभूमि में

355. तथ्यों पर, जैसा कि वे हैं, यह मुश्किल है, बल्कि असंभव है

कहें कि प्रस्तावित घोषणा को दुर्भावनापूर्ण बनाया जा रहा है

एक गुप्त उद्देश्य के साथ। अन्य तकनीकी और बीमाकर्ता के अलावा

चढ़ाई योग्य कठिनाइयाँ जो वादी के रास्ते में हैं या

मांगी गई किसी भी राहत को प्राप्त करने के लिए मैंने सोचा है कि यह उचित है

अपने विनम्र तरीके से समर्थन में मुख्य आधार को इंगित करने के लिए

आदेश हम पहले ही घोषित कर चुके हैं।

फजल अली, जे. हमारे जैसे बड़े लोकतंत्र में लोकप्रिय रूप से निर्वाचित

कार्यकारी सरकार को कभी-कभी कठिन और नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

स्थिति और अपने कार्यों के अभ्यास में इसे कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है

कर्तव्यों का निर्वहन और भारी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो बहुत आसान नहीं हैं

या एक सुखद कार्य। जहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वहाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार राजनीतिक, नैतिक, कानूनी या नैतिक रूप से एक

प्रदत्त शक्तियों के विवेक का सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक प्रयोग

देश के संविधान द्वारा सरकार। भले ही

हो सकता है कि सरकार ने अपने सर्वोत्तम इरादों, अपने कार्यों के साथ काम किया हो। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं और दूसरों को खुश कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर

विवाद और समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो तत्काल और असंतोष का आह्वान करती हैं

कारखाना समाधान। कुछ राज्यों द्वारा दायर वर्तमान मुकदमे और

विधान सभा के तीन सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिकाएँ पंजाब के कारण कानूनी और संवैधानिक समस्याओं से ग्रस्त हैं

केंद्र सरकार द्वारा बैठक करने के लिए की गई कार्रवाई, इसमें क्या है राय एक अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति थी। मेरे प्रभु प्रमुख

न्याय ने वर्तमान मुकदमों के तथ्यों को संक्षिप्त रूप से विस्तृत किया है और याचिकाएँ और मेरे लिए इसे दोहराना आवश्यक नहीं है, सिवाय [1978] 1 एस. सी. आर. के।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

98

जहाँ तक वे निष्कर्षों के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं

जो मैं पहुँचता हूँ। मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूं कि मैं फैसले से पूरी तरह सहमत हूं।

पूर्ण कारण बताते हुए मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव

उस आदेश के लिए जिसे न्यायालय ने 29 अप्रैल को सर्वसम्मति से पारित किया था,

1977 , मुकदमों के साथ-साथ रिट याचिकाओं को भी खारिज करना और

अपने स्वयं के कारणों को उच्च देना पसंद करते हैं-कुछ महत्वपूर्ण को प्रकाश में लाना मामले में उत्पन्न होने वाले पी. ई. टी.

18 जनवरी 1977 के राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर

भारत के राजपत्र में प्रकाशित-असाधारण, भाग I-धारा 1

19 जनवरी, 1977 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने खंड के उपखंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख

(2) कला की। 85 संविधान ने लोकसभा को भंग कर दिया। यह

जल्द ही एक और अधिसूचना जारी की गई। 10 तारीख की अधिसूचना

फरवरी 1977 कानून, न्याय और कंपनी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया

मामलों ने सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव करने का आह्वान किया एस के अनुसार बेर। 14 (2) जनता का प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951। इस अधिसूचना के अनुसरण में चुनाव आयोग

सायन ने उसी दिन तारीखें निर्धारित कीं जब चुनाव होने थे

विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित। यह आदेश एस के तहत पारित किया गया था। 30 ol

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। अधिक विवरण नहीं है

इस मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से आवश्यक।

यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि चुनावों के परिणामस्वरूप जो थे

मार्च 1977 में आयोजित, कांग्रेस पार्टी बिहार में लगभग हार गई थी।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, और विशेष रूप से कुछ राज्यों में

कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए एक भी उम्मीदवार को वापस नहीं किया गया।

इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस ने लोकसभा में भी अपना बहुमत खो दिया।

वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद शपथ ली गई 24 मार्च, 1977 को पार्टी के नेता बने और उन्होंने अपनी परिषद का चयन किया।

25 मार्च, 1977 को मंत्री। इसके तुरंत बाद यूनियन होन

मंत्री महोदय ने उपरोक्त नौ राज्यों, बिहार, को एक पत्र संबोधित किया।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब,

राजस्थान और पश्चिम बंगाल, उन्हें अपने संबंधित लोगों को सलाह देने के लिए कहते हैं

राज्यपाल विधानसभाओं को भंग करेंगे और उनसे नए सिरे से जनादेश की मांग करेंगे

लोगों को।

छह वादी, अर्थात् राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश

प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा ने आवेदन किया है।

इस न्यायालय में वाद एक घोषणा के लिए प्रार्थना करते हैं कि गृह मंत्री अवैध और संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे

वादी पर बाध्यकारी और एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रतिबंध के लिए प्रार्थना की

केंद्र सरकार को कला का सहारा लेने से रोकना। 356 कॉन का

व्यवस्था। मैदान द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई थी

केंद्र सरकार को स्थायी रूप से रोकने के लिए विवाद

विधानसभाओं को उनकी सामान्य अवधि तक भंग करने के लिए कोई भी कदम उठाना छह साल पूरे हो गए। रिट याचिकाकर्ता जो कुछ सदस्य हैं

पंजाब विधान सभा ने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट याचिका दायर की है और इसी तरह के निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की है। वादियों की प्रार्थना और राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.) की भी प्रार्थना।

99

याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी/प्रतिवादी भारत संघ द्वारा गंभीरता से चुनौती दी गई है, जिसकी ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने कई प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं और गुण-दोष के आधार पर दावे को भी चुनौती दी है।

वादी द्वारा दावे की प्रकृति पर चर्चा करने के बाद, यदि

अब वादी और याचिकाओं द्वारा मुकदमों की स्थिरता के लिए प्रतिवादी द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्तियों की जांच करने के लिए तैयार रहें। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाई गई पहली प्रारंभिक आपत्ति यह थी कि मुकदमे कला के तहत बनाए रखने योग्य नहीं थे। 131 क्योंकि यह कला की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। 131 यह था कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होना चाहिए, और वर्तमान विवाद, वादी द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच है, जिस पर अनुच्छेद द्वारा विचार नहीं किया गया है। 131 संविधान से। हालाँकि, कुछ वादियों की ओर से श्री निरेन डे ने प्रस्तुत किया कि कला की भाषा। 131 यह न केवल राज्यों बल्कि राज्य सरकारों को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त है जो अकेले राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और राज्यों की ओर से किसी भी कानूनी अधिकार का संदर्भ दे सकते हैं।

इसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि

भले ही कला की पहली शर्त हो। 131 संतुष्ट है, कोई विवाद नहीं था जैसा कि कला द्वारा विचार किया गया था। 131. श्री निरेन डे ने इस तर्क का यह तर्क देते हुए खंडन किया कि गृह मंत्री का पत्र जिसमें उन आधारों का खुलासा किया गया है जिन पर केंद्र सरकार ने विधानसभाओं को भंग करने के लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया था, एक पर्याप्त विवाद था जिसमें वादी को अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का शीर्षक दिया गया था। 131 .

अंत में, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

जबकि वादी ने अस्थायी और स्थायी दोनों निषेधाज्ञाओं की राहत के लिए प्रार्थना की है, यह न्यायालय, कला के तहत एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। 131 संविधान की ओर से, निषेधाज्ञा के लिए राहत नहीं दी जा सकती है और एकमात्र राहत जो यह न्यायालय दे सकता है वह विशुद्ध रूप से घोषणात्मक होगी। हालाँकि, इस बिंदु को बाद में आदी द्वारा छोड़ दिया गया था।

राष्ट्रीय सॉलिसिटर-जनरल, और हमारी राय में सही है, क्योंकि एस। 204 संविधान से पहले के भारत सरकार अधिनियम, 1935 में एक स्पष्ट प्रावधान था, अर्थात। उप-एस। (2) जो एक घोषणात्मक को छोड़कर कोई भी राहत देने के न्यायालय के अधिकार को स्पष्ट रूप से बाधित करता है, जबकि अनुच्छेद में। 131 संविधान के उस विशेष खंड को जानबूझकर हटा दिया गया है और भारत सरकार अधिनियम द्वारा उस खंड के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह न्यायालय कोई भी राहत प्रदान कर सकता है जो वह उपयुक्त समझता है और जो किसी विशेष मामले की आवश्यकताओं द्वारा उचित है।

द्वारा प्रस्तुत दलीलों की वैधता की जांच करने के लिए

पक्षकारों के लिए परामर्श, कला के प्रावधानों को निकालना आवश्यक हो सकता है। 131 संविधान का, जिसका अंतिम भाग इस प्रकार है:

" 131. उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता। - उप.

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, सुप्रीम [1978] 1 एस. सी. आर.

न्यायालय, किसी भी अन्य न्यायालय के अपवर्जन के लिए, प्राधिकृत होगा।

किसी भी विवाद में मुख्य क्षेत्राधिकार

(क) भारत सरकार और एक या अधिक के बीच

राज्य; या

((ख) भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या

एक तरफ के राज्य और एक या अधिक अन्य राज्य

दूसरा, या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच,

यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है

(चाहे कानून का हो या तथ्य का) जिस पर अस्तित्व या विस्तार

कानूनी अधिकार निर्भर करता है।

इस न्यायालय द्वारा इस उपबंध के अधीन निम्नलिखित उपबंधों पर विचार किया जाए: शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

((i) विवाद होना चाहिए;

((ii) विवाद सरकार के बीच होना चाहिए।

भारत और एक या अधिक राज्यों या सरकार के बीच

भारत और किसी भी राज्य या राज्यों का एक तरफ

और दूसरे पर एक या अधिक अन्य राज्य, या शर्त

दो या दो से अधिक राज्य;

(iii) कि विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल होना चाहिए (क्या

कानून या तथ्य) जिसका अस्तित्व या विस्तार कानूनी अधिकार निर्भर करता है; और

((iv) संविधान में कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

जिसका उपयोग इस तरह के विवाद को हल करने के लिए किया जा सकता है।

इससे पहले कि हम इन शर्तों को पूर्ववर्ती मामले के तथ्यों पर लागू करें, गृह मंत्री के पत्र की सामग्री के साथ-साथ उनके और कानून मंत्री द्वारा दिए गए प्रेस साक्षात्कारों को भी देखना आवश्यक हो सकता है, जो वादी के अनुसार गृह मंत्री से उन्हें प्राप्त संचार का एक अभिन्न अंग है। मेरे स्वामी, मुख्य न्यायाधीश ने प्रेस के बयानों के साथ-साथ राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों को लिखे गए गृह मंत्री के पत्र की सामग्री को भी विस्तृत रूप से निकाला है और मैं चाहूंगा कि मामले में वास्तविक विवाद उत्पन्न हुआ या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से उसमें निहित मुख्य बिंदुओं का संकेत दिया जाए।

गृह मंत्री का प्रेस को दिया गया बयान यहाँ निकाला गया है

पी। 25 1977 के मूल सूट संख्या 2 में और उसी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" हमने अपना सबसे गंभीर विचार दिया है

आभासी से उत्पन्न अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति

कांग्रेस के हाल के लोकसभा चुनावों में अस्वीकृति

कई राज्यों में उम्मीदवार। मुझे पंजाब याद है,

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

बड़े पैमाने पर लोग अब सम्मान नहीं करते हैं

इन राज्यों में कांग्रेस सरकारों का औचित्य, मतदाताओं से नए सिरे से जनादेश की मांग किए बिना सत्ता में बने रहना।

इसी तरह मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री के पत्र की सामग्री का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला जा सकता है:

" हमने अपना गंभीर और गंभीर विचार दिया है,

हाल के लोकसभा चुनावों में विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की आभासी अस्वीकृति से उत्पन्न सबसे अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति। हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि इससे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मतभेद की भावना पैदा हुई है। बड़े पैमाने पर लोग अब किसी पार्टी के सत्ता में बने रहने के औचित्य की सराहना नहीं करते हैं जिसे मतदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

(जोर दिया गया)

श्री शांति भूषण द्वारा आकाशवाणी के एक प्रमुख कार्यक्रम में दिए गए साक्षात्कार के उद्धरणों के प्रासंगिक हिस्सों को राजस्थान राज्य द्वारा दायर 1977 के मूल नल सूट संख्या 1 में पेपर बुक के अनुलग्नक 'बी' से भी उद्धृत किया जा सकता है जो इस प्रकार है:

" सभी के स्पॉट-लाइट कार्यक्रम में एक साक्षात्कार में

इंडिया रेडियो ने कहा कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता लोकतंत्र है, जिसका अर्थ है कि सरकार को लोगों की व्यापक सहमति के साथ तभी काम करना चाहिए जब तक उसे उनका विश्वास प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकारें लोगों का विश्वास खोने के बाद लोगों पर शासन करने का विकल्प चुनती हैं, तो वे अविकसित सरकारें होंगी।

(जोर दिया गया

बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता

संविधान लोकतंत्र था जिसका अर्थ था कि एक सरकार को लोगों की व्यापक सहमति के साथ तभी काम करना चाहिए जब तक उसे लोगों का विश्वास प्राप्त हो।

श्री शांति भूषण ने कहा कि केवल एक तथ्य यह है कि

जिस समय राज्यों में सरकार को लोगों का विश्वास प्राप्त था, उन्होंने उन्हें शासन करने का अधिकार तब तक नहीं दिया जब तक कि वे उस विश्वास का आनंद लेते रहें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें लोगों के निरंतर विश्वास को खुश करते हुए सरकार पर गंभीर संदेह किया जाता है, तो विधानसभा को समय से पहले भंग करने का प्रावधान तुरंत लागू हो जाता है।

प्रावधान न केवल शक्ति देता है बल्कि यह एक

कर्तव्य क्योंकि यह शक्ति कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात्, विधानसभा को तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए और सरकार को यह देखने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए कि क्या उसे शासन करने के लिए लोगों का निरंतर विश्वास है।

इस प्रकार गृह मंत्री द्वारा उठाए गए रुख का विश्लेषण करते हुए और

विधि मंत्री महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर भरोसा किया है ताकि विधानसभाओं को भंग किया जा सके और मुख्यमंत्री स्वयं राज्यपालों को तदनुसार सलाह दे सकें:

(1) कि हाल के लोकसभा चुनावों में आभासी अस्वीकृति से एक अप्रत्याशित राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी। संबंधित राज्यों में कांग्रेस उम्मीदवारों की,

अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सहित छह मुकदमों में वादी);

(2) कि बड़े पैमाने पर लोगों ने कांग्रेस सरकारों के लिए नए सिरे से जनादेश की मांग किए बिना जारी रखना समीचीन नहीं समझा, जब कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों में संबंधित राज्यों से पूरी तरह से हरा दिया गया था।
(3) कि संवैधानिक विशेषज्ञों ने गृह मंत्री को यह भी सलाह दी है कि राज्य सरकारों ने

लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो दिया;

(4) कि अनिश्चितता का माहौल है जिसने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर मतभेद की भावना पैदा की है;

(5) कि अनिश्चितता के ऐसे माहौल ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है

कानून और व्यवस्था के लिए खतरा;

(6) कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता लोकतंत्र है, एक सरकार को तब तक लोगों की व्यापक सहमति से काम करना पड़ता था जब तक कि उसे अपना विश्वास प्राप्त हो। अगर राज्य सरकार लोगों का विश्वास खो देती है तो यह उनके लिए अलोकतांत्रिक होगा

जारी रखें;

(7) कि यदि कोई ऐसी धारणा उत्पन्न होती है जिसमें लोगों का निरंतर विश्वास प्राप्त करने वाली सरकार पर गंभीर संदेह किया जाता है, तो विधानसभा को समय से पहले भंग करने का प्रावधान तुरंत आकर्षित होगा। जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ संविधान में निहित शक्ति को विधानसभा को भंग करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है और सरकार को लोगों के पास जाने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या उसे लोगों का निरंतर विश्वास है।

लोग उन्हें नियंत्रित करें।

वादी द्वारा दायर दस्तावेजों से ऊपर उद्धृत उद्धरणों की शुद्धता पर अतिरिक्त सॉलिसी द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

टोर-जनरल। श्री निरेन डे का तर्क है कि कानून मंत्री और गृह मंत्री द्वारा लिए गए रुख को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक स्पष्ट असहमति पैदा हुई ताकि इस न्यायालय द्वारा निर्णय की मांग की जा सके। मेरी राय में, विचार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई विवाद है या नहीं। मंत्रियों द्वारा या यहां तक कि सरकार द्वारा या एक पक्ष द्वारा दिए गए और दूसरे द्वारा अस्वीकार किए गए बयान विवाद के रूप में नहीं हो सकते हैं, जब तक कि राजस्थान बनाम संघ (फजल अली, जे।)

इस तरह का विवाद कानूनी अधिकार पर आधारित है। वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में एक "विवाद" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" मौखिक विवाद: तर्क का विरोध करके झगड़ा या

विरोधी विचारों या दावों की अभिव्यक्ति: विवादित बयान आघात "।

इसलिए, एक विवाद स्पष्ट रूप से यह मानता है कि ऐसे विरोधी दावे होने चाहिए जिन्हें एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की जाती है और जिसका विरोध किया जाता है

दूसरों के द्वारा। कला के आवश्यक अवयवों में से एक। 131 यह है कि

विवाद में कानून या तथ्य के आधार पर कानूनी अधिकार शामिल होना चाहिए। सवाल यह है

कौन सा कोई पूछेगा कि कानूनी अधिकार क्या है जो इसमें शामिल है

गृह मंत्री या कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान या गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र?

सरकारी अधिकारियों ने केवल परिणामों की व्याख्या की है

संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

विधानसभाओं का विघटन। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कला के तहत।

356 यह अकेले केंद्र सरकार है, जो अपनी परिषद के माध्यम से मंत्री, राष्ट्रपति को भंग करने की घोषणा जारी करने की सलाह दे सकते हैं

सभाएँ। "अन्यथा" शब्द में स्पष्ट रूप से एक आकस्मिकता शामिल है।

जहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य नहीं करता है लेकिन

अन्य तरीकों के माध्यम से, जिनमें से एक सलाह हो सकती है

मंत्रिपरिषद। कला के तहत। 74 संविधान द्वारा संशोधित

(बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976, जिसका प्रासंगिक भाग

इसे नीचे निकाला जा सकता है:

" प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।

राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख मंत्री जो अपने कृत्यों के प्रयोग में, इसके अनुसार कार्य करेगा -

ऐसी सलाह "।

मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देनी होती है और एक बार

सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना पड़ता है, वहाँ नहीं है

विवेक उसके अंदर रह गया। इस प्रकार यदि केंद्र सरकार चुनती है

राष्ट्रपति को एक विधानसभा को भंग करने की घोषणा जारी करने की सलाह दें,

राष्ट्रपति के पास घोषणा जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार को कानूनी अधिकार है एक के विघटन के लिए एक घोषणा जारी करने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करें

आवश्यक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में सभा जो मिनिस की परिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देते समय उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। द.

हालाँकि, राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह आदेश देता हो कि राज्य

सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए या उनकी सहमति मान ली जानी चाहिए।

मंत्रिपरिषद के समक्ष अपनी सलाह प्रस्तुत करते हुए

जहाँ तक राज्य से संबंधित किसी मामले के संबंध में राष्ट्रपति

विधानसभा के समाधान का संबंध है। अनुच्छेद 356 भी जो

राष्ट्रपति को भंग करने वाली घोषणा जारी करने की शक्ति देता है

विधानसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए या तो पूर्व की आवश्यकता हो।

या बाद में राज्य सरकार से परामर्श या सहमति

राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले। इन परिस्थितियों में, क्या यह हो सकता है कहा कि राज्य सरकारों को यह दावा करने का अधिकार है कि

कला के तहत एक आदेश। 356 राष्ट्रपति द्वारा पारित नहीं किया जाएगा या [1978] एस. सी. आर. दाखिल नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

104

एक घोषणा के लिए एक मुकदमा कि राष्ट्रपति को प्रतिबंधित किया जा सकता है

ऐसा आदेश पारित करना? राज्य सरकारों का अस्तित्व का अधिकार

356. यदि राष्ट्रपति परिषद की सलाह को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं केंद्र सरकार के मंत्री और एक घोषणा जारी करते हैं

विधानसभाओं को हल करने पर राज्य सरकारों को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है

कला में निहित संवैधानिक अधिदेश के लिए। 356. यह स्वीकार किया जाता है

श्री निरेन डे द्वारा कि यदि राष्ट्रपति, परिषद की सलाह पर मंत्रियों ने राज्य को भंग करने की अधिसूचना पारित की होगी

कला के तहत सभाएँ। 356 , वादी पूरी तरह से बाहर थे अदालत और मुकदमे बनाए रखने योग्य नहीं होते। यह नहीं है।

यह समझ में आता है कि स्थिति कैसे अलग या बदतर होगी, यदि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को उन आधारों के बारे में सूचित करके निष्पक्ष होने का विकल्प चुनती है जिनके आधार पर उन्हें अपने राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह देने के लिए कहा गया था। केवल यह तथ्य कि इस तरह के पत्र राज्य सरकार को अनावश्यक सलाह के आधार पर भेजे गए थे, कोई विवाद पैदा नहीं करेगा, यदि कोई पहले मौजूद नहीं था, और न ही इस तरह के आचरण से राज्य सरकार को निम्नलिखित निर्णय लेने का कानूनी अधिकार मिलेगा:

कला. 131. यदि राज्य सरकारों के पास ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है, या उस मामले के लिए कोई अधिकार नहीं है, तो वे घोषणा या निषेधाज्ञा के लिए अदालत के समक्ष कोई दावा नहीं कर सकते हैं। श्री निरेन डे ने हालांकि कहा कि यह तथ्य कि गृह मंत्री को राज्यपालों को विशेष विधानसभाओं को भंग करने की सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने के लिए मजबूर किया गया था और मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री की सलाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, यह दर्शाता है कि एक विवाद उत्पन्न हुआ था। हालाँकि, मेरी राय में, विवाद अच्छी तरह से आधारित नहीं लगता है। यह मानते हुए कि मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री के पत्र ने किसी तरह का विवाद खड़ा कर दिया था, जिस क्षण मुख्यमंत्रियों ने उस पत्र का जवाब दिया और गृह मंत्री द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा दिया, विवाद समाप्त हो गया और अस्तित्व में नहीं रहा। जब तक कि पक्षों के बीच कानूनी अधिकार को बढ़ाने में मौजूदा विवाद न हो, तब तक कला द्वारा प्रदान किया गया मंच। 131 इसका लाभ किसी भी पक्ष द्वारा नहीं उठाया जा सकता

है। संयुक्त प्रांत बनाम में संघीय न्यायालय के एक निर्णय से मैं अपने विचार में मजबूत हूं। गवर्नर नौर-जनरल इन काउंसिल, (1) जहाँ ग्वायर, सी. जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" संघीय न्यायालय ने एस। 204 (1) संविधान का

के बीच किसी भी विवाद में एक अनन्य मूल क्षेत्राधिकार अधिनियम

इसमें कोई भी प्रश्न शामिल है, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। यह स्वीकार किया जाता है

कि प्रांत का अब जुर्माना लगाने का कानूनी अधिकार है

चर्चा के तहत प्रांतीय राजस्व को श्रेय दिया जाता है और न कि छावनी निधि वैधता या अन्य पर निर्भर करती है

एस के बुद्धिमान। 106 1924 का अधिनियम। याचिकाकर्ता इनकार करते हैं कि धारा की वैधता, प्रतिवादी इस पर जोर देता है; और ऐसा लगता है

मेरे लिए कि यह स्पष्ट रूप से एक विवाद है जिसमें एक प्रश्न शामिल है

जिसका कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है।

(1) [1939] एफ. सी. आर. 124,136।

राजस्थान बनाम. यूनियन (फजल अली, जे.)

105

यह मामला कानूनी अधिकार से जुड़े वास्तविक विवाद का स्पष्ट चित्रण करता है। उस मामले में मुख्य विवाद इस सवाल के बारे में था कि क्या प्रांतीय राजस्व में जमा किया गया जुर्माना, न कि छावनी कोष में, छावनी के माध्यम से प्रांत या केंद्र सरकार का था। यह ध्यान दिया जाएगा कि संघीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि ऐसा विवाद स्पष्ट रूप से एस के दायरे में आता है। 204 (1) भारत सरकार अधिनियम जो कला के समान सामग्री में था। 131 संविधान से। वह मामला विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक है और यह तय करता है कि यह केवल ऐसे प्रकार के विवाद हैं जिन पर कला द्वारा विचार किया गया है। 131. इन कारणों से, इसलिए, मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

यह स्थापित नहीं किया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकार से जुड़ा कोई विवाद था, और इसलिए यह कला के आवश्यक अवयवों में से एक है। 131 पूरा नहीं किया गया

सूट अकेले इस मैदान पर बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई अगली प्रारंभिक आपत्ति

जनरल ने कहा कि भारत सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है

और राज्य क्योंकि क्या कला है। 131 अभिधारणा यह है कि विवाद

भारत सरकार और राज्यों के बीच निम्नानुसार होना चाहिए:

उचित अर्थों में खड़ा था, अर्थात्, राज्य में शामिल क्षेत्र

या इसमें शामिल स्थायी संस्थान, जैसे, राज्यपाल,

विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग और

जैसे। दूसरे शब्दों में, जहां केंद्र सरकार स्पष्ट करना चाहती है

विधानमंडल को पूरी तरह से या राज्यपाल की संस्था को समाप्त करने के लिए

या उच्च न्यायालय, यह एक ऐसा मामला होगा जो राज्य से संबंधित होगा

और राज्य सरकार को भी। मैं सहमत होने के लिए इच्छुक हूँ अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा प्रस्तुत विवाद। क्या कला है।

131 अपने तह में S.ate सरकार नहीं है जिसमें एक

मंत्रियों का विशेष समूह, लेकिन स्वयं सरकार, जो इसके लिए मौजूद है

कभी भी, भले ही सरकार चलाने वाले कर्मचारी बदल सकते हैं

समय-समय पर। संविधान का अनुच्छेद 12, जिसका दायरा

केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, यह प्रावधान करता है कि

" "राज्य" में भारत की सरकार और संसद शामिल हैं और

प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। यहाँ शब्द है " राज्य को एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम दिया गया है क्योंकि परिभाषा

मौलिक अधिकारों और इसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या से संबंधित है। जिन घटनाओं की व्यापक संभव अर्थों में व्याख्या की जानी चाहिए

ताकि अवधि में शामिल किसी भी संस्था से नागरिक की रक्षा की जा सके।

" राज्य "जिसमें न केवल राज्य की सरकार शामिल है, बल्कि

अध्याय IV जहाँ कला। 131 होता है और जो संघ से संबंधित है न्यायपालिका। वास्तव में "राज्य" शब्द का उल्लेख कला में किया गया है। 131 नहीं है।

संविधान में कहीं भी परिभाषित किया गया है। कला के तहत। 367 अगर कोई है

संविधान में परिभाषित नहीं किया गया शब्द का सहारा लिया जा सकता है

माध्य को समझने के उद्देश्य से सामान्य खंड अधिनियम, 1897

इस तरह के एक शब्द। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) परिभाषित करती है

" "इस प्रकार कहें:

" राज्य "

(क) प्रारम्भ होने से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956

इसका अर्थ है भाग ए राज्य, भाग बी राज्य या भाग सी राज्य; और 106

((ख) ऐसी शुरुआत के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में,

इसका अर्थ संघ की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य से होगा।

प्रावधान और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा:

केंद्र सरकार और किसी भी राज्य दोनों को शामिल करते हुए सरकार सरकार। इस प्रकार दी गई "राज्य" की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा।

एस में। 3 (58) सामान्य खंड अधिनियम जो "राज्य" में नहीं है राज्य सरकार को बदनाम करें।

कला के प्रासंगिक भाग। 1 और संविधान की धारा 3 इस प्रकार है:

" 1. संघ का नाम और क्षेत्र: --

(1) भारत, अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा।

(2) राज्य और उनके क्षेत्र विशिष्ट होंगे।

पहली अनुसूची में चित्रित किया गया।

(3) भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे

((क) राज्यों के क्षेत्र; (बी) पहली योजना में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश

द्वैत; और

(ग) ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है।

" 3. नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन,

मौजूदा राज्यों की सीमाएँ या नाम —

संसद कानून द्वारा -

(क) किसी भी क्षेत्र से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाना।

राज्य या यूनी द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों या भागों में राज्य या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी भाग में मिलाकर

राज्य;

(ग) किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना; ((घ) किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना;

(ई) किसी भी राज्य का नाम बदलें:

इन अनुच्छेदों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

जहाँ कहीं भी संविधान ने बिना किसी शर्त के "राज्य" शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ है "राज्य" अपने शब्द के सामान्य अर्थ में, अर्थात्,

संसद को क्षेत्र या क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने की शक्ति कोई भी राज्य। इसका राज्य सरकार या उसके लिए कोई संदर्भ नहीं है।

जो किसी विशेष दल द्वारा संचालित किसी विशेष राज्य सरकार के लिए मायने रखता है। इसलिए, मेरी राय में, कला में "राज्य" शब्द है। 131 इस सामान्य अर्थ में भी उपयोग किया गया है ताकि केवल क्षेत्र को शामिल किया जा सके

राज्य और उसमें निहित स्थायी संस्थान। एक विवाद

संस्थानों को चलाने वाले कर्मियों के बीच बढ़ना इससे परे है

कला की परिधि। 131. इसके अलावा, यह दिखाई देगा कि सी. एल. एस। (ए) और (बी) कला। 131 जानबूझकर और सलाह से "सरकार की सरकार" शब्द का उपयोग करें।

.

राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

107

भारत और एक या अधिक राज्य "। यदि इरादा मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित राज्य सरकार को भी इस प्रावधान के दायरे में लाने का था, तो "राज्य" शब्द का उपयोग करने के बजाय "एक या अधिक राज्य सरकार" शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए था। इसलिए, यह एक आंतरिक परिस्थिति है जो दर्शाती है कि संविधान के संस्थापकों का इरादा था कि विवाद को केवल भारत सरकार और राज्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, न कि उनके द्वारा उठाए गए विवाद को लाने के लिए।

एक विशेष मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित सरकार जो राज्य से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार, इस बिंदु पर मेरे निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, स्थिति यह है -

कि कला का आयात और उद्देश्य। 131 के बीच विवादों को तय करना है

एक राज्य और दूसरा या भारत सरकार और एक राज्य के बीच

या अधिक राज्य। संविधान के संस्थापकों ने उपयोग किया है कला में "राज्य" शब्द। 131 दोनों जानबूझकर और सलाह के साथ ताकि

राज्य को संघ की एक घटक इकाई के रूप में इसके साथ विचार करें

क्षेत्र और स्थायी संस्थान। कर्मचारियों के बारे में सवाल

जो इन संस्थानों को चलाते हैं, वे एक के अस्तित्व से पूरी तरह से असंबंधित हैं

किसी राज्य और भारत सरकार के बीच विवाद। केवल तभी जब

एक के किसी भी स्थायी संस्थान का पूर्ण उन्मूलन है

बता दें कि एक वास्तविक विवाद उत्पन्न हो सकता है। केवल एक अस्थायी विघटन

कला के तहत एक सभा। 356 एक के उन्मूलन के बराबर नहीं है

राज्य विधानसभा, क्योंकि इस तरह के विघटन के बाद के प्रावधानों के तहत संविधान चुनाव आने वाले हैं और एक नया विधानमंडल

स्पष्ट रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने के बाद अस्तित्व में आएगा उम्मीदवार। दुर्भाग्य से, इस न्यायालय का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है

सीधे इस बिंदु पर, लेकिन कला के सही और उचित निर्माण पर।

कला का दायरा। 131 संविधान से। इन कारणों से इससे पहले, मेरा मानना है कि जिन राज्य सरकारों ने विवाद उठाया है

इस मामले में कला में दिखाई देने वाले "राज्य" शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। 131

और इसलिए सूट इस आधार पर भी बनाए रखने योग्य नहीं हैं। मैं,

इसलिए, मेरे स्वामी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से मेरी सम्मानजनक असहमति दर्ज करें। इस विशेष बिंदु पर मुख्य न्यायाधीश और भाई न्यायाधीश।

इसी तरह रिट याचिकाओं के मामले में, अतिरिक्त सॉलिसिटर

याचिकाएँ। यह तर्क दिया गया कि सदस्यों के रूप में याचिकाकर्ताओं का अधिकार पंजाब विधान सभा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था क्योंकि

संविधान के भाग III द्वारा परिकल्पित। अधिक से अधिक, अधिकार

विधानसभा के सदस्यों के रूप में भत्ते प्राप्त करना केवल एक कानूनी कार्य था

विधानसभा के सदस्यों के रूप में उनके चुनाव के परिणामस्वरूप अधिकार। यह.

यह ऐसा अधिकार नहीं था जो संविधान से निकला हो। इस प्रकार तर्क दिया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल कि किसी भी फंड का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है

मानसिक अधिकार, याचिकाकर्ताओं को कला का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

32 भारत का संविधान। यह तर्क मांगा गया था

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री गर्ग द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि

एच. एच. महाराजाधिराज माधव मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए

राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य। वी. भारत संघ (1) कॉम

आर्थिक रूप से "प्रिवी पर्स केस" के रूप में जाना जाता है-भत्ते प्राप्त करने का अधिकार

याचिकाकर्ताओं द्वारा निस्संदेह संपत्ति का अधिकार था और

(1) [1971] 3 एस. सी. आर 9.

8-722 एससीआई/77 108 *

[

1978] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानसभा को भंग करने की धमकी दी गई थी, जिससे सीधे तौर पर खतरा था

संपत्ति का मौलिक अधिकार जो याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद के तहत दोनों था।

19 (1) (च) और कला। 31 संविधान से। बहुत आकर्षक हालांकि वे

हालाँकि, हम उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

श्री गर्ग। प्रिवी पर्स मामले में यह अदालत एक कानूनी मामले पर विचार कर रही थी

बिल्कुल अलग संदर्भ में, अर्थात् कला। 291 संविधान का जिसे तब से संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया है (छब्बीस)

संशोधन) अधिनियम, 1971। अनुच्छेद 291, जो उस समय था, पूर्व हो सकता है।

इस तरह से खींचा गया

" 291. शासकों की निजी बटुआ राशि:

जहाँ द्वारा की गई किसी वाचा या समझौते के तहत

के गठन से पहले किसी भी भारतीय राज्य का शासक

* इस संविधान में कर से मुक्त किसी भी राशि का भुगतान किया गया है।

डोमी की सरकार द्वारा गारंटी या आश्वासन दिया गया था भारत के किसी भी शासक या ऐसे राज्य को प्रिवी पर्स के रूप में

((क) ऐसी राशियों पर प्रभार लगाया जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा।

भारत की समेकित निधि, और

(ख) किसी भी शासक को इस प्रकार दी गई राशि से छूट दी जाएगी।

आय पर सभी कर।

इस प्रावधान का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि स्थापना

संविधान के जनक ने कुछ कानूनी अधिकारों की गारंटी देने की मांग की शासकों को भुगतान की गई राशि पर शुल्क लगाकर उन पर हमला किया गया

भारत की समेकित निधि। भुगतान करने वाले। शासकों के लिए बनाए गए थे

संविधान द्वारा ही इसकी गारंटी दी गई थी और यह इस विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए था और विशेष प्रावधान जो इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शासकों का अधिकार

कर मुक्त भुगतान प्राप्त करना केवल एक कानूनी अधिकार नहीं था। संविधान, लेकिन संपत्ति का अधिकार भी, क्योंकि एक आरोप था

शासकों द्वारा प्राप्त। दूसरे शब्दों में, संपत्ति का अधिकार पैदा हुआ संविधान के तहत शासकों द्वारा कब्जा किए गए दर्जे से सीधे

स्वयं प्रावधान और यह शासकों द्वारा एक प्राप्त करने पर परिणामी नहीं था

विधानसभा के सदस्यों के रूप में या अन्यथा विशेष स्थिति जो

उनकी बाद की स्थिति के अधिग्रहण के लिए परिणामी होगा। में

तत्काल मामले में, याचिकाकर्ताओं का अधिकार केवल एक सीमित अधिकार है क्योंकि यह केवल तब तक रहता है जब तक विधानसभा छह का अपना सामान्य पाठ्यक्रम चलाती है।

वर्षों से। यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो यह अधिकार भी समाप्त हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत एक घोषणा जारी करके। 356. दाहिनी ओर,

इसलिए, केवल तब तक रहता है जब तक ये दोनों आकस्मिकताएँ नहीं होती हैं।

इसके अलावा, संविधान किसी भी अधिकार की गारंटी या अनुमति नहीं देता है।

विधानसभा के सदस्यों को जो पुरस्कार उनके द्वारा दिए जाते हैं

स्थानीय अधिनियम या नियम। इन परिस्थितियों में, इसलिए, प्रिवी पर्स मामले का अनुपात निर्णय याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं हो सकता है। हेज, जे., द्वारा प्राप्त कानूनी अधिकार की प्रकृति से निपटते हुए

प्रिवी पर्स मामले में शासकों ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" जैसा कि मैं संतुष्ट हूं कि कला के तहत अधिकार हैं। 31 और

19 (1) (च) का उल्लंघन किया गया है यह आवश्यक नहीं है

अन्य अधिकारों का कथित उल्लंघन।

राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

109

मैं पहले इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पाने का अधिकार

कला के तहत प्रिवी पर्स। 291 यह एक कानूनी अधिकार है। उसी से

यह इस प्रकार है कि यह न्यायालयों के माध्यम से लागू करने योग्य अधिकार है

कानून। यह अधिकार निस्संदेह एक संपत्ति है। एक अधिकार

इसके द्वारा वार्षिक रूप से नकद अनुदान प्राप्त करने पर विचार किया गया है

एक संपत्ति होने के लिए न्यायालय-एम. पी. बनाम राज्य देखें। रनोजीराव शिंदे

और अन्र-(1968) 3 एस. सी. आर. 489। भले ही यह एक माना जाता है

उसी के रूप में पेंशन कानून के तहत देय है जिसका नाम अनुच्छेद है। 291 ,

वही संपत्ति है-माधोराव फाल्के बनाम देखें। की स्थिति

मध्य भारत-(1961) 1 एससीआर 957 "।

यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की टिप्पणियां उन याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं हो सकती हैं जिन्हें संविधान के भाग III में निहित कोई मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है। इन कारणों से, इसलिए, मेरी राय है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति अच्छी तरह से स्थापित है और प्रबल होनी चाहिए।

चूँकि हमने मुकदमों और गुण-दोष पर याचिकाओं को बड़े पैमाने पर सुना है

इसके अलावा, भले ही हम यह मान लें कि रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य हैं, हम मुकदमों और रिट याचिकाओं दोनों के गुणदोष पर विचार करेंगे। अब हम मुकदमों और रिट याचिकाओं के गुण-दोषों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि हम सोचते हैं कि वादी के मुकदमों के साथ-साथ

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।

गुण-दोष की बात करें तो इससे पहले तीन विवाद सामने रखे गए थे

हम वादी और याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा:

(1) कि गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र

मंत्री केंद्रीय सरकार द्वारा एक निर्देश के बराबर थे

संबंधितों को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्रियों को निर्देश

विधानसभाओं को भंग करने के लिए राज्यपाल

राज्यों के संघीय ढांचे में उग्रता पर विचार किया गया

संविधान द्वारा;

(2) कि भले ही गृह मंत्री का पत्र एक नहीं था

निर्देश, यह स्पष्ट रूप से अधिकार के लिए एक खतरे के बराबर था

वर्तमान सरकार पद पर बनी रहेगी और रहेगी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए जाने पर इसे भंग कर दिया जाता है।

नहीं किया गया;

(3) कि पत्र में उल्लिखित परिस्थितियाँ सहमत नहीं थीं

विधानसभाओं के विघटन के लिए पर्याप्त कारण

कला के तहत। 356 और केंद्र सरकार की कार्रवाई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने और हस्तक्षेप करने के लिए

प्रेस और ऑल इंडिया रेडियो में विचारों की मात्रा

एक दुर्भावनापूर्ण और रंगीन कार्रवाई जो पर्याप्त थी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को खराब करें।

राष्ट्रपति को कला का सहारा लेने के लिए दें। 356 कॉन का

व्यवस्था।

अंत में, श्री निरेन डे और श्री गर्ग ने भी उस कला को प्रस्तुत किया। 356 होगा।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

अब हम कौंस द्वारा उठाए गए तर्कों पर अलग से विचार करेंगे।

स्वयं पार्टियों के लिए। जहाँ तक पहले तर्क का संबंध है कि [1978] 1 एस. सी. आर. का पत्र।

गृह मंत्री से वादी के मुख्यमंत्रियों को-राज्यों की राशि

केंद्र सरकार द्वारा जारी एक निर्देश के लिए, यह स्पष्ट किया गया था

• वादी के लिए वकील कि केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था

संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत। मुखिया को निर्देश देना

विशुद्ध रूप से राज्यों से संबंधित मामलों में मंत्री। सबसे पहले,

पत्र की सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन और एक कुशल विश्लेषण

यह बिल्कुल नहीं दिखाता है कि यह केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश के बराबर है

मुख्यमंत्रियों के लिए सरकार। हालांकि गृह मंत्री ने

इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन के समापन भाग में

पत्र में उन्होंने बिना हस्तक्षेप किए केवल मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है

अपने पूर्ण विवेक के साथ। पत्र का अंतिम भाग

इस प्रकार निकाला गया

इसलिए, मैं आपकी सहमति के लिए ईमानदारी से आदेश दूंगा।

उपहास कि आप अपने राज्यपाल को इसे भंग करने की सलाह दे सकते हैं

अभ्यास में राज्य विधानसभा। अनुच्छेद 174 (2) के तहत शक्तियां

(ख) और मतदाताओं से एक नया जनादेश प्राप्त करें। यह

केवल हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, कॉन के अनुरूप होगा

संवैधानिक पूर्ववर्ती और लोकतांत्रिक प्रथाएँ "।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रमुख पर कोई मजबूरी नहीं लाई गई थी

गृह मंत्री द्वारा मंत्रियों और उन्होंने कुछ तथ्यों को बताने की मांग की

मुख्यमंत्रियों के विचार के लिए बहुत दबाव के साथ। द.

शब्द "आपके विचार के लिए ईमानदारी से सराहना करते हैं ताकि आप विज्ञापन कर सकें

vice "स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गृह मंत्री ने एक दोस्ताना देने की कोशिश की

मुख्यमंत्रियों को सलाह दें कि उन्हें तथ्यों में क्या करना चाहिए और

स्थिति की परिस्थितियाँ। "सलाह दे सकते हैं" शब्द आगे भारतीय हैं।

कहा कि गृह मंत्री का कोई अनिवार्य देने का इरादा नहीं था

इस मामले में मुख्यमंत्रियों को निर्देश। दूसरे शब्दों में, यदि उपरोक्त पत्र का ठीक से अर्थ लगाया जाता है तो यह पुलिस के कार्य से अधिक कुछ नहीं है।

एक सुझाव या एक सलाह या एक उत्साही अपील युक्त शिष्टाचार

मुख्यमंत्रियों को सलाह देने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए

राज्यपाल तथ्यों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभाओं को भंग करेंगे

उक्त दस्तावेज़ में प्रकट नृत्य। यह किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। मुख्यमंत्रियों पर और यह उनके लिए खुला है कि वे कार्रवाई करने से इनकार करें

गृह मंत्री द्वारा दी गई अनावश्यक सलाह जो मुख्यमंत्री ने दी

मंत्री पहले ही कर चुके हैं। पत्र को समग्र रूप से पढ़ना, जैसा कि मैं करता हूँ,

मैं इस पत्र को केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देश के रूप में नहीं मान सकता।

सरकार और जैसा कि कला द्वारा सोचा गया है। 256 और कॉन के 257

भारत का शासन। वास्तव में कला। 256 जो इस प्रकार चलता है:

" राज्यों और संघ का दायित्व: प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा।

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और कोई मौजूदा कानून जो उस राज्य में लागू होते हैं, और

संघ की कटौती की शक्ति इस तरह के देने तक विस्तारित होगी किसी राज्य को दिए गए निर्देश जो सरकार को दिखाई दें

भारत को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक होना चाहिए।

स्पष्ट रूप से उन सीमाओं को परिभाषित करता है जिनके भीतर पार्लिया की कार्यकारी शक्ति है।

मन मौजूद हो सकता है और कला द्वारा विचार किए गए निर्देश हो सकते हैं। 256 हो सकता है

अनुच्छेद द्वारा विहित सीमित क्षेत्र के भीतर ही राज्यों को दिया जाता है। 256 अर्थात्, संसद द्वारा बनाए गए मौजूदा कानूनों और राजस्थान बनाम संघ (फजल अली, जे.) के संबंध में।

111

कानून जो राज्यों में लागू होते हैं। अनुच्छेद 257 में संघ और राज्यों दोनों को इस तरह से काम करने के खिलाफ चेतावनी और चेतावनी दी गई है ताकि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह पैदा हो। अनुच्छेद 257 में भारत सरकार पर एक और प्रतिबंध है कि शक्ति का प्रयोग केवल कला में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाना है। 256 और 257।

मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश के उचित सम्मान के साथ, मैं असमर्थ हूँ

उनके इस विचार को स्वीकार करें कि पत्र में निहित निर्देश का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी स्पष्ट राय है कि पत्र कला द्वारा विचार किए गए निर्देश के बराबर नहीं है। 256 और संविधान की धारा 257 के अनुसार मुख्यमंत्रियों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है।

विशुद्ध रूप से एस के लिए दाग: संबंधित मामले, अर्थात्, विधानसभाओं को भंग करने के लिए राज्यपालों को सलाह देना। हमारा संविधान

इसमें विभिन्न घटकों पर नियंत्रण और संतुलन की एक अच्छी तरह से वितरित प्रणाली शामिल है, अर्थात्, संघ, राज्य, कार्यपालिका,

विधानमंडल और न्यायपालिका। प्रावधानों का विश्लेषण

संविधान बताएगा कि प्रत्येक घटक इकाई के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया गया है और उन्हें अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या कक्षा की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा, जैसा कि मेरे स्वामी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। एक चिकनी और इफ़ेक्ट सुनिश्चित करने के लिए

संविधान का विवेकपूर्ण, व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण कार्यकरण यह आवश्यक है कि संघ और राज्य निकट सहयोग से काम करें

एक-दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय। किसी भी टकराव से संवैधानिक पतन हो सकता है जिससे बचा जा सकता है।

परिस्थितियाँ। कला के तहत। 174 (2) खंड (ए) और (बी) राज्यपाल

सदन का सत्रावसान करने या विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। यह स्पष्ट है कि इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा आम तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। राज्य में मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री के पास राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह देने का निस्संदेह विवेकाधिकार है यदि कोई विशेष स्थिति इस तरह के कदम की मांग करती है। मुख्यमंत्री उन परिस्थितियों का आकलन करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं जिनके तहत

राज्यपाल को ऐसी सलाह दी जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार अनुच्छेद के तहत निर्देश देकर राज्य सरकार की इस कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 256 या कला। 257 संविधान का, क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन है

विशुद्ध रूप से राज्य से संबंधित मामला है और यह किसी भी कला के चारों कोनों में नहीं आता है। 256 या कला। 257 संविधान से।

यह भी तर्क दिया गया कि पत्र में निहित निर्देश

गृह मंत्री का हस्तक्षेप संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय व्यवस्था में गंभीर हस्तक्षेप के बराबर है और इसके आने की संभावना है।

राज्यों द्वारा प्राप्त स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती है। माई लॉर्ड द चीफ जस्टिस ने संविधान के संघीय पहलू पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और कहा है कि हमारा संविधान एक संघीय पैटर्न पर आधारित है, लेकिन डॉ. अंबेडकर को उद्धृत करते हुए, "संविधान का एक कड़ा सांचा है।

संघवाद "ताकि यह एक संघीय से एकात्मक स्तर पर जा सके, एसी

स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन। हमारे संविधान की संघीय प्रकृति

शिक्षा को मेरे लॉर्ड द चीफ जस्टिस और मैंने स्पष्ट रूप से समझाया है।

उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं और इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। यह है,

हालाँकि, मेरे लिए इस बिंदु पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 112 में

मेरा विचार है कि गृह मंत्री का पत्र बिल्कुल भी निर्देशात्मक नहीं है और इसलिए राज्य सरकार के स्वायत्त अधिकारों में हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बारे में कि अगर केंद्रीय सरकार द्वारा इस तरह के मामले में निर्देश दिया जाता तो क्या होता, यह विशुद्ध रूप से एक काल्पनिक प्रश्न है जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई जवाब नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मामले के इस दृष्टिकोण में यह स्पष्ट है कि वादी को इस घोषणा के लिए राहत नहीं मिल सकती है कि पत्र एक निर्देश के बराबर था और कानून के अधिकार के खिलाफ था और इसलिए वादी पर बाध्यकारी नहीं था। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि वादी ने स्वयं इस पत्र को निर्देश के रूप में नहीं लिया था और इसलिए गृह मंत्री को उन्हें दी गई सलाह को स्वीकार करने से इनकार करते हुए वापस लिख दिया था।

अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या

गृह मंत्री का पत्र विधानसभा को भंग करने की धमकी के बराबर है। हालांकि पत्र या साक्षात्कारों में यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं हैं कि संबंधित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी या बल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह मानते हुए भी कि पत्र में एक छिपी हुई धमकी थी, मैं यह देखने में विफल हूं कि वादी को किस तरह की राहत मिल सकती है, भले ही ऐसा ही हो। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने या ऐसा न करने की सलाह देने का अधिकार था। भले ही गृह मंत्री द्वारा धमकी दी गई हो, वे धमकी को नजरअंदाज कर सकते थे क्योंकि सलाह देने का अधिकार

विधानसभाओं को भंग करने के लिए राज्यपाल स्वयं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के थे, और जैसा कि मैंने संकेत दिया है कि केंद्रीय सरकार को मुख्यमंत्री के इस विवेक में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री गर्ग ने हालांकि कहा कि

केंद्र सरकार की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार के लिए खतरा थी और वह केंद्र सरकार को अनुच्छेद का सहारा लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करने का हकदार था। 356. सबसे पहले, मैंने पहले ही कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 32 संविधान से। यह मानते हुए कि उनके पास अधिकार था, धमकी इतनी आसन्न नहीं थी और याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना अपरिपक्व थी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जब याचिकाएं दायर की गई थीं। अंत में, यदि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति को अनुच्छेद के तहत

विधानसभाओं को भंग करने की सलाह देने की संवैधानिक शक्ति थी। 356 , न्यायालय उस शक्ति के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मौलिक अधिकार तब तक मौजूद था जब तक कि विधानसभा भंग नहीं हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 172 में ही यह प्रावधान है कि

प्रत्येक राज्य छह साल तक बना रहेगा, जब तक कि पहले भंग नहीं हो जाता। इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास अनुच्छेद द्वारा दिए गए अधिकार से बेहतर अधिकार नहीं हो सकता था। 172. यदि विधानसभा को छह साल से पहले, यानी इसकी पूरी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया गया था, तो संविधान के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा सकती थी कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें याचिकाकर्ताओं के पास संपत्ति का अक्षम्य अधिकार था जो खुद खतरे में था। याचिकाकर्ताओं का अधिकार, यदि कोई हो, केवल एक अस्थायी और असंबद्ध अधिकार था।

इन कारणों से, यहां तक कि राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

113

यदि गृह मंत्री के पत्र को एक परोक्ष धमकी माना जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल सकती है।

तीसरे तर्क पर आते हुए कि जिन परिस्थितियों में उल्लेख किया गया है

अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं को भंग करने के लिए पत्र पर्याप्त कारण नहीं था। 356 , इसे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि न्यायालय उन सामग्रियों की पर्याप्तता या पर्याप्तता में नहीं जा सकते थे जिनके आधार पर केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद कुछ भी दे सकती थी।

राष्ट्रपति को सलाह। यह भी तर्क दिया गया कि यह मामला नहीं था

एक न्यायोचित मुद्दा। इस तर्क का जवाब देने के लिए हमें दो अलग-अलग पहलुओं पर विचार करें। सबसे पहले, क्या मुद्दा था या नहीं

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने न्यायिक जांच की ओर इशारा किया कि सी. एल. से पहले भी। (5) जिसे संविधान द्वारा जोड़ा गया था (चालीस

दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, प्रिवी परिषद और उच्च न्यायालय एक ही थे। रिलायंस को रखा गया था

भगत सिंह और अन्य मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय v. द.

राजा-सम्राट, (1) जहां प्रिवी काउंसिल, प्रश्न पर निवास करती है आपातकाल का अस्तित्व न्यायसंगत था या नहीं

इस प्रकार:

" आपातकाल की स्थिति एक ऐसी चीज है जिसकी अनुमति नहीं है।

किसी भी सटीक परिभाषा का; यह बुलाने वाले मामलों की स्थिति को दर्शाता है

कठोर कार्रवाई के लिए, जिसे किसी के द्वारा इस तरह से आंका जाना है।

यह स्पष्ट से अधिक है कि किसी को सरकार होनी चाहिए-,

अर्नर जनरल, और वह अकेला। कोई अन्य दृश्य देखा जा सकता है

उन्होंने पूरे प्रावधान को पूरी तरह से अक्षम कर दिया।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

फिर भी, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया दृष्टिकोण सही है, तो

गवर्नर-जनरल का फैसला भी परेशान कर सकता है

(क) इस बोर्ड द्वारा यह घोषणा करते हुए कि एक बार अध्यादेश था

बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकुट के माध्यम से कार्यवाही में चुनौती दी गई

न्यायालय के समक्ष सकारात्मक रूप से साबित करना चाहिए कि

आपातकाल मौजूद था, या (बी) इस बोर्ड के निष्कर्ष के बाद

उदारता मौजूद थी, और यह कि अध्यादेश उन सभी के साथ जो इसका पालन करते हैं इस पर एड अवैध था।

वास्तव में, विवाद पूरी तरह से बिना आधार के है।

इसके चेहरे पर यह कहना कि एक एप्पेल की अनुमति देना बेकार होगा

इसके बारे में बहस करने के लिए। "

संघीय अदालत ने लाखी नारायण दास मामले में भी ऐसा ही विचार रखा था।

वी. बिहार प्रांत (2), जहाँ की प्रकृति और घटनाओं का वर्णन किया गया है

एक अध्यादेश में, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" खंड की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह है

केवल राज्यपाल और राज्यपाल जिन्हें संतुष्ट करना है

स्वयं उन परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में जो आवश्यक हैं

(1) एल. आर. 58 आई. ए. 169,172।

(2) [1949] एफ. सी. आर. 693,699

एक अध्यादेश की घोषणा। ऐसी आवश्यकताओं का अस्तित्व

सी. आई. टी. एक न्यायोचित मामला नहीं है जिसे अदालतें कर सकती हैं। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू करके निर्धारित करने के लिए कहा गया।

मैसर्स एस. के. जी. शुगर लिमिटेड के मामले में भी इस अदालत ने यही विचार रखा था।

वी. बिहार राज्य और अन्य (1) जहां इसे इस प्रकार मनाया गया था:

" हालाँकि यह अच्छी तरह से तय है कि आई. एम. एम. ई. की आवश्यकता है।

डायेट कार्रवाई और "एक अध्यादेश जारी करना एक मामला है। विशुद्ध रूप से राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए। वह.

परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में एकमात्र न्यायाधीश है

एक अध्यादेश बनाने की आवश्यकता। उनकी संतुष्टि यह न्यायोचित मामला नहीं है। इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

निर्णय की त्रुटि का आधार या अन्यथा

अदा

लत-देखें

पंजाब राज्य बनाम। सत पाल डांग (1969) 1 एस. सी. आर. 633 "।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यही विचार व्यक्त किया है।

रे में। ए. एस. श्रीरामुलु (2) जहाँ यह इस प्रकार मनाया गया था:

" हमने देखा है कि स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला है

जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत कार्य कर सकता है। दा इम।

ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में ऐसा नहीं है

स्थितियों की गणना करें और कोई संतोषजनक मानदंड नहीं है।

'प्रासंगिक विचार क्या हैं' के न्यायिक निर्धारण के लिए

टियोन। संतोषजनक मानदंडों की अनुपस्थिति से

प्रश्न एक जो आंतरिक रूप से राजनीतिक है और उससे परे है

अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई और उन लोगों के वजन के लिए विचार स्पष्ट रूप से राजनीतिक समझदारी के मामले प्रतीत होते हैं।

डोम, न्यायिक जांच के लिए नहीं "।

विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

आंध्र की एक अन्य खंड पीठ ने भी यही विचार रखा था।

एस. आर. के. हनुमंत राव बनाम में प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश राज्य। (3)

यह स्पष्ट है कि कला के तहत विवेक का प्रयोग। 356 द्वारा

राष्ट्रपति विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मामला है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से मिलने वाली सलाह पर निर्भर करता है। मंत्री परिषद स्थिति की जरूरतों, आसपास की परिस्थितियों, लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं और समय के स्वभाव का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है। यदि इन कारकों के समग्र मूल्यांकन पर मंत्रिपरिषद अपने राजनीतिक ज्ञान या प्रशासन की त्रियात्मक योग्यता में राष्ट्रपति को एक विशेष सलाह देने का निर्णय लेती है। न्यायालय इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जो पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे है। भले ही मुख्यमंत्रियों ने विधानसभाओं को भंग करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके विचार बाध्यकारी नहीं हैं

(1) [1975] 1 एस. सी. आर. 312,317
(2) ए. आई. आर. 1974 ए. पी. 106.

(3) (1975) 2 ए. डब्ल्यू. आर. 277.

राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

115

केंद्र सरकार पर जो अपनी राय बना सकती है। कला के तहत शक्ति का प्रयोग। 356 राष्ट्रपति द्वारा किया जाना एक ऐसा मामला है जो सीधे केंद्र की शक्तियों के प्रयोग के अंतर्गत आता है और इस शक्ति के प्रयोग में मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्रियों के विचारों से निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है। कोलेग्रोव वी।

ग्रीन (1) न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने बहुत उपयुक्त रूप से इस प्रकार टिप्पणी की:

" हमारी राय है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय से पूछते हैं

जो देने की अपनी क्षमता से परे है। यह एक

न्यायिक शक्ति पर वे माँगें जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है

"अधिकार क्षेत्र" के बारे में मौखिक बाड़ लगाना। इसका समाधान होना चाहिए।

जिन विचारों के आधार पर यह न्यायालय, समय-समय पर, विवादों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

जूडी को शामिल करना एक लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति शत्रुतापूर्ण है

लोगों की राजनीति में सहायक। और यह प्रति कम नहीं है।

यदि इस तरह का न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से राजनीतिक है तो यह अशुभ है।

प्रतियोगिता को कानून के अमूर्त वाक्यांशों में तैयार किया जाए।

यह स्पष्ट है कि न्यायालय के पास वे संसाधन नहीं हैं जो सरकार के हाथों में हैं ताकि वह उन राजनीतिक जरूरतों का पता लगा सके जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं और राष्ट्र की भावनाओं या आकांक्षाओं का पता लगा सके जिनके लिए एक निश्चित समय पर विशेष कार्रवाई की आवश्यकता होती है। न्यायालय के लिए इस प्रकार की जांच शुरू करना मुश्किल है। इस प्रकार संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद में खंड (5) जोड़कर क्या किया है। 356 न्यायालय द्वारा बहुत पहले निर्धारित कानून को वैधानिक मान्यता देना है।

श्री निरेन डे ने विद्वानों के तर्क के जवाब में प्रस्तुत किया

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल कि दो मामलों में प्रिवी काउंसिल के पास था

एक विपरीत दृष्टिकोण लिया। राजा सम्राट बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर रिलायंस को रखा गया था। बेनोआरी लाल सरमा (2) जहाँ विस काउंट साइमन, एल. सी. ने इस प्रकार कहा:

" उनके अधिपति रोलैंड प्रथम के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

कि ऐसी परिस्थितियाँ, यदि आवश्यक हो, उचित रूप से हो सकती हैं

यह निर्धारित करने में विचार किया गया कि क्या कोई आपातकाल उत्पन्न हुआ था; लेकिन, जैसा कि उस विद्वान न्यायाधीश ने आगे बताया, और, जैसा कि था

उच्च न्यायालय में पहले ही जोर दिया जा चुका है, सवाल क्या उस समय कोई आपातकाल मौजूद था जब एक आदेश था

नान्स बनाया जाता है और घोषित किया जाता है जिसका विषय है

गवर्नर-जनरल एकमात्र न्यायाधीश होता है। यह प्रस्ताव था

भगत सिंह बनाम में बोर्ड द्वारा निर्धारित। राजा द.

सम्राट-एल. आर. 58 एल. ए. 169 ",

हालाँकि उनके अधिपतियों की टिप्पणियों का पहला भाग कुछ हद तक श्री निरेन डे के तर्क का समर्थन करता है, लेकिन टिप्पणियों के दूसरे भाग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनके अधिपतियों ने भगत सिंह के मामले (ऊपर) में अदालत द्वारा निर्धारित प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया था। अतः इन परिस्थितियों में यह प्राधिकरण श्री निरेन डे की कोई सहायता करता प्रतीत नहीं होता है।

(1) [1945] 328 यू. एस. 549

(2) एल. आर. 72 आई. ए. 57,64।

रिलायंस को पैडफील्ड वी पर भी रखा गया था। कृषि मंत्री, मत्स्य पालन और खाद्य (1) जहाँ लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. ने कहा था निम्नलिखित है:

" यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि मंत्री ने,

या बाहरी विचारों से प्रभावित होना चाहिए

जिसे उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए था-या, इसके विपरीत,

विचार करने में विफल रहा, या विफल रहा होगा

जिन बातों ने उन्हें प्रभावित किया होना चाहिए था-अदालत ने

हस्तक्षेप करने की शक्ति "।

हालाँकि, ये टिप्पणियां श्री के तर्क का समर्थन नहीं करती हैं।

निरेन डे बिल्कुल। भले ही कोई मुद्दा न्यायोचित न हो, अगर परिधि

कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा निर्भर किए जाने वाले कार्य बिल्कुल अतिरिक्त हैं।

असंबद्ध और अप्रासंगिक, न्यायालयों के पास निस्संदेह शक्ति है

कार्यकारी शक्ति के इस तरह के प्रयोग की जांच करें। ऐसा न्यायिक

जांच वह है जो तब अमल में आती है जब कार्यकारी शक्ति रंगीन या दुर्भावनापूर्ण होती है और बाहरी पर आधारित होती है।

या अप्रासंगिक विचार। मैं इस मामले के इस पहलू पर थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। हालाँकि, यहाँ यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि एक आदेश कला के तहत पारित किया गया था। 356 न्यायिक जांच से मुक्त है

और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि राष्ट्रपति को अतिरिक्त द्वारा निर्देशित किया गया है न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है।

यह हमें इस तर्क के दूसरे पहलू पर लाता है, अर्थात्,

चाहे गृह मंत्री के पत्र में बताए गए तथ्य हों या

प्रेस या रेडियो साक्षात्कार केंद्र सरकार को राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देने का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

गृह मंत्री। सेन के मंत्रियों द्वारा किए गए ये दावे त्राल सरकार, हालांकि, में पढ़ा और समझा जाना है

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से स्थापित होने वाली मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे।

गृह मंत्रालय के आधार पर अधिसूचना सं।

जी. एस. आर. 353 (ई) दिनांक 26 जून, 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने एक घोषणा जारी की जिसमें घोषणा की गई कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसके तहत

आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा था। यह सूचना

घोषणा के बाद गृह मंत्रालय की एक अन्य अधिसूचना नं. जी. एस. आर. 361 (ई) दिनांक 27 जून, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के खंड (1) के तहत जारी किया गया। 359 संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए

किसी भी व्यक्ति के किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके दौरान आपातकाल की घोषणा लागू थी। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा रखरखाव (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 4) का पालन किया गया, जिसे 29 जून, 1975 को जारी किया गया था और भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा I दिनांक जून, 1975 में प्रकाशित किया गया था। पीपी। 213-15 . अध्यादेश की धारा 5 जोड़ी गई। 16 ए और उप-एस।

(1) एल. आर. [1968] ए. सी. 997,1007

राजस्थान बनाम. यूनियन (फजल अली, जे.)।

117

(6) एस. 16 ए बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को खुलासा करना आवश्यक नहीं होगा। एक निरोध आदेश के तहत हिरासत में लिया गया जिस आधार पर आदेश उस अवधि के दौरान दिया गया था जब ऐसे व्यक्ति के संबंध में की गई घोषणा लागू थी। इसके बाद 25 जनवरी, 1976 को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव (संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित किया गया, जिसमें उप-अनुभाग जोड़े गए। (9) से एस। 16 प्रधान अधिनियम का ए जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जिन आधारों पर निरोध का आदेश दिया गया था या एस के तहत किया जाना था। 3 किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसके संबंध में उप-धाराओं के तहत घोषणा की गई थी। (2) या उप-एस। (3) और ऐसी कोई जानकारी या सामग्री जिसके आधार पर

उप-धाराओं के तहत घोषणा। (2) या उप-धाराओं के तहत एक घोषणा या पुष्टि। (3) ऐसा किया गया था जिसे गोपनीय माना जाना था और इसे राज्य के मामलों के लिए संदर्भित माना जाएगा और इसका खुलासा करना लोक हित के खिलाफ होगा। इस प्रकार इस प्रावधान का प्रभाव यह था कि कोई भी न्यायालय उन सामग्रियों की मांग नहीं कर सकता था जिनके आधार पर निरोध का आदेश पारित किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान की गई किसी भी नजरबंदी को न्यायिक जांच से परे रखा गया था। जबकि यह स्थिति मौजूद थी, राष्ट्रपति ने 18 जनवरी, 1977 के आदेश द्वारा अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर दिया। 85 संविधान के रूप में

भारत सरकार के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 19 जनवरी, 1977 की लोकसभा सचिवालय अधिसूचना दिखाई देगी। नेरी, भाग I, धारा I, दिनांक 19 जनवरी, 1977। इसके बाद विधि मंत्रालय द्वारा 10 फरवरी, 1977 को अधिसूचना जारी की गई। न्याय

और कंपनी मामले उप-धाराओं के तहत पारित किए गए। (2) एस. 14 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान किया

उक्त अधिनियम और नियमों और आदेश के प्रावधानों के साथ - इसके नीचे। इस अधिसूचना के अनुसरण में चुनाव आयोग

भारत के सायन ने उसी दिन एक अधिसूचना जारी की

विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनावों की तारीखें जो अलग-अलग थीं

16 से 20 मार्च, 1977 तक। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार में 54 निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में 10 निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा में 4 निर्वाचन क्षेत्र थे।

हिमाचल प्रदेश में 40, मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 85

उत्तर प्रदेश में 42, पश्चिम बंगाल में 21, उड़ीसा में 21 और पंजाब में 13।

इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और

मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लोकसभा के परिणाम

पंजाब में निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा में 10 निर्वाचन क्षेत्र एक भी नहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वापस कर दिया गया। एक ही स्थिति

हिमाचल प्रदेश में प्राप्त किया गया जहां 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक नहीं

कांग्रेस का एकल उम्मीदवार चुना गया। मध्य राज्यों में प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, कांग्रेस पार्टी

ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश से बाहर

40 कांग्रेस पार्टी केवल एक सीट जीत सकी, जबकि राजस्थान में भी कांग्रेस को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उसे केवल

1 25 सीटों में से। उड़ीसा में भी कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिलीं।

21 में से और पश्चिम बंगाल में इसे 42 में से केवल 3 सीटें मिलीं। यह होगा।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित नौ राज्यों में कांग्रेस पार्टी व्यावहारिक रूप से पराजित थी। यह भी स्पष्ट है कि मतदाता जो

राज्यों में लोकसभा के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए मतदान किया 118

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1

978] 1 एस सी आर।

कमोबेश वही थे जिन्होंने पिछले चुनावों के दौरान राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था।

इस प्रकार, स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, यह स्पष्ट है

(1) कि पूरे देश में एक गंभीर आपातकाल लगा दिया गया था

कोशिश करें;

(2) कि नागरिक स्वतंत्रता को काफी हद तक वापस ले लिया गया था; (3) कि लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे

निलंबित;

(4) कि प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई थी; और

(5) कि न्यायिक शक्तियों को काफी हद तक अपंग कर दिया गया था।

नए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को नौ राज्यों में एक बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा और लोगों ने कांग्रेस पार्टी में पूर्ण विश्वास की कमी दिखाई। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के सामूहिक प्रभाव से एक उचित निष्कर्ष निकल सकता है कि लोगों ने न केवल लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ बल्कि चुनाव से पहले के बीस महीनों के दौरान केंद्र या राज्यों में समग्र रूप से कांग्रेस सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों और विचारधाराओं के लिए भी एक विशाल निर्णय दिया था। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि

गृह मंत्री द्वारा यह कहना कि राज्य सरकारों ने लोगों का विश्वास खो दिया है, उचित नहीं है या अनुच्छेद के तहत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। 356 बिनि थाखाय।

विधानसभाओं का समाधान।

यह इन स्वीकृत तथ्यों की पृष्ठभूमि में था कि केंद्रीय

सरकार ने यह राय बनाई कि राज्य सरकारों को लोगों से एक नया जनादेश मांगें क्योंकि उन्होंने आनंद लेना बंद कर दिया

संबंधित राज्यों के लोगों का विश्वास। दूसरे शब्दों में कहें तो। केंद्र सरकार ने सोचा कि संबंधित की प्रकृति से,

चुनाव के परिणाम एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

संबंधित राज्य सरकारों ने विश्वास खो दिया था

लोग। हालाँकि, यह वादी द्वारा जोरदार तर्क दिया गया था और

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल यह तथ्य कि कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया

लोकसभा में यह इस अटूट निष्कर्ष की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने भी उन राज्यों में लोगों का विश्वास खो दिया जहां वे भारी दबाव में थे।

बहुमत ताकि विधानसभाओं को भंग करने और नए सिरे से गठन का आह्वान किया जा सके

चुनाव। पंजाब राज्य की ओर से श्री एच. आर. गोखले,

तर्क दिया कि अतीत में भी अक्सर ऐसा हुआ था कि लोगों ने

लोकसभा के लिए एक दल और दूसरे दल के उम्मीदवारों को वोट दिया

राज्यों के लिए और एक समान अंतर द्वारा किया गया प्रतीत होता है

इस बार भी मतदाताओं ने श्री गोखले द्वारा उद्धृत उदाहरण था -

1967 के चुनाव। मेरी राय में यह अकेली परिस्थिति है

अधिक लाभप्रद प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परिधि को ध्यान में रखते हुए

पिछले चुनावों से पहले प्रचलित रुख क्या निष्कर्ष होना चाहिए

तैयार किया गया एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए और

अदालतों द्वारा नहीं। केंद्र सरकार, पूरी तरह से और

चुनाव परिणामों और पूर्व परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन

जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, आपातकाल के दौरान फंडा राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.)

119

लोगों के मानसिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, बंदियों का अदालतों में जाने का अधिकार लगभग पंगु कर दिया गया था, प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई थी, और यह स्थिति लगभग 20 महीनों तक बनी रही जब चुनाव हुए जिसके बाद लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ अपना स्पष्ट निर्णय दिया, जहां तक लोकसभा चुनाव का संबंध था, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ औचित्य हो सकता है कि राज्य सरकारों ने लोगों का विश्वास खो दिया था। यह सच है कि यदि केंद्र सरकार की राय बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित थी या यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत विचारों या गुप्त उद्देश्यों से निर्देशित थी, तो न्यायालय इस तरह की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण मान सकता था और इसे रद्द कर सकता था। डॉ. अक्षैबर लाल और

ओआरएस। वी. कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (1) यह न्यायालय यह समझाया गया कि दुर्भावना की वास्तविक प्रकृति और चरित्र क्या था कार्रवाई, और वॉरिंगटन, एल. जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया, जहाँ यह इस प्रकार देखा गया:

" अपीलकर्ताओं ने पूरी कार्रवाई को अभाव बताया। ईमानदारी से। कार्रवाई पर तभी सवाल उठाया जा सकता है जब वहअति अधिकार, और विदेशी या अप्रासंगिक उद्देश्य का प्रमाण केवल एक है क्रिया के अति अधिकार चरित्र का उदाहरण, जैसा कि देखा जा सकता है निम्नलिखित अंश में वॉरिंगटन, एल. जे. द्वारा संपादित किया गया:

" तब मेरा विचार है कि केवल वही मामला है जिसमें न्यायालय कर सकता है। किसी सार्वजनिक निकाय के किसी कार्य में हस्तक्षेप करना जो, इसका चेहरा, नियमित और इसकी शक्तियों के भीतर है जब यह हैयह वास्तव में अल्ट्रा वायर्स साबित हुआ, और यह कि संदर्भ तर्क में उद्धृत कई मामलों में निर्णयों में दुर्भावना, भ्रष्टाचार, विदेशी और अप्रासंगिक उद्देश्यों के लिए, संपार्श्विक और अप्रत्यक्ष वस्तुएँ, और इसी तरह, केवल जब चटाई के उदाहरण के रूप में ठीक से समझा जाता है
ters जो यदि मौजूद साबित हो जाता है तो अल्ट्रा स्थापित कर सकता है विचाराधीन कार्रवाई का चरित्र "।

उनके द्वारा की गई टिप्पणियों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

वॉरिंगटन, एल. जे., ऊपर निकाला गया।लेकिन यहाँ विचार करने के लिए गंभीर सवाल यह है कि क्या प्रमुख को मनाने की कोशिश में केंद्र सरकार की कार्रवाई मंत्री राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह दे सकते हैं कहा जाता है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या व्यक्तिगत उद्देश्यों या बाहरी साजिश से दूषित है साइडरेशन्स। यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल चाहता था कि अपनी पसंद का एक राष्ट्रपति है और इसलिए, यह भंग करना चाहता था सभी विधानसभाएँ और नए चुनावों का आदेश दें ताकि वे सक्षम हों

विभिन्न विधानसभाओं के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनें। सबसे पहले, इस तथ्य को साबित करने के लिए या यह दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से इन तथ्यों से प्रभावित थी, कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है विचार करें। दूसरा, यदि राज्यों में कांग्रेस की सरकारें

संबंधित लोग अपनी स्थिति के बारे में इतने निश्चित थे, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वे चुनौती का सामना करने में सक्षम क्यों न हों और नया जनादेश लेने के बाद

लोगों से अपने रुख को सही साबित करते हैं। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए ऊपर सूचीबद्ध परिस्थितियों को देखना होगा क्या उन परिस्थितियों से केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निष्कर्ष उचित कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अनुमान भी लगाएँ कि ऊपर वर्णित परिस्थितियों से, दूसरा अनुमान है कि मतदाता राज्यों के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं और लोकसभा समान रूप से संभव है कि वह अपने आप कार्रवाई न करे

केंद्र सरकार के दुर्भावनापूर्ण या अति अधिकार। यदि दो निष्कर्ष यदि संभव हो तो दुर्भावना की नींव ही गायब हो जाती है। दूसरी ओर, खुद से पूछने के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्याऊपर वर्णित परिस्थितियों में और जिस तरीके से लोगों ने आपातकाल और पोस्ट पर कार्रवाई की है और प्रतिक्रिया दी है आपातकाल के दौर में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा फैसला लौटाकर, यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार विशुद्ध रूप से अविवेकी द्वारा निर्देशित थी उपयुक्त या अयोग्य विचार या बाहरी या बाहरी उद्देश्य विधानसभाओं के लिए नए सिरे से चुनाव कराना चाहते हैं? इसका जवाब नकारात्मक होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ध्यान में रखते हुए ऊपर वर्णित परिस्थितियाँ, गृह मंत्री द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और कानून मंत्री को बाहरी नहीं कहा जा सकता है।

या अप्रासंगिक या दुर्भावनापूर्ण। मैदान के लिए वकील का तर्क इसलिए, इस मुद्दे पर मतभेद और याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया जाता है। इस समस्या का एक और पहलू भी है। यह मानते हुए कि गृह मंत्री द्वारा अपने पत्र में बताए गए कारण और आधार बाहरी या अप्रासंगिक हैं यह मामले का केवल पहला चरण है। दूसरा चरण-जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह है जो यह तब अस्तित्व में आता है जब मंत्रिपरिषद जानबूझकर और अंत में राष्ट्रपति को

सलाह देने का निर्णय लेते हैं। इसके अलावा और क्या आधार हो सकते हैं उस समय उनके द्वारा विचार किया जाना किसी का अनुमान है। यह काफी पॉज़िट है

कि मंत्रिपरिषद सलाह को आधारों पर आधारित कर सकती है गृह मंत्री के पत्र में उल्लिखित लोगों के अलावा। लेख 74 (2) जो इस प्रकार चलता है:

(2) सवाल यह है कि क्या कोई है, और यदि है तो क्या सलाह है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था जिसमें नहीं होगा किसी भी अदालत में पूछताछ की। किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में किसी भी जांच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का विषय राष्ट्रपति। इसलिए यह न्यायालय इस मामले की जांच नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में, वादी के वकील का तर्क और याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि जबकि

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत पारित आदेश। 356 जूडी से परे रखा गया है सी. एल. द्वारा सी. आई. एल. जांच। (5) कला की। 356 , लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यहाँ तक कि सम्मान में भी

सी. एल. (5) कला की। 356 , न्यायालयों के संचालन का एक सीमित क्षेत्र है उस में राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में दिए गए कारणों पर यदि न्यायालय पता लगाएँ कि वे बिल्कुल बाहरी और अप्रासंगिक हैं और इस पर आधारित हैं व्यक्तिगत और अवैध विचार न्यायालयों के लिए शक्तिहीन नहीं हैं

यदि सिद्ध हो जाता है तो दुर्भावनापूर्ण आधार पर आदेश को निरस्त कर दें। हालाँकि, हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय सरकार के पास किसी भी मनमाने या निरंकुश आदेश को पारित करने या अच्छी तरह से स्थापित कानूनी मानदंडों या राजनीतिक नैतिकता के सिद्धांतों के खिलाफ अपनी पसंद का कुछ भी करने के लिए एक पूर्ण शक्ति के साथ एक स्वतंत्र लाइसेंस है। इस तरह

एक उपयुक्त मामले में मनमाना या नग्न कार्रवाई संविधान के साथ धोखाधड़ी हो सकती है और प्रयोग की गई शक्ति की जड़ों को नष्ट कर सकती है। वास्तव में अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यदि राजस्थान बनाम संघ (फजल अली, जे.)

कला के तहत कार्रवाई। 356 यह पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से बेतुका है या प्रति श्लोक या स्वयं-स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है और की गई कार्रवाई और कला के दायरे और उद्देश्य के बीच किसी भी तरह की सांठगांठ का पूर्ण अभाव है। 356 , ऐसे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप उपलब्ध हो सकता है। जिन कारणों से मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरी राय में, यह यहाँ की स्थिति नहीं है। हालाँकि, हम सोचते हैं कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद के रूप में इतने उच्च और परिपक्व

प्राधिकरण से इसकी कम से कम उम्मीद की जाती है। हम इस तथ्य पर भी जोर देना चाहेंगे कि चूंकि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए दिए गए कारणों की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, इसलिए हम केंद्र सरकार से संविधान के कामकाज पर दूरगामी परिणाम देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेने, बहुत सावधानी और सावधानी के साथ और कुछ मात्रा में निष्पक्षता के साथ कार्य करने की उम्मीद करते हैं ताकि

इसके फायदे और नुकसान और विभिन्न रंगों और विशेषताओं पर विचार करें। उनके सामने शांत और एकत्रित तरीके से समस्याएं हैं। पथप्रदर्शक ऐसे मामलों में सिद्धांत बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण होना चाहिए। और संविधान को मजबूत और संरक्षित करने का इरादा, और हम क्या उम्मीद है कि इस मामले पर सरकार गंभीरता से ध्यान देगी

वार्निश। सी. एल. द्वारा दी गई अंतिमता की मुहर। (5) कला की। 356 में से संविधान केंद्र सरकार को मुफ्त लाइसेंस का संकेत नहीं देता है। राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देना और कारणों पर आदेश पारित कराना। जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अप्रासंगिक हैं या जिनके पास बिल्कुल नहीं है आदेश के पारित होने के साथ संबंध। इस हद तक न्यायिक पुनः दृश्य शेष है। तत्काल मामले में, हालांकि, परिधि पर विचार करते हुए मंत्री को इस मुद्दे के साथ एक स्पष्ट संबंध मिला है, अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के अधीन आदेश पारित करना। 356 ऐसा करने के लिए राज्य विधानसभाओं को हल करें। दुर्भावनापूर्ण तर्क सामने रखा गया इसलिए, वादी और याचिकाकर्ताओं द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अब मैं मैदान के वकील द्वारा उठाए गए अंतिम विवाद पर आता हूं। झगड़ालू और याचिकाकर्ता। श्री गर्ग, याचिकाकर्ता के वाहन की ओर से पेश हुए ईमेंटली ने तर्क दिया कि कला। 356 बिल्कुल कोई आवेदन नहीं है वर्तमान मामले के तथ्य, क्योंकि यह अध्यक्ष को कोई शक्ति नहीं देता है विधानसभा को भंग करने के लिए। इस तर्क की जांच करने के लिए

बारीकी से, कला के प्रासंगिक भाग को निकालना आवश्यक हो सकता है। 356 इस प्रकार:

" 356. (1) यदि राष्ट्रपति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी राज्य का राज्यपाल या अन्यथा, संतुष्ट है कि एक स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसमें राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है इस विपक्ष के प्रावधानों के अनुसार किया जाए शीर्षक, राष्ट्रपति घोषणा द्वारा कर सकते हैं

(ए) के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं मान लें राज्य सरकार और सभी या कोई भी शक्तियाँ राज्यपाल या किसी निकाय में निहित या प्रयोग करने योग्य या विधानमंडल के अलावा राज्य में प्राधिकरण

(3) इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक घोषणा रखी जाएगी।संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष और [1978] 1 एस. सी. आर. को छोड़कर। जहाँ यह पिछले प्रो को रद्द करने वाली घोषणा है क्लैमेशन, दो की समाप्ति पर काम करना बंद कर देता है महीनों तक जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया है

(5) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, खंड (1) में उल्लिखित राष्ट्रपति की संतुष्टिअंतिम और निर्णायक होगा और प्रश्न नहीं होगा। किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में प्रस्तुत किया गया। कला का पहला भाग। 356 (1) राष्ट्रपति को जारी करने की शक्ति देता है एक घोषणा यदि वह राज्यपाल की रिपोर्ट पर संतुष्ट है घोषणा करने के लिए कहें या अन्यथा कहें। तत्काल मामले में किसी भी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की कोई रिपोर्ट नहीं है अन्य तरीकों पर कार्य कर सकता है जिसमें उसे दी गई सलाह शामिल है

मंत्रिपरिषद। एक और शर्त जो आवश्यक है

कला का अनुप्रयोग। 356 राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि राज्य सरकार के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

संविधान के प्रावधान। इस पर बहुत जोर दिया गया था। कला के घटक का हिस्सा। 356 (1) वादी के वकील द्वारा और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सामग्री का एक अंश भी नहीं है यह दर्शाता है कि कोई आशंका थी कि सरकार राज्य को प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सका संविधान या संविधान का कोई उल्लंघन हुआ था

मशीनरी। हालाँकि, यह एक ऐसा मामला है जो उपजेसी पर निर्भर करता है। परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि मंत्रियों का। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेइस प्रश्न का विचार करना जैसे कि यह सलाह पर अपील में बैठा थामंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया या राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि परिधि को ध्यान में रखते हुए जिन नौ राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार बनने की संभावना लोगों का विश्वास खोने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यदि ऐसा है तो इसके बाद भी पद पर बने रहना पूरी तरह से अनुचित होगा। चरित्र में क्रैटिक। जैसा कि हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक से जुड़ा हुआ है सरकार का स्वरूप, यदि कोई विशेष राज्य सरकार बंद हो जाती है लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करे, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के अनुसार किया जाता है संविधान के प्रावधान। इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया जाता है।

संविधान के मूल भाव और भावना के अनुरूप। इन परिस्थितियों में, इसलिए, हमारे सामने रखे गए तथ्यों और सामग्रियों पर, दूसरा भाग कला में उल्लिखित। 356 प्रथम दृष्टया संतुष्ट प्रतीत होता है और वादी और पेटी के लिए विद्वान वकील का तर्कइस जमीन पर टियोनर टिकने योग्य नहीं हैं।

श्री गर्ग ने तब यह तर्क दिया कि खंड (3) का अवलोकन कला की। 356 और उसके परंतुक से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घोषणा यह केवल दो महीने की अवधि के लिए काम कर सकता है और इस अवधि की समाप्ति पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि विधानसभा भंग कर दी जाती है और यह कार्रवाई दो महीने के भीतर संसद द्वारा पुष्टि करने में सक्षम नहीं है, तो यह राजस्थान वी. यूनियन (फजल अली, जे.) के लिए अक्षम है।

संसद द्वारा अनुसमर्थन, और इसलिए, उचित निष्कर्ष यह होना चाहिए कि अनुच्छेद। 356 राज्यों में विधानसभाओं के विघटन सहित कुछ भी करने की किसी भी शक्ति को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह तर्क निस्संदेह आकर्षक और दिलचस्प है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर यह मुझे प्रभावित नहीं करता है। सबसे पहले, कला के तहत। 356 (1) (क) राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति अनुच्छेद में निहित है। 174 (2) संविधान जो राज्यपाल को विधान सभा का सत्रावसान या विघटन करने का अधिकार देता है। कला के बल से यही शक्ति है। 356 (1) (क) राष्ट्रपति को निहित रूप से प्रदान किया जाता है, और एक बार यह शक्ति कला के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। 356 (1) (क) राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की समान शक्ति ग्रहण करके विधान सभा को भंग करने का निस्संदेह अधिकार क्षेत्र है। 174 (2) . के. के. अबू बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ। भारत संघ और अन्य, () कला के इस विशेष पहलू की व्याख्या करते हुए। 356 निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" कला. 356 (1) (ख) राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है, जब भी वह राज्य में संवैधानिक टूटने से संतुष्ट है, अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करते हुए एक उद्घोषणा जारी करें कि " राज्य का विधानमंडल इसके द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जा सकेगा। संसद का अधिकार "। इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति। इसलिए कोई रिसॉर्ट नहीं है राष्ट्रपति को कला के प्रावधानों की आवश्यकता होती है। 356

(1) (क) कला के साथ पढ़ें। 172 या कला। 174 राज्य को भंग करना विधान सभा। राज्य को भंग करने की शक्ति विधानमंडल सी. एल. में निहित है। (1) ((ख) कला। 356 स्वयं "। मैं उपरोक्त टिप्पणियों का पूरा समर्थन करता हूं जो मामले के इस विशेष पहलू पर इस विषय पर सही कानून निर्धारित करते हैं। कला के रूप में। 356 संविधान के भाग XVIII में होता है जो

आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में, यह स्पष्ट है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तो कोई मंत्रिपरिषद मौजूद नहीं होती है और इसलिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह लेने का कोई अवसर नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, इसलिए, मेरी स्पष्ट राय है कि कला। 356 (1) (क) अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शक्तियां प्रदान करता है। 174 (2) राष्ट्रपति पर स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में और मैं अनुमान नहीं लगा सकता केवल इस तथ्य से शक्ति का अपवर्जन कि घोषणा दो महीने के बाद समाप्त होने वाली है। भले ही विधानसभा को भंग करने के आदेश को सी. एल. के तहत संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। (3) कला की। 356 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीएल। (3) की गई कार्रवाई, कार्यवाही पूरी, परिणाम और आदेशों को नहीं छूता है

निष्पादित किया। जिस समय संसद नियंत्रण का प्रयोग करती है, ये सभी कार्य पहले ही हो चुके हैं और समय को पीछे हटाना या उन कार्यों को उलटना संभव नहीं है जो पहले ही किए जा चुके हैं और पूरे किए जा चुके हैं, और न ही संविधान के संस्थापकों द्वारा ऐसी आकस्मिकता पर विचार किया गया था। इसलिए मैं असमर्थ हूँ

इस मुद्दे पर श्री गर्ग के तर्क पर जोर दें।

श्री गर्ग और श्री भाटिया ने भी आगे तर्क दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए यह मानते हुए भी कि कला. 356 (1) (क) राज्यपाल को अनुच्छेद द्वारा दी गई शक्ति प्रदान करता है। 174 (2) यह अध्यक्ष के विवेक का उचित प्रयोग होगा।

चरम रास्ता अपनाने के बजाय विधानसभा को स्थगित करने के लिए डेंट डिसॉल्व का। एनजी यह। हालाँकि, यह विशुद्ध रूप से एक ऐसा मामला है जो इसके भीतर निहित है। राजनीति का क्षेत्र। न्यायालय अपने विवेक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

राष्ट्रपति के लिए और न ही यह न्यायालय की भूमिका निभाने के लिए है राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद को क्या करना चाहिए, इसके बारे में सलाहकार किसी विशेष घटना में करें। केंद्र सरकार जो सलाह देती है

राष्ट्रपति तथ्यों का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है जो यह तय करता है कि किसी विशेष मामले में कौन सा मार्ग अपनाया जाना चाहिए, अर्थात्, क्या विधान सभा को स्थगित किया जाना चाहिए या भंग किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए इन दोनों में से कोई भी कार्रवाई करने के लिए खुला है और यदि वह एक दूसरे को पसंद करता है, तो यह मामला न्यायिक समीक्षा से परे है। इन कारणों से, मेरी स्पष्ट राय है कि कला। 356 राज्यपाल की प्रकृति या कार्यों पर कोई स्पष्ट या निहित सीमाएँ नहीं हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत किया जाना है। 356 (1) (ए)।

मैं आम तौर पर दूसरी ओर अपने लॉर्ड द चीफ जस्टिस से सहमत हूं। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के संबंध में उनकी टिप्पणियों के संबंध में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से चर्चा किए गए बिंदु जिसे मैं किसी भी राय को व्यक्त करने से बचूंगा, क्योंकि इस मामले में निर्णय के लिए वास्तव में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सर्वसम्मत आदेश के समर्थन में ये मेरे कारण हैं इस न्यायालय द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को मुकदमों और रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए और निषेधाज्ञा और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं को खारिज करते हुए।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(मुकदमे और याचिकाएं खारिज)।

एसआर.